{ संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 16 अप्रैल 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

संघ को कांग्रेस की फिर से चुनौती

अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जरिये कांग्रेस ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह कहकर बड़ी ललकार लगाई है कि 'लोकसभा का आसन्न चुनाव मनुवाद से देश को बचाने तथा संविधान की रक्षा के लिये है।' नागपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे के पक्ष में सोमवार को आयोजित एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए खरगे ने साफ किया कि उनके लिये 'यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या नितिन गडकरी के खिलाफ नहीं बल्कि मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है।' उल्लेखनीय है कि नागपुर में ही संघ का मुख्यालय है और ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विरूद्ध मैदान में हैं। खरगे ने चेताया कि अगर इस बार के चुनावों में भाजपा व मोदी की जीत होती है तो देश में फिर कोई चुनाव नहीं होंगे।

खरगे द्वारा जनता को आरएसएस के गढ़ में खड़े होकर चेताना एक तरह से उन्हें इस चुनाव के महत्व एवं स्थिति की गम्भीरता से अवगत कराना है। देश किस नाज़ुक स्थिति में है- यह संदेश जनसामान्य तक जाना ज़रूरी है। संघ की देश के स्वतंत्रता आंदोलन से अनुपस्थिति की आलोचना करते हुए खरगे ने कहा कि अब ये लोग (भाजपा वाले) राममंदिर तथा बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर वोट मांगने आते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इतने वर्षों तक संघ के लोगों ने अंबेडकर की एक तस्वीर भी नहीं लगाई और कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज तक नहीं लगाते थे। मोदी के पिछले दस वर्षीय कार्यकाल में देश की गिरती जीडीपी, भ्रष्टाचार आदि के बारे में मोदी का दोहरा रवैया आदि अनेक बातें थीं, लेकिन उनके भाषण का केन्द्र संघ की विचारधारा को चुनौती देना रहा जिसका संदेश दूर तक जायेगा।

यह पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस ने संघ की सोच को उसके ही मुख्यालय में चुनौती दी हो। पिछले साल 28 दिसम्बर को कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस इसी शहर में मनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिये थे। तब भी खरगे ने अपने भाषण में कहा था कि इस आयोजन के लिये उनकी पार्टी ने नागपुर को इसलिये चुना है ताकि जनता में संदेश जाये कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के बल पर आगे बढ़ेगी। वह संघ की विभाजनकारी तथा नफ़रती विचारधारा के विरोध में खड़ी रहेगी। वैसे नागपुर के उस कार्यक्रम के बहुत पहले ही संघ के खिलाफ कांग्रेस की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत उसी दिन से मानी जानी चाहिये जब 7 सितम्बर, 2022 को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की लगभग 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। उन्होंने इसका नाम दिया था- 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दूकान'। यह नारा अपने आप में संघ पर खुला प्रहार था। इसके साथ ही कांग्रेस की संघ से वैचारिक लड़ाई का बड़ा व खुला स्वरूप देशवासियों के सामने आ गया था।

अपने दो कार्यकालों में मोदी व भाजपा ने जो अनेक तरह की प्रशासनिक अराजकता व आर्थिक बदहाली फैलाई है, उसे अगर एक तरफ रख दें तो जनता के बीच वैमनस्यता फैलाना तथा विभिन्न सम्प्रदायों व वर्णों को आमने-सामने खड़ाकर उसका राजनैतिक फायदा उठाना ही भाजपा का प्रमुख हथियार बन गया है। राहुल की यात्रा 30 जनवरी, 2023 को श्रीनगर के लालचौक में झंडा फहराने के साथ समाप्त हुई थी। यात्रा के दौरान पुनर्रचित विमर्श के माध्यम से कांग्रेस ने संघ व भाजपा की विचारधारा से सीधी लड़ाई प्रारम्भ की थी। यह लड़ाई परवान चढ़ी मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हुई 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के नाम से निकली राहुल की दूसरी यात्रा से। इसका समापन हुआ था 18 मार्च को मुम्बई पहुंचकर। अगले दिन यहीं के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में संयुक्त प्रतिपक्ष 'इंडिया' के बैनर तले हुई विशाल रैली ने साबित कर दिया कि संघ की विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिये लोग अब कांग्रेस के साथ हैं।

नागरिकों के लिये न्याय हासिल करना संघ एवं भाजपा के साथ लड़ाई का एक अन्य महत्वपूर्ण मोर्चा है। संघ एक तरफ़ सामाजिक विद्वेष फैलाता है, तो दूसरी ओर उसकी मान्यता नागरिक आजादी छीनने और आर्थिक गैरबराबरी में भरोसा करती है। संघ तमाम राजनैतिक व आर्थिक शक्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सौंप देने में विश्वास करता है। पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखें तो यही साबित होता है।

आज कांग्रेस को नया रूप और लौटी हुई शक्ति इसी लड़ाई के ऐलान से प्राप्त हुई है। कांग्रेस का वैचारिक आधार ही संघ तथा उसकी संकीर्ण व मध्ययुगीन सोच के मुकाबले समतामूलक व न्यायपूर्ण समाज की रचना करना है। कांग्रेस के लिये यह कोई नयी बात नहीं है क्योंकि देश ने देखा है कि लगभग 65 वर्षों तक भारत इसी रास्ते पर चला है। बीच में कई बार ऐसा भी हुआ जब भारत में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं, परन्तु देश व संविधान के निर्माताओं द्वारा जो राह दिखाई गयी थी, उससे किसी ने भी अलग राह नहीं पकड़ी। स्वतंत्रता, समानता व बन्धुत्व पर आधारित समाज और शासन प्रणाली देखने के आदी हो चुके भारत को जब मोदी एवं भाजपा ने अलग राह पर हांकने की कोशिश की तो उसे कुछ हद तक कामयाबी तो ज़रूर मिली लेकिन जैसे-जैसे भाजपा के काम करने के कुटिल उद्देश्य व बुरे परिणाम आने शुरू हुए, देश को समझ में आने लगा कि उसके लिये वही सारा कुछ सही है जो आजादी की लड़ाई के नायकों ने तय किया था। कांग्रेस को भी पता चल गया है कि उसकी ताकत का राज संघ के विरोध में है। प्रगतिशील व लोकतांत्रिक लोगों की उससे अपेक्षा भी यही है।

सुप्रीम कोर्ट की बाबा रामदेव को फटकार

पिछले कुछ दशकों में भारत में कई बाबाओं का उदय हुआ है। इसके पहले भी बाबा हुआ करते थे मगर इन दिनों बाबाओं का जितना राजनैतिक और सामाजिक दबदबा है, उतना पहले शायद कभी नहीं रहा कई बाबा अनेक तरह के काले कामों में लिप्त भी पाए गए हैं मगर उनकी दैवीय छवि के चलते उनके अपराधों को नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर उनके आश्रम के एक कर्मी शंकर रमण की हत्या का आरोप था। सत्य सांई बाबा के प्रशांति निलयम में भी एक हत्या हुई थी. गुरमीत राम रहीम के कुकर्मों को उजागर करने के लिए पत्रकार छत्रपति रामचंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। अंतत: राम रहीम कानून के पंजे में फंस गया और इन दिनों जेल में है. यह अलग बात है कि वो अधिकांश समय पैरोल पर बाहर रहता है। आसाराम बापू लम्बे समय तक कानून की पकड़ से दूर रहे मगर अब वह सीखचों के पीछे है। इस समय बागेश्नर धाम नामक एक बाबा काफी लोकप्रिय हैं। ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। देश में असंख्य बाबा हैं जो अपने-अपने अंधभक्तों की भीड़ से घिरे रहते हैं। उनकी रईसी देखते ही बनती है।

दो अन्य बाबाओं का ज़िक्र ज़रूरी है। एक हैं -श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने अपने उत्सव के लिए यमुना को बर्बाद कर दिया था। वे अन्ना हजारे के आरएसएस-समर्थित आन्दोलन से भी जुड़े हुए थे। फिर बाबा रामदेव हैं। रामदेव ने अपने कॅरियर की शुरुआत योग गुरु के रूप में की थी। लेकिन बाद में उन्होंने पतंजलि ब्रांड नेम से व्यापार शुरू कर दिया। आयुर्वेदिक उत्पादों को बनाने और बेचने वाली इस कंपनी ने बाबा रामदेव को अरबपतियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है और उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है या कम से कम अब तक तो नहीं था। उनके आयुर्वेदिक उत्पादों का जबरदस्त प्रचार-प्रसार हुआ और मीडिया का एक बड़ा तबका उनका गुणगान करने लगा।

बाबा और आचार्य की शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बहुत नहीं जानते। इस समय देश में कई आयुर्वेदिक कॉलेज हैं मगर इन दोनों के पास शायद आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं हैं। पड़ताल से बचने के लिए रामदेव ने देशभक्ति का लबादा ओढ़ लिया और यह कहते रहे कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं।

असली खेल शुरू हुआ कोविड-19 महामारी के दौरान। एक ओर सरकार ने पुणे स्थित भारत बायोटेक को कोवैक्सीन का विकास और उत्पादन करने हेतु भारी आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई वहीं बाबा रामदेव ने यह दावा किया कि उनकी कंपनी ने कोविड-19 के इलाज और उससे बचाव के लिए एक दवाई विकसित की है जिसका नाम है कोरोनिल। हमें यह भी बताया गया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुमोदन प्राप्त है। जब आयुष मंत्रालय ने इस दावे को चुनौती दी तो पंतजलि की ओर से यह कहा गया कि कोरोनिल 'डब्लूएचओ के मार्गनिर्देशों के अनुरूप है'। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के बारे में दावों को सत्यापित करने से इंकार कर दिया। इसके बाद भी कोरोनिल के कांबो पैक को बड़ी धूमधाम से दो केबिनेट मंत्रियों- डॉ. हर्षवर्धन और नितिन गडकरी, की उपस्थिति में जारी किया गया। हर्षवर्धन स्वयं एलोपैथिक डाक्टर हैं। इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति से यह जाहिर है कि वे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के कितने अंधभक्त हैं।

बाबा ने दावा किया कि कोरोनिल का परीक्षण मामूली से लेकर मध्यम श्रेणी के कोविड संक्रमण से पीड़ित लोगों पर किया गया और कोरोनिल का सेवन करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका कोविड टेस्ट निगेटिव हो गया। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में किसी भी नई दवा को सामान्य उपयोग के लिए जारी करने के पहले उसका जैव रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, पशुओं पर उसका परीक्षण किया जाता है और फिर समुचित आकार के नमूनों पर उसकी 'डबल ब्लाइंड' ट्रायल की जाती है। कोरोनिल के मामले में इनमें से कुछ भी नहीं किया गया।

राम पुनियानी

> आस्था पर आधारित ज्ञान और उससे जुड़ी चिकित्सा प्रणालियों पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। हर बाबा अपनी तरह से रोगों का इलाज करता है। चिकित्सा प्रणालियों के प्रोटोकाल में लगातार सुधार इसलिए होता रहता है क्योंकि उसकी समीक्षा करने का अधिकार सभी को होता है। इसके विपरीत रामदेव जैसे लोग अपने दैवीय दर्जे का लाभ उठाते हुए मनमाने दावे करते हैं और उन्हें न तो कोई चुनौती देता है और न कोई उनकी आलोचना करता है।

अपनी व्यवसायिक सफलता से गदगद बाबा रामदेव ने गोदी मीडिया की प्रशंसा को कबूल किया। इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एलोपैथी को एक बेवकूफाना विज्ञान बताना शुरू कर दिया। इससे व्यथित होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने रामदेव के खिलाफ प्रकरण दायर किया जिसकी सुनवाई हाल में हुई। रामदेव ने अदालत में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अपमान करन के लिए आईएमए से क्षमायाचना की। यहां पाठकों को यह याद दिलाना श्रेयस्कर होगा कि बाबा रामदेव ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी तब उन्होंने यह दावा किया था कि योग के कारण उनका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि वे लंबे समय तक बिना भोजन के रह सकते हैं। मगर उपवास प्रारंभ करने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी हालत इतनी पतली हो गई कि उन्हें एक एलोपैथिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इसी तरह करीब एक वर्ष पहले जब आचार्य बालकृष्ण बीमार पड़े तो वे एक एलोपैथिक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो गए।

उच्चतम न्यायालय की चेतावनियों के बाद भी बाबा की कंपनी भ्रामक विज्ञापन जारी करती रही। अदालत ने उन्हें बुलाया और बाबा ने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। मगर अदालत ने उनकी माफी मंजूर नहीं की।

अदालत में चल रहे प्रकरण का नतीजा चाहे जो हो सवाल यह है कि देसी चिकित्सा पद्धतियों और आस्था पर आधारित ज्ञान के आधार पर कोई भला किस तरह आधुनिक चिकित्सा पद्धति का मखौल बना सकता है? यह मानने से किसी को इंकार नहीं है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में ही नहीं बल्कि दादी मां के नुस्खों में भी कुछ ज्ञान हो सकता है। मगर आधुनिक चिकित्सा पद्धति साक्ष्य और साथी चिकित्सकों व वैज्ञानिकों की समीक्षा पर आधारित होती है। हर दावे को हर तरह की समीक्षा और समालोचना का सामना करना पड़ता है और इसके नतीजे में ही ऐसी चीजें विकसित होती हैं जो मानवता के लिए उपयोगी साबित होती हैं।

इसके विपरीत आस्था पर आधारित ज्ञान और उससे जुड़ी चिकित्सा प्रणालियों पर प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। हर बाबा अपनी तरह से रोगों का इलाज करता है। चिकित्सा प्रणालियों के प्रोटोकाल में लगातार सुधार इसलिए होता रहता है क्योंकि उसकी समीक्षा करने का अधिकार सभी को होता है। इसके विपरीत रामदेव जैसे लोग अपने दैवीय दर्जे का लाभ उठाते हुए मनमाने दावे करते हैं और उन्हें न तो कोई चुनौती देता है और न कोई उनकी आलोचना करता है। बाबा ने यह दावा भी किया था कि वे कैंसर और एड्स का इलाज भी कर सकते हैं। वे तो समलैंगिकता को भी एक रोग मानते हैं और उनका दावा है कि वे इलाज से उसे ठीक कर सकते हैं।

अब तक उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और इसी के चलते वे इतने अहंकारी हो गए थे कि वे एलोपैथी का मजाक बनाते थे और 'अपनी' प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताते थे।

बाबा लोग इतने मजे में क्यों हैं? इसका कारण यह है कि पिछले कुछ सालों में भारत में धर्म के नाम पर राजनीति का बोलबाला बढ़ा है। इसके साथ ही प्राचीन ज्ञान का भी महिमामंडन किया जा रहा है। वैज्ञानिकता और तार्किकता में विश्वास करने वाले लोग चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा जाए। यही बात डॉक्टर दाभोलकर, गोविंद पंसारे, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश कहते थे। और उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज हमारे देश में तार्किक सोच और पद्धतियों को परे हटाकर केवल आस्था पर आधारित ज्ञान का ढोल पीटा जा रहा है। यहां तक कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी आस्था आधारित ज्ञान विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है।

बाबा रामदेव श्रद्धा और अंधश्रद्धा के कांबो से पीड़ित रोगी समाज के लक्षण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा की दुनिया में बाबाओं की मनमानी को रोकने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया)

5 ट्रिलियन का मोदी का लक्ष्य चूक गया, 5 साल के लिए आगे खिसकाया

■ के रवीन्द्रन

भाजपा के 2019 के घोषणापत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई थी, जो एक साहसिक लक्ष्य था, जिसे कर सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के बल पर हासिल किया जाना था। जैसे-जैसे देश समय सीमा के करीब पहुंच रहा है, पार्टी ने लक्ष्य हासिल करने के लक्ष्य को और आगे बढ़ा दिया है, अब 2029 तक, यानी लोकसभा के एक और कार्यकाल तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने का वायदा किया है।

शायद 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात से तंग आकर इस बार घोषणापत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लक्ष्य की बात की गई है, जिसका मूल अर्थ एक ही बात को अलग ढंग से कहना है। जापान, जिसे भारत प्रतिस्थापित करना चाहता है, की वर्तमान अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 4.2 ट्रिलियन और पीपीपी-समायोजित आकार 5.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो कमोबेश यह 2019 के लक्ष्य के अनुरूप है। यह कहना भी कम ही होगा कि भारत ऐसा करने में विफल रहा क्योंकि सपना सिर्फ टिमटिमाता रहा लेकिन प्रज्वलित नहीं हुआ। 'मेक इन इंडिया' अभियान विफल हो गया और 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण को अंतर्निहित गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा था।

> बुनियादी ढांचे का विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में भारी निवेश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पहुंच और सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया जैसी पहल पर ध्यान देने के साथ डिजिटलीकरण के प्रयास भी चल रहे हैं। ये सुधार, यदि सफल रहे, तो व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।

भारत का आर्थिक उत्थान वैश्विक आकर्षण का विषय बन गया है। नया लक्ष्य भी कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया पर आधारित है, जो संभावित और जोखिम दोनों से भरा मार्ग प्रस्तुत करता है।

भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका जनसांख्यिकीय लाभांश है। देश में एक विशाल युवा आबादी है, जिसमें 65 प्रतिशत से अधिक 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह आसानी से उपलब्ध कार्यबल में तब्दील हो जाता है, जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। युवा आबादी घरेलू खपत को भी बढ़ावा देती है, जिससे व्यवसायों के लिए एक बड़ा बाजार तैयार होता है। यह जनसांख्यिकीय लाभ कई दशकों तक बने रहने की उम्मीद है, जिससे भारत को आर्थिक विस्तार के लिए एक लंबा रास्ता मिलेगा।

बुनियादी ढांचे का विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में भारी निवेश तेजी से प्रगति कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पहुंच और सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया जैसी पहल पर ध्यान देने के साथ डिजिटलीकरण के प्रयास भी चल रहे हैं। ये सुधार, यदि सफल रहे, तो व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं और अधिक प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण बना सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अनुमान है कि भारत की निरंतर विकास दर, जो वर्तमान में 7 प्रतिशत से अधिक है, आने वाले वर्षों में इसे जर्मनी और जापान जैसी आर्थिक शक्तियों से आगे ले जायेगी। यह आशावाद इस विश्वास से उपजा है कि उपरोक्त सुधार, जनसांख्यिकीय लाभ के साथ मिलकर, आर्थिक गतिविधि का एक अच्छा चक्र बनायेंगे।

हालांकि, सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, भारत के आर्थिक सुपरस्टार बनने की राह में चुनौतीपूर्ण बाधाएं हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक आय असमानता है। जबकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो रहा है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी में रहता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इससे न केवल सामाजिक अशांति पैदा होती है बल्कि घरेलू खपत भी सीमित होती है, जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है।

एक अन्य चुनौती ग्रामीण स्थिरता है। जबकि शहरी केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र लगातार पिछड़ रहे हैं। इससे विकास में असमानता पैदा होती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने की क्षमता सीमित हो जाती है। समावेशी और सतत विकास के लिए इस अंतर को पाटना महत्वपूर्ण है।

नियामक वातावरण भी विवाद का एक मुद्दा है। आलोचकों का तर्क है कि नियमों का जटिल जाल निवेश को हतोत्साहित करता है और नये प्रयासों को रोकता है। घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और बनाये रखने के लिए नियमों को सुव्यवस्थित करना और अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक होगा।

घरेलू चुनौतियों के अलावा, बाहरी कारक भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय बढ़ती मुद्रास्फीति से जूझ रही है, जिससे भारत की विकास संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा, यूक्रेन में चल रहे युद्ध जैसे भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और तेल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की लागत में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता पर और असर पड़ेगा।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अधिक यथार्थवादी समय-सीमा 2030 की शुरुआत हो सकती है। यह उन चुनौतियों को स्वीकार करता है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है और आर्थिक विकास के लिए अधिक नपे-तुले दृष्टिकोण की अनुमति देता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के होंगे। इसकी सफलता आय असमानता और ग्रामीण ठहराव जैसी आंतरिक बाधाओं को दूर करने की क्षमता के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितताओं से निपटने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि भारत अपनी ताकत, विशेषकर अपनी युवा आबादी का लाभ उठा सके और प्रभावी सुधार लागू कर सके, तो दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब उसकी पहुंच में हो सकता है। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, व्यवसायों और समग्र रूप से आबादी के ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। भारत का आर्थिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन चुनौतियों पर काबू पाने और अपनी क्षमता को निरंतर और समावेशी विकास में कैसे परिवर्तित किया जाता है।

पावन प्रसंग

नवरात्रि में आदि शक्ति महागौरी स्वरूप की उपासना

मां दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी हैं। जो देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है देवी उनके पापों को नाश करती हैं और शुद्ध अंत:करण देती हैं। मां अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका वर्ण पूर्णत: गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां महागौरी की आराधना से मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। उजले वस्त्र धारण किये हुए महादेव को आनंद देवे वाली पवित्रता की मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी हैं।

इनका वर्ण पूर्णत: गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चन्द्र और कुन्द के फूल से की गई है। इनका दाहिना ऊपरी हाथ में अभय मुद्रा में और निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। बांये ऊपर वाले हाथ में डमरू और बांया नीचे वाला हाथ वर की शान्त मुद्रा में है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि व्रियेअहं वरदं शम्भुं नान्यं देवं महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार इन्होंने शिव के वरण के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया था इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव जी ने इनके शरीर को पवित्र गंगाजल से मलकर धोया तब वह विद्युत के समान अत्यन्त कांतिमान गौर हो गया, तभी से इनका नाम गौरी पड़ा।

महागौरी आदी शक्ति हैं इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाश-मान होता है इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। मां महागौरी की अराधना से भक्तों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है।

दुर्गा सप्तशती में शुम्भ निशुम्भ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वह महागौरी हैं। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ जिसने शुम्भ निशुम्भ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी हैं यही शिवा और शाम्भवी के नाम से भी पूजित होती हैं।

मां महागौरी पूजा विधि-नवरात्रि के दसों दिन कुंवारी कन्या भोजन कराने का विधान है परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी मां को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने मां की पूजा की है उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की पंचोपचार सहित पूजा करें। महागौरी रूप में देवी करूणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं।

महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है इसके जिसके अनुसार, एक सिंह काफी भूखा था, वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठीं तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है, और मां उसे अपना सवारी बना लेती हैं क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं।

संजीव ठाकुर

आपके पत्र

बंधुआ मजदूरी का जीवन जीने को मजबूर हैं ईंट भट्ठे के मजदूर

ईंट भट्ठों पर मजदूर दिन-रात काम करते रहते हैं. यहां पर काम का कोई समय निर्धारित नहीं है। सारा काम पीस (ईंट के टुकड़े) पर निर्धारित होता है. उसी आधार पर मजदूरी मिलती है। हालांकि ईंट भट्टों पर मजदूरों को नियमित रूप से मजदूरी नहीं मिलती है। शुरुआत में पेशगी दी जाती है और बीच-बीच में खाने के खर्चे के नाम पर 15 दिन में एक बार खर्चा दिया जाता है। भीलवाड़ा जिले के कई ईंट भट्टों पर तो बिहार के मजदूरों को खाने के खर्चे के नाम पर पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। उन्हें पैसे के नाम पर सिर्फ एक पर्ची दी जाती है। इस पर्ची से उन्हें एक निश्चित राशन दुकान पर जाकर बिना मोल भाव किये सामान खरीदना होता है। यह दुकान भी भट्ठा मालिक व इनके ही किसी रिश्तेदार की ही होती है। भट्टों पर मजदूरी का हिसाब व भुगतान सीजन के अंत में ही होता है। जहां इनके राशन के पैसे भी काट लिए जाते हैं। कई बार सीज़न के अंत में बहुत से मजदूरों को राशन और अन्य भुगतान का हवाला देकर उनके पैसे काट लिए जाते हैं और नाममात्र की मज़दूरी अदा की जाती है।

इस संबंध में भट्टे पर काम करने वाले उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के मिथलेश रैदास बताते हैं कि 'मैं यहां के ईंट भट्टों पर पिछले कई सालों से परिवार सहित काम कर रहा हूं। यहां पर जितनी मेहनत लगती है हमें उसकी आधी मजदूरी भी नहीं मिलती है। यह ऐसा जाल है जिसमें एक बार कोई मज़दूर आ जाता है तो पूरे सीजन भर के लिए उलझकर रह जाता है। हमारी मजबूरी है इसलिए हम इतना दूर आकर यहां इतना मेहनत वाला काम करते हैं। हमें शुरुआत में पेशगी देकर बांध दिया जाता है और भट्ठा मालिक व ठेकेदार उस दबाव में पूरे सीजन काम कराता रहता है। अगर हम जैसे अनपढ़ों के लिए गांव में ही रहकर रोज़गार का कोई इंतज़ाम हो जाता तो हमें इतनी दूर परिवार के साथ प्रवास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन पैसे के लिए हम यहां बंधुआ मज़दूरी करने के लिए विवश हैं।'

ईंट भट्ठा मजदूरों के काम के समय के आधार पर देखा जाए तो इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। ईंट भट्ठे गांवों से दूर होने की वजह से उनके बच्चे शिक्षा व स्वास्थ्य से कोसों दूर हैं। वहीं दूसरे राज्य के निवासी होने के कारण सरकारी योजनाएं इनकी पहुंच से बाहर होती हैं। यहां के ज्यादातर मजदूर वोट देने के अधिकार से भी वंचित रहते हैं, क्योंकि यह मजदूर अक्सर बाहर के राज्यों में ही काम करते हैं। ऐसे में जब चुनाव होते हैं तब मतदान के समय भट्ठे मालिक इन मजदूरों को घर नहीं जाने देता है ताकि उसके काम का किसी प्रकार से नुकसान न हो। वोट बैंक नहीं होने के कारण स्थानीय राजनीतिक दल भी इनके हितों के लिए आवाज़ उठाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।

इन ईंट भट्टों पर मजदूरों को कर्ज देकर काम पर लाया जाता है। उन्हें कभी भी नियमित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। यह मजदूर कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यह सब भट्ठा मालिक की मर्जी पर निर्भर होता है। इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है एवं भट्ठों पर काम करने का कोई हाजरी रजिस्टर, काम व मजदूरी का हिसाब संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं होता है। जिससे यह साबित किया जा सके कि कौन मज़दूर किस भट्ठे पर कब से काम कर रहा है और उसकी मज़दूरी कितनी है? यूं कहें कि इतने सारे श्रम कानूनों के बावजूद एक भी श्रम कानून इन ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मज़दूरों पर लागू नहीं होता है।

शैतान रेगर,
भीलवाड़ा राजस्थान

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

मोदी 3 की आर्थिक चुनौतियां

आरती कुमारी

पिछले कुछ समय से तमाम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पंडितों को धता बताते हुए भारत, वैश्विक अपेक्षाओं से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इसी के फलस्वरुप पूरी दुनिया अब भारत को निर्विवाद रूप से सबसे तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था मान चुकी है। इसी क्रम में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद तेजी से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। परंतु इसी के साथ अपने प्रतिस्पर्धी एवं पड़ोसी देश चीन के साथ अपनी तुलना करने पर हमें कुछ कठोर यथार्थ का भी सामना करना पड़ता है। आज नहीं तो कल वैश्विक मंच पर चीन को पछाड़ने के लिए हमें ऐसे कठोर यथार्थ को स्वीकार करते हुए उन सभी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जहां हम चीन से पीछे रह गए हैं।

एक और जहां चीन का प्रति कैपिटा इनकम 12000 अमेरिकी डॉलर से अधिक है वहीं दूसरी ओर भारत का प्रति कैपिटा इनकम मात्र 2200 अमेरिकी डॉलर है। एक तरफ चीन ने अपने देश से गरीबी का उन्मूलन कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर भारत में गरीबी एक यक्ष प्रश्न है। देश की आजादी के समय भारत की स्थिति चीन से काफी बेहतर थी, परंतु भारत के अर्थव्यवस्था के विकास में हुई कुछ भारी गलतियों के कारण हम चीन से विकास की रफ्तार में बहुत पीछे छूट गए थे जिसे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में सरकार के अथक प्रयासों के बलपर बदतर होने से रोकते हुए सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ हो पाई है और दुनिया उसके प्रारंभिक रुझान कुछ समय से देख रही है। परन्तु मोदी-3 के लिए भी आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियाँ कम नहीं हैं। बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मोदी -3 सरकार को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य साधने के क्रम में देश की कुछ कठिन चुनौतियों के स्थायी और ठोस समाधान की कर आगे बढ़ना होगा। आज इन्हीं चुनौतियों और समाधानों की चर्चा इस लेख में की जा रही है।

करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा: अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर देश अपने आयात एवं निर्यात का एक खाता रखता है। यह वैसा ही है जैसे हमारा बचत खाता सभी निकासी एवं जमा पैसों का अलग अलग हिसाब रखता है। सभी आयात एवं निर्यात संबंधी गणना को बैलेंस आफ पेमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो तरह के खाता होते हैं पहले कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। कैपिटल अकाउंट में वह सभी ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं जिससे किसी दीर्घकालिक एसेट या लायबिलिटी से संबंध रखते हैं। उदाहरण स्वरूप कोई कर्ज लेना एक लायबिलिटी है तो कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एसेट का निर्माण करता है। इसके इतर करंट अकाउंट वह खाता है जहां दर्ज किए गए ट्रांजैक्शन किसी एसेट अथवा लायबिलिटी से संबंध नहीं रखते। यह करंट अकाउंट पुनः दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला ट्रेड अकाउंट जिसमें सभी वस्तुएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, कृषि संबंधित उत्पाद आदि तथा दूसरे इनविजिबल अकाउंट में सेवाएं, लाभांश, दान, उपहार, ब्याज आदि को दर्ज किया जाता है। यदि करंट अकाउंट के इन्हीं ट्रेड एवं इनविजिबल खातों का कुल योग ऋणात्मक होता है तो इसे करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। यही करंट अकाउंट डेफिसिट भारत की लगभग एक स्थाई समस्या बन चुकी है। आसान शब्दों में भारत लंबे समय से निर्यात कम करता है और आयात अधिक करता है। हम विश्व मंच पर एक आयात प्रधान देश बन कर रह गए हैं। यद्यपि केंद्र की मोदी सरकार इस बात के लिए प्रशंसा की पात्र है कि इस क्षेत्र को गंभीरता से लेते हुए अपने दूरगामी लक्ष्य पर जिस प्रकार से कार्य कर रही है उसी का परिणाम है कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट कम होने की और अग्रसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल-सितंबर 2022 के 48.8 बिलियन डॉलर के मुकाबले आधे से अधिक घटकर वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 17.5 बिलियन डॉलर का हो गया। परंतु इस घाटे से उबर कर सरप्लस अकॉउंट बनने में अभी समय लगेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो भारत का ट्रेड अकाउंट 189.45 बिलियन के घाटे के साथ बंद हुआ जबकि इनविजिबल अकाउंट में 150.7 बिलियन डॉलर का सरप्लस मौजूद था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत सेवाओं के क्षेत्र में तो मजबूत स्थिति में है परंतु वस्तुओं के निर्यात में स्थिति चिंताजनक है। अब प्रश्न यह जाता है कि आखिर चालू खाता घाटा देश के विकास के लिए इतना खतरनाक क्यों है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को व्यापार करने के लिए विदेशी या अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता की मुद्रा की आवश्यकता होती है। यदि चालू खाता सदैव घाटे में रहेगा तो अपना व्यापार बनाए रखने के लिए उसे देश को हर साल अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का उपयोग करना पड़ेगा और इस तरह से उसे देश का यह रिजर्व बेहद कमजोर हो जाएगा। और अंततः ऐसे देश दिवालिया घोषित हो जाते हैं। भारत के साथ अच्छी बात यह है कि साल दर साल हमारे चालू खाते का घाटा देश के कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से बैलेंस हो जाता है और इस तरह से भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार मजबूत होता रहता है। परंतु कैपिटल अकाउंट को मजबूती विदेशी निवेश तथा कर्ज से मिलती है और इसलिए बहुत हद तक इस पर वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थितियों का नियंत्रण होता है। मंदी की चपेट में आते ही किसी देश का कैपिटल अकाउंट सरप्लस खत्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा प्राकृतिक गैस के आयात पर संकट उत्पन्न हो सकता है और इन पर संकट का अर्थ है देश में गंभीर स्थितियां पैदा होना। साथ ही कैपिटल अकाउंट का मूल्यवर्धन होने का अर्थ लाभ, ब्याज एवं डिविडेंड के रूप में पैसा बाहर जाना भी होता है। इसलिए कैपिटल अकाउंट के बढ़ने से विदेशी मुद्रा कोष बढ़ रहा है तो यह है तो इसे पूर्णतया स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं माना जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला यह उपकरण भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।

करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करने के तरीके: भारत का बड़ा ऊर्जा आयातक होना इस घाटे में बड़ा रोल अदा करता है। आज भारत अपने पूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं का 80% विदेश से आयात करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में खनिज तेलों का आयात 4.59 लाख करोड़ का था। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 8.99 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इस दबाव को कम करने के लिए जरूरी है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार ने साल 2030 तक भारत की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय माध्यमों से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार देश में विद्युत चलित गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा आधारित अवसंरचनाओं पर बड़ा निवेश किया जा रहा है। साथ ही तात्कालिक परिणाम के लिए खनिज तेलों में एथेनॉल मिश्रण को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा 10% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को समय से पहले पूर्ण कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा स्वर्ण के आयात से भी भारत को आर्थिक हानि होती है परंतु भारतीय समाज के परंपराओं में स्वर्ण के महत्व को देखते हुए भारत सरकार आयात के लिए मजबूर होती है। सरकार द्वारा स्वर्ण के आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए सावरेन गोल्ड बांड जैसी योजनाओं को लाया गया है। खाद्य तेलों का आयात भी हमारे लिए आर्थिक घाटे का कारण है और यह भारत के खराब कृषि नीति एवं बाजार के समन्वय में कुप्रबंधन का एक उदाहरण है। भारत सरसों, कपास, चावल, पाम और सोयाबीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने में सक्षम है जिनसे खाद्य तेल बनाए जाते हैं। परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सरकारी खरीद का फोकस सदैव चावल एवं गेहूं तक ही सीमित रहता था। केंद्र की मोदी सरकार इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हुए उसके सरकारी खरीद का आश्वासन किसानों को दिया गया है। हमारे आयात को बढ़ाने में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स का भी बड़ा योगदान है। इस क्रम में अपनी आत्मनिर्भरता को तेजी से बढ़ते हुए मोदी सरकार ने उत्पादन आधारित इंसेंटिव योजनाएं लाकर घरेलू बाजारों में निर्माण को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों के फल स्वरूप विश्व प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी एप्पल, चीन को छोड़कर भारत में अपने निर्माण इकाइयां स्थापित कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म कर सीधे रुपए में ट्रेड को सुगम बनाने के लिए विशेष vastro खातों की व्यवस्था को प्रारंभ किया है।

असमानता, बेरोजगारी, रोजगार एवम् कौशल गुणवत्ता की समस्या: वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बाद अब हम घरेलू अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर दृष्टि डालें तो सबसे बड़ी समस्या असमानता है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को अत्यधिक असमान देशों की लिस्ट में रखा गया है। भारत के शीर्ष 10% लोग, देश के 57 प्रतिशत संपदाओं के मालिक हैं। 50% आबादी के पास मात्र 13 प्रतिशत संपदा है। लेकिन इस असमानता की स्थिति की गहराई में जाएं तो इसके कई मूल कारण दिखाई देंगे जैसे बेरोजगारी, रोजगार की गुणवत्ता में कमी तथा कौशल विकास एवं नवाचारों में कमी। इन विषयों को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय आर्थिक विकास नीति को गहराई से समझना पड़ेगा। भारत ने देश के आजाद होने के बाद एक ऐसे मिले-जुले आर्थिक ढांचे को स्वीकार किया जिसमें सरकार अग्रणी की भूमिका में रही एवं निजी क्षेत्र को बेहद सीमित अधिकार दिए गए। सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलते हुए भारत सरकार आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदाई थी एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्णय लिया जाता था कि देश के मानव संसाधन को किस क्षेत्र में लगाया जाएगा। देश की आजादी के समय भारत एक कृषि आधारित देश था एवं देश की अधिकतर जनसंख्या खेती-बाड़ी के कामों में लगी रहती थी। तत्कालीन नेहरू सरकार ने विनिर्माण एवं भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे पंडित नेहरू का विचार था कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भारी उद्योगों का विकास आवश्यक है। और इस तरह से इस विकास का लाभ ऊपर से नीचे की ओर स्वयं जाएगा। विकास की जी अधोमुखी अवधारणा पर नेहरू जी ने भारत के आर्थिक विकास का स्वप्न देखा था वास्तव में सरकार के अधिकारी नियंत्रित कर रहे थे। अंततोगत्वा भ्रष्टाचार एवं लाल फिताशाही के चलते योजना के अनुरूप लाभ कभी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सका। इसी के साथ भारी उद्योग के निर्माण में देश ने इतनी अत्यधिक पूंजी लगाई की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधन बहुत कम बचे।

भारत में कौशल विकास: आजादी के बाद भारी विकास की योजनाओं में इस बात को भुला दिया गया कि एक कृषि आधारित समाज को शिक्षा के द्वारा ही भारी उद्योग आधारित कल कारखानों में नौकरियां मिलेंगी। साथ ही कृषि जिस पर देश की अधिकतर जनता का जीवन निर्भर करता था उसे क्षेत्र को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। इसके फल स्वरुप देश के पढ़े लिखे समाज ने उद्योगों में तेजी से नौकरियां तो हथिया लिया परंतु कृषि पर जीवन ज्ञापन करने वाले लोग शिक्षा के अभाव में गरीब के गरीब बने रहे। 1980 90 के दशक में अंत सरकारों को इस भारी गलती का एहसास हुआ और कृषि को अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाने का निर्णय लिया गया। परंतु इस फैसले को क्रियान्वित करने के क्रम में देश लगभग 40 वर्ष पीछे चला गया। साथ ही कृषि पर जीवन यापन करने वाली एक बहुत बड़ी जनता द्वारा सरकार की योजनाओं एवं सुधारो पर से विश्वास भी उठ गया। भारत में कौशल विकास की स्थिति एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में स्थापित है। मोदी सरकार के लगातार प्रयासों से आज भारत में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है परंतु यदि फिनटेक एवं फार्मास्यूटिकल को छोड़ दिया जाए तो भारतीय नवाचारों के द्वारा कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव घरेलू मार्केट में नहीं आया है जिससे इंटेल, एप्पल या गूगल जैसी क्रांति खड़ी की जा सके। भारत को नवाचारों की दिशा में अभी बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। कुल मिलाकर नवाचारों की कमी कौशल विकास की कमी तथा बेरोजगारी एक दूसरे से अंतर संबंधित विषय हैं जिनका स्थाई समाधान शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े निवेश के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के आगामी कार्यकाल में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की अपेक्षा है।

अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च: विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जीडीपी का 0.66% अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करता है जो विश्व औसत 2.63 प्रतिशत से चिंताजनक रूप से बहुत कम है। इजरायल अपने जीडीपी का 5.5% तथा अमेरिका 3.5% अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करता है। इन सभी समस्याओं को हल करने का रास्ता औद्योगिक विकास से होकर गुजरता है और इसलिए भारत सरकार चैतन्य होकर इस दिशा में कार्य कर रही है। इसी प्रयासों के क्रम में विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों जैसे एप्पल, लोकहिड मार्टिन, सैमसंग, एअरबस आदि भारत में अपने विनिर्माण इकाई बना रहे हैं। इन सभी के द्वारा भारत में अनुसंधान एवं विकास को गति मिलेगी। साथ ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अपनी शैशव अवस्था से है जो आगामी 10 वर्षों में एक बड़े क्रांति के रूप में विश्व मंच पर दिखाई देगा। वर्तमान में ड्रोन विनिर्माण तथा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रमोट किया जा रहा है। परंतु सकारात्मक क्रांति के लिए भारत को अनुसंधान एवं विकास पर अपने जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। कौशल विकास के माध्यम से जिन नई तकनीकियों पर युवाओं को कुशल बनाने की आवश्यकता है उसमें अभी भी संयोजन की समस्याएं आ रही हैं जैसे ट्रेनिंग संस्थाओं एवं उद्योगों के बीच समन्वय न होने के कारण युवाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। **विश्वीकरण के नकारात्मक पहलू**: वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कई सकारात्मक पहलू हैं जिनसे 1991 के बाद देश की आर्थिक प्रगति के साथ देशवासी रूबरू हुए। परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिनसे हमें समय-समय पर दो-चार होना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा उछाल तो दिया परंतु इसी वैश्वीकरण के कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ गई है तथा दुनिया के दूसरे गोलार्ध में भी कोई नकारात्मक आर्थिक गतिविधि दुनिया के सभी देशों को कमोबेश प्रभावित करता है। वर्तमान में जब विश्व के कई देश मंदी की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे भंगुर वैश्विक आर्थिक स्थितियों में यह स्थिरता भारत की आर्थिक गतिविधि के लिए एक शक्तिशाली संकट बन सकता है। वैश्विक स्तर पर एक लंबे समय के बाद आर्थिक मंदी की वापसी हुई है। भारत जैसे विकासशील देशों में सामान्य से उच्च मुद्रा स्फीति एक सामान्य घटना बनी रहती है जिसके अपने नफे नुकसान भी हैं। चिंताजनक बात यह है कि आज अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के सभी बड़े देशों में मुद्रास्फीति की स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों से भी विकराल हो गई है। मुद्रास्फीति महंगाई को आमंत्रित करता है जिससे एक सामान्य व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। विश्व विकसित देशों की मुद्रा स्थिति के कारण भारत के निर्यात में एक गिरावट दर्ज की गई साथ ही आयत में बढ़ोतरी हो गई है जो चिंताजनक है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वैश्वीकरण के इस दौर में भारत के "विश्व का कल्याण हो" की प्रार्थना की प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है। कैसे संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण के दौर में एक गांव बन गया है जहां सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं इसलिए सभी को एक दूसरे के कल्याण की बात सोचनी पड़ेगी। इसी विश्व के कल्याण के अंतर्गत रूस एवं यूक्रेन के युद्ध ने पूरे विश्व की आर्थिक मंदी के दौर में कोढ़ में खाज का काम किया है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया है जिसका प्रभाव भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर नकारात्मक रूप से पड़ा है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मौद्रिक विनिमय पर भी पड़ता है और रुपया कमजोर होने लगता है। अभी हाल ही में एक्स एवं फेसबुक जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भारत में कर्मचारियों की छटनी किया है साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी विदेशी निवेश कम प्राप्त हो रहा है। इन सभी जटिल परिस्थितियों में मोदी सरकार के द्वारा बहुत सूझबूझ से कदम रखते हुए "आपदा में अवसर" तथा "वोकल फॉर लोकल" का नारा दिया गया है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्थितियां से संगरोध करने के लिए अपने घरेलू बाजारों की ओर मुड़ना होगा। वैश्विक बाजारों से आत्मनिर्भरता को कम करना होगा। निवेश के लिए आम जनता के पैसों को बैंक खातों से निकाल कर स्टॉक मार्केट तक लाना होगा जिससे विदेशी निवेशकों पर निर्भरता को निर्णायक रूप से कम किया जा सके। इसी के साथ भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के स्थान पर नई रणनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी होगी। 21वीं शताब्दी को एशिया की शताब्दी कहा गया है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस एशिया की शताब्दी का नेतृत्व भारत के हाथों में रहे। 75 वर्षों के अंतराल में हमने अपने कॉलोनाइजर को पीछे छोड़ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक नज़ीर कायम किया है। अब हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी करना है।

मेष राशिः आज आपका दिन मिला-जुला रहेगा। आज सफलता मिलने से थकान दूर हो जाएगी। आज आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे। इसके साथ घर में भी आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों के मान-सम्मान का विशेष ध्यान रखें। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे, समाज में आपका सम्मान होगा। मां कात्यायनी को फूल अर्पित करें, शुभ समाचार सुनने को मिलेगा।

वृष राशिः आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे आप कोई नई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। आज घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अपनी कार्य कुशलता को बढाने के लिए आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें, सेहत अच्छी रहेगी।

मिथुन राशिः आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी परंतु आप उचित व्यवस्था बनाकर हल भी निकाल लेंगे। आज संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा। आज मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए योगा, मेडिटेशन आदि का सहारा ले। मां दुर्गा को हलवा का भोग लगाएं, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

कर्क राशिः आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। अनुभवी लोगों से मेल-मिलाप और नई जानकारियां हासिल होंगी। आज क्रोध के कारण परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती हैं। आज कोई भी परेशानी आने पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक होगा। वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है।

सिंह राशिः आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। आज कई तरह के गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आज किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर अवश्य विचार कर ले। आज किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार से किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। आज अधिकतर समय मार्केटिंग और बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही बीत सकता है।

कन्या राशिः आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कार्यप्रणाली बेहतर होगी और किसी काम में उचित सफलता मिलने से उत्साह और अधिक बढ़ेगा। युवाओं और विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। समय अनुसार कोई भी निर्णय ले। आज जल्दबाजी और आवेश की वजह से किसी कार्य में समय लग सकता हैं। लवमेट आज किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जाएंगे।

तुला राशिः आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में लगाए। ज्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उचित भोजन का ध्यान रखें। आज व्यायाम करें इससें आपके अंदर सकरात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। बच्चे आज किसी खिलौने की मांग कर सकते हैं।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। आज अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और फिजूलखर्चे पर भी नियंत्रण रखें। आज अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं। लेकिन अपनी योजनाएं सार्वजनिक ना करें। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा।

धनु राशिः आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। आज उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के साथ आपका समय बीतेगा। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है। आज अपने व्यवसाय की गतिविधियों में भी बदलाव करेंगे।

मकर राशिः आज आपकी कई योजनाएँ समय से पूरी हो जायेंगी। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा प्राप्त होगी और उनके मार्गदर्शन में आप कोई खास निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। आज नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों की किसी भी सलाह पर विश्वास ना करके अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। आज व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

कुंभ राशिः आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते है। आज का दिन परिवार के साथ हर्षोल्लास में बीतेगा। आज आप अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं खालीपन का एहसास रहेगा। आज सिर्फ सुनी सुनाई और आलोचनात्मक बातों पर ध्यान ना दें और अपनी भावनाओं व क्रोध पर नियंत्रण रखें।

मीन राशिः आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जायेंगे। आज आप बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें और उनकी समस्याओं को सुने और सुलझाएं, इससे उनकी आत्म निर्भरता बढ़ेगी। आज व्यवसाय में इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत मेहनत और सजग रहने की जरूरत है। आज बाहरी लोगों का अपने कार्यस्थल पर हस्तक्षेप ना होने दें। आज कोई भी निर्णय लेने में समय ना लगाएं। व्यापार में धन लाभ की प्राप्ति होगी।

75 साल से चल रहा है गरीबी हटाओ का नारा क्या केवल चुनावी शगूफा बन जाता है !

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी माहौल गरमाने लगा है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश में गरीबी चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में गरीबी मुद्दा था। 1971 के लोकसभा चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा ही दे दिया था। माना जाता है कि यह नारा उनके प्रधान सचिव पीएन हक्सर के दिमाग की उपज थी।अब साल 2024 में जब भारत 18वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी में है, तब भी चुनाव में गरीबी एक मुद्दा है। अंतर यह है कि सत्ताधारी भाजपा इस दावे के साथ इसे मुद्दा बना रही है कि उसके शासन काल में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। विपक्ष तरह-तरह के आंकड़े देकर इस दावे की हवा निकाल रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था । पीएम मोदी ने राहुल पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की है कि एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छिपा था?पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई। अब इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ऐसे दावे करते हैं और हंसी के पात्र बन जाते हैं। दरअसल साल की शुरुआत में नीति आयोग ने दावा किया था कि नौ साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकल चुके हैं। पिछले दिनों नीति आयोग के CEO ने HCES के आधार पर दावा किया कि भारत की कुल आबादी में गरीबों का अनुपात पांच फीसद से अधिक नहीं है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर सरकार गरीबी कम होने के दावे कर रही है। लेकिन, विशेषज्ञ इन आंकड़ों तक पहुंचने के रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं। जिस सर्वे के आधार पर नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत की कुल आबादी में गरीबों का अनुपात पांच फीसद से अधिक नहीं है, उस सर्वे का मकसद यह पता लगाना होता है कि हर माह लोग कितना खर्च कर रहे हैं। अंग्रेजी में से Monthly Per Capita Expenditure या (MPCE) कहते हैं। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच आयोजित इस HCES में 8,723 गांवों और 6,115 शहरी क्षेत्रों के 2,61,745 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों से 60 फीसद और शहरी क्षेत्रों से 40 फीसद) को शामिल किया गया था।सर्वे से प्राप्त आंकड़ों को चार भागों में बांटकर देखने से पता चलता है कि कुल आबादी के 50 प्रतिशत का प्रति व्यक्ति खर्च 3,094 रुपये (ग्रामीण) और 4,963 रुपये (शहरी) से अधिक नहीं है। सबसे गरीब पांच प्रतिशत लोग तो 1,373 रुपये (ग्रामीण) और 2,001 रुपये (शहरी) प्रति माह में गुजारा कर रहे हैं। दिन के हिसाब से बांट दें तो यह 45 रुपये (ग्रामीण) और 66 रुपये (शहरी) प्रति दिन हो जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े और मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम नीति आयोग के आंकड़ों को पेश करने के तरीके को दुरुस्त नहीं मनाते। चिदंबरम पांच फीसद वाले दावे पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, "अगर यह दावा सच है तो सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो मुफ्त अनाज क्यों बांटती है?" चदिंबरम का सवाल यह भी है कि क्या नीति आयोग ने इस बात पर कभी गंभीरता से विमर्श किया कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में महीने का (खाद्य और गैर-खाद्य पर) लगभग 2,112 रुपए या प्रतिदिन 70 रुपए खर्च करते हैं, वे गरीब नहीं हैं? या शहरी इलाकों में जिन लोगों का मासिक खर्च 3,157 रुपए या प्रतिदिन 100 रुपए है, वे गरीब नहीं हैं? अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर भी सर्वे करने के तरीकों को सही नहीं मानते। वह टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत संदिग्ध डेटा के मामले में एक संपन्न देश है।अय्यर इसका बेहतरीन उदाहरण HCES के डेटा को बताते हैं। वह लिखते हैं कि सर्वे का डेटा और उसका विश्लेषण दोनों त्रुटिपूर्ण है। अय्यर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के हवाले से बताते हैं कि 2011-12 से अब तक मात्र दो प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उनके मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 28.7 से घटकर 27 और शहरी क्षेत्रों में 36.7 से घटकर 31.9 हो गयी है। भल्ला प्रति दिन 70 रुपये कम में जीवन यापन करने वालों को गरीब मानते हैं। अय्यर मानते हैं कि HCES का डेटा कलेक्ट करने का तरीका ही गलत है क्योंकि सर्वे के दौरान लोगों से यह सवाल तो किया जाता है कि उन्होंने अपने खाने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया, लेकिन अन्य खर्चों जैसे यात्रा आदि को लेकर सवाल नहीं किया जाता है। साथ ही कई बार लोग सही जानकारी भी नहीं देते। ऐसे में HCES के डेटा से गरीबी या अमीरी का सही तस्वीर नहीं मिल पाती। इस साल की शुरुआत में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि पिछले नौ साल में भारत के 24.8 करोड़ गरीबी (Multidimensional Poverty) से बाहर निकल गए हैं। 2013-14 में भारत में गरीबी दर 29.17 थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत हो गई। यानी 17.89 प्रतिशत लोग गरीबी से निकले हैं। गरीबी से निकलने वाले लोगों के आकलन के लिए नीति आयोग ने बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल जैसे मानदंडों के आधार बनाया था। यह समझ लेना आवश्यक है कि गरीबी मापने के लिए आय के डेटा या व्यय के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कौन कितना गरीब है यह पता लगाने के लिए व्यक्ति की कमाई या उसके खर्च करने की क्षमता का आकलन किया जाता है। हंगर वॉच नेशनल सर्वे के अनुसार दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच लोगों की आय में गिरावट आई है। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर और हाशिए के वर्गों में खाने-पीने तक का संकट गहराया है।हंगर वॉच के सर्वे में 80 प्रतिशत लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी की समस्या को स्वीकार किया है। 25 प्रतिशत ने भोजन में कटौती करने और भूखे पेट सोने की बात कबूल की है। इसके अलावा, प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि महामारी से आई आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2022 में भारत में लगभग 75 मिलियन अधिक लोग गरीबी के दलदल में फंस गए। इस अध्ययन में गरीबों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रतिदिन 2 डॉलर (165 रुपये) या उससे कम पर जीवन यापन करते हैं। मौजूदा एनडीए सरकार गरीबी दूर करने के नाम पर कई योजनाएं चल रही है और आगामी चुनाव में उनके नाम वोट मांगने की भी तैयारी है, जिसकी झलक विज्ञापनों और भाषणों में दिखने लगी है।गरीबों को ध्यान में रखकर चलायी जाने वाली केंद्र की मुख्य योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना को गिना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कराए जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5 – 2019-21) के डेटा पर आधारति एक अध्ययन में अंदाजा लगाया गया है कि भारत में 19.3 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें पिछले 24 घंटों में न तो ठोस आहार ही दिया गया है और न तरल पदार्थ ही दिया गया है। भारत से ज्यादा केवल अफ्रीकी देश गुयाना में ऐसे बच्चों (Zero food children) की संख्या 21.8 प्रतिशत और माली में 20.5 प्रतिशत है। बांग्लादेश में 5.6 प्रतिशत, पाकिस्तान में 9.2 प्रतिशत, कांगो में 7.4 प्रतिशत, नाइजीरिया में 8.8 प्रतिशत और इथोपिया में 14.8 प्रतिशत जीरो फूड चल्ड्रिेन पाए गए। हालांकि, भारत में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े भोजन की कमी के चलते नहीं हैं, बल्कि माताओं द्वारा बच्चों को दूध पिलाने या खाना देने में असमर्थता के चलते आए हो सकते हैं। जिन बच्चों को पिछले 24 घंटों में दूध-पानी या कोई अन्न नहीं दिया गया, उन्हें जीरो फूड चल्ड्रिेन माना गया। यह सर्वे 2010 से 2021 के बीच अलग-अलग समय पर 92 देशों में 6 से 24 महीने के बच्चों के बीच कयिा गया।IMF के मुताबिक, भारत में 2014 से 2023 के बीच प्रति व्यक्ति आय में 67 फीसदी बढ़ोतरी हुई, जबकि 2004 से 2014 के बीच 145 प्रतिशत बढ़ी थी। एक अंतरराष्ट्रीय रपिोर्ट के मुताबकि आर्थकि समानता के मामले में भी भारत की स्थति अच्छी नहीं है।

युद्ध विस्तार की आशंका

छह माह से गाजा पट्टी पर इजराइल की निरंकुश कार्रवाई के बाद दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की प्रतिक्रिया में इजराइल पर हुए ईरानी हमले ने मध्य पूर्व के संकट को और गहरा दिया है। अब इजरायल ईरान पर जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी में जुटा है। ऐसे में पहले रूस-यूक्रेन युद्ध की मार झेल रही दुनिया गहरे आर्थिक संकट की चपेट में आ सकती है। शनिवार की रात ईरान ने तीन सौ से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों व सैकड़ों ड्रोन के जरिये इस्राइल पर भीषण हमला किया था। हालांकि इस्राइल ने अपने सशक्त एअर डिफेंस सिस्टम से नब्बे फीसदी से अधिक हमलों को विफल कर दिया। जिसका जवाब देने के लिये इस्राइली तैयारियां चरम पर हैं। इस्राइल की आईडीएफ ईरान को घुटनों पर लाने की तैयारी में जुटी है। आशंका जतायी जा रही है कि इस्राइल ईरान के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना सकता है। उधर खाड़ी के देश युद्ध के विस्तार को लेकर खासे चिंतित हैं और अमेरिका को युद्ध से दूरी बनाए रखने को लेकर चेता रहे हैं। हाल ही में जिस तरह ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मूज जलडमरूमध्य में एक इस्राइली समुद्री जहाज को कब्जे में लिया है, उससे आशंका है कि इस संघर्ष से वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का बड़ा भाग प्रभावित हो सकता है। आशंका यह भी जतायी जा रही है कि यदि इस्राइल जवाबी कार्रवाई करता है तो युद्ध का विस्तार बड़े इलाके में हो सकता है।हालांकि ईरान ने अपने कदम को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताते हुए कहा है कि यह दमिश्क में उसके दूतावास पर हुए हमले का जवाब है। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि इस कार्रवाई के बाद उसकी तरफ से मामले को खत्म माना जा सकता है, लेकिन अगर इजरायल ने फिर कोई गलती की तो नतीजे इससे भी गंभीर होंगे। हमले से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपना यह सिद्धांत घोषित किया था कि ह्यजो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे।ह्न वैसे भी ईरान की प्रतिक्रिया को अपेक्षा से ज्यादा सख्त माना जा रहा है। ऐसे में इजरायल अपनी जमीन पर सीधे हमले की ईरानी कार्रवाई को चुपचाप स्वीकार कर लेगा, इसके आसार नहीं दिखते। भारत के लिए यह स्थिति खास तौर पर असमंजस पैदा करने वाली है। इजरायल और ईरान दोनों से ही उसके बहुत अच्छे और करीबी रिश्ते रहे हैं। मिसाइल हमले से एक दिन पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में इजरायल से जुड़े जिस कार्गो शिप पर कब्जा किया, उसमें 17 भारतीय नागरिक भी हैं। इसलिए भारत की पहली चुनौती इन भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें छुड़ाने की बन गई है।

भाजपा की झोली कितनी भरेगी पूर्वोत्तर से

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

जिस पूर्वोत्तर भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले पहुँचती हैं वहाँ की जानता तैयार है, एकबार फिर लोकसभा चुनावों में अपना फैसला सुनाने के लिए। बेशक, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है , तो 25 सीटें पूर्वांचल प्रदेशों की भी उसमें शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आगामी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को लोक सभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

अगर बात पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने जो झंडे गाड़े थे, उसे इस बार भी थामे रखने का पार्टी को पूरा भरोसा है। इस भरोसे के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह से पूर्वोत्तर की विकास की योजनाएं सिरे चढ़ाई हैं, उसके बाद वहां की जनता उनकी पार्टी और सरकार को कभी नहीं भूलेगी। इसमें एक पक्ष यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूरे पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न शांति समझौते के तहत एक स्थायी शांति का माहौल बनाया है। चुस्त आंतरिक सुरक्षा के कारण ही पूर्वोत्तर के पूरे इलाके में कोई बड़ी हिंसक वारदात सुनाई नहीं पड़ रही है। हां मणिपुर इसका एक अपवाद अवश्य है और वहाँ भी गृह मंत्रालय ठोस समाधान की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर की सेवन सिस्टर्स या सात बहनें कही जाने वाली राज्य इकाइयों समेत क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को मिलाकर कुल 25 लोक सभा की सीटें हैं। असम में सबसे ज्यादा लोकसभा की 14 सीटें हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 25 में से 21सीटें मिलीं थीं। भाजपा अब की बार पिछला आंकड़ा पार करना चाहती है।अभी तक इंडिया गठबंधन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक पूर्वोत्तर के राज्यों में लगा है। ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी पिछले चुनावों में यहां कुछ करने की एक अलग कोशिश की भी थी, लेकिन इस बार वह कोशिश भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शरद पवार खुद अपनी पार्टी और अपनी वजूद के लिए अपने भतीजे से लड़ रहे हैं तो ममता बनर्जी अपने घर में ही भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक उपद्रवियों को बचाने के कारण घिरी हुई हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा पर विश्वास की वजह पिछले दस साल में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सक्रिय रूप से विकास पर फोकस और शांति स्थापना की कोशिश है।इसके अतिरिक्त पूर्वांचल प्रदेशों के प्रभारी और सह - प्रभारी डॉ. संबित पात्रा और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा के लगातार प्रवासों और दिन - प्रतिदिन को मॉनिटरिंग ने पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के संगठन को मजबूत ही किया है ।

मणिपुर में हालांकि केवल 2 लोक सभा की सीटें है, लेकिन मोदी सरकार के लिए वहाँ के जनजातीय संघर्ष को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मणिपुर हिंसा इस समय एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, जो एकतरह से पिछली कांग्रेसी सरकारों की देंन ही मानी जाती है।इस दशकों पुरानी समस्या के किसी सर्वमान्य निर्णय की लगातार कोशिश गृह मंत्री अमित शाह कर भी रहें हैं। हाल ही में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सामान्य रूप से उत्तर पूर्व और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की संभावना को जन्म देता है।

पहली बार है कि घाटी स्थित एक मणिपुरी सशस्त्र समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानूनों का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से हजारों लोगों की जानें लीं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। यूएनएलएफ 1964 से ही सक्रिय था और यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह अपना ऑपरेशन चला रहा था।

पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही तत्पर और सक्रिय हैं। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों की नीतियां समस्याओं से ध्यान भटकाने और सत्ता का आनंद लेने की रही थी। जिसके कारण क्षेत्र में हजारों लोगों की मौत हुई। मोदी सरकार ने न केवल इन समस्याओं के स्थायी निदान के लिए पहल की, बल्कि उग्रवादी गुटों को भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ईमानदारी से कोशिश की। असम में पिछले 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा ने भारत और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर कायम है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में हिंसा के काले दौर को समाप्त करने की एक ईमानदार कोशिश हुई।

मोदी सरकार के आने के बाद असम का सबसे पुराना उग्रवादी संगठन उल्फा हिंसा छोड़ने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर पूर्णतः सहमत हुआ। अमित शाह कहते रहे हैं कि उग्रवादी बहकाये हुए अपने ही लोग हैं। इन्हें अगर रोजगार के अवसर और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा नए भारत की तस्वीर दिखाई जाए तो यह हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे आएंगे। उल्फा के कैडरों का आत्मसमर्पण इसी विश्वास का परिणाम है। शाह की नीतियों की यह सफलता ही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9000 से ज्यादा उग्रवाद पर चल रहे कैडरों ने समर्पण किया है।

पूर्वोत्तर के राज्यों में लोगों की समस्याओं का तुरंत निदान नहीं हो पाने की बड़ी वजह संचार की सुविधा की कमी रही। मोदी सरकार ने इस पर एक बहुत बड़ी पहल की। उन्होंने पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुदूर कोनों को भी 5ऋ कनेक्टिविटी से जोड़ना शुरू किया। मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सैकड़ों टावर गांवों में लगाए गए। पूर्वोत्तर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए मोदी सरकार इस क्षेत्र को आर्थिक संबंधों के लिए पूरब के द्वार के रूप में विकसित कर रही है। भारत के विकास में यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं भी जोड़ रही है। इस समय पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में जबर्दस्त काम हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में, पूर्वोत्तर में कई चीजें पहली बार हुई हैं। पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से जुड़ रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 साल बाद अब अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रेलवे स्टेशन पहुंची। सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिला।

मणिपुर में जातीय हिंसा पर विपक्ष मोदी सरकार की काफी आलोचना कर रहा है। जबकि केंद्र सरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। जब वहां संघर्ष चरम पर था, तब खुद गृहमंत्री अमित शाह वहां गए थे। तनाव को खत्म करने के लिए उन्होंने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ तमाम बैठकें की । यह उम्मीद भी मोदी और अमित शाह से ही है कि मणिपुर में स्थाई शांति लाने में कामयाब होंगें। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों के दरवाजे तक गवर्नेंस पहुंचाने का प्रण लिया है। उन्होंने इस धारणा को बदल दिया है कि पूर्वोत्तर बहुत दूर है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूर्वोत्तर को दिल्ली से दिल से बेहद करीब लेकर आई है। यहाँ निवेश पहले से चार गुना अधिक हो रहा है। हाल ही में अरुणाचल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सेला टनल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और चीन को अपना इरादा बता दिया। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की गई है। 8 राज्यों में 200 से अधिक 'खेलो इंडिया सेंटर' बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लग यही रहा है कि पूर्वोत्तर भारत भाजपा को आगामी चुनाव में दिल खोलकर समर्थन देगा।

'रेवड़ी पैक' घोषणा पत्र और विवेकपूर्ण मतदान की चुनौती

अजय बोकिल

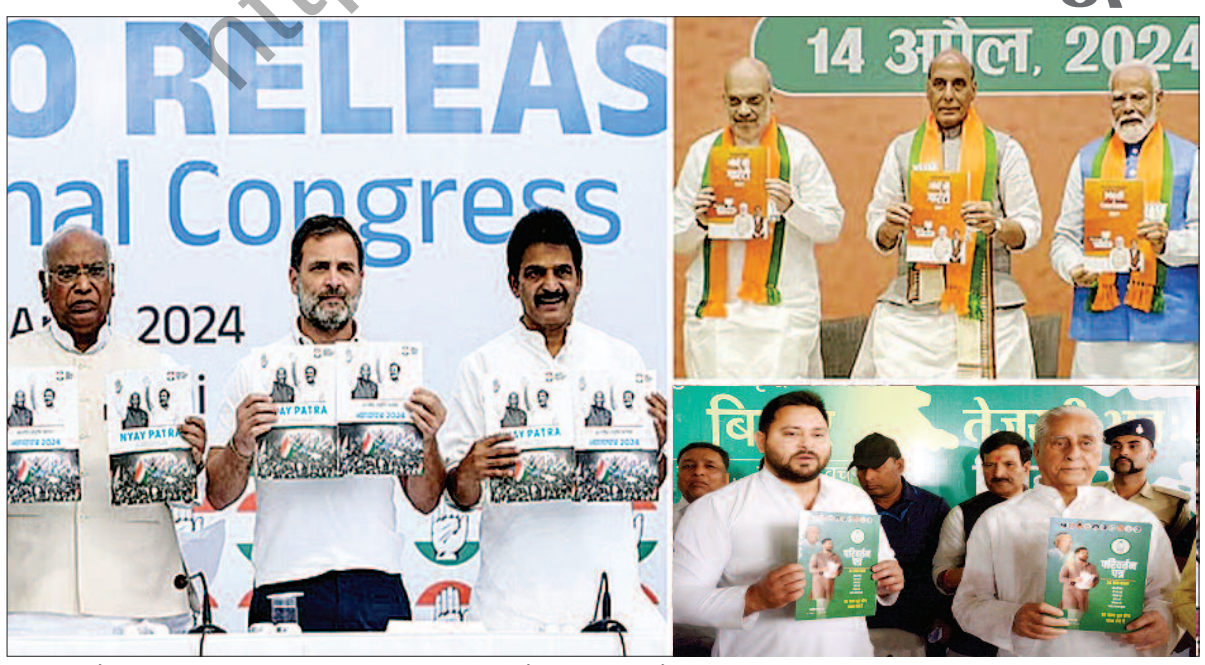

भाजपा और कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक दलों के 18 वीं लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं। सरसरी तौर पर देखा जाए तो सभी पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र में रेवड़ी कल्चर की होड़ है। हालांकि अब तक के अनुभव को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस पार्टी का घोषणा पत्र जितना लोकलुभावन और 'रेवड़ी पैक' होता है, उसके सत्ता में आने की संभावना उतनी ही कम होती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस पार्टी का राजनीतिक जनाधार जितना कम होता है, उसकी सियासी शिगूफे बाजी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर आप इसी पैमाने पर सारे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों की टेस्टिंग करें तो सचाई समझ आ जाएगी। इसी के साथ यह सवाल भी नत्थी है क्या चुनावों में मतदाता घोषणा पत्र देख-सुनकर भी वोट देता है या फिर मतदान का हरेक का अपना एक ईको सिस्टम होता है, जिसके अनुरूप वोटर वोट डालता है? वोटर के सामने बड़ी चुनौती यही है कि वह विवेकपूर्ण ढंग से मतदान कैसे करें?

देश के चुनाव नतीजों के ट्रेंड को समझें तो बीते कुछ वर्षों से मतदाता वैचारिक आग्रह- दुराग्रहो और शाब्दिक लफ्फाजी के झांसे में आए बगैर मतदान के लिए उन बातों को प्राथमिकता देता ज्यादा लगता है, जो उसे किसी न किसी न रूप में सीधा फायदा पहुंचाती हैं फिर वह चाहे नकदी के रूप में हों, अवसर के रूप में हो या सुरक्षा अथवा आश्वस्ति के रूप में हो। वह जान चुका है कि चुनाव घोषणा पत्र हर चुनावी सावन में नए सिरे से किया जाने वाला राजनीतिक सुंदरकांड का पाठ है, जिसका व्यवहार के स्तर पर न तो कोई खास महत्व है और न ही वो पार्टियां भी चुनाव बाद इसकी धूल झाड़ती हों, जो जोर- शोर से इसे हर चुनाव की बेला में जारी करती हैं।

लेकिन मतदाता हमेशा चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर वोट दे, यह जरूरी नहीं है। वह प्रसंगानुरूप प्राथमिकताएं तय करके भी कई बार वोट करता है। इसलिए एक बार जारी घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियों को भी अगले चुनाव में याद नहीं रहता। घोषणा पत्रों की पुरानी शब्दावलियां और जुमले अब अपने अर्थ खो चुके हैं। (कुछेक राजनीतिक दल अभी भी उसी से चिपके हुए हैं, वो अलग बात है)। ऐसे में मतदाता को लुभाने के लिए दरकार है नए जुमलों, प्रतीकों और प्रलोभनों की। इसकी छाया हमे खुद घोषणा पत्रों की वैकल्पिक संज्ञाओं में देखने को मिलती है। ज्यादातर पार्टियों ने घोषणा पत्रों के राजनीतिक पर्यायवाची खोज लिए हैं।

मसलन न्याय पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र, दृष्टि पत्र, गांरटी पत्र आदि। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे घोषणापत्रों में गांरटियों का पलडा भारी होता जा रहा है, विचार पक्ष का स्पेस उतना ही कम होता जा रहा है। घोषणा पत्र जारी करने में भी प्रतीकात्मक राजनीति का पूरा खयाल रखा गया है। मसलन कांग्रेस ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री व दलित नेता बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन पर घोषणा पत्र जारी किया तो भाजपा ने संविधान निमार्ता डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर अपना घोषणा पत्र जारी किया।

इस बार चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस का न्याय पत्र चर्चा में है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि यह घोषणा पत्र, वर्क, वेल्थ और वेलफेयर (काम, धन और कल्याण) के तत्वों पर आधारित है। इस घोषणा पत्र की भावना अच्छी है, लेकिन वादे हवाई ज्यादा हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा सबकी महालक्ष्मी योजना का है। इसके तहत गरीब परिवारों को सीधे एक लाख रुपये नकद देना का वादा है। देश में बीपीएल परिवारों की संख्या करीब 30 लाख है। प्रत्येक परिवार को हर साल 1 लाख नकद देने के लिए सालाना 3 खरब रूपए चाहिए। ये कहां से आएंगे, स्पष्ट नहीं है।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियां मोदी सरकार द्वारा 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना देने की आलोचना इस आधार पर करती हैं कि सरकार फ्री अनाज के बजाए काम दे। अब इस 1 लाख रू. को किस श्रेणी में रखा जाएगा। वैसे देश के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की वजह से देश में 10 सालों में 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले थे। वहीं अब मोदी सरकार का दावा है कि बीते दस साल में 24.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले (नीति आयोग की रिपोर्ट)।

अगर दोनों को सही मान लिया जाए तो बीते 20 साल में कुल 50 हजार करोड़ आबादी जो कि कुल आबादी का एक तिहाई है, गरीबी रेखा से बाहर आ चुकी है। तो फिर सरकार किन 80 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है? इसी तरह कांग्रेस के न्याय पत्र में 30 लाख युवकों को सरकारी नौकरी देने की बात है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज देश में केन्द्र सरकार के पास कुल नौकरियां ही 40 लाख हैं। इनमें भी 10 लाख पद खाली हैं। ये भर भी दिए जाएं तो बाकी 20 लाख को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, यह सोचने की बात है। घोषणा पत्र में एक अहम वादा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रू. करने और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने संविधान संशोधन करने का भी है, हालांकि यह जाति जनगणना के बाद ही संभव है। कांग्रेस जाति जनगणना का वादा भी कर रही है, जिसकी वजह से खुद कांग्रेस के अगड़े नेताओं में भारी खदबदाहट है। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर संवैधानिक संस्थाओं की आजादी ह्यबहालह्न करने तथा इलेक्टोरल बांड, पीएम केयर्स फंड, सरकारी संपत्तियों को बेचने तथा रक्षा सौदों की डील की जांच करने के भी वादे किए किए हैं।

हालांकि, ये मतदाता को कितना प्रभावित कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। साथ ही कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी गारंटी कानून लाने का वादा भी पूरा करना आसान नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव घोषणा पत्र गरीब परिवारों को, हर महीना 6000 रुपये देने का वादा किया था। इसी के साथ देशभर के लिए 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज की योजना (हालांकि राजस्थान में राहुल गांधी ने 50 लाख रु. तक के फ्री इलाज की घोषणा की थी, इसके बाद कांग्रेस वहां हार गई थी)।

उधर भाजपा के ह्यसंकल्प पत्रह्न में किसी नई लोकलुभावन योजना का वादा नहीं है, सिवाय आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को सम्मिलित करने के। पार्टी आत्म संकल्प और आत्ममुग्धता के झूले में झूल रही है। चुनाव में भाजपा मुख्यतः अपने काम के आधार पर ही वोट मांग रही है। पार्टी मान रही है कि मोदी का नेतृत्व, राम मंदिर का निर्माण और 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन चुनाव जीतने के ऐसे शर्तिया नुस्खे हैं, जिनके परे जाकर मतदाता कम ही सोचेगा। अलबत्ता दक्षिण भारत में लड़ा जरा अलग तरह की और ज्यादा कठिन है।

भाजपा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर आमादा है। उसके घोषणा पत्र में देश के स्वर्णिम भविष्य के सपने ज्यादा हैं। वह खुद भी उम्मीदों की बुलेट ट्रेन में सवार है। पार्टी 'एक देश, एक जनादेश' पर कायम है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी का सारा प्रचार मोदी केन्द्रित और मोदी निर्भर ही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अब केवल अपनी ही गारंटियों, काबिलियत और दूरदर्शिता की तारीफ करते नहीं थकते। इसका मतदाता पर कैसा असर होगा, यह चुनाव नतीजों से पता चलेगा। बावजूद इन तमाम बातों के बीजेपी के घोषणा पत्र में यह सावधानी अंतनिर्हित है कि सत्ता में लौटने पर कोई वादा उसे भारी न पड़ जाए। विकास की दिशा वही रहे, जो उसने तय कर रखी है।

उधर कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में ऐसी बातें भी शामिल की हैं, जो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को परिलक्षित करती हैं। साथ में रेवड़ियां तो हैं ही। राष्ट्रीय जनता दल ने वादा किया है कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 1 लाख 60 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। राजद का एक बड़ा वादा देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने, 30 लाख खाली पदों को भरने तथा 70 लाख नए पद सृजित करने का है। यह प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू भी हो जाएगी। यह बात अलग है कि आज देश में केन्द्र व राज्य सरकारों की मिलाकर कुल नौकरियां (सार्वजनिक उपक्रम भी मिला लें) सवा करोड़ से ज्यादा नहीं हैं।

खाली पद करीब भी 25 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। राजद कुल जमा 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह डीएमके के घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रति माह 1 हजार रू. देने व तमिलनाडु को नीट से छूट देने और पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का वादा है। पार्टी ने सीएए कानून रद्द करने तथा समान नागरिक संहिता लागू न करने का वादा किया है। माकपा ने भारत के परमाणु निरस्त्रीकरण का वादा भी किया है। विश्व शांति के आग्रह से उपजे इस वादे में देश को सैन्य शक्ति के मामले में 1962 वाले दौर में ले जाने का मंतव्य ज्यादा झलकता है। मजेदार बात यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल माकपा ने कुछ मुद्दों पर जैसे कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के मुद्दे पर सहयोगी कांग्रेस को कुछ मुद्दों पर फ्रेंडलीघेराह्नभी है। एक समय था जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हुआ करते थे। वामपंथी इतिहासकार मृदुला मुखर्जी ने एक लेख में बताया था कि देश के पहले आम चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र इसी चिंता पर आधारित था कि कम्युनिस्टों से मुकाबला कैसे किया जाए। इसी तरह सपा के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जाति जनगणना, सबको न्याय, फ्री शिक्षा,महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती, किसान कर्जमाफी व रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने का वादा है।

बसपा सुप्रीमो मायावती अपने वादे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की पैरवी कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लागू ह्यलक्ष्मीर भांडारह्न, कन्याश्री तथा स्वास्थ्य साथी योजना पूरे देश में लागू करने की बात कही है। खास बात यह है कि दोनो प्रतिदंद्वी राजनीतिक दलों के गठबंधनों का कोई समन्वित घोषणा पत्र चुनाव में नहीं है। लिहाजा ये सभी सत्ता की लड़ाई स्वार्थ जनित शस्त्रास्त्रों से ही लड़ रहे हैं। मतदाता के सामने चुनौती यह है कि वह रेवड़ियों, हवाई वादों और जिंदगी से जुड़े मुद्दों के बीच किसको तरजीह दे। देश को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को, धर्म या जाति को अथवा अपने हाथ और पेट को?

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कूड़ा-करकट डालने का स्थान बनते जा रहा समुद्र तल

मनीष कुमार चौधरी

सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है।समुद्र की ऊपरी परतों में माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य श्रृंखला पर आक्रमण किया है। जैसे-जैसे कोई शिकार की परतों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है, उच्च और उच्चतर सांद्रता में एकत्रित होता जाता है। व्हेल और पक्षी जैसे जानवर बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग कर रहे हैं, जिससे कुपोषण हो रहा है और उन जीवों के कई अंगों को नुकसान हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा उजागर किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2050 तक चौगुना हो सकता है,

उन्नीसवीं सदी की शुरूआत तक गहराई की अधिक विस्तृत वैज्ञानिक समझ ने आकार लेना शुरू नहीं किया था। जैसे-जैसे यूरोपीय और अमेरिकियों की वाणिज्यिक और क्षेत्रीय आकांक्षाएं दुनिया भर में विस्तारित हुई, महासागर के बारे में अधिक सटीक और अधिक विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ी, लेकिन जल्द ही विकास की अंधाधुंध दौड़ में समुद्र की इन गहराइयों का बेजा इस्तेमाल शुरू हो गया। समुद्र की गहराई का उपयोग बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में भी किया गया।पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश, अमेरिकी, सोवियत, ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई सरकारों ने सैकड़ों-हजारों टन अप्रचलित रासायनिक हथियारों को दुनिया भर के पानी की गहराई में या तो ड्रमों में या टुकड़ों में भेज दिया। हालांकि सार्वजनिक आक्रोश के कारण इस प्रथा को 1972 में समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2019 के एक अध्ययन में आर्कटिक महासागर के तल पर कम से कम 18 हजार रेडियोधर्मी वस्तुएं बिखरी हुई पाई गई, उनमें से कई को सोवियत संघ द्वारा वहां फेंक दिया गया था। जब ये वस्तुएं अपनी जहरीली विरासत को पानी में छोड ?ा शुरू कर देंगी, तब क्या होगा? कई पर्यावरणविदों ने इस स्थिति को समुद्र तल पर धीमी गति से चल रहा चेर्नोबिलइ कहा है।हालांकि सोवियत संघ ने किसी भी अन्य देश की तुलना में समुद्र तल पर अधिक परमाणु कचरा फेंका था, लेकिन वह निश्चित रूप से अकेला नहीं था। 1948 और 1982 के बीच, ब्रिटिश सरकार ने लगभग 70 हजार टन परमाणु कचरा समुद्र की गहराई में भेज दिया। भले ही कम मात्रा में ही सही, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान और नीदरलैंड ऐसे कुछ देश हैं, जिन्होंने रेडियोधर्मी सामग्री के निपटान के लिए समुद्र का उपयोग किया है। 2019 में चीनी वैज्ञानिकों ने मारियाना ट्रेंच के तल पर रहने वाले उभयचरों के शरीर में 1940 और 50 के दशक में परमाणु बमों के विस्फोट से

उपजे रेडियोधर्मी कार्बन-14 की खोज की।अब जबकि अंतरराष्ट्रीय संधियां समुद्र में रेडियोधर्मी सामग्री के डंपिंग पर रोक लगाती हैं, ब्रिटिश सरकार कुम्ब्रिया के समुद्र तल के नीचे 100 टन से अधिक प्लूटोनियम सहित 750,000 क्यूबिक मीटर परमाणु कचरे के निपटान की योजना तलाश रही है। 1946 से 1993 तक, तेरह देशों ने मुख्य रूप से चिकित्सा, अनुसंधान और परमाणु उद्योग से निकले लगभग 200,000 टन परमाणु/रेडियोधर्मी कचरे को निपटाने के लिए समुद्रों का किसी डंपिंग यार्ड की तरह उपयोग किया। भले ही समुद्र में डंपिंग के मामले में अब तक केवल निम्न स्तर के रेडियोधर्मी कचरे को ही डंप किया गया है, लेकिन समुद्र तल पर फैले सैकड़ों-हजारों टन परमाणु कचरे के धीमे क्षय की तरह, समुद्री जीवों के शरीर में लिखी गई मानव उद्योग की जहरीली विरासतें याद दिलाती हैं कि गहराई भूलने की जगह नहीं है कि जहां कुछ भी डाल दो और भूल जाओ।यह मान लेना आसान है कि हमारा ग्रह केवल स्थलीय वातावरण द्वारा परिभाषित है, वास्तव में विपरीत सच है। समुद्र में परमाणु कचरे की डंपिंग लापरवाही और लालच की एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं के रूप में भी मानव अपशिष्ट गहरे समुद्र में हर जगह है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का निर्माण होता है, इसमें से लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे के रूप में हर साल समंदर में फेंक दिया जाता है।समुद्र में परमाणु कचरे की डंपिंग लापरवाही और लालच की एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं के रूप में भी मानव अपशिष्ट गहरे समुद्र में हर जगह है। खेल बैग, पुतले, समुद्र तट की गेंदें और बच्चों की बोतलें कई हजारों मीटर की गहराई तक समुद्र तल पर फैली हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में ऐसी वस्तुओं की संख्या 300 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। जब खोजकर्ता विक्टर वेस्कोवो 2019 में मारियाना ट्रेंच के निचले भाग पर पहुंचे, तो उन्हें न केवल एम्फिपोड्स की पहले से अज्ञात प्रजातियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें प्लास्टिक बैग और मीठे रैपर भी मिले। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात समुद्र की गहराई में माइक्रोप्लास्टिक का बढ़ता संचय है।समुद्र की ऊपरी परतों में माइक्रोप्लास्टिक ने खाद्य श्रृंखला पर आक्रमण किया है। जैसे-जैसे कोई शिकार की परतों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है, उच्च और उच्चतर सांद्रता में एकत्रित होता जाता है। व्हेल और पक्षी जैसे जानवर बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग कर रहे हैं, जिससे कुपोषण हो रहा है और उन जीवों के कई अंगों को नुकसान हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा उजागर किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण 2050 तक चौगुना हो सकता है, जबकि माइक्रोप्लास्टिक्स संभावित रूप से 2100 तक पचास गुना बढ़ सकता है। यह समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा तो है ही, कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा सकता है।

संपादकीय

सख्त निर्णय जरूरी

भारत सीमापार से होने वाले किसी भी आतंकवादी कृत्य का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने यह प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री शुक्रवार को 'यह भारत क्यों मायने रखता है: युवाओं के लिए अवसर और वैश्विक परिदृश्य में भागीदारी' विषय पर बोल रहे थे। 2008 में हुए मुंबई हमलों का जवाब देने को लेकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग सरकार पर निशाना साधने हुए उन्होंने कहा कि काफी चर्चा के बावजूद कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। उन्होंने माना पाकिस्तान पर हमला करने की कीमत उस पर हमला न करने से अधिक होगी। 2014 में आतंकवाद की शुरूआत नहीं हुई, यह मुंबई हमले के साथ नहीं हुई, बल्कि यह 1947 में हो चुकी थी। उन्होंने कश्मीर हमले को आतंकवादी कृत्य माना। शिवशंकर ने कहा कि वे गांव और शहर जला रहे थे, लोगों की नृशंस हत्या कर रहे थे। 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में आए बदलावों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस देश से संबंध बनाए रखना मुश्किल है, वह है पाकिस्तान है। पाकिस्तान समेत अन्य देशों में मारे गए आतंकवादियों के पीछे भारत का हाथ होने वाली ब्रिटिश अखबार 'गार्जियन' में छपी खबरों का भी उन्होंने तीव्र प्रतिकार करते हुए इन खबरों का तीव्र खंडन किया। ऐसा पहली बार नहीं है, जब विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी बात सख्ती से दोटूक अंदाज में रखी। विश्व पटल पर भारत की छवि मोदी सरकार ने लगातार बदली है। यह कहना कि आतंकवादी किसी नियम से नहीं चलते, उन्हें जवाब भी वैसे ही मुंहतोड़ तरीके दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हितों का पालन करते हुए भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने तथा मानवाधिकारों का सम्मान और बहुपक्षवाद पर केंद्रित रहता है। आज भारत के लिए हालात इतने साजगार हो चुके हैं कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वैश्विक अगुवा बने रहने और दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखने में भारत हिचकता नहीं। निःसंदेह हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए विदेशी निवेश, संयुक्त उद्यम और निर्यात के क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था प्रदर्शन बेहतर नजर आ रहा है। ऐसे में सीमापार से होने वाले आतंकवादी उपद्रव को लेकर यदि कड़ाई नहीं बरती जाती है तो न केवल भारत की छवि धूमिल होती है, बल्कि आतंकवाद के प्रति सटीक और तत्काल निर्णय न लेने के कारण देश की अखंडता और शांति भी खंडित होती है जिसे बनाए रखना सरकार की महती जिम्मेदारी है।

सूक्ति

दंड द्वारा प्रजा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन बिना कारण किसी को दंड नहीं देना चाहिए।
- रामायण

शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए शांति की इच्छा नहीं बल्कि आवश्यक है इच्छाओं की शांति।
- स्वामी ज्ञानानंद

चिंतन-मनन

संयम से जीवन की उन्नति

कार्तिय माहात्म्य प्रवचनों में पं. रामनिवास ब्रजवासी जी ने कहा शरद ऋतु में की जाने वाली उपासनाओं से जहाँ चंद्र किरणों से प्राप्त होने वाले अमृत तत्व से देह का सिंचन होता है, वहीं सूर्य की रश्मियों की प्रचुर ऊर्जा से उस अमृत तत्व की शरीर में स्थिरता होती है इसीलिए कार्तिक मास में प्रात? पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु शालीग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है।

इन दिनों ब्रजवासी जी कार्तिक माहात्म्य के माध्यम से श्रद्धालुओं को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में संयम एवं धर्म में चलने की प्रेरणा मिलती है। जीवन को उन्नत बनाने में संयम का बहुत महत्व है। संयमी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं छोड़ता।

शालिग्राम पूजन में पंचामृत का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा गाय का दूध, दही, घी व शहद और शक्कर से शालिग्राम भगवान का अभिषेक करना चाहिए। वस्तुतः इन पांचों का मंत्रोच्चारण के साथ मिल जाना ही पाँच प्रकार के अमृतों का मिलना है।

इसमें तुलसीदल डाल देने के बाद यह चरणामृत बन जाता है जिसका प्रसाद में ग्रहण कर लेने पर सभी प्रकार की आधियाँ-व्याधियाँ अर्थात मानसिक रोग तथा शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। हमारी उपासना विधियाँ जहाँ मनुष्य को धार्मिक बनाती है वही शारीरिक-मानसिक रूप से स्वस्थ भी बनाती है।

देश की रक्षा हेतु आवश्यक है परमाणु अस्त्र

संजय गोस्वामी

देश की सुरक्षा सबसे पहले है क्योंकि आज किसी देश पर हमला होता है जो किसी देश के भाग पर गलत तरीके से कब्जा हो जाता है। क्योंकि यदि उसके पास परमाणु अस्त्र नहीं है तो दूसरा देश हमेशा कब्जा करेगा। क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है परमाणु अस्त्र के नष्ट करने के बारे में किसी भी नेताओं को सोचना नहीं चाहिए क्योंकि ऐ देश की एकता और ताकत देता है जैसे अगर आप किसी राह पर चल रहें हों और रात का समय हों तो आप अपनी रक्षा हेतु लाठी डंडा रखरखाव और अपने बचने के लिए करते है डंडा से सभी को पीटना मेटा उद्देश्य नहीं है लेकिन अगर मेरी माँ बहने को छेरे तो पीटना आवश्यक है इसी तरह परमाणु हथियार है जो यदि कोई हमला करे तो डराया जा सके आज दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है इसके परिणाम हम सभी जानते हैं 79 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था. इसके तीन दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया. दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो गए. डेढ लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई और जो बच गए वो अपंग हो गए और आज भी जो बच्चे जन्म लेते हैं वे अपंगता के शिकार होते हैं क्योंकि रेडिएशन का खतरा 100वर्षों ?ा इससे भी अधिक रहता है लेकिन सभी देशों में एक सहमति नहीं बनी की सभी नस्ट करें ऐसे में हमारा परोसी देश आतंकवादी हमला और परमाणु बम छोड़ने की बात करता है। कहता है इधर चीन है तो दूसरा पाकिस्तान दोनों के पास भरपूर एटम बम है अतः भारत को भी अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए जरुरी है। जब भारत में अटलजी जैसा प्रधानमंत्री हुआ तो 11 मई 1998 को उन्होंने इतिहासिक फैसला लिया परमाणु परीक्षण को मंजूरी देने के लिए भारत की अमेरिका का आर्थिक प्रतिबन्ध भी और दिया लेकिन पहले है। कागजी को थे जमीन सुरक्षा अमल की बहुत कठिन होता होड़ में सभी देश विज्ञान के आधार पर अपने देश को प्रगतिशील,समृद्धशाली, समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। इस होड़ अर्थात प्रतिस्पर्धा को लेकर सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्रा-शस्त्रों का उत्पादन करने में जुट गए हैं।अब ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध में कहीं परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल न हो जाए लेकिन ऐसा किस उद्देश्य के लिए हो रहा होगा उधर चीन और ताईवान मेँ भी युद्ध के बादल मंडरा रहें हैं चीन और अमेरिका के इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है आज सारे देश में हथियार खरीदने की होड़ लगी है नित्य नये-नये घातक अस्त्रा-शस्त्रों का निर्माण हो रहा है ईरान अब इजराइल में युद्ध की आहट सुनाई दें रही है क्योंकि दोनों राष्ट्र में परमाणु अस्त्र है ऐसे में परमाणु अस्त्र को नष्ट करने की सोचना भी नहीं चाहिए ऐ हमारी रक्षा हेतु अति आवश्यक है हैं।रूस और यूक्रेन के युद्ध में निर्दोष नागरिकों की बहुत अधिक संख्या में जान जा रही है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्थ हो गया है इस जंग में यूक्रेन व रूसी सैनिकों की भी मौत हो रही है एक देश दुसरे देश के शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में अपने देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है व विश्व शांति पर खतरा मंडराने लगा है 2 साल व 3महीने से चल रहे इस युद्ध में केवल तबाही मची है व बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है अब ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध में कहीं परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल न हो जाए लेकिन ऐसा किस उद्देश्य के लिए हो रहा होगा ऐ सीमा विवाद के कारण है चीन और ताईवान में भी युद्ध के बादल मंडरा रहें हैं जैसा चीन और अमेरिका के इस पर चिंतन करने की आवश्कता है हमारा भारत पर कोई आँख दिखाने की कोशिश तभी नहीं करेगा जब उसे मालूम होगा कि हमें भी अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता है उक्रेन के पास परमाणु हथियार जब तक थे उससे पंगा मोल लेने के लिए कोई सोचा भी होगा तो कर नहीं सका होगा लेकिन यूएस के कहने पर जैसे ही परमाणु अस्त्र नष्ट किया बाद मे हमला हो रहा है और हथियार के लिए दूसरे देश पर निर्भर होना पर रहा है नुकसान दोनों को हों रहा है भारत ने किसी का समर्थन ना कर उचित कदम उठाया है ऐसा इसलिए की हमारे वैज्ञानिक ने इतिहास रचा परमाणु इसके स्व स्व कलाम साहब ने अतुलनीय योगदान किया और देश की ताकत बेतहाशा बढ़ि सभी देशों मे डंका बजा और राष्ट्र एकजुट हुआ था उस वक्त उसी का देखा देखी कर पाकिस्तान ने बड़ी भारी कर्ज लेकर मामूली सा परमाणु परीक्षण किया तो बाद मे कर्ज का भार बढ़ते बढ़ते आज खाने के लाले पड़ रहें हैं अतः इसपर राजनीती करना बिलकुल सही नहीं है यदि किसी विपक्ष ने मैंनोफेस्टो मे डाला है तो ये बिलकुल देश हित मे नहीं है जैसा की प्रधानमंत्री जी के किसी भाषण में जिक्र किया है ऐ सही थे अतः हमें इसमें बिलकुल राजनीति करना उचित नहीं है नहीं तो फिर परोसी दो देश केवल आंखे दिखा रहा है वो हमला भी कर सकता है आप जरा सोचिये बैंक की सुरक्षा हेतु गार्ड मशीनगन लेकर खड़ा रहता है लेकिन कभी किसी पर गोली नहीं चलाता है लेकिन यदि किसी ने लूटने की कोशिश की तो सुरक्षा हेतु चलाना होता है.भगवान राम ने आखिर रावण से युद्ध क्यों किया अपने लिए नहीं माँ सीता की रक्षा हेतु अतः जब युद्ध होता है तो सबसे बड़ा नारी सुरक्षीत नहीं रहती है इसलिए गुरुगोविंद सिंहजी ने नारी की रक्षा हेतु शांति के साथ साथ तलवार भी देश की रक्षा के लिए उठाई जो पूज्यनीय है देश सर्वोपरि है और नारी सहित सभी की सुरक्षा हेतु परमाणु अस्त्र भी उतना ही जरूरी है मानवता की भलाई हेतु परमाणु अस्त्रों पर अंकुश लगाना जरुरी है लेकिन जब सभी राष्ट्र सही में नष्ट करें तभी नहीं तो परमाणु अस्त्र बहुत जरुरी है जिसे वैज्ञानिकों ने अपने पसीने से सींचा है नव भारत की रक्षा हेतु इस बात की आवश्यकता है कि उचित निदान द्वारा विश्वजनित मतभेदों को भुलाकर अशांति का माहौल खत्म किया जाए। अतः परमाणु निःशस्त्रीकरण कोई सही कदम नहीं है नहीं तो दूसरा देश मौके का फायदा उठा लेगा और युद्ध में कोई किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं लें सकता है.अतः देशहित में शांति और क्रांति दोनों जरुरी है.निःशस्त्रीकरणह्व का शाब्दिक अर्थ है-घातक हथियारों पर नियंत्रण रखना और शस्त्रों की बढ़ती संख्या को रोकना ना की नष्ट करना अपनी रक्षा हेतु परमाणु अस्त्र अति आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश : फिर से कसौटी पर

डॉ. सी.पी. राय

देश में राजनीतिक और लोकतांत्रिक सत्ता का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भागीदार प्रदेश है, जहां की 80 सीट देश का भाग्य तय करती हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आज तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से आधे उत्तर प्रदेश से रहे। पिछले दो चुनावों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा के लिए आधार का काम किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार दो बार से बनारस से सांसद हैं।

इस बार उत्तर प्रदेश बहुत खामोश है। यह खामोशी सभी दलों को बेचैन किए हुए है। राजनीतिक पंडितों का मानना है की अगर मतदाता का रु झान सत्ता की तरफ होता है तो वो चुनाव शुरू होने के साथ ही दिखाई देने लगता है। ज्यों-ज्यों चुनाव उठान लेता है, सत्ता समर्थक मतदाता ज्यादा मुखर होता जाता है। इस बार वो या तो खामोश है, या अलग-अलग खांचे में सत्ता से जुड़े प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी जता रहा है। भाजपा ने अपने काफी सांसदों को फिर से टिकट दिया है। इनमें से अधिकांश जीतने के बाद लौट कर अपने क्षेत्र में गए ही नहीं या जिस केंद्रीकृत तरीके से भाजपा की सत्ता चल रही है, और उसमें केंद्र तथा प्रदेश के चंद लोगों को छोड़ कर किसी की भी प्रभावी भूमिका नहीं है। यहां तक कि मंत्री, सांसद और विधायक का अधिकारी या दरोगा फोन तक उठाने की जहमत नहीं करते। जनप्रतिनिधि जनता या कार्यकर्ता की आवश्यक मदद करने में असफल रहे हैं, और इसलिए भी लोगों से कटे रहे। इसलिए उनका क्षेत्र में जबरदस्त विरोध है। एक दूसरा विरोध, जो बड़े पैमाने

पर हाल में दिखा, सहारनपुर में हुआ जब क्षत्रिय समाज ने विशाल सम्मेलन किया जिसमें भाजपा का विरोध करने का फैसला किया गया। कुछ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अज्ञात कारणों से एक हवा चल गई है कि यदि केंद्र में दुबारा मोदी सरकार आ गई तो उसमें न तो राजनाथ सिंह के लिए स्थान होगा और न गडकरी के लिए और उससे भी ज्यादा चर्चा व्यापक है कि उस स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मोदी और अमित शाह तुरंत हटा देंगे क्योंकि योगी इन लोगों के सामने मजबूत विकल्प के रूप में उठ खड़े हुए हैं। इस अफवाह का असर भी मतदाता के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता दिख रहा है।

इस बार के चुनाव को अचानक उठ खड़े हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के बवंडर ने भी ग्रहण लगा दिया है। इसके उजागर होने के बाद पीएमकेयर फंड को लेकर शंका के बादल घुमड़ने लगे हैं। देखा गया है कि जब भी कोई सत्ता नौकरशाही और व्यवस्था को सारी ताकत सौंप कर खुद को सुरक्षित समझने लगती है, दरअसल तभी वो ज्यादा असुरक्षित हो जाती है क्योंकि राजनीति नेता या कार्यकर्ता, कैसा भी हो, को जनता का लिहाज करना ही होता है। दरवाजे पर आए व्यक्ति के लिए निकलना ही होता है। नौकरशाही के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जनता के साथ उनके व्यवहार का खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। यही स्थिति इस बार नासूर जैसी दिख रही है।

उत्तर प्रदेश में कैराना से इकरा हसन, सहारनपुर से इमरान मसूद, आजमगढ़ से धम्रेद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के पुत्र, मैनपुरी से डिंपल यादव, बांदा से शिवशंकर पटेल, बिजनौर से यशवीर सिंह, हाथरस से जसवीर बाल्मिकी, फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबू लाल के पुत्र रामेर सिंह, अलीगढ़ से बृजेंद्र सिंह, लालगंज से दरोगा सरोज, मछली शहर से तूफानी सरोज, फरूखाबाद से डॉ. नवल किशोर शाक्य, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, रामपुर से विपक्षी प्रत्याशी, अमरोहा से दानिश अली, कानपुर से आलोक मिश्र, उन्नाव से अनु टंडन, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, गोंडा से श्रेया वर्मा, घोसी से राजीव राय, बासगांव से सफल प्रसाद, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, संभल से जियाउर्रहमान वर्क सहित मुलायम सिंह यादव के परिवार वाली अन्य सीट तथा अमेठी और रायबरेली सहित करीब 45 सीटें ऐसी हैं, जो सत्ताधारियों के लिए कठिन डगर साबित हो रही हैं, और ये विपक्षी उम्मीदवार चुनौती देते दिख रहे हैं, तो भाजपा के नाराज लोग भितरघात करते भी दिखलाई पड़ रहे हैं। गौर करने की बात है कि जहां 2014 में भाजपा 71 सीट जीती थी, वहीं 2019 में पुलवामा और बालाकोट की लहर के बावजूद उत्तर प्रदेश में उसकी सीट घट कर 62 हो गई थीं, इस बार तो कोई लहर भी नहीं है। इस कारण लगता है कि मतदाता ने खामोशी बरतते हुए मतदान के दिन ही फैसला सुनाने का निश्चय कर लिया है।

राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियां और समीक्षकों की समीक्षा तथा एग्जिट पोल वालों को अक्सर मतदाता झुठलाता दिखता रहा है। बहरहाल, हमें 4 जून का इंतजार करना होगा और उसका इंतजार भविष्य को भी है, और भारत में रुचि रखने वाली दुनिया में भी सभी को।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रधान संपादक : राघवेंद्र, पटना कार्यालय : रामनगरी आशियाना रोड, पटना/रांची कार्यालय: 201 मानस भवन,कांके रोड, रांची। संपर्क : 7488117482...

संपादकीय

"हृदय की गहन खुशी एक चुंबक की तरह है, जो जीवन का मार्ग बताती है। -मदर टेरेसा

आज अगर दुनिया में बिकने वाला हर सातवां आईफोन भारत में ही बन रहा है, तो इससे देश में 2014 में शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान की सार्थकता ही साबित होती है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ऐसी कामयाबियों को अन्य उत्पादों के संदर्भ में दोहराना भी जरूरी है।

मेक इन इंडिया

आईफोन निर्माता कंपनी एपल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से करीब दस अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात करके, जो उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में किसी सिंगल ब्रांड उत्पाद का भारत से किया गया अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है, एक नया कीर्तिमान तो स्थापित किया ही है, देश की अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक असर भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एपल का वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत दस अरब डॉलर का निर्यात-लक्ष्य था, जिसे एक वर्ष पहले ही हासिल कर लेना निस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि एपल ने 2023-24 के दौरान भारत में 14 अरब डॉलर के आईफोन निर्मित किए, और अब दुनिया में बिकने वाले कुल आईफोन के 14 फीसदी का उत्पादन भारत में ही हो रहा है। आज अगर दुनिया में बिकने वाला हर सातवां आईफोन भारत में ही बन रहा है, तो इससे 2014 में शुरू 'मेक इन इंडिया' अभियान की सार्थकता ही साबित होती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका व चीन के बीच तल्ख रिश्तों को देखते हुए एपल को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए उसने चीन से, जो अब भी सबसे ज्यादा आईफोन बनाने वाला देश है, बाहर कुछ विनिर्माण प्लांट लगाने की सोची और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार भारत की ओर रुख किया। 2017 में भारत में आईफोन का निर्माण शुरू करने के बाद एपल ने पीएलआई योजना के अनुरूप ताइवान की दिग्गज कंपनियों, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की मदद से अपने स्थानीय उत्पादन का विस्तार किया। इसके अलावा, कर्नाटक में विस्ट्रान कारपोरेशन का भी संयंत्र है, जिसका कुछ ही समय पहले टाटा समूह ने अधिग्रहण किया था। गौरतलब है कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा पहले देश में स्मार्टफोन का प्रसार हुआ और शुरुआत में भारतीय खरीदारों का रुझान अपने बजट के अनुकूल चीन में निर्मित हैंडसेट की ओर ही दिखा,

लेकिन हालिया वर्षों में स्टेटस सिंबल के तौर पर आईफोन के प्रति भारतीयों का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। एपल के इस प्रसार से देश में विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ने के साथ एक सशक्त विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा भी स्थापित हुई है। यही नहीं, पीएलआई की शुरुआत के बाद से इसने डेढ़ लाख नई प्रत्यक्ष और करीब तीन लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। कुल मिलाकर देखें, तो यह 'मेक इन इंडिया' की कामयाबी की कहानी है, जिसे, 2047 तक विकसित राष्ट्र होने के लिए, अन्य उत्पादों के संदर्भ में दोहराना भी जरूरी है।

पूरा इलाज बनाम मरहम-पट्टी

जहां भाजपा ने अपने घोषणापत्र को महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीबों पर केंद्रित रखा है, वहीं कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों एवं वंचित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय की बात की है।

क्या अकेले चुनाव घोषणापत्र से चुनाव जीता जा सकता है? खैर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ऐसा ही सोचती हैं। उन्होंने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें भविष्य के भारत के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने जहां अपने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है, वहीं भाजपा ने 'संकल्प पत्र'।

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, भाजपा का घोषणापत्र विकसित भारत के चार स्तंभों-महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीबों पर केंद्रित है। यह 'जीवन की गरिमा', 'जीवन की गुणवत्ता', 'अवसरों की संख्या' के साथ-साथ 'अवसरों की गुणवत्ता' की बात करता है। दूसरी तरफ, कांग्रेस का घोषणापत्र राहुल गांधी के नजरिये को प्रतिबिंबित करता है अथवा वह समस्याओं के वास्तविक समाधान के बारे में क्या सोचते हैं। यह पांच 'न्याय' अथवा युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों एवं हाशिये के समुदाय के लिए सामाजिक न्याय की पांच गारंटी की बात करता है। इसमें सरकारी नौकरी, जातिगत जनगणना, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के खाते में धन हस्तांतरण का वादा किया गया है। यह 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी का वादा करता है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

कई विशेषज्ञों ने यह समझने के लिए दोनों घोषणापत्रों की तुलना करने की कोशिश की है कि कौन-सी पार्टी पूर्ण उपचारों की बात करती है और कौन-सी अनिवार्य रूप से मरहम-पटटी की। कांग्रेस का घोषणापत्र मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत ही आकर्षक और सरल समाधान जैसा दिखता है। भाजपा का घोषणापत्र भी पार्टी की कल्याणकारी राजनीति को जारी रखने और विस्तारित करने, गरीबों और हाशिये पर रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा रोजगार पैदा करने वाली नीतियों का वादा करता है।

भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं, गरीबों, युवाओं एवं किसानों समेत 10 सामाजिक समूहों और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था समेत 14 क्षेत्रों को गारंटी सूची में शामिल किया गया है। हरेक मामले में मोदी ने नीतिगत हस्तक्षेप, जमीनी कार्यान्वयन और योजनाओं के पूरा होने का आश्वासन दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाजपा के अंत्योदय का मार्गदर्शक मंत्र पूरा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा के वादों को मोदी की गारंटी का समर्थन है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने और फिर 2019 में दूसरा कार्यकाल पाने के बाद से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी सरकार अकेले सभी वादों को पूरा करने में विश्वास करती है। इससे यह भी समझ में आता है कि भाजपा 'हिंदुत्व' पर ज्यादा जोर नहीं देगी, बल्कि यह मोदी के इच्छानुसार 'सबका विकास' पर जोर देगी। भाजपा मध्यवर्ग और नव-मध्यवर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसे उसने पिछले दशक में गरीबी से बाहर निकाला है। हर पहल के लिए मोदी की गारंटी की वजह यही है कि मतदाताओं की समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता पर भरोसा दिलाने के लिए भाजपा पूरी तरह से मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर है।

गरीबों से अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन, रियायती स्वास्थ्य सेवा, आवास सुविधाएं, सौर ऊर्जा उत्पादन जैसी योजनाओं के जरिये शून्य बिजली बिल का वादा किया गया है। मध्य वर्ग के लिए, दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के शहरों में उच्च वेतन वाली नौकरी के सृजन, जीवन की सुगमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का वादा किया गया है।

महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, कल्याण, सुरक्षा और कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया है। गौरतलब है कि महिलाओं ने पिछले लोकसभा चुनाव एवं कई राज्यों के चुनावों में जीत हासिल करने में भाजपा की मदद की थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी लगातार मोदी सरकार की पहुंच में बने हुए हैं। घोषणापत्र में उनकी विरासत और संस्कृति की रक्षा, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके लिए आजीविका के स्तरों का विस्तार करने की बात कही गई है।

दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि उसे गरीब समर्थक एवं कल्याणोन्मुख घोषणापत्र पर टिके रहना चाहिए। यह गरीबों के लिए आर्थिक भुगतान, श्रमिकों को उच्च मजदूरी एवं ग्रेजुएटों के लिए अनिवार्य तौर पर भुगतान के साथ इंटर्नशिप का वादा करता है। कांग्रेस ने अपने मूल मतदाताओं का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है। इसने सभी गरीब परिवारों को एक लाख रुपये देने का वादा किया है, हालांकि 2011 के बाद से देश में कितने गरीब हैं, उसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, जब आखिरी बार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। कांग्रेस ने दूसरे भूमि सुधार में अतिरिक्त सरकारी जमीन को गरीबों में बांटने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनाने का भी वादा किया है, जिसके तहत किसी को भी एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज खरीदने की इजाजत नहीं होगी। यह फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन देने और खेती को भी मनरेगा के दायरे में लाने का वादा करती है। पार्टी ने कहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। और किसानों की ऋण आवश्यकता और उनकी वित्तीय स्थिति तथा मंडियों से बाहर भी किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता की समीक्षा करने के लिए भी एक निकाय बनाने का वादा किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया है कि इन सभी वादों को पूरा करने के लिए वह धन कहां से लाएगी, क्योंकि इन्हें पूरा करने पर सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा हटाने और मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने जैसे विभिन्न वादों को लागू करने की समय सीमा भी नहीं बताई गई है। कांग्रेस के वादों का राजकोष पर बोझ बढ़ सकता है। वर्ष 2012 के गरीबी अनुमान के अनुसार, प्रति गरीब परिवार को एक लाख रुपये का भुगतान करने पर सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च करना पड़ सकता है। सभी खाली पदों को भरने से भी खजाने पर बार-बार बोझ बढ़ेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि मतदाता किस पर भरोसा करते हैं-नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के वादों पर!

जीवन धारा

आचार्य विद्यासागर

भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य योग है। भोग, आशा-तृष्णा के द्वारा अलौकिक शांति नहीं मिल सकती है। दवा के द्वारा रोग निकल सकता है, शक्ति भोजन से ही मिलती है।

नाम के पीछे पड़कर हम भाव को भूल गए

आचार्यों, संत-महात्माओं की दृष्टि द्वेष की तरफ नहीं जाती है। आंतरिक विशेषता की तरफ ही आचार्यों की दृष्टि रहती है। यदि हम शीतल जल चाहते हैं, तो हमें पानी को गर्म हवा व उष्णता से दूर रखना पड़ेगा। अनादिकाल से कर्म का संबंध आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसे प्रेरणा, क्षेत्र, काल इत्यादि को पाकर विशुद्ध बनाया जा सकता है। अनेक व्यक्ति इस रहस्य के बारे में जानते भी नहीं हैं।

वर्तमान में विद्या का प्रचार बहुत हो रहा है। आज से 50 साल पूर्व अगर कोई मैट्रिक पास कर लेता था, तो उसे बहुत आदर मिलता था, पर आज तो अनेकों बीए, एमए, पीएचडी पास घूमते हैं। आज हम नाम के पीछे खुश हो जाते हैं। अपने गुरु का भी आदर नहीं करते। गुण दो प्रकार के होते हैं-जो विपरीत दिशा की तरफ झुक जाएं, वे अवगुण और सीधी तरफ झुक जाने पर सद्गुण हो जाते हैं। कीमत फ्रेम की नहीं है, बल्कि उसमें जड़े कांच की होती है। लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है। फ्रेम की कीमत है और कांच की नहीं। फ्रेम सारयुक्त तभी बन सकता है, जब उसमें दृष्टि के अनुसार कांच हो। हालांकि कांच की रक्षा फ्रेम से होती है। लेकिन कांच के बिना भी फ्रेम की कोई कीमत नहीं है। हमारी दृष्टि सिर्फ फ्रेम तक ही जाती है। हम आत्मा रूपी दर्पण (कांच) की तरफ नहीं देख रहे हैं। हमारी दृष्टि अंतरंग की ओर न जाकर, बाहर की ओर जा रही है। आज ऐसी विद्या की तरक्की हो रही है, जिसे ग्रहण करके विद्यार्थी दास बनता जा रहा है। विद्या ऐसी ग्रहण करनी चाहिए कि जिससे दास बनने के बजाय हम मार्गदर्शक बन जाएं। पहले व्यापार और त्याग करने में हमारा नाम पहले आता था, पर आज हम सिर्फ नाम के पीछे पड़ गए। नाम-निक्षेप के पीछे पड़कर भाव-निक्षेप को भूल गए। भाव-निक्षेप वाला ही कृत-कृत्य कहलाता है। वही सुखी बन पाता है।

आज जीवन का लक्ष्य बना है अर्थ कमाना। हमने विद्या को अर्थ का माध्यम बना रखा है। इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है, जब वह समीचीन विद्या ग्रहण करे। आज सभी अर्थ के लिए विद्या ग्रहण करते हैं। इस विद्या से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं।

भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य योग है। भोग, आशा-तृष्णा के द्वारा अलौकिक शांति नहीं मिल सकती है। दवा के द्वारा रोग निकल सकता है, शक्ति भोजन से ही मिलती है। लौकिक विद्या व भोगों में भारत से बाहर के देश बहुत आगे हैं, लेकिन वहां पर अरबपति भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। विदेशों में भी इसलिए लोग भोग से ऊब चुके हैं। हमारे आचार्यों ने ऐसी विद्या बताई है कि जिससे आना-जाना गति-भ्रमण सब खत्म हो जाता है। विद्या पाकर इधर-उधर भटकना नहीं है। समझदार व्यक्ति स्वर्गादि की इच्छा नहीं करते।

धन का सदुपयोग...

सूत्र

कीमत जौहरी की है, जवाहरात की नहीं। जवाहरात के नष्ट होने पर तो और भी उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु जौहरी का नाश होने पर जवाहरात की कीमत कौन आंकेगा? सुख के लिए हमें प्रवृत्ति को रोककर निवृत्ति को अपनाना पड़ेगा। मानव कल्याण केवल लौकिक शिक्षा से नहीं कर सकते। आज समाज के लाखों रुपये विपरीत दिशा में खर्च हो रहे हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए।

दूसरा पहलू

हरियाणा दुनिया का संभवतः पहला राज्य है, जिसने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को भी पेंशन देने की योजना शुरू की है।

बुजुर्गों की तरह पेड़ों को भी पेंशन

हरियाणा देश ही नहीं, दुनिया का संभवतः पहला राज्य है, जिसने बुजुर्गों की तरह 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को भी पेंशन देने की योजना प्रारंभ की है। दरअसल, 'प्राण वायु देवता पेंशन योजना' के तहत राज्य में कुल 3,810 पेड़ों का चयन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पेड़ को सालाना 2,750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि उस व्यक्ति के खाते में भेजी जाएगी, जो उस पेड़ की देखभाल करेगा। यही नहीं, पेड़ों के लिए निर्धारित पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। यह इसलिए भी अहम है कि इसमें पेड़ों को 'आर्थिक वस्तु' नहीं, बल्कि एक 'जीवित इकाई' के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ों को पेंशन देने का अर्थ है, उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना। इससे उनकी ऑक्सीजन व अन्य उपदान देने की क्षमता का विस्तार होगा। इस पेंशन योजना के तहत 40 प्रजातियों के पेड़ों को शामिल किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर और कदंब जैसे पेड़ शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य पारिस्थितिक महत्व के विशाल पेड़ों का संरक्षण करना है। इससे छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है और पुराने पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है, क्योंकि पेंशन मिलने की उम्मीद में ऐसे पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है और जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने में मददगार साबित हो सकती है पेड़-पौधे वातावरण से नुकसानदेह ग्रीनहाउस गैसों को अपने अंदर सोख कर ग्लोबल वार्मिंग से हमारी रक्षा करते हैं। एक वयस्क पेड़ एक साल में वातावरण से लगभग 48 पौंड से अधिक कार्बन डाई-ऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। शोध बताते हैं कि एक वर्ष में एक एकड़ में लगे पेड़ उतना कार्बन डाई-ऑक्साइड सोख लेते हैं, जितना एक कार औसतन 2,600 मील की दूरी तय कर उत्पन्न करती है। कुछ साल पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने एक पेड़ की औसत कीमत 74,500 रुपये बताई थी। इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने की लागत और समस्त पारिस्थितिक लाभों को जोड़ा गया था। पेड़-पौधों का संरक्षण पृथ्वी की खुशहाली के लिए जरूरी है। ये वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा जैव-विविधता का पोषण करने में भी सहायक हैं। बहरहाल, बुजुर्ग नागरिकों की तरह बुजुर्ग पेड़ों को भी संरक्षित करने की यह पहल स्वागतयोग्य है, इससे देश सामाजिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से सबल हो सकता है।

सुधीर कुमार

इस योजना के तहत 40 प्रजातियों के पेड़ों को शामिल किया गया है, जिनमें पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर और कदंब आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक महत्व के पेड़ों का संरक्षण करना है।

पेड़-पौधे वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा जैव-विविधता का पोषण करने में भी सहायक हैं।

आंकड़े

भारतीय स्मार्ट फोन आयातक

2023-24 के अप्रैल से जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मूल्य के 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन अमेरिका ने आयात किए।

देश	आयात
अमेरिका	406.92
यूएई	222.12
नीदरलैंड	83.27
इटली	59.57
चेक	57.40

(आंकड़े करोड़ डॉलर में) स्रोत : DoC

मन मिट्टी से सनी हुई सुई है और ईश्वर है चुंबक। मिट्टी के रहते हुए सुई का चुंबक के साथ संयोग नहीं हो सकता, इसलिए मिट्टी को धोना जरूरी है।

सत्संग और प्रार्थना

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आया और बोला, 'महाराज, आप कहते हैं कि संसार में रहकर में भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मैं तो रोज ईश्वर को पुकारता हूं, परंतु मन को कोई सुकून ही नहीं मिलता।'

स्वामी जी ने कहा, 'ईश्वर को पाने के लिए निरंतर सत्संग और प्रार्थना करनी चाहिए।'

उस व्यक्ति ने कहा, 'प्रार्थना तो मैं निरंतर करता हूं, प्रभु! लेकिन प्रार्थना के बाद सत्संग क्यों आवश्यक है?'

स्वामी जी ने समझाया, 'जिस प्रकार तुम अपने बाग को जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर बाड़ लगाते हो, उसी प्रकार सत्संग भी तुम्हारे मन को विकारों से दूर रखता है।'

उन्होंने उस व्यक्ति को प्रार्थना के नए ढंग बताते हुए कहा कि ईश्वर के सम्मुख रोकर प्रार्थना करो, क्योंकि रोने से मन का मैल धुल जाता है। मन मिट्टी से सनी हुई सुई है और ईश्वर है चुंबक।

मिट्टी के रहते हुए सुई का चुंबक के साथ संयोग नहीं हो सकता, लेकिन जब सुई की मिट्टी धुल जाती है, तो चुंबक स्वयं उसे अपनी ओर खींच लेता है। यहां सुई से लगी मिट्टी से तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय-वासना आदि से है।

आज का इतिहास

बम्बई से ठाणे के बीच चली पहली छुक छुक गाड़ी

आज भले ही सुपरफास्ट, बुलेट ट्रेन का जमाना हो, लेकिन भारतीय रेलवे के इतिहास में 16 अप्रैल के दिन की खास अहमियत है और हमेशा रहेगी। दरअसल 1853 को 16 अप्रैल के दिन देश में पहली रेल चली थी।

साल का यह 106वां दिन एक और कारण से भी सदा याद किया जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग. हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा और उपवास की घोषणा की। 1945 में एक सोवियत पनडुब्बी के कारण जर्मन शरणार्थी पोत डूब गया, जिससे 7000 लोग मारे गए।

1964: ब्रिटेन के चर्चित अपराधों में शामिल 'द ग्रेट ट्रेन रॉबरी' के लिए 12 लोगों को 307 साल की सजा सुनाई गई।

पैसा है, तो दिखाएंगे

देश में नए तरह के व्यवसाय पनपने से समृद्ध भारतीयों की नई पौध जन्मी है, जिनकी क्रय शक्ति ज्यादा है और वे शानो-शौकत से जीना चाहते हैं।

मधुरेंद्र सिन्हा | चलन

जब कोई देश तरक्की के रास्ते पर चलने लगता है, तो वहां के पैसे वाले लोगों के जीने का तरीका ही बदल जाता है। वे शानो-शौकत की जिंदगी जीते हैं और खूब खर्च भी करते हैं। ऐसे में विलासिता और बड़े ब्रांड के सामान की बिक्री बढ़ जाती है। पुरुषों की कलाइयों पर महंगी घड़ियां चमकने लगती हैं, तो महिलाओं के हाथों में महंगे हैंडबैग होते हैं। स्वदेशी कारें उनकी पसंद नहीं होती हैं, बल्कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और यहां तक कि लैंबोर्गिनी उनकी पसंद हो जाती हैं। मध्य वर्ग फ्लैटों से निकल कर प्रीमियम मकान या फिर पेंट हाउस खरीदने लगता है।

ये सारी बातें इस सदी के शुरू में चीन में खूब देखने में आईं। कहते हैं कि जब पैसा आता है, तो वह सिर चढ़कर बोलता है। दुनिया का हर नामी ब्रांड वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा था। इसी तरह नब्बे के दशक में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो यहां भी

बदलाव दिखने लगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत तेजी आई है। कभी एक लैंडलाइन फोन के लिए धक्के खाने वाला शहरी भारतीय आज लाखों रुपये के मोबाइल फोन चमकाता दिख जाएगा। छोटी-सी मारुति या हुंडई की कारों में संतुष्ट रहने वाला भारतीय आज धड़ल्ले से लग्जरी कारें खरीद रहा है। वर्ष 2023 में भारत में हाई एंड कारों की बिक्री में उसके पिछले साल की तुलना में 21 फीसदी का इजाफा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और समृद्ध लोगों के रुझान बता रही है। लैंबोर्गिनी कारों की कीमतें साढ़े तीन करोड़ से लेकर पौने नौ करोड़ रुपये तक होती है। वर्ष 2023 में भारत में उसकी बिक्री बढ़कर 100 तक पहुंच गई। इसी तरह सुपर बाइकों का बाजार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दस-दस लाख रुपये की सुपर बाइकें सड़कों पर दौड़ती दिख रही हैं। नई समृद्धि से प्रीमियम सेगमेंट के मकानों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और अब रियल एस्टेट में लग्जरी मकानों की भरमार होती जा रही है। बड़े डेवलपर करोड़ों रुपये कीमत वाले मकान बनाते जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण दिल्ली के समीप नोएडा में दिखाई पड़ रहा है, जहां कभी एक करोड़ रुपये के मकान बहुत ही कम दिखते थे और उसे प्रीमियम हाउसिंग माना जाता था, लेकिन अब वहां दस-दस करोड़ रुपये के मकान बनने लगे हैं। गुरुग्राम तो इसमें हमेशा आगे रहा है और वहां तो 30-35 करोड़ तक के मकान बन गए हैं और प्रीमियम सेगमेंट के मकानों की बाढ़ आ गई है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो छोटा-सा प्लॉट भी अरबों रुपये में बिकता है। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ ने बताया कि वहां इस समय तीन करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक के मकानों की खूब मांग है। जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में अच्छा-खासा पैसा कमा लिया है, वे खुलकर जिंदगी जीना चाहते हैं। उनका मोटो है-*लिव लाइफ किंग साइज।* आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 में लग्जरी मकानों की बिक्री में 2022 की तुलना में 81 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लग्जरी मकानों की मांग इतनी है कि गुरुग्राम के एक शीर्ष डेवलपर ने सिर्फ तीन दिनों में 72 अरब रुपये के मकान बेच दिए। इनमें अल्ट्रा लग्जरी मकान भी शामिल हैं, जिनकी मांग बरकरार है। महानगरों में एक नया ट्रेंड आया है विला का। कई डेवलपर इस सेगमेंट में प्रवेश कर गए है, क्योंकि खरीदारों की मांग बढ़ती जा रही है। लग्जरी मकानों की यह चाहत अपने रुतबे को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। अति समृद्ध लोगों की लग्जरी मकानों में जबर्दस्त दिलचस्पी न केवल प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि बढ़िया निवेश का रास्ता भी। इसलिए एक से बढ़कर एक लग्जरी मकान देखने में आ रहे हैं। लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनियां, जैसे गुच्ची, लुई वितो, क्रिश्चियन डीओर, शानेल, प्रादा वगैरह जो हैंड बैग बनाती हैं, उनकी कीमत लाखों में होती है और अब इनका इस्तेमाल करने वाली महिलाएं आपको भारतीय महानगरों में खूब दिखेंगी। यह उनका स्टेटस दिखाने का एक प्रयास भर है। भारत में लग्जरी घड़ियों का चलन रहा है और आने वाले समय में यह और बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में नए तरह के बिजनेस पनपे हैं। टेक्नोलॉजी ने इनमें बहुत साथ दिया है। देश में सैकड़ों स्टार्ट-अप को भारी सफलता मिली है, वेंचर कैपिटल कंपनियां काफी सक्रिय हैं। इन्हीं वजहों से समृद्ध भारतीयों की नई पौध सामने आई है, जिनकी क्रय शक्ति बहुत है और वे राजाओं की तरह शानो-शौकत से रहना चाहते हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 60 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

सम्पादकीय

पेपर लीक और फर्जी खेल प्रमाण पत्रों से प्रदेश की सरकारी नौकरियां और कर्मचारी हुए बदनाम

प्रदेश में आरपीएससी की बदनामी में सबसे बड़ा रोल पेपर लीक का रहा। इसके बाद कई बार फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरियां लेने के खुलासे हुए। पिछले पांच साल में जिस तरह से आरपीएससी के पदाधिकारियों और सरकार में बैठे कुछ लोगों ने चांदी के सिक्के जमा करने का खुला खेल खेला इससे प्रदेश की बदनामी हुई और आज प्रदेश के सरकारी बेड़े में शामिल नए कर्मचारी शक की निगाह से देखे जा रहे हैं। अभी हाल में एक खुलासा हुआ है कि एक गैंग ने खेल के फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए गैंग ने सौ से अधिक लोगों को नौकरियां दिला दी। सरकारी नौकरी लगाने वाली गैंग ने एसओजी की पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। गैंग के सदस्य यू-ट्यूब चैनल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। गैंग के सदस्य फर्जी डिग्री, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, फर्जी मेडल और बैक डेट में एडमिशन दिलाने का काम करते थे। मामले में सुभाष पूनिया (52) निवासी बेरासर घुमाना, राजगढ़ (चूरू), उसके बेटे परमजीत हाल पीटीआई राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बसेड़ी (धौलपुर), प्रदीप शर्मा निवासी सरदार शहर चूरू को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद बीकानेर सीबीईओ ऑफिस में यूडीसी मनदीप सांगवान, उच्च माध्यमिक स्कूल देशनोक (बीकानेर) में यूडीसी जगदीश और फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले राकेश कुमार निवासी सरदारशहर (चूरू) को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी 6 आरोपी आज दिनांक तक रिमांड पर है। गिरोह में शामिल 11 सदस्यों को चिह्नित किया है, जिनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। राजस्थान में पिछले 10 साल से गैंग सक्रिय थी। इन दस सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारें रह चुकी हैं। फर्जी डिग्री गिरोह में बड़ी संख्या में सदस्य जुड़े हुए हैं। कई यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों के साथ ही सरकारी नौकरी में लगे लोग भी गिरोह से जुड़े हैं। करोड़ों रुपए वसूलकर गिरोह अभी तक 100 से अधिक लोगों को फर्जी डिग्री, मेडल और सर्टिफिकेट दिलाकर सरकारी नौकरी लगवा चुका है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सुभाष पूनिया पहले चूरू जिले के राजगढ़ में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। इसके चलते यूनिवर्सिटी में उसकी अच्छी जान-पहचान थी। जॉब पर रहने के दौरान कुछ लोगों को उसने फर्जी डिग्री बनवाकर दी। फर्जी डिग्री बनवाकर सरकारी नौकरी लगाने से क्षेत्र में उसका दबदबा बनने लगा। धीरे-धीरे उसने फर्जी डिग्री के लिए 7 यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया। हालांकि ज्यादातर फर्जी डिग्री वह ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से ही बनवाता था।

हमें सामाजिक, आर्थिक, न्याय की गारंटी चाहिए

संविधान की जगह आस्था को ही राष्ट्र में विकास की राजनीति करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि डॉ. अंबेडकर और महात्मा गांधी ने भारत का जो सपना देखा था उसे ऐसी संकीर्ण अवधारणाओं से कितना नुकसान हुआ है। सोची समझी आस्था की आंधी का ये परिणाम हुआ है कि कुछ वर्षों में ही भारत तो हिंदुस्तान हो गया है तथा हमारा समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जैसी धार्मिक आस्थाओं का रण क्षेत्र बन गया है। हमारे लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को आस्था की राजनीति ने इतना अधिक जाति धर्म के ध्रुवीकरण में बांट दिया है कि राम और रहीम एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हो गए हैं। संविधान और लोकतंत्र में कानून के शासन की जगह भीड़ का शासन फैल रहा है।

वेदव्यास

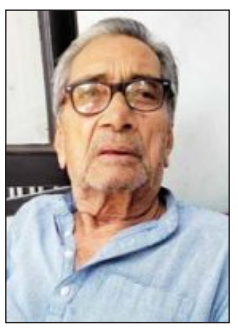

अब नए भारत के निर्माण में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह जैसे महापुरुषों के जीवन दर्शन को भी कोई याद नहीं करता और संविधान के प्रति अपनी आस्थाओं को भी नहीं दोहराता। लेकिन वह अब चारों तरफ राम मंदिर को ही अपनी राष्ट्रवादी आस्थाओं का मूल मंत्र मानकर संसद से सड़क तक असहिष्णुता फैला रहा है। सभी संवैधानिक संस्थाएं निर्बल और असहाय बनाई जा रही हैं ताकि आस्था का सम्राज्य लोगों के मन में भय और अविश्वास पैदा कर सके तथा लोकतंत्र को शासन की निरंकुशता में बदल सके। आस्था की राजनीति का ही ये दुष्परिणाम है कि आज एक पार्टी का बहुमत लोकतंत्र और संविधान के 70 प्रतिशत मतदाताओं को भेड़ बकरी समझकर गड़रिए की तरह हांक रहा है। यह नया भारत बेहद खतरनाक दौर में भारत की आजादी को धकेल रहा है। क्योंकि भारतीय गणतंत्र के इतिहास की सभी प्रेरणाओं को भुलाकर गाय, गंगा, गीता, मंदिर-मस्जिद और राष्ट्रवाद में धकेल रहा है। और सत्ता में बैठे लोग खुलेआम असहमतियों की हर आवाज को कुचल रहे हैं। और लोग नफरत को ही विकास और विकसित भारत का एजेंडा बना रहे है। अब हम बहुत चिंता के साथ ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक आस्थाओं पर आधारित राष्ट्रवाद 21वीं शताब्दी में किसी विकास समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का पर्याय नहीं हो सकता और दुनिया में कहीं भी और कोई देश तानाशाही और अधिनायकवाद में अपना सुरक्षित स्वर्ग स्थापित नहीं कर सकता। भारत की स्वतंत्रता का संविधान शक, हूण, मुगल और अंग्रेजों की लूट और अत्याचारों की पीड़ा भोगकर लोकतंत्र का सवेरा देख रहा है। लोग तब के हिटलर, मुसोलिनी, तोजो और तरह-तरह के चंगेज खां तथा सिकंदर से संघर्ष करके इस मुकाम पर आए हैं और जानते हैं कि आपातकाल और राष्ट्रवाद का जीवन क्षणिक होता है। जो लोग झूठ, फरेब और सपनों के सौदागर बनकर आंधी की तरह आते हैं, वे तूफान की तरह लहरों के लोकतंत्र में समा जाते हैं।

आज मनु की स्मृतियों को केवल चुन-चुन कर संस्थान प्रतिष्ठान, बुतों और मूर्ति पूजा में इसीलिए बदला जा रहा है कि नई पीढ़ी उनके योगदान और प्रेरणाओं को भूल जाए। रूस, चीन, यूरोप के देश और दो विश्व युद्धों के बाद जन्मे सभी लोकतंत्र आज इसी मूर्ति पूजा में बर्बाद हो रहे हैं। भारत में ये मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा एक महामारी है और हजारों साल से हम इस कर्मकांड को करते-करते गैर बराबरी और हिंसा के जंगल में समाप्त हो रहे हैं। आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र ने लगातार गांधी और अंबेडकर के जीवन योगदान की अवहेलना की है उसी का आज ये नतीजा है कि हम मंदिरों में आस्था का हरी कीर्तन करते-करते एक के बाद एक गुलामी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा लोकतंत्र सिमट रहा है। गांधी के आग्रह और नेहरू, पटेल की सहमति पर ही वे अपने जातीय उत्पीड़न को छोड़कर नए भारत का संविधान निर्माण करने में जुटे थे। आस्था और जातीय गौरव जैसी कोई संकीर्णता अंबेडकर के विचार में नहीं थी। जो लोग आजकल ये कहते हैं कि अंबेडकर के हम ऋणी हैं उन्हें आज ये सोचना चाहिए कि अंबेडकर के निर्वाण को ही उन्होंने आस्था के उपद्रव के दिन में कैसे चुना? कोई हमें बता सकता है कि आज सामाजिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र कैसे बचेगा तथा आजादी, समानता और बंधुत्व को नष्ट करके अकेला हिंदुत्व का राष्ट्रवाद कैसे और कब तक विकास का झूठ सच दोहराएगा? चार दिन की चांदनी में हिंदुत्व के राष्ट्रवाद को अंबेडकर ने कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो हिटलर और गोयबल्स को मरते हुए देख चुके थे। इसीलिए डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक वोट और हर वोट का समान मूल्य पर चल रहे होंगे। परंतु अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभास के जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे नकारना जारी रखते हैं तो हम केवल अपने राजनीति प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके, इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेकेंगे जिसे हम सभी ने परिश्रम से खड़ा किया है।

सिद्ध योगिनी नागेश्वरी माँ मनसा

डॉ. मनीषा शर्मा

ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार नाग कुल की रक्षक माँ मनसा को सिद्धयोगनी प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में वर्णित किया है, राजस्थान में आमेर, पुष्कर, शेखावाटी में माँ की चमत्कारिक प्रतिमा के मंदिर है। हरिद्वार और हिमाचल के मंदिर दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। एक समय जनमेजय का सर्प यज्ञ हो रहा था, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा- जगत् में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, अतः अब जरत्कारू नाम के एक ऋषि होंगे, जरत्कारू ऋषि की पत्नी का नाम भी जरत्कारू ही होगा, वह सर्पराज वासुकि की बहिन होगी, उसके गर्भ से आस्तीक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। तब एलापत्र नाम के एक नाग ने सर्पराज से कहा-हे वासुके ! ठीक है, मेरे विचार से भी आपकी बहिन जरत्कारू का विवाह उस जरत्कारू ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें, उसी समय आप उन्हें अपनी बहिन दे दें। इस बात के थोड़े दिनों बाद ही समुद्र-मन्थन हुआ, जिसमें वासुकि नाग को मथने वाली रस्सी बनाई गई। इसलिए देवताओं ने वासुकि नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही

बात कहलावा दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकि ने सर्पों को जरत्कारू ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उससे कह दिया कि जिस समय जरत्कारू ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय जाकर फिर से वही बात कहलावा दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकि ने सर्पों को जरत्कारू ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उससे कह दिया कि जिस समय जरत्कारू ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय आकर मुझे सूचित करना।

महाभारत के आदि पर्व की कथा के अनुसार जरत्कारू ऋषि की पत्नी जरत्कारू ही बाद में ''मनसा देवी'' के नाम से विख्यात हुई। कथा के अनुसार ऋषि जरत्कारू ने प्रयत्न किया था कि मुझे मेरे नाम वाली कन्या मिल जाएगी और वो भी भिक्षा की तरह, जिसके भरण-पोषण का भार मेरे ऊपर न रहे तो मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर उससे विवाह करूंगा तथा पितरों, देवताओं की इच्छा (मनसा) पूरी करने और स्वयं ऋषि की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वासुकि नाग की बहिन जरत्कारू का नाम सबकी मनसा पूरी करने के कारण ''मनसा देवी'' विख्यात हुआ। 'देवी भागवत महापुराण के अनुसार माँ मनसा देवी के बारह नाम है। मनसा देवी के बारह नामों की चर्चा देवीभागवत में इस प्रकार की गई है-

जरत्कारु जगद गौरी मनसा सिद्धि योगिनी, वैष्णवों की नागभामिनी और शैव नागेश्वरी। जरत्कारु, आस्तिक की प्रिय माता, विषैली बुद्धि, महान ज्ञान से संपन्न, वह दुनिया द्वारा पूजी जाती है। 1. जरत्कारू - जरत्कारू मुनि के समान क्षीण शरीर देखकर श्री कृष्ण ने इसका नाम जरत्कारू रखा। 2. जगद्गौरी:- स्वर्ग लोक, नागलोक ब्रह्मलोक, पृथ्वी लोक तक पूजा हुई तथा सुन्दरी और मनोहर है। 3. मनसा:- यह भगवती कश्यप की कन्या है, मन से क्रीड़ा करने के कारण मनसा देवी के नाम से अधिक विख्यात है, जो मनसा ईश्वर का ध्यान करती है, वह मनसा देवी इसी कारण उस योग से क्रीड़ा करती है। 4. सिद्ध योगिनी:- इसने तीन युग पर्यन्त कठिन तप किया था। शिवजी से सिद्धयोग प्राप्त होने से यह महाज्ञान योगदायक मृत संजीवनी पराविद्या है। 5. वैष्णवीरू विष्णु के प्रति अत्यधिक समर्पित होने के कारण इन्हें वैष्णवी कहा जाता है। 6. नागभामिनी:- नागों के देवता वासुकि नाग की भामिनी (बहन) होने के कारण वह नागभामिनी बन गई। 7. शैवी - शिव की शिष्या होने के कारण उन्हें शैवी कहा जाता है। 8. नागेश्वरी-जनमेजय के यज्ञ में इसी ने नागों की प्राण रक्षा की थी इसीलिए इसका नाम नागेश्वरी भी हुआ। 9. जरत्कारु प्रिया- इन्हें महात्मा जरत्कारु मुनिद्र की प्रिय पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। 10. आस्तिक माता- महाज्ञानी, चारों वेदों की ज्ञाता, तपस्वी आस्तिक ऋषि की सर्वश्रेष्ठ माता हैं। 11. विषहरी:- विष का हरण करने में स्वतन्त्र होने से विषहरी कहलाती है। 12. महाज्ञानयुता:- मनीषी इसे महाज्ञानवती कहते हैं। महाज्ञानवान होने से ये देवी सारे विश्व द्वारा पूजने योग्य है। अतएव इन बारह नामों द्वारा मनसा देवी की पूजा होती है।

जो इन बारह नामों से पूजा करते हैं उनको तथा उनके वंश वालों को सर्पों का भय नहीं रहता। जो इस महा फलदाई श्लोक को पढ़ता है, उसे देखकर सर्प समूह भाग जाते हैं। इस श्लोक को सच्चे मन से दस लाख बार जपने से सिद्धि होती है। जिसको स्तोत्र सिद्धि हो जाए वह विष भी खा जाये तो कोई भय नहीं है। ऐसा पुराणों का कथन है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आज का इतिहास

16 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- भारत में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी।
- पेट्रोग्राड में रूसी सैनिकों का 1917 को विद्रोह।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी ने 1919 में आज ही के दिन उपवास की घोषणा की।
- सोफिया में 1925 में चर्च पर हमला किया गया था जिसमें लगभग 150 लोगों की जान गईं।
- एक सोवियत पनडुब्बी के कारण 1945 में जर्मन रिफ्यूजी शिप डूब गया था, जिसकी वजह से 7000 लोग मर गए थे।
- द्वितीय विश्वयुद्ध में 1945 के दौरान अमेरिकी सेना जर्मनी के नुरेम्बर्ग इलाके में घुस गयी।
- रेड आर्मी ने 1945 में बर्लिन की लड़ाई शुरू की।
- यूरोपीय देश फ्रांस में 1970 में आये बर्फीले तूफान से 70 लोगों की मौत।
- अमेरिका ने 1980 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
- अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने 1992 में इस्तीफा दिया।
- अद्बैलाजीज बोतेफ्लिका 1999 में अल्जीरिया के नये राष्ट्रपति नियुक्त हुए।
- दक्षिण कोरिया में 2002 को एक विमान दुर्घटना में 120 यात्रियों की मौत।
- भारत ने 2004 में रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 में मात दी।
- लंदन में 2008 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ।
- ईरान में 2013 को आये एक भूकंप से 37 लोगों की मौत हो गयी।

16 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति

- तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में 'गद्य ब्रह्मा' के नाम से ख्याति मिली उनका कंदुकूरी वीरेशलिंगम का 1848 में जन्म।
- दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 को हुआ।
- एक भारतीय राजनीतिज्ञ राम नाईक का 1934 में जन्म।
- भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का 1978 में जन्म।

16 अप्रैल को हुए निधन

- 1951 में प्रसिद्ध बांग्ला लेखक अद्वैत मल्लबर्मन का निधन।
- 1961 में प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी रणधीर सिंह का निधन।
- 1966 में भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का निधन।
- 2011 में महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर भवानी सिंह का निधन।

विश्व युद्ध के अनुभवों से समय रहते दुनिया को सबक लेने की जरूरत

पिछले दो विश्व युद्धों के इतिहास से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। दो देशों के बीच शुरू हुआ टकराव कब एक युद्ध में बदल जाए, कब वह दोनों पक्षों के सहयोगी देशों के बीच फैल जाए और विश्व युद्ध की शक्ल ले ले, कहा नहीं जा सकता। विडंबना है कि अतीत के अनुभवों से सबक लेना जरूरी नहीं समझा जाता। अमूमन हर युद्ध में इसी गलती को दोहराया जाता है। अब इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष की आग अन्य देशों की ओर भी फैलती दिखने लगी है। गौरतलब है कि हाल ही में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल की ओर से हमला करने की खबर आई थी। उसमें ईरान के दो जनरलों की मौत हो गई थी। उसके बाद से ईरान ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। मगर अब मामला धमकियों से आगे बढ़ गया लगता है और ईरान ने जिस तेवर में जवाबी कार्रवाई की बात की है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने भी ईरान के हमले की तैयारी को लेकर चेतावनी दी है। भारत और अमेरिका सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे इस समय इजराइल और ईरान जाने से बचें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग अभी ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, वे वहां के भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। ईरान में फिलहाल लगभग चार हजार और इजराइल में साढ़े अठारह हजार भारतीय रहते हैं। मगर ईरान के तेवर तीखे होने के बाद जिस तरह युद्ध का दायरा फैलने की आशंका मंडराने लगी है, उसके मद्देनजर भारत सरकार इन दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की संभावित निकासी के साथ-साथ अचानक पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है।

विशेष आलेख

गरीबी हटाओ का नारा केवल चुनाव में ही क्यों सुनाई पड़ता है?

अशोक भाटिया

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी माहौल गरमाने लगा है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश में गरीबी चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में गरीबी मुद्दा था। 1971 के लोकसभा चुनाव में तो इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा ही दे दिया था। माना जाता है कि यह नारा उनके प्रधान सचिव पीएन हक्सर के दिमाग की उपज थी।अब साल 2024 में जब भारत 18वीं लोकसभा के चुनाव की तैयारी में है, तब भी चुनाव में गरीबी एक मुद्दा है। अंतर यह है कि सत्ताधारी भाजपा इस दावे के साथ इसे मुद्दा बना रही है कि उसके शासन काल में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। विपक्ष तरह-तरह के आंकड़े देकर इस दावे की हवा निकाल रहा है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने राहुल पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की है कि एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छिपा था? पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई। अब इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ऐसे दावे करते हैं और हंसी के पात्र बन जाते हैं। दरअसल साल की शुरुआत में नीति आयोग ने दावा किया था कि नौ साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकल चुके हैं। पिछले दिनों नीति आयोग के सीईओ ने एचसीईएस के आधार पर दावा किया कि भारत की कुल आबादी में गरीबों का अनुपात पांच फीसद से अधिक नहीं है। इन्हीं आंकड़ों का हवाला देकर सरकार गरीबी कम होने के दावे कर रही है। लेकिन, विशेषज्ञ इन आंकड़ों तक पहुंचने के रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं। जिस सर्वे के आधार पर नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि भारत की कुल आबादी में गरीबों का अनुपात पांच फीसद से अधिक नहीं है, उस सर्वे का मकसद यह पता लगाना होता है कि हर माह लोग कितना खर्च कर रहे हैं। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच आयोजित इस एचसीईएस में 8,723 गांवों और 6,115 शहरी क्षेत्रों के 2,61,745 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों से 60 फीसद और शहरी क्षेत्रों से 40 फीसद) को शामिल किया गया था। सर्वे से प्राप्त आंकड़ों को चार भागों में बांटकर देखने से पता चलता है कि कुल आबादी के 50 प्रतिशत का प्रति व्यक्ति खर्च 3,094 रुपये (ग्रामीण) और 4,963 रुपये (शहरी) से अधिक नहीं है। सबसे गरीब पांच प्रतिशत लोग तो 1,373 रुपये (ग्रामीण) और 2,001 रुपये (शहरी) प्रति माह में गुजारा कर रहे हैं। दिन के हिसाब से बांट दें तो यह 45 रुपये (ग्रामीण) और 66 रुपये (शहरी) प्रति दिन हो जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े और मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम नीति आयोग के आंकड़ों को पेश करने के तरीके को दुरुस्त नहीं मनाते। चिदंबरम पांच फीसद वाले दावे पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, 卐अगर यह दावा सच है तो सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो मुफ्त अनाज क्यों बांटती है? चिदंबरम का सवाल यह भी है कि क्या नीति आयोग ने इस बात पर कभी गंभीरता से विमर्श किया कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में महीने का (खाद्य और गैर-खाद्य पर) लगभग 2,112 रुपए या प्रतिदिन 70 रुपए खर्च करते हैं, वे गरीब नहीं हैं? या शहरी इलाकों में जिन लोगों का मासिक खर्च 3,157 रुपए या प्रतिदिन 100 रुपए है, वे गरीब नहीं हैं? अर्थशास्त्री स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर भी सर्वे करने के तरीकों को सही नहीं मानते। वह टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत संदिग्ध डेटा के मामले में एक संपन्न देश है। गबअय्यर इसका बेहतरीन उदाहरण एचसीईएस के डेटा को बताते हैं। वह लिखते हैं कि सर्वे का डेटा और उसका विश्लेषण दोनों त्रुटिपूर्ण है। अय्यर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के हवाले से बताते हैं कि 2011-12 से अब तक मात्र दो प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उनके मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 28.7 से घटकर 27 और शहरी क्षेत्रों में 36.7 से घटकर 31.9 हो गयी है। भल्ला प्रति दिन 70 रुपये कम में जीवन यापन करने वालों को गरीब मानते हैं। अय्यर मानते हैं कि एचसीईएस का डेटा कलेक्ट करने का तरीका ही गलत है क्योंकि सर्वे के दौरान लोगों से यह सवाल तो किया जाता है कि उन्होंने अपने खाने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया, लेकिन अन्य खर्चों जैसे यात्रा आदि को लेकर सवाल नहीं किया जाता है। साथ ही कई बार लोग सही जानकारी भी नहीं देते। ऐसे में एचसीईएस के डेटा से गरीबी या अमीरी का सही तस्वीर नहीं मिल पाती। इस साल की शुरुआत में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि पिछले नौ साल में भारत के 24.8 करोड़ गरीबी (डनसजपकपउमदेपवदंस च्वअमतजल) से बाहर निकल गए हैं। 2013-14 में भारत में गरीबी दर 29.17 थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत हो गई। यानी 17.89 प्रतिशत लोग गरीबी से निकले हैं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
गृहस्थ जीवन में सुख- शांति का अनुभव होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। आय में वृद्धि होगी। उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनी रहेगी। आज आपके हरेक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे।

वृष
आज यात्रा को टालना हित में होगा। पाचन तंत्र संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से किसी को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। आज आप सभी काम दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से पूरा करेंगे।

मिथुन
व्यवसाय करने वालों को सरकार की तरफ से लाभ मिलने और नौकरीपेशा को उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि मिलेगी। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कर्क
विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान के अध्ययन या अन्य मामलों के पीछे धन खर्च या पूंजी निवेश होगी। कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का उत्तम समय है। नौकरी- धंधे में उच्च अधिकारी या भागीदार के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा।

सिंह
आप पूरे दिन शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। परिश्रम की अपेक्षा कम सफलता मिलने से निराशा रह सकती है। नौकरी और व्यापार के संबंध में थोड़ा चिंतित रहेंगे। काम की भागदौड़ में परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे।

कन्या
पिता तथा अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा। मन आनंदित रहेगा। फिर भी स्वभाव में उग्रता का असर आपकी वाणी पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामूली शिकायत रहेगी। सरकार से लाभ होने की संभावना है।

तुला
गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति होगी। अधिकारी और घर में बड़ों से लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। व्यापारियों को उधार दिया पैसा मिलेगा। संतान की प्रगति से मन खुश रहेगा।

वृश्चिक
लंबे प्रवास का आयोजन संभव होगा। विरोधियों से विजय प्राप्त करेंगे। दिन के दौरान आकस्मिक घटनाओं में व्यस्त रहेंगे। आज आप शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। परिणामस्वरूप मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे।

धनु
किसी के साथ गलतफहमी होने के कारण मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक वातावरण खराब हो सकता है। अत्यधिक धन खर्च होगा। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ निर्णय के कारण आज आप कोई भी काम त्वरित निर्णय लेकर पूरा करेंगे।

मकर
शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। उग्र वाणी और अहं के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है।

कुंभ
शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। मित्रों, स्नेहीजनों से लाभ होगा। शरीर में थकान और बेचैनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। मन चिंता से व्याकुल रहेगा। आज यात्रा स्थगित रखने की सलाह दी जाती है। संतान के विषय में चिंता रहेगी।

मीन
कोर्ट-कचहरी का कामों को आज टाल देना हितकर है। आज विविध क्षेत्र में लाभ मिलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात, रमणीय स्थानों पर प्रवास पर्यटन का आयोजन होगा। भाग्य साथ न देता हुआ प्रतीत होगा।

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

मर्यादा लांघती राजनीतिक बयानबाजी

देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों में बयानों की आंधी सी चल रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने आपको आम जनता का हितैषी सिद्ध करने का प्रचार कर रहे हैं। इन बयानों में कहीं कहीं राजनीति की मर्यादा का भी उल्लंघन भी होता दिख रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दल अपने अपने हिसाब से ढोल पीटकर जनता को अपने पाले में लाने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, वह देखने में तो ऐसा ही लगता है कि यह सब बातें अप्रमाणिक सी लगती हैं। अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया है, वह उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन यह भी सही है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष, सत्ता पक्ष पर किसी प्रकार का ठोस आरोप नहीं लगा पा रहा है। जहाँ तक चुनावी चंदे के भ्रष्टाचार की बात है तो इस खेल में सभी दल शामिल हैं। कहने का तात्पर्य है राजनीति में जो सुना जाता है वह होता नहीं है। परदे पर कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। कौन नहीं जानता कि विपक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं। ऐसे में बयान देने से पहले नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर भी देख लेना चाहिए। वर्तमान में एक और बात महत्वपूर्ण यह भी है कि राजनीतिक दल धरातल पर बाहुबल और धनबल के सहारे चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं। जबकि यह सब इतनी सावधानी से किया जाता है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन आम जनता को यह मालूम है कि वास्तविकता क्या है। सारे चुनावों की छिपी हुई हकीकत यही है कि चुनाव में पैसा पानी की तरह प्रवाहित किया जाता है? जो लोग पैसे की भाषा नहीं समझते, उन्हें समझाने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं, यानी बाहुबल का सहारा लिया जाता है। हालांकि इस सत्य को राजनेता इतनी सफाई से करते हैं कि कोई भी संस्था इसे सिद्ध नहीं कर सकती? आज की राजनीति को देखकर सहज़ ही यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक बयान मर्यादा को लांघ रहे हैं। विपक्ष की ओर से आधारहीन तर्क किए जा रहे हैं। कोई लोकतंत्र को बचाने की राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है तो कोई संविधान बचाने का प्रहसन कर रहा है। वर्तमान में भारत की राजनीति में प्रतिद्वंद छिड़ा हुआ है। राजनीति में जिस प्रकार का वाद प्रतिवाद चल रहा है वह या तो मूर्ख बनने की प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर मूर्ख बनाने की। अब आज के हालात में कौन मूर्ख बनता है और कौन बनाता है, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। जैसे ही समय की सीमा पूरी हो जाएगी, इसके पीछे का अर्थ सामने आता चला जाएगा। आज हमारे देश की राजनीति में नेताओं के कई रूप देखने को मिल जाते हैं, यानि जैसी स्थिति होती है नेता लोग अपने को वैसा ही प्रचारित करने लग जाते हैं। इसको और व्याख्या करके कहा जाये तो तर्क संगत ही होगा कि हमारे नेता बहुरूपिया बन जाते हैं और भारत देश की भोली भाली जनता उनके इस नकली रूप को देखकर भ्रमित हो जाती है। देश भर में सारे नेता इस होड़ में आगे दिखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ही जनता के असली हितैषी हैं। नेताओं का यह रूप हमारे देश को किस दिशा में ले जाएगा या ले जा रहा है, पता नहीं।

अमेठी और रायबरेली के बारे में गांधी परिवार क्या सोच रहा है?

राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम बड़ी ही इमोशनल चिट्ठी लिखी थी - और पुराने रिश्तों को कायम रखते हुए आगे भी परिवार के लिए सपोर्ट सिस्टम बने रहने की सोनिया गांधी ने अपील की थी। अपनी चिट्ठी के जरिये रायबरेली को लेकर जो संकेत सोनिया गांधी ने देने की कोशिश की थी,राहुल गांधी ने कभी ऐसे भाव नहीं व्यक्त किये।

- अशोक भाटिया

यदि हम पिछले 2019 के चुनाव पर नज़र फेरे तो तब कांग्रेस की 15 उम्मीदवारों की पहली सूची में अमेठी और रायबरेली शामिल थे। इस बार कांग्रेस ने 15 सूची में 244 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए लेकिन इन दोनों सीटों के नाम सामने नहीं आए। रायबरेली से चुनाव लड़ती रही सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन चुकी है। ऐसे में वे अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी जगह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम कई बार सामने आया, लेकिन पार्टी ने अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अमेठी में 2019 में राहुल गांधी भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए जबकि वायनाड से जीते थे। वायनाड से राहुल के बतौर उम्मीदवार नाम पहली सूची में आ गया, लेकिन अमेठी की घोषणा रोक दी। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ाने का विकल्प खुला हुआ है। कांग्रेस नेता तर्क देते हैं कि अमेठी-रायबरेली में चुनाव 20 मई को है इसलिए अभी फैसले के लिए काफी समय है। दूसरी ओर कांग्रेस वाराणसी, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है जहां अंतिम चरण में एक जून को मतदान है। ऐसे काफी समय होने का पार्टी का तर्क दमदार नजर नहीं आता। कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह डर भी सता रहा है कि दोनों सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तो भाजपा चुनाव में यह मुद्दा बना सकती है वह डर गए हैं। ऐसे में पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और सोच विचार के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड के साथ-साथ अमेठी सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के आला नेता का कहना है कि अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस सांसद का मन बदल रहा है। पहले वायनाड छोड़ू तो अमेठी नाराज और अमेठी छोड़ू तो वायनाड नाराज के चलते राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हाल में जब राहुल पर हार के डर से भागने की तोहमत बीजेपी ने लगाई, तो कांग्रेस नेता ने भी अपने फैसले पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी बैठक में राहुल गांधी ने कहा, 'हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी व्यक्तिगत वजहें थीं, लेकिन डर के भागने जैसी बात की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया। ये संदेश गलत है, इसको नेस्तनाबूद करना होगा। कांग्रेस के भीतर भी नेता अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। भले ही वे मीडिया के सूत्र बनकर कुछ न कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन वे भी हवा में ही कयास लगा रहे हैं - लेकिन अमेठी पर फैसले में वायनाड फैक्टर की एक खास भूमिका जरूर लगती है। रही बात रायबरेली लोकसभा सीट की तो उसे सोनिया गांधी की चिट्ठी से समझने की थोड़ी कोशिश की जा सकती है। राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम बड़ी ही इमोशनल चिट्ठी लिखी थी - और पुराने रिश्तों को कायम रखते हुए आगे भी परिवार के लिए सपोर्ट सिस्टम बने रहने की सोनिया गांधी ने अपील की थी। अपनी चिट्ठी के जरिये रायबरेली को लेकर जो संकेत सोनिया गांधी ने देने की कोशिश की थी, राहुल गांधी ने कभी ऐसे भाव नहीं व्यक्त किये। हां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो अमेठी और रायबरेली गये जरूर थे - लेकिन उस दौरे को लेकर वहां के कांग्रेस नेताओं की नाराजगी ही सामने आई थी। स्थानीय कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस नेता के स्वागत के लिए जगह जगह जरूरी इंतजाम किये गये थे लेकिन राहुल गांधी किसी भी जगह अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। राहुल गांधी की नाराजगी स्वाभाविक लगती है। हैं तो वो भी इंसान ही, नेता और राजनेता होने से क्या होता है? वैसे भी अमेठी के लोगों ने जो सलूक राहुल गांधी के साथ किया है, रायबरेली के लोगों ने तो सोनिया गांधी के साथ नहीं किया। 2019 में भी रायबरेली के लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे लेकिन अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी समझ से अमेठी की ही तरह रायबरेली में भी तो कभी गांधी परिवार के करीबी रहे कांग्रेस नेता को सोनिया गांधी के खिलाफ उतार दिया था। हां, दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी में बड़ा फर्क तो है ही।

बहरहाल, सीनियर कांग्रेस नेता एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली को लेकर जो संकेत दिया है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे वक्त जब दोनों सीटों पर आम लोगों के साथ साथ बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हों। क्योंकि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ने भी अमेठी और रायबरेली में से किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है - वैसे भी अमेठी और रायबरेली में वोटिंग वायनाड के बाद ही होनी है। गांधी परिवार के लिए ये भी बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। एक इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों कांग्रेस उम्मीदावार को लेकर सवाल पूछा गया था। एंटनी ने साफ साफ तो कुछ नहीं बताया लेकिन काफी हद तक तस्वीर साफ भी कर दी - कम से कम ये तो साफ कर ही दिया है कि गांधी परिवार ने यूपी छोड़ देने का फैसला नहीं किया है। वैसे भी यूपी छोड़ देने के मतलब तो उत्तर भारत ही छोड़ देने जैसा समझा जाएगा। एके एंटनी का कहना है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर कयास लगाये जाने की जरूरत नहीं है। एके एंटनी कहते हैं, आप अमेठी और रायबरेली लोक सभा सीटों पर फैसले का इंतजार कीजिये। और इंटरव्यू में एके एंटनी ने जो सबसे खास बात कही है, वो है - 'नेहरू परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में होगा।' एके एंटनी का ये जवाब एक चीज तो स्पष्ट कर ही रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से नाता तोड़ लिये जाने की बातें पूरी तरह बकवास हैं - लेकिन दायरा बढ़ा कर एके एंटनी ने नये नये कयासों को दावत दे डाली है। कांग्रेस नेता ने सिर्फ गांधी परिवार का नाम न लेकर नेहरू परिवार की बात कही है, यानी गांधी परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार हो सकता है - हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर एके एंटनी ने फुल स्टॉप लगा दिया है। इंटरव्यू में एके एंटनी से अमेठी और रायबरेली सीटों को लेकर तो सवाल पूछा ही गया, अमेठी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाये जाने की संभावनाओं पर भी पूछ लिया गया। जवाब तो एके एंटनी ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों को लेकर भी दिये, लेकिन सबसे ज्यादा स्पष्ट रिस्पॉन्स उनका रॉबर्ट वाड्रा को लेकर ही लगा। असल में हाल ही में एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने एक साथ कई दावे किये थे। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि चाहते तो वो यही हैं कि पहले प्रियंका गांधी ही संसद पहुंचें और उसके बाद उनका नंबर आये। अमेठी के लोगों का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि वे चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ने का फैसला करूं तो अमेठी से ही - और लगे हाथ, रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी दावा कर डाला था कि कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी दलों से भी उनके पास टिकट के ऑफर हैं। कांग्रेस नेता ने रॉबर्ट वाड्रा के नाम को तो खारिज कर दिया है लेकिन जो बात कही है, उसमें तो राहुल और प्रियंका के साथ साथ वरुण गांधी भी शामिल हो जाते हैं। अभी तक ऐसे कोई संकेत तो नहीं मिले हैं कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस ने नो-एंट्री वाला बोर्ड हटा लिया है लेकिन पीलीभीत से बीजेपी ने उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट देकर ऐसी संभावनाओं के द्वार तो खोल ही दिये हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से चुनाव लड़ना करीब करीब पक्का है लेकिन जो स्थिति है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में राहुल गांधी की तुलना में बीजेपी की स्मृति ईरानी को ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती हैं और जिस तरह से राहुल गांधी को वारिस के तौर पर पेश किया जाता रहा है, रायबरेली का मैदान उनका ज्यादा सूट करता है। अमेठी को लेकर राहुल गांधी के अलावा दो नाम चर्चा में हैं। एक नाम है एमएलसी रह चुके कांग्रेस नेता दीपक सिंह का - और दूसरा नाम है, बीजेपी सांसद वरुण गांधी का। दीपक सिंह को सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी से बड़े ही सख्त लहजे में दो-दो हाथ करते देखा जा सकता है - और वरुण गांधी के बारे में यहां तक बातें हो रही हैं कि वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी सीट तो वैसे भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस के ही पास है। वरुण गांधी को लेकर ऐसी चर्चाओं को एक ही बात कमजोर करती है वो है मेनका गांधी का ताज़ा बयान कि 'हम ऐसे लोग नहीं हैं।'

भगवान भास्कर करेंगे राम का सूर्यतिलक, ऐतिहासिक होगा अवसर

- पंकज कुमार मिश्रा

17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के पावन अवसर पर, दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से अयोध्या मंदिर में प्रथम बार भगवान राम का राजतिलक होगा। हिंदू नववर्ष 'विक्रम संवत 2081' की शुरुआत के साथ रामनवमी पर्व पर अयोध्या यह ऐतिहासिक आयोजन करने जा रहा जिसकी योजना पर काम चल रहा है और ट्रायल पूर्ण हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर सूर्य की किरणें लगभग चार मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी। इसको लेकर चल रहा ट्रायल सफल रहा।वैज्ञानिकों ने जिस तरह से प्रयास किया है, वह बहुत सराहनीय और अद्भुत है। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का विश्व साक्षी बना अब विश्व भारतीय वैज्ञानिकों के अध्यात्म का अवलोकन करेगा, राम मंदिर में विज्ञान के चमत्कार को रामनवमी के अवसर पर लाईव देखेगा। कुल पांच मिनट भगवान भास्कर की किरणों से हनुमत आराध्य का तिलक होता दिखेगा। यह सूर्य तिलक 75 मिमी का होगा। ट्रस्ट के अनुसार सूर्य तिलक के इस प्रोजेक्ट को रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक संभालेंगे। वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए मिरर, लेंस व पीतल का प्रयोग करेंगे। इसको बिना बिजली व बैटरी की मदद से किया जाएगा। हर साल रामनवमी के अवसर पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआइ) रुड़की के विज्ञानियों की टीम ने सूर्य तिलक और पाइपिंग के डिजाइन पर काम किया है।

सूर्य तिलक प्रोजेक्ट के अंतर्गत राम मंदिर की दूसरी मंजिल से लेकर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा तक पाइप और आप्टो-मैकेनिकल सिस्टम (लेंस, मिरर, रिफ्लेक्टर आदि) से सूर्य की किरणों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उच्च गुणवत्ता के चार शीशे व चार लेंस का प्रयोग किया गया है। दो शीशे मंदिर की दूसरी मंजिल और दो निचले तल पर लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल पर लगाए गए शीशों के माध्यम से सूर्य की किरणें लेंस से टकराते हुए अष्टधातु के पाइप से गुजरेंगी। इसके बाद सूर्य की किरणें पाइप से होते हुए निचले तल पर लगे शीशे और लेंस से टकराकर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा के मस्तक पर तिलक के रूप में पहुंचेंगी। दूसरी मंजिल से लेकर निचले तल तक लगाए गए पाइप की लंबाई आठ से नौ मीटर तक होगी। इसके लिए गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है यानी शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया गया है। ताकि हर साल रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों से तिलक हो सके। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट पर सीबीआरआइ रुड़की के विज्ञानी डा. एसके पाणिग्रही और उनकी टीम ने कार्य किया है। इस प्रोजेक्ट में जहां सीबीआरआइ रुड़की ने तिलक और पाइपिंग के डिजाइन पर काम किया है, वहीं कंसल्टेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आइआइए) बैंगलौर और फेब्रिकेशन आप्टिका बैंगलौर ने किया है। गर्भगृह में स्थापित श्रीराम की प्रतिमा का 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से तिलक होगा। दूसरी मंजिल से लेकर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा तक पाइपिंग और आप्टो-मैकेनिकल सिस्टम से सूर्य की किरणों को पहुंचाया जाएगा।अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर दोपहर 12:00 बजे सूर्य की किरण भगवान राम लला का तिलक करेंगी, इसको लेकर चल रहा प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा। वैज्ञानिकों ने दर्पण के जरिये सूर्य की किरण को भगवान के मस्तक पर पहुंचा दिया है. सूर्य की किरणें लगभग चार मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी. ठीक रामनवमी के दिन दोपहर 12:00 बजे इसे भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर तिलक करते हुए देखा जा सकेगा। पूर्वाभ्यास हुआ जो कि प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा। वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान राम लला का तिलक सूर्य देव इस बार ही रामनवमी के मौके पर करेंगे। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मंदिर पूर्ण होने के बाद ही यह प्रयोग सफल हो सकेगा लेकिन वैज्ञानिकों ने सूर्य की किरण को भगवान के मस्तिष्क तक सफल रूप से पहुंचाया।

(राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार, जौनपुर, यूपी)

कविता

नमोस्तुते परमेश्वरी

...अमेय विक्रमा क्रूरा हो
असीम पराक्रम वाली मां
दैत्य दलन तुम करती हो
लक्ष्मी हो तुम विमला हो
विद्या बुद्धि दायनी मां
कालरात्रि नारायणी हो
परमेश्वरी कात्यायनी प्रतयक्षा
ब्रहमवादिनीमहादेवी शोकविनाशिनी हो
तरयी भगवती परमेश्वरी
दुर्ग पारा तुम सारा हो

धूम्रा कृष्णा सर्व कारिणी
वामेशवरी सुरेश्वरी हो
विधादायनी सरस्वती
वैभव प्रदायिनी लक्ष्मी
शक्ति दायनी
मां काली
सर्वेश्वरी माहेश्वरी हो
नमोस्तुते परमेश्वरी
जग के संकट हरती हो

अनामिका गुप्ता

प्रधानमंत्री मोदी इस बार 370 और 400 पार का नारा शुरू से लेकर चले हैं। अनेक एजेंसियों और न्यूज चैनलों के सर्वे भी ऐसे ही आए हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए का 350 से अधिक जाना एकदम सुनिश्चित है। विश्लेषणकर्ता प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों के आंध्र प्रदेश,तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में बीजेपी उल्लेखनीय बढ़त लेने वाली है। जीत के सपने देखने में कोई हर्ज नहीं,लोकतंत्र में सारी कवायद सत्ता के लिए ही तो है।

विदेशी निर्भरता बनाम कांग्रेस

- राज सक्सेना

विगत माह राहुल गांधी ने एक सर्वे के सन्दर्भ से घोषणा की थी कि बीजेपी एनडीए को 2024 के चुनाव में 180 सीट मिल रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और प्रियांक खड़गे ने बैंगलुरु में राहुल के हवाले से यही आंकड़ा जारी करने में जरा सी देर भी नहीं की। राहुल ने इस सर्वे का आधार आरएसएस द्वारा कराए गए देशव्यापी सर्वे को बताया था। इसका सीधा अर्थ है कि सर्वे उन्होंने नहीं आरएसएस ने कराया था जिस पर राहुल को अटूट विश्वास है?।

इसके बाद संघ ने बाकायदा स्पष्टीकरण दिया था कि वह कभी भी चुनावी सर्वे नहीं कराता। इस बार भी उसने कोई सर्वे नहीं कराया है। ऐसे में राहुल को इस गोपनीय सर्वे की जानकारी कहां से मिली, वे ही जानें। वैसे तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। सबको अधिकार है कि अपनी जीत के दावे कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए। आखिर ढेरों दलों को मिलाकर इंडी गठबंधन जीतने और खासकर मोदी को सबक सिखाने के लिए ही तो बनाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो बता भी दिया है कि गठबंधन की सरकार बनते ही शाह, मोदी के साथ क्या क्या करना है। राहुल गांधी के चुनावी सर्वे ने सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार 370 और 400 पार का नारा शुरू से लेकर चले हैं। अनेक एजेंसियों और न्यूज चैनलों के सर्वे भी ऐसे ही आए हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए का 350 से अधिक जाना एकदम सुनिश्चित है। विश्लेषणकर्ता प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा में बीजेपी उल्लेखनीय बढ़त लेने वाली है। जीत के सपने देखने में कोई हर्ज नहीं, लोकतंत्र में सारी कवायद सत्ता के लिए ही तो है। यह और बात है कि कोई महीन सपने और कोई हसीन सपने देखता है। राजनीति में सब राजनीति करने आते हैं। सत्ता सबको चाहिए और कांग्रेस का तो सत्ता पर जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बनाने के लिए कैंब्रिज एनालिटिका के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी एक व्यक्ति सैम पित्रोदा पूर्व आइएएस को दे रखी है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के भी बेहद करीबी हुआ करते थे। देश की आंतरिक रणनीति के लिए जयराम रमेश प्रभारी हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका लेने वाली ब्रिटिश प्रोपेगेंडा एजेंसी कैंब्रिज एनालिटिका पूरी तरह सक्रिय है और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा दरअसल यही एजेंसी तय कर रही है। एजेंसी भारत में भी वही कर रही है जिसके लिए वो दुनिया भर में बदनाम रही है। ये काम है लोगों के पर्सनल डेटा चोरी करने का और फिर उन्हें ऐसी जानकारियां भेजना जिससे उनकी सोच को तात्कालिक रूप से प्रभावित किया जा सके। कुछ समय पहले कैंब्रिज एनालिटिका की एक रिपोर्ट लीक हुयी थी जिसमें जिक्र था कि अगर देश में बड़े पैमाने पर जातीय दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाए, दलितों पर अत्याचार की खबरें उड़ाई जाएं तो इससे कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा। इससे हिंदुत्व का मुद्दा फुस्स हो जायेगा। पिछले करीब एक वर्ष से कैंब्रिज एनालिटिका बिना किसी शोर शराबे के इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। जातीय नफरत फैलाने वाली उसकी रणनीति ने कांग्रेस को शुरुआती फायदा जरूर दिया लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर मामलों की सच्चाई सामने आ गई। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले गुजरात में घुड़सवारी करने पर एक दलित की हत्या की खबर कैंब्रिज एनालिटिका ने ही अखबारों और चैनलों के जरिए फैलाई थी लेकिन 2-3 दिन में ही यह खबर सामने आ गई कि ये छेड़खानी का मामला था और हत्या के आरोप में गिरफ्तार लोग उसकी ही जाति के हैं। लिहाजा समय के साथ ऐसी खबरों की विश्वसनीयता कम होती गई। जातीय नफरत पैदा करने के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकोर और चंद्रशेखर रावण जैसे जितने भी नेता पैदा किए, उन सबकी सच्चाई धीरे धीरे जनता के सामने आ चुकी है।

इसके अतिरिक्त कैंब्रिज एनालिटिका फिलहाल दो मुख्य मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी के मुद्दे पैदा करना और दूसरा, राहुल गांधी की छवि में सुधार करना। जहां तक छवि सुधारने की बात है वह तो फिर भी ठीक है लेकिन सरकार के खिलाफ नाराजगी के मुद्दे पैदा करने में कैंब्रिज एनालिटिका की महारत मानी जाती है। इसमें उसका सबसे खास औजार बनता है सोशल मीडिया और मुख्य मीडिया। इन दोनों की मदद से पिछले कुछ दिनों में यह माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, भारत पाकिस्तान और चीन के मुकाबले हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है, ऐसे माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जनता की परेशानियों के लिए उदासीन है। ये सब वे मुद्दे हैं जिनका सन्दर्भ कैंब्रिज एनालिटिका की लीक हुई रिपोर्ट में भी था। ज्यादातर झूठी खबरों और फर्जी विश्लेषणों के जरिए इन सभी को हवा देने की भरपूर कोशिश की गई है लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। समस्याएं हर देश में होती हैं, लेकिन फिलहाल कोई समस्या इतनी भी नहीं है कि लोग सड़कों पर उतर आएं। जब सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ खुलकर बोल नहीं सकी। लिहाजा इस मुद्दे पर भी दलितों को शक पैदा करने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर रावण जैसे तत्वों को दी गई। इसी तरह से पिछले दिनों बेरोजगारी के फर्जी आंकड़े मीडिया में जारी किए जाने के मामले में भी कैंब्रिज एनालिटिका का ही हाथ था लेकिन जब आप कांग्रेस नेताओं के भाषणों को सुनेंगे, या कांग्रेस के लिए काम कर रहे मीडिया संस्थानों की खबरों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कैंब्रिज एनालिटिका ने ही कांग्रेस नेतृत्व को सुझाव दिया था कि महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना लाभप्रद होगा लेकिन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के चलते कांग्रेस इसमें अब तक कुछ खास कामयाब नहीं हो सकी है। एजेंसी के इस सुझाव का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस हाईकमान शुरू से ही इतने दबाव में आ गया कि हर जगह सहयोगी पार्टियों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब उसका जोर उम्मीदवार उतारने में तालमेल बिठाने और नतीजे आने के बाद की सौदेबाजी पर टिका है। अगर राहुल गांधी कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ और इलाके में भ्रष्टाचार से सड़क बनी है तो जनता तुरन्त समझ जाती है कि वे झूठ बोल रहे हैं।

यही बात उज्जवला, बिजली और मकान देने की स्कीमों पर भी लागू होती है। फिलहाल की स्थिति को देखकर यही लगता है कि अमेरिका से यूरोप तक अपनी कुटिल नीतियों से कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली कैंब्रिज एनालिटिका भारत में लाचार दिख रही है। पहली बार उसे राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिसको लोग भरोसे के लायक नहीं मानते। आधी से ज्यादा आबादी के लिए राहुल गांधी की छवि हास्यास्पद, झूठ बोलने वाले और फर्जी आरोप लगाने वाले नेता की हो चुकी है। उधर जयराम रमेश प्रवक्ताओं के माध्यम से और राहुल गांधी को रटाये गये भाषणों के माध्यम से उनकी छवि को और अधिक खराब करते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की छवि का भगवान ही मालिक है।

विश्व हीमोफिलिया दिवस - लगातार खून बहे तो हो जाएं सावधान

- बाल मुकुन्द ओझा

विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा हर साल 17 अप्रैल को हीमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सभी के लिए समान पहुंच = सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना रखी गई है। दुनियाभर में तरह तरह की बीमारियां है जिनसे निजात पाने के लिए वैश्विक संगठन अपने स्तर पर प्रयासरत है। बीमारियां है तो उसका इलाज भी है। मगर जागरूकता के आभाव में ये रोग तेजी से पनपते है। ऐसी ही एक बीमारी हीमोफीलिया है जिसके बारे में लोग कम ही जानते है। आश्चर्य की बात है इस बीमारी में भारत अव्वल है। विश्व हीमोफिलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया द्वारा की गई थी। इस दिन को दुनिया भर के रोगी समूहों द्वारा 1989 से देखा गया है। विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया के संस्थापक फ्रैंक नाबेल की जयंती को सम्मानित करने के लिए तारीख का चयन किया गया था। विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया के मुताबिक हीमोफिलिया एक रक्त विकार है जिसमें रक्त ठीक से नहीं जमता है। इसके कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसमें फैक्टर की विशेषता यह है कि यह बहते हुए रक्त के थक्के को जमाकर उसका बहना रोकता है। जागरूकता की कमी की वजह से कई लोग इस समस्या से अनजान रहते हैं। यह दिवस हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवंशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बढ़ी हुई जागरूकता उन लाखों लोगों की देखभाल के लिए बेहतर निदान और पहुंच बढ़ाएगी जो बिना इलाज के रहते हैं। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में चोट लगने पर अधिक खून बहता है। यह बीमारी कभी-कभी जानलेवा हो जाती है। इसमें खून का बहना शुरू हो जाए, तो बंद नहीं होता। कोई हादसा होने पर मरीज की जान बचानी मुश्किल हो जाती है। शरीर में नीले निशान बन जाते हैं। जोड़ों में सूजन आना और रक्तस्राव होना। अचानक कमजोरी आना और चलने में तकलीफ होना। नाक से अचानक खून बहना भी इसके ही लक्षण है। यदि यह रक्तस्राव रोगी की आंतों में अथवा दिमाग के किसी हिस्से में शुरू हो जाये तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसका इलाज जल्द से जल्द होना अति आवश्यक है। कई बार इस बीमारी की वजह से लीवर, किडनी, मसल्स जैसे इंटरनल अंगों में बिना किसी कारण रक्तस्राव होने लगता है।

इस बीमारी से महिलाओं की तुलना में पुरुषों के प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। यह रोग 'हीमोफीलिया ए' तथा 'हीमोफीलिया बी' दो प्रकार का होता है। आनुवंशिक की स्थिति है, जो कि चोट या सर्जरी के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव और या चोट के बाद या बिना चोट के बाद जोड़ों में दर्दनाक सूजन का कारण है। विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के मुताबिक आनुवंशिक का मतलब है, कि यह रोग जींस के माध्यम से माता-पिता से बच्चों में पारित होता है। हीमोफिलिया रोग के वाहक एक्स गुणसूत्र में पाए जाते है। एक शोध के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत भारतीय इस बीमारी की चपेट हैं, जिसमें ज्यादातर संख्या पुरूषों की है। हीमोफीलिया के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है जहां ऐसे 2 लाख केस देखने को मिलेगें जिसका सबसे मुख्य कारण लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी है। देश में हीमोफीलिया से ग्रस्त केवल 20,000 मरीज रजिस्टर हैं जबकि इस आनुवंशिक बीमारी से कम से कम दो लाख लोग पीड़ित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इससे बचाव किया जा सकता है। डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन फूड को शामिल करें। एस्परिन या नॉन स्टेरॉयड दवाओं से परहेज करें। साथ ही हेपेटाइटिस बी का वैक्सिनेशन जरूर लगवाएं। अपनी रूटीन में योग व प्राणायाम को जरूर शामिल करें, जिससे हड्डियां एवं मांसपेशियां मजबूत हो। अगर बच्चे के जन्म से ही इस बीमारी का पता चल जाए तो उसका खास-ख्याल रखें। हीमोफिलिया को शाही रोग कहा जाता है। हीमोफिलिया जीन रूस (स्पेन, जो 1837 में इंग्लैंड की रानी बन गया था) से रूस, स्पेन और जर्मनी के शासक परिवारों को प्रेषित किया गया था। क्वीन विक्टोरिया में हीमोफिलिया के लिए जीन सहज परिवर्तन के कारण हुआ था। हीमोफिलिया अनुसंधान 1900 के आसपास शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया कि मानव रक्त को समूहों या प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इस खोज ने रक्त संक्रमण को और अधिक सफल बना दिया। 1930 में वैज्ञानिकों ने इसके प्रमुख भागों, प्लाज्मा और लाल कोशिकाओं में रक्त को अलग करना सीखा। 1960 के दशक में डॉ जुडिथ ग्राहम पूल ने क्रायोप्रिसेपिट्रेट प्रक्रिया की खोज की, जो हेमोफिलिया ब्लड्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 16 अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

ईरान की दृढ़ता

ईरान की ओर से शनिवार देर रात इस्राइल पर किये गये ड्रोन और मिसाइल हमलों से पश्चिमी एशिया में एक नया शक्ति समीकरण उभरने के संकेत मिल रहे हैं। एक अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इस्राइली हमले के बाद तेहरान ने तेल अवीव पर हमला करने की घोषणा कर दी थी। हांलाकि अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ईरान पर बदले की कार्रवाई करने से दूर रहने का काफी दवाब बनाया था। लेकिन ईरान का नेतृत्व हमला करके राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने साफ तौर पर कहा है कि इस्राइल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब है और ईरान ने अपने आत्म रक्षा के अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद इस मामले को खत्म समझा जाये। लेकिन अगर इस्राइल की ओर से अब कोई हमला होता है तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यह संघर्ष ईरान और इस्राइल के बीच का है और

अमेरिका को इससे दूर रहना चाहिए। जाहिर है ईरान के नेतृत्व का यह रुख बताता है कि वह पश्चिमी एशिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबावों का कड़ा प्रतिरोध करेगा ईरान की इस दृढ़ता से इस क्षेत्र में उसकी नयी साख बनी है। ईरान और इस्राइल संघर्ष के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ जिसमें रूस खुलकर ईरान के पक्ष में आ गया है और चीन की भी तेहरान के साथ सहानुभूति है। गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी मुस्लिम देश ने ईरान का समर्थन नहीं किया है। लेकिन सुरक्षा परिषद में इस्राइल के प्रधान प्रतिनिधि ने विभाजनकारी बयान देते हुए कहा है कि ईरान शिया वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सीरिया, इराक, लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही शिया समुदाय के हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हमास सुन्नी है और हिजबुल्ला तथा हूती जैसे संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में पिछले छह महीनों से इस्राइल द्वारा नरसंहार जारी हैं जिसके कारण पश्चिमी एशिया का पूरा क्षेत्र अशांत बना हुआ है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान और इस्राइल संघर्ष को और बढ़ाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन ने संकेत दिया है कि अगर इस्राइल ईरान के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। भारत ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की है। उसने यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूसी हमले की निंदा नहीं की थी। इसी तरह ईरानी हमले की भी निंदा नहीं की है। फिलहाल भारत की प्राथमिकता ईरान के कब्जे वाले जहाज से 17 भारतीयों की रिहाई कराने की है।

उम्मीदों की घोषणाएं

लोक सभा चुनाव के लिए भारतीय जनात पार्टी (भाजपा) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे वे 'संकल्प पत्र' कहते हैं। यह युवाओं, महिलाओं, किसानों व गरीबों पर केंद्रित है। संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस निवेश से लेकर नौकरी तक का है। मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी। पांच लाख तक मुप्त इलाज जारी के रहने के साथ ही इसके दायरे में अब ट्रांसजेंडर भी आएंगे। पाइप के जरिए घर-घर गैस पहुंचाई जाएगी। तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने व महिलाओं को लखपति दीद बनाने की भी बात दोहराई। उन्होंने का जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मोदी पूजता है। गरीबों को लूटने वाले जेल जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चालू रहने की बात भी

उन्होंने की। विपक्ष ने इसे भाजपा का केंद्र से विदाई का घोषणापत्र बताया। एक राष्ट्र-एक चुनाव समान नागरिक संहिता लाने जैसे मुद्दों को दोहराने के साथ ही भाजपा ने तीन तलाक, अनुच्छेद 370 हटाने व राम मंदिर बना मर अपना वायदा निभाने की गारंटी देने का प्रयास भी किया है। घोषणा पत्र की अमूमन बातें प्रधानमंत्री अपने भाषणों में पहले ही करते रहे हैं। इसलिए इसमें कुछ नया तो नहीं कहा जा सकता। मुफ्त योजनाओं के जारी रखने की बात से जनता को यह आश्वासन जरूर मिल जाता है कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी इन्हें बंद नहीं कर देगी। कांग्रेस अपने घोषणा को न्याय पत्र का नाम देकर इसी रास्ते पर नजर आ रही है। पार्टी ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, गरीब लड़कियों को आर्थिक मदद, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, युवा-नारी-किसान-श्रमिक-आर्थिक व पर्यावरणीय न्याय के बूते सभी को समेटने के प्रयास किया है। यह सच है कि मतदाता को लुभाने वाले ये घोषणा पत्र कुछ तक प्रभावी होते हैं। मगर देश में इस वक्त युवा मतदाताओं की बढती दर ने राजनीतिक दलों को संकट में ला खड़ा किया है। इस नए मतदाता को प्रभावित करना उतना आसान भी नहीं है। जिन्हें शिक्षा, रोजगार व बेहतर भविष्य की आशाएं हैं। काफी हद तक वे मुफ्त योजनाओं व बड़े-बड़े वायदों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। मगर उनके भीतर अपने बेहतर भविष्य व सुकून भरे जीवन को लेकर आश्वस्त रहने के सवाल भी हैं। राजनीतिक पार्टियां घोषणाएं कितनी भी कर लें मगर सच तो यह है कि मतदाता को प्रभावित कर पाना आसान भी नहीं है। इनका भरोसा जीतना वाकई दुष्कर कार्य है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

कुल्फी की जगह ऑमलेट

रेहड़ी पर ठुमरी प्रसाद मिले, आज कुल्फी की रेहड़ी थी। ठुमरी प्रसाद सर्दी में अंडा आमलेट की रेहड़ी लगाते हैं। मैंने पूछा-भाई आमलेट से कुल्फी पर आ लिये।

ठुमरी प्रसाद ने कहा-धंधा है जी मौसम के हिसाब से बदलना पड़ता है।

उधर कांग्रेस के जांबाज भाजपा के खिलाफ आग उगल प्रवक्ता भाजपा में आ गए, मैंने उनसे यह ना पूछा कि यह क्या किया। क्या पता उनका जवाब वही होता, जो ठुमरी प्रसाद का है-धंधा है मौसम के हिसाब से बदलना होता है। मौसम ना भी बदले, तो भी कई नेता धंधे बदल लेते हैं। क्योंकि कुछ लगता है कि उनका सैकुलरिज्म का मौसम होता है, राष्ट्रवाद का मौसम होता है। मौसम के हिसाब से धंधा बदलने वाले चतुर होते हैं। चतुर ही कामयाब होते हैं। गंगा जब बह रही हो, तो हाथ ना धोना बेवकूफी माना जाएगा। गंगा बह रही है, उधर वाले इधर आ लिये हैं। पॉलिटिक्स बहुत टेढ़ा धंधा है। जिनको लोगों को पार्टनर मान कर चलो, ऐन टाइम पर रेहड़ी से भगा देते हैं। पश्चिम बंगाल में यही हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी को कांग्रेस वाले अपना पार्टनर मान कर चल रहे थे, फिर कांग्रेस वालों को भगा दिया गया। सारी जगह ममता बनर्जी ने खुद घेर ली। अब कांग्रेस की आफत यह है कि बंगाल में जाएं तो कहां जाएं। पश्चिम बंगाल में कहीं भी जाएं, ममता बनर्जी पीछे आ जाती हैं। कांग्रेस पॉलिटिक्स के धंधे की पुरानी कारोबारी पार्टी है। पर साहबो, धंधे में क्या नया और क्या पुराना। जिसका जहां दांव लग जाए, वहीं वो अपनी मनमानी कर गुजरता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को टरका दिया एक भी सीट ना दी, पर दिल्ली में कुछ सीटें कांग्रेस से झटक लीं। कांग्रेस की हालत उस पुराने बड़े कारोबारी जैसी हो गई है, जिसके पुराने मुनीम, इंप्लाई ही उससे मोल-तोल कर रहे हैं। कांग्रेस होना बहुत मुश्किल है। कल के दुकानदार ऐसे बरताव कर रहे हैं कांग्रेस के साथ कि पुराने कारोबारियों में दहशत है। राजनीति के धंधे के नए स्टार्टअप पुराने कारोबारियों को डरा रहे हैं। वही कारोबारी कामयाब रहेगा, जो मौसम के हिसाब से धंधा बदल सके। जो धंधा ना बदल सके, वह चौपट हो जाता है।

अभी साफ नहीं तस्वीर

सामयिक

अवधेश कुमार

इस समय लोक सभा चुनाव को लेकर कई तरह के मत हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे प्रबल मत यह है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपने सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार में लौट रही है। कुछ लोग प्रधानमंत्री के 370 भाजपा के और सहयोगी दलों के साथ 400 सीटें मिलने तक की भी भविष्यवाणी करने लगे हैं। दूसरी ओर, विपक्ष इसे खारिज करते हुए कहता है कि भाजपा चुनाव हार रही है और वह 200 सीटों से नीचे चली पाएगी।

विपक्ष भाजपा की आलोचना करती है, नरेन्द्र मोदी पर सीधे प्रहार भी करती है, पर अपने समर्थकों और भाजपा विरोधियों के अंदर भी विश्वास नहीं दिला पाती कि वाकई वह भाजपा से सत्ता छीनने की स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। आईएनडीआईए गठबंधन (इंडिया) की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से नेताओं के छोड़कर जाने का कायम सिलसिला इस बात का प्रमाण है कि पार्टी के अंदर कैसी निराशा और हताशा है। तो फिर इस चुनाव का सच क्या हो सकता है? आखिर 4 जून का परिणाम क्या तस्वीर पेश कर सकता है? इस चुनाव की एक विडंबना और है। भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक वर्ग स्वयं निराशाजनक बातें करता है।

व्यक्तिगत स्तर पर मेरी ऐसे अनेक लोगों से बातें होती हैं, जो चुनाव में जमीन पर हैं या वहां होकर लौट रहे हैं। इनमें ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है जिनमें उत्साह या आशावाद का भाव न के बराबर मिलता है। वे बताते हैं कि जैसी दिल्ली में या बाहर हवा दिखती है धरातल पर वैसी स्थिति नहीं है। जब उनसे प्रश्न करिए कि धरातल की स्थिति क्या है तो सबके उत्तर में कुछ सामान बातें समाहित होती हैं, गलत उम्मीदवार के कारण लोगों के अंदर गुस्सा या निराशा है, गठबंधन को सीट देने के कारण अपने लोगों के अंदर निराशा है, गठबंधन ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनका बचाव करना या जिनके लिए काम करना भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कठिन हो गया है आदि। कुछ लोग अनेक क्षेत्रों में जातीय समीकरण की समस्या का उल्लेख भी करते हैं। एक समूह यह कहता है कि आम कार्यकर्ताओं और नेताओं की सरकार में उपेक्षा हुई है, उनके काम नहीं हुए हैं, उनको महत्त्व नहीं मिला है और अब लोगों का धैर्य चूक रहा है। यहां तक कि जिस तरह के लोगों को पुरस्कार, पद, प्रतिष्ठा या टिकट दिया गया है उनसे भी लोग असहमति व्यक्त करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ विपक्ष की बातों को मिला दिया जाए तो निष्कर्ष यही आएगा कि भले भाजपा 400 पार का नारा दे, लेकिन यह हवा हवाई ही है। किंतु क्या यही 2024 लोक सभा चुनाव की वास्तविक स्थिति है? यह बात सही है कि अनेक राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि को शामिल

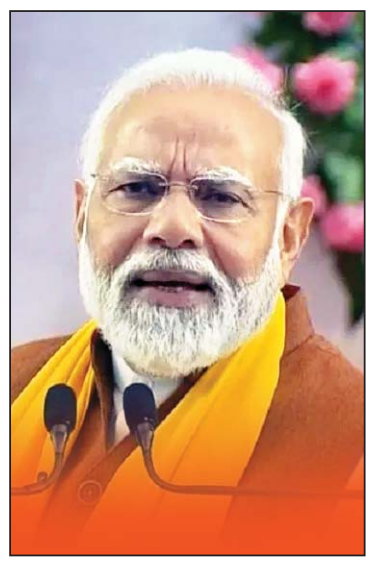

किया जा सकता है वहां पार्टी के अंदर कई जगह उम्मीदवारों को लेकर विरोध है। कुछ उपयुक्त लोगों को टिकट न मिलना तथा ऐसे सांसदों को फिर से उतारना जिनको लेकर कार्यकर्ता नाराजगी प्रकट करते रहे हैं विरोध का एक बड़ा कारण है। साथी दलों ने भी भाजपा के लिए समस्याएं पैदा की है। उदाहरण के लिए बिहार में लोजपा ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो परिवारवाद का साक्षात प्रमाण है और भाजपा के लोगों के लिए इनका बचाव करना कठिन है।

कुछ साथी दलों ने प्रभाविता और साक्षमता की जगह व्यक्तिगत संबंध और परिवार को टिकट देने में प्रमुखता दिया। बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रचार के लिए गए और वहां भाजपा के लोगों ने पूरी ताकत लगाई। इसका असर भी हुआ। बावजूद यह प्रश्न किया जा रहा है कि किसी नेता के बहनोई या 26 साल की एक लड़की को, जिसके पिता साथी दल में नेता हैं उनको हम अपना नेता या प्रतिनिधि मानकर कैसे काम करें? स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीति परिवार के इर्द-गिर्द सिमटी रही। जद (यू) की ओर से भी ऐसे कई उम्मीदवार हैं, जिन्हें भाजपा और राजग के परंपरागत कार्यकर्ता और समर्थक स्वीकार नहीं कर रहे। भाजपा के भी कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम पर उन्हें थोप दिया गया है। झारखंड में भी बाहर से लाकर टिकट देने और ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करने, जिनको भाजपा पहले नकार चुकी हो समस्या पैदा कर रही है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि 4 जून का परिणाम भी इसी के अनुरूप आएगा।

यह सही है कि अगर भाजपा और राजग में उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा सतर्कता बरती जाती, स्थानीय नेतृत्व के चयन की सही तरीके से जांच होती तो स्थिति पूरी तरह वैसी ही उत्साहप्रद होती जैसी चाहिए। बावजूद देशव्यापी व्याप्त अंतर्धारा क्या है? 10 वर्षों की नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की स्वयं की छवि, वर्षों तक संगठन परिवार द्वारा हिंदू समाज के बीच किए गए सकारात्मक कार्य, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, विरोधियों द्वारा हिन्दुत्व को लेकर उपेक्षा या प्रहार का व्यवहार तथा अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए विपक्षी दलों की प्रतिस्पर्धा भाजपा के पक्ष में ऐसा आधार बनाती है जिसका कोई विकल्प नहीं। भाजपा के समर्थकों में एक बड़ा वर्ग विचारधारा के कारण जुड़ाव रखता है और पिछले कुछ वर्षों के कार्यों के कारण हिन्दुओं के अंदर हिन्दुत्व एवं भारतीय राष्ट्रभाव की चेतना प्रबल हुई है। वह बहस करते हैं कि आखिर भाजपा नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनता और ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होती? वे धारा 370 से लेकर समान नागरिक संहिता, तीन तलाक कानून, नागरिकता संशोधन कानून आदि की चर्चा करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून का तो आईएनडीआईए के ज्यादातर दलों ने विरोध किया है। उन्हें लगता है कि घातक अल्पसंख्यकवाद पर अगर किसी पार्टी की सरकार द्वारा नियंत्रण लगा है तो भाजपा ही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रभावों के कारण जिन माफियाओं पर सरकारें उनके समुदाय के कारण हाथ डालने से बचती थी, वे मटियामेट हुए हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ है। स्वाभाविक ही उन्हें लगता है कि आने वाले समय में कोई पार्टी अगर इन सब पर काम कर सकती है तो वह भाजपा ही है। दूसरी ओर सामाजिक न्याय एवं विकास को मोदी सरकार ने जिस तरह से व्यावहारिक रूप दिया है उसका बड़ा आकर्षण समाज के हर वर्ग में है।

यह सही है कि अगर भाजपा और राजग में उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा सतर्कता बरती जाती, स्थानीय नेतृत्व के चयन की सही तरीके से जांच होती तो स्थिति पूरी तरह वैसी ही उत्साहप्रद होती जैसी चाहिए। बावजूद देशव्यापी व्याप्त अंतर्धारा क्या है? 10 वर्षों की नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की स्वयं की छवि, हिंदू समाज के बीच किए गए सकारात्मक कार्य, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा आधार बनाती है जिसका कोई विकल्प नहीं

2030 तक छह सौ किलोटन तक पहुंच सकता है देश का सौर कचरा

- भारत का सौर कचरा 2030 तक 600 किलोटन तक पहुंच सकता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा स्वतंत्र शोध संस्थान काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायर्नमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात कही गई है
- अध्ययन के मुताबिक, इस कचरे का लगभग 67 प्रतिशत पांच राज्यों- राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आएगा।

(स्रोत : फाडा)

160 वर्ष की संयुक्त आयु वाले दो शख्स 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अत्यधिक ध्रुवीकृत देश जिसे भी चुने, अमेरिका के लिए समस्या तेजी से बढ़ती वैश्विक विश्व व्यवस्था में युवा, करिश्माई नेताओं की कमी है।

मिन्हाज मर्चेंट, लेखक/पत्रकार
@MinhazMerchant

फार्मा सेक्टर संदीप भूषण

आर्थिक तेजी की दवा भारत के पास

कोविड के दौरान और उसके बाद दुनियाभर के फार्मा सेक्टर में नई चुनौतियों के साथ कई सकारात्मक बदलाव आए। दवा बनाने वाली कंपनियां और सरकार आज लोगों को किफायत और गुणवत्ता के नाम पर अपने साथ जोड़ने में जुटी है। खासकर दक्षिण एशियाई देशों की सरकारें अपने यहां फार्मा कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। यह प्रोत्साहन नीतिगत तो है ही वित्तीय भी है। इसका एक बड़ा प्रभाव आज हर तरफ दिख रहा है। विकसित के साथ विकाशील देशों के बाजार में भी ब्रांडेड दवा की हिस्सेदारी घटी है। वैसे ग्लोबली देखें तो 56 फीसद बाजार हिस्सेदारी के साथ अब भी ब्रांडेड दवाओं का बड़ा दखल है। बड़ा परिवर्तन यह जरूर है कि 36 फीसद हिस्सेदारी के साथ जेनिरक और ब्रांडेड जेनरिक दवाओं ने ग्रोथ दिखाया है। इस बदलाव ने फार्मा सेक्टर को चर्चा में ला दिया है।

ट्रेड और बिजनेस मैगजीन्स की मानें तो फार्मा सेक्टर आज ग्लोबली तकरीबन सात फीसद के सालाना दर से बढ़ रहा है। 2025 तक इसके 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने की संभावना है। इस ग्लोबल ग्रोथ में 120 वर्ष से भी पुराना भारत का फार्मा सेक्टर बहुत आगे चल रहा है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फॉर्मा उत्पाद बनाने वाला देश है। यह उपलब्धि असाधरण है। फार्मा सेक्टर के इस ग्रोथ के समांतर एक दूसरी स्थिति भी है। कोविड के बाद वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक का बाजार भी खूब गरमाया। इस दौरान भारत भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक देश के रूप में उभरा। अमेरिका और यूरोपीय देशों की कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने के लिए चीन की जगह भारत की तरफ आकर्षित हुईं। दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा दोनों ने एक साथ भारत में जोर पकड़ा। अलबत्ता यह जरूर है कि भारतीय संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले फार्मा सेक्टर के ग्रोथ को बड़ा बताया जा रहा है। ऐसा इस सेक्टर से जुड़ी भविष्य की संभावनाओं और सरकार के नीतिगत समर्थन के कारण भी है। जो स्थिति है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में दवाओं का हमारा निर्यात बढ़ रहा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू निर्माण के प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम शुरू होने के बाद दवा बनाने के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी तेज हुआ है, जिससे हमारी चीन

जैसे देशों पर निर्भरता कम हुई है। भारतीय फार्मा कंपनियों के बढ़ते रुतबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब विश्व में कुल वैक्सीन की 60 प्रतिशत भारत से निर्यात की गईं। इसी प्रकार जेनिरक दवाओं में भी वैश्विक जरूरत का 20 प्रतिशत से अधिक दवाएं भारतीय कंपनियों ने भेजीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में दवा व्यापार के लिए खासा सख्त कानून है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों ने इन बाजारों में भी अपनी पैठ बनाई है। इन्वेस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का दवा उद्योग आज 50 बिलियन डॉलर से बड़ा हो गया है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के एक सर्वे के मुताबित देश के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 118 फार्मा क्लस्टर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 40 फार्मा क्लस्टर महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद गुजरात में 13, आंध्र प्रदेश में 8, हिमाचल प्रदेश में 7, राजस्थान में छह, उत्तर प्रदेश में छह, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में 5-5 हैं। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी फार्मा क्लस्टर हैं। इन राज्यों में बनने वाली दवाओं का बड़े स्तर पर विकसित देशों में निर्यात किया जा रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में संजीवनी की तरह काम कर रहा है। बीते कुछ वर्षों में भारत में केंद्र के साथ राज्यों ने अलग से निवेश आकर्षित करने के बड़े प्रयास किए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा आदि जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्य हर वर्ष अपने यहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं। ऐसे में पहले से विकसित प्रदेश भला पीछे कैसे रह सकते हैं। गोवा इस लिहाज से एक बड़ा उदाहरण है। गोवा ने हाल के दिनों में अपने यहां इससे अलग निवेश की कई संभावनाएं खोली हैं।

डॉ. प्रमोद सावंत की नेतृत्व वाली राज्य सरकार अपने फार्मा सेक्टर को बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। नतीजा है कि भारत में निर्मित कुल दवाओं का 12 फीसद उत्पादन अकेले गोवा कर रहा है। यहां की बनी लगभग 70 फीसद दवाएं विकसित देशों को निर्यात हो रही हैं। पर्यटन के लिए मशहूर इस राज्य में 2.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दवाओं का उत्पादन सालाना हो रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल आदि राज्य भी भारत के फार्मा सेक्टर को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे है। दरअसल, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत हिस्सेदारी जमाने के लिए फार्मा सेक्टर का बढ़ना सोने पर सुहागा है। आने वाले एक दशक फार्मा सेक्टर के ग्रोथ के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण हैं और भारत अपने सामर्थ्य से इस सेक्टर में नंबर वन बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

लड़ो मत वासना से ओशो

झेन फकीरों की कथा है : एक बूढ़ा फकीर और एक युवक फकीर आश्रम वापिस लौट रहे हैं। छोटी-सी नदी पड़ती है। और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है, गहरी हो, खतरनाक हो, बड़ी तेज धार है। बूढ़ा संन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह पार होना चाहती है, हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डर जाता है। हाथ का सहारा! इस बात में पड़ना ठीक नहीं! लेकिन युवक संन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है। वह युवती से पूछता है कि क्या कारण है। सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी। युवती कहती है : मैं बहुत डरी हुई हूं। पानी में उतरते घबराती हूं। मुझे उस पार जाना है। तो वह युवक संन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है। बूढ़ा संन्यासी उस पार पहुंच गया, तब उसे याद आती है कि मेरे पीछे एक युवा संन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में न पड़ जाए! लौटकर देखता है तो उसकी आंखों को भरोसा ही नहीं आता है : वह कंधे पर बिठाए हुए लड़की को नदी पार कर रहा है! बूढ़ा तो आग से जल-भुन गया। युवक संन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया, फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। दो मील तक कोई बात न हुई। दो मील बाद बूढ़े को बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा : यह ठीक नहीं हुआ और मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा; नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने उस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों बिठाया! उस युवक ने जो कहा, वह याद रखना। युवक ने कहा : 'आप बहुत थक गए होंगे। मैं तो युवती को नदी के तट पर ही उतार आया; आप अभी कंधे पर बिठाए हुए हैं! आप बहुत थक गए होंगे! बात आई और गई भी हो गई, अभी तक आप भूले नहीं!' जिसको तुम महात्मा कहते हो, वह आंख तो झुका लेगा; लेकिन आंख झुकाने से कहीं वासनाएं समाप्त होती है! आंख फोड़ भी लो तो भी वासनाएं समाप्त नहीं होती। आंखों पर पट्टियां बांध लो, तो भी वासनाएं समाप्त नहीं होती, वासनाओं का आंखों से क्या संबंध है? क्या तुम सोचते हो, अंधे को वासना नहीं होती? अंधे को इतनी ही वासना होती है, जितनी तुमको; पलटू इसके समर्थन में नहीं हैं। पलटू कहते हैं: एक और रास्ता है। लड़ो मत वासना से। लड़कर कहां जाओगे? घाव बन जाएंगे। कुछ और बड़ी वासना को जगा लोपरमात्मा की वासना।

रीडर्स मेल

सख्त सजा मिले

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 लागू है, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। इसके बावजूद भारी मुनाफे के लालच में मिलावट का यह धंधा खूब फल-फूल रहा है। मिलावटी खाद्य उत्पादों, फलों और सब्जियों के खतरे को रोकने में नियामक संस्थाओं द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है। जबकि बेईमान व्यापारियों और किसानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर और व्यापक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। मिलावट अक्सर किसान स्तर पर शुरू होती है और अब समय आ गया है कि किसानों को भी कठघरे में खड़ा किया जाए। चूंकि लालच किसानों और व्यापारियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन में जहर घोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान करके कानूनों को और अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को व्यापक जागरूकता की पहल शुरू करनी चाहिए।

देवेन्द्रराज सुथार, जालोर, राजस्थान

यूएन का घटता प्रभाव

संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में दुनिया के पास एक ऐसी संस्था है जिससे उम्मीद की जाती है कि वह अराजक शक्तियों पर प्रभावशाली रोक लगाएगी, लेकिन इस संस्था के प्रभावशाली कार्य में कुछ बाधाएं हैं। मसलन इसके जिन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पॉवर है, अधिकतर संघर्षरत देश दस या उस देश के पक्षधर हैं। ऐसे में अनेक महत्त्वपूर्ण मौकों पर किसी विशेष देश के खिलाफ कार्रवाई का फैसला टल जाता है। 25 अक्टूबर 1945 को जब 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उनमें से अधिकांश देश वो थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता के तौर पर उभरे थे। विजेताओं के अपने मानदंड होते हैं, सामाजिक संरक्षण को लेकर। इसी मानसिकता को चुनौती देते हुए तो पोरस नाम के भारतीय राजा को युद्ध में हराने के बाद सिकंदर ने पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो सिकंदर ने कहा था -'मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए।'

अतुल कनक, कोटा, राजस्थान

सोशल मीडिया से संभल कर

सोशल मीडिया भारत में अभी अपने उत्कर्ष पर है, इसलिए उसकी आक्रामकता स्वाभाविक है, परंतु यहां उसे अपनी मर्यादाओं और जिम्मेदारियों को समझना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझते हुए उसका दुरुपयोग करने से बचने की जरूरत है। ऐसा न हो कि सोशल मीडिया के धुरंधरों की ये नादानियां सत्ता को इस माध्यम पर अंकुश लगाने का अवसर दे बैठे। सोशल मीडिया में जो आवश्यक कार्य हो उसका ही उपयोग किया जाए। इसमें भ्रामक और फालतू की बातों से बचना चाहिए। बच्चों को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। इसका उपयोग सदैव सही कार्यों के लिए करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है फेक मीडिया पोस्ट के लिए दंडित करे। पोस्ट्स यूजर के आधारकार्ड व मोबाइल नंबर के बिना पोस्ट नहीं हो। आर्थिक व आपराधिक दंड की व्यवस्था हो।

अंकित सोनी 'आदित्य', धार, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय।** **स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750

वर्ष-33, अंक 242

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

संपादकीय

'सबको स्वास्थ्य' की दिशा में बड़ा कदम लिया गया है

मोदी सरकार ने छह वर्ष पहले आयुष्मान योजना में हर गरीब परिवार को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देकर 55 करोड़ लोगों को एक बड़ी राहत दी थी। वहीं अब भाजपा के संकल्प-पत्र में इस योजना में 70 वर्ष से ज्यादा के हर व्यक्ति (कुल 5.26 करोड़) को शामिल करना 'सबको स्वास्थ्य' की दिशा में एक बड़ा कदम है। निजी बीमा कंपनियों को छोड़िए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करवाने पर 60-65 साल से ऊपर के व्यक्ति को औसतन 40 हजार रुपए सालाना प्रीमियम देना पड़ता है। लिहाजा इस वर्ग के करीब साढ़े चार करोड़ से ज्यादा लोग इस स्थिति में नहीं होते कि इतना प्रीमियम देकर अपने जर्जर हो रहे स्वास्थ्य का बीमा करवा सकें। लिहाजा इस नई घोषणा से, उन लोगों को बड़ा लाभ होगा, जिन्हें जरावस्था के कारण ज्यादा चिकित्सा सुविधा की जरूरत है। यहां सरकार को यह भी देखना होगा कि क्या वास्तव में चिकित्सा का ढांचा देश के आयुष्मान में आच्छादित 61 करोड़ लोगों को सर्विस देने के काबिल है भी या नहीं। आयुष्मान कार्ड हासिल करने और उससे बेहतर चिकित्सा पाने में जमीन-आसमान का अंतर है। क्या जिला अस्पताल इस हालत में हैं कि गंभीर रोगों का इलाज कर पाएं? क्या मेडिकल कॉलेजों में इतने लोड को झेलने की क्षमता है? क्या इस योजना की सफलता की पहली शर्त अस्पतालों, इक्विपमेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जिले तक ले जाना नहीं है? इसके लिए कई वर्ष लगेंगे। फिर आज सरकार स्वास्थ्य पर जीडीपी का मात्र 1.28 प्रतिशत खर्च कर रही है जबकि संसद में नई स्वास्थ्य नीति रखते हुए वर्ष 2018 में इसे 2.5 प्रतिशत करने का संकल्प लिया गया था। क्या निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड के तहत बुजुर्गों का इलाज करेंगे? अभी तक का अनुभव कुछ और ही कहानी कहता है।

प्रेरणा

चीजों को देर तक देखना परिपक्व बनाता है और उनके गहरे अर्थ समझाता है। -विन्सेंट वॉन गॉग

बामुलाहिजा • क्या समय के साथ भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे में भी परिवर्तन आया है?

भाजपा में क्या बदला है और क्या नहीं?

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X@ShekharGupta

1977 में जनता पार्टी के रूप में जो प्रयोग किया गया था और जिसके तहत भारतीय जनसंघ का उसमें विलय हुआ था, उसके नाकाम हो जाने के बाद 6 अप्रैल 1980 को उस पार्टी का भाजपा के रूप में पुनर्जन्म हुआ। उस समय लालकृष्ण आडवाणी ने घोषणा की थी कि यह सबसे अलग तरह की पार्टी होगी। वो ईस्टर का दिन था। कॉन्वेंट में पढ़े आडवाणी ने तब बड़ी खुशी के साथ कहा था कि उनकी पार्टी का उसी दिन पुनर्जन्म हो रहा है, जिस दिन जीसस क्राइस्ट का पुनरुत्थान हुआ था।

उसके 44 साल बाद आज भाजपा जब लगातार तीसरी बार केंद्रीय सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, तब यह बहस दिलचस्प होगी कि वह आडवाणी के उस दावे पर कितनी खरी उतरी है? और आज से छह साल बाद जब वह 50 की हो जाएगी, तब कैसी दिखेगी? दूसरी पार्टियों (मुख्यतः कांग्रेस) से उसके अंतर के ये बुनियादी आधार माने जा सकते हैं- बेबाक हिंदुत्ववादी विचारधारा, वैचारिक शुद्धता से लगाव, अपने संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीति, धुर राष्ट्रवाद, संयमित जीवन शैली और शिक्षकीय नेतृत्व।

लेकिन आज जब यह पार्टी शिखर पर है, उसमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो उसे उसकी मूल प्रस्तावना से 'अलग' साबित करते हैं। सबसे पहला लक्षण तो व्यक्ति-पूजा का है। नरेंद्र मोदी के उभार से पहले तक यह सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी थी। लंबे समय तक तो इसका नेतृत्व अटल-आडवाणी की जोड़ी के हाथों में था। नेपथ्य से नेतृत्व नागपुर में बैठे रणनीतिकार करते थे। आज यह पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। मोदी एकमात्र नेता के रूप में उभरे हैं। बेशक यह उनकी अपनी उपलब्धि है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के लिए जो किया, उसी तरह मोदी की यह उपलब्धि पार्टी के लिए अतिरिक्त वोट हासिल करने की उनकी क्षमता की देन है, जिसके बिना पार्टी को लोकसभा में 200 सीटें जीतने के लिए भी कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ज्यादा 182 सीटें ही जिता पाए थे।

पार्टी को आज इतने प्रतिशत वोट और इतनी सीटें हासिल हैं, जिनका सपना इसके संस्थापक देखते तो होंगे मगर उन्हें यह सपना अपने जीवनकाल में साकार होता नहीं दिखता होगा। भाजपा के लिए यह शानदार है, लेकिन यह उसके अपनी मूल प्रस्तावना से अलगाव को उजागर करता है, जिसमें व्यक्ति-केंद्रित (इंदिरा कांग्रेस) पार्टी का विरोध किया गया था।

आडवाणी ने और पार्टी के जिस 'थिंक टैंक' का वे नेतृत्व करते थे, उसने समय के साथ उसे ऐसा 'चाल, चरित्र और चेहरा' दिया, जिसके बूते उनकी पार्टी भारत में प्रतियोगिता में आगे निकल गई। जहां तक 'चाल' की बात है, पार्टी ने इसे नहीं बदला है। अपनी विचारधारा और अपने कदमों तथा नीतियों पर भी वह स्थिर रही है। 'सबका साथ, सबका विकास' नारा पार्टी के किसी संस्थापक ने या आरएसएस ने दिया होगा, लेकिन पार्टी के तौर-तरीके और उसकी दिशा भी अपरिवर्तित रही है, चाहे यह विदेश नीति का मामला हो या अर्थनीति का, या जनकल्याण, धर्म और समाज से जुड़ी नीति का। जहां तक दूसरी विशेषता 'चेहरा' या छवि की बात है, इसमें

जबकि जनता का मानना यह कि भ्रष्टाचार बढ़ा है ...

पिछले सप्ताह प्रकाशित सीएसडीएस-लोकनीति सर्वे के अनुसार 55 फीसदी लोगों का मानना था कि पिछले पांच साल में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। फिर भी भाजपा खुद को ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है।

हम बदलाव देख रहे हैं। हमारे यहां इंदिरा गांधी के बाद मोदी ही पहले नेता हैं, जिन्होंने पूरे देश में 'लैम्प पोस्ट' चुनाव करवाने की क्षमता साबित की है कि ये बिजली का खंभा हमारा उम्मीदवार है, इसे वोट दो!

पार्टी पर आरएसएस के दबदबे में जो कमी आई है, वह एक तरह से हुआ नुकसान है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि संघ इसे इस तरह देखता होगा। भाजपा की यह वैचारिक पाठशाला आज जिस सत्ता और प्रभाव का उपभोग कर रही है, उसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। और उसके कई सपने साकार भी हुए हैं- अनुच्छेद 370, राम मंदिर, तीन तलाक आदि।

मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस तेजी से तरक्की की, उसकी वजह से ही शायद उसे जल्द ही मानव संसाधन के संकट का एहसास हुआ। आरएसएस के पुराने अनुयायियों में उसके लिए पर्याप्त संभावित नेता नहीं थे। इसलिए उसे फटाफट कई विलय कराने और अधिग्रहण करने की जरूरत महसूस हुई। इसका एक रूप हमने पिछले दिनों महाराष्ट्र और बिहार में देखा। दूसरा रूप यह है कि पुराने प्रतिद्वंद्वियों में से दलबदल करने वालों के लिए पार्टी ने अपना फाटक पूरा खोल रखा है। उन प्रतिद्वंद्वियों में से कई तो केवल सत्ता पाने के लिए आ रहे हैं, कुछ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने नेता पसंद नहीं हैं, लेकिन बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं या 'एजेंसियों' से बचने के लिए शरण ले रहे हैं। विपक्ष इस 'वॉशिंग मशीन' वाली सियासत के विरोध में चाहे जितना शोर मचा रहा हो, भाजपा बेपरवाह है। उसका मानना है कि चुनाव नतीजे ही कसौटी हैं, बाकी सब बेकार का शोर है।

नतीजा यह है कि इन अधिग्रहीतों को न केवल संरक्षण मिला है, उनमें से कई प्रमुख पदों पर पहुंच गए हैं। इनमें से चार तो मुख्यमंत्री हैं, सभी पूर्वोत्तर राज्यों के जहां भाजपा का शायद ही कोई नामोनिशान था। हिमंत बिस्व सरमा तो पूर्वोत्तर में पार्टी के प्रमुख बन गए हैं। बीजद से आए बैजयंत पांडा यूपी में चुनाव प्रभारी हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल संसदीय दल के सदस्य हैं। बाहर से आए नेता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की सूची में भी शामिल हैं। कभी लालू परिवार के वफादार रहे सम्राट चौधरी बिहार में उप-मुख्यमंत्री हैं। यह पार्टी के 'चरित्र' में परिवर्तन को उजागर करता है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

ईशकृपा के प्रकाश में हम दुर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे

हम सब नवरात्र की पूर्णाहुति के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास अवसर है कि हम यह जान सकें कि प्रभु की कृपा हमारे जीवन में प्रकाश के रूप में आती है और फिर इस प्रकार से दुर्गुणों का अंधेरा मिट जाता है। इस सिद्धांत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है। उन्होंने रामराज्य की चर्चा करते हुए कहा कि जब से रामजी रूपी सूर्य उगा है, तीनों लोक प्रकाश से भर गए और बहुत लोगों को सुख और बहुत लोगों के मन में शोक हुआ। अब किन लोगों के मन में शोक हुआ? तो तुलसीदास जी कहते हैं, 'जिन्हहि सोक ते कहउं बखानी। प्रथम अबिद्या निसा नसानी'। 'जिन-जिनको शोक हुआ, उनका मैं बखान करता हूं। पहला अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। दूसरा पाप रूपी उल्लू छिप गया। काम, क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। वहीं, बंधनकारक गुण, कर्म, काल और स्वभाव यह चकोर हैं, जो इस सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर भी किसी ओर नहीं चल पाता।' कुल मिलाकर तुलसीदास जी हमें कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे प्रयास करें। उस प्रयास का नाम ही नवरात्र है और उस कृपा के प्रकाश में फिर हम दुर्गुणों से मुक्त हो जाएंगे।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • इस बार चुनावों में वोटरों की अलग-अलग राय है और कम से कम तीन प्रकार के विचार मौजूद हैं...

चुनावों के इस मौसम में जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं

शीला भट्ट
वरिष्ठ पत्रकार
X@sheela2010

इस चुनावी सीजन में अगर आप जनता के बीच जाएं तो ज्यादातर लोग मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर इतने आश्वस्त हैं, मानो नतीजे पहले ही आ चुके हों और मतदान महज एक औपचारिकता रह गई हो। उनका मानना है कि राम मंदिर, वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ा कद और मोदी का व्यक्तित्व भाजपा को वोट देने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं। उनका आत्मविश्वास तब देखने को मिलता है, जब वे कहते हैं- अब की बार, 400 पार। यह चुनावी इतिहास में नई घटना है, जहां सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग का आत्मविश्वास चुनाव को आगे बढ़ा रहा है।

वहीं लोगों का एक दूसरा समूह भी है- और इनकी संख्या भी कम नहीं- जो हमें वास्तविकता से अवगत कराना चाहता है। वे कह रहे हैं कि बीजेपी की 400 पार सीटें हरगिज नहीं आ रही हैं, अलबत्ता वो 300 पार जरूर होगी। ये लोग मतदाताओं के मानस पर मोदी की गहरी पकड़ के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि हिंदी पट्टी भाजपा को हारने नहीं देगी। यूपी, गुजरात, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों के अलावा कर्नाटक, असम और झारखंड में 253 सीटें हैं। इनमें से 221 पर भाजपा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल को छोड़कर इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा के लिए जमीनी स्थिति में कोई खास प्रतिकूल बदलाव नहीं आया है। उपरोक्त गणना में महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की बात नहीं की गई है। जबकि भाजपा इन तीन राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त है। जो मतदाता भाजपा-भक्त नहीं हैं लेकिन राजनीतिक रुझानों को करीब से समझते हैं, वे कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति में मोदी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष है कहां?- यह आज भारत में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला प्रश्न है।

एक तीसरा समूह भी है। इनमें कट्टर कांग्रेस समर्थक, संघ-विरोधी, सेकुलर और क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देने वाले शामिल हैं। 2019 में ऐसे मतदाता 55% थे। उनका दावा है कि 2024 का यह चुनाव अलग नहीं है, यह अधिकांश भारतीय चुनावों की तरह ही है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। उनकी सलाह है कि चुनाव का आकलन दिल्ली में बैठकर न करें, क्योंकि जमीन पर भाजपा को कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्हें ममता बनर्जी, स्टालिन, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं, तेलंगाना- आंध्र प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई पर भरोसा है और वे बिहार में तेजस्वी यादव से उम्मीदें लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि भाजपा के खिलाफ मुस्लिम वोटरों की एकजुटता से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को लाभ होगा, बशर्ते कमंडल की जगह मंडल की लहर चले।

जो लोग मोदी सरकार के धुर विरोधी हैं, वे कह रहे हैं कि जातिगत फैक्टर्स, क्षेत्रीय अस्मिता, बेरोजगारी आदि के कारण दस साल की एंटी इनकम्बेंसी, सम्पत्ति का असमान वितरण और ईडी-सीबीआई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भाजपा की हार के कारण बनेंगे। चुनावी बॉन्ड के खुलासे ने भाजपा के भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। वामपंथी और कांग्रेसी मतदाताओं के बीच इस पर भी गम्भीरता से बहस हो रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। वे मानते हैं कि 1977 के चुनावों की तरह लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे। कुछ भाजपा में अंतर्कलह की भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि अगर बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र के मतदाता भाजपा को खारिज कर देते हैं और हिंदी पट्टी के वोटर 2019 के मुकाबले भाजपा को सिर्फ 20% कम सीटें देते हैं तो इससे मोदी के सपनों के सफर पर ब्रेक लग जाएगा।

यानी इस बार चुनावों में वोटरों की अलग-अलग राय है। भाजपा और मोदी के खिलाफ उपरोक्त सभी तर्कों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यह दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव नहीं हार सकते। क्योंकि पिछले दस वर्षों में मोदी ने खुद को अन्य नेताओं से ऊपर उठाने के लिए काफी मेहनत की है। सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन पर मोदी की निरंतर उपस्थिति और पूरे भारत में उनकी अथक यात्राएं इस धारणा को बढ़ाती है कि वे मजबूत हो रहे हैं। भारतीय मतदाताओं की यह वृत्ति है कि अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार उन्हें यह यकीन दिला दें कि वे जीत रहे हैं तो वे फायदे की स्थिति में रहते हैं। इसका यह मतलब है कि जिन मतदाताओं की विचारधारा बहुत मजबूत नहीं है, वो जीतने वाली पार्टी को वोट दे आते हैं। क्योंकि वोटरों का मानना है कि अगर वे किसी ऐसे उम्मीदवार को वोट देते हैं, जिसकी हार की सम्भावना है, तो उनका वोट बेकार चला जाता है। उनका दृष्टिकोण यह है कि चुनावी जीत एक प्रकार की सत्ता है और वे सत्ता के साथ होना चाहते हैं। यानी बहुत सम्भव है कि फ्लोटिंग वोटर्स या वो मतदाता- जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है- वो मोदी को वोट दे आएं। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

https://t.me/AINewsPaperPaid

वेब भास्कर

जब मां की गुदगुदी से खिलखिला कर हंस पड़ा नन्हा चिम्पैंजी

चिम्पैंजी हम इंसानों के सबसे नजदीकी रिश्तेदार माने जाते हैं। तभी तो इनमें हम इंसानों की तरह कई गुण मिलते हैं। वे न सिर्फ हमारी तरह व्यवहार करते हैं, बल्कि आपस में संवाद भी करते हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, मध्य अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में जब मां ने इस नन्हे चिम्पैंजी को गुदगुदी की, तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इस निश्छल मुस्कान को शौकिया फोटोग्राफर रमेश कृष्णमूर्ति ने अपने कैमरे में कैद किया। बीबीसी अर्थ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह तस्वीर शेयर की है। एक शोध में यह भी सामने आया है कि चिम्पैंजी निस्वार्थ भाव से एक-दूसरे की मदद करते हैं।

विमर्श • मेहनत बिना मिलने वाला ज्ञान नुकसानदेह है

सर्च इंजन ही सब जान चुके होंगे तो हम कैसे नया सीखेंगे?

डॉ. चन्द्रकांत लहारिया
जाने माने चिकित्सक
c.lahariya@gmail.com

आपने सुकरात के बारे में सुना होगा। वे अपने समय के एक महत्वपूर्ण यूनानी दार्शनिक थे, जो लगभग 2,750 वर्ष पहले हुए थे। वे एथेंस में रहते थे, जहां लोकतंत्र के पहले ज्ञात रूपों में से एक का जन्म हुआ था। एथेंस में कुछ नागरिकों- जैसे कि वे जिनके पास जमीन थी तथा पुरुष और जो गुलाम नहीं थे- को साझा निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार था। यह सब नगरसभा (अगोरा) में होता था। सुकरात लोकतंत्र के समर्थक तो थे लेकिन इस प्रणाली के आलोचक भी थे। उनका मानना था कि इस तरह की सभा-प्रणाली में निर्णय वो लोग लेते हैं जो अच्छे वक्ता होते हैं और भावनाओं को छूते हैं- भले ही उनकी बातों में तर्क, गहराई, गम्भीरता कम हो।

इसके अलावा- अपने पूरे जीवन में- सुकरात ने उच्च अधिकारियों पर सवाल उठाए। वे हर बात की आलोचनात्मक जांच में विश्वास करते थे और गलत परम्पराओं की खुले तौर पर आलोचना करते थे, भले ही वह शीर्ष नेतृत्व से ही क्यों न आई हो। जाहिर है, सुकरात की आलोचना ने उन्हें अलोकप्रिय बना दिया। 70 वर्ष की आयु में, सुकरात पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया और उन्हें एथेंस शहर छोड़ने या जहर पीकर मौत की सजा देने का विकल्प दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो के अनुसार सुकरात ने अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय जहर पीकर मरने का विकल्प चुना।

हिन्दू धर्म में भी शंकराचार्य से लेकर कई अन्य उदाहरण मिलते हैं, जिसमें शास्त्रार्थ और तर्क-वितर्क को समाज के सुधार के लिए उपयोग करने का जिक्र किया जाता है। प्राचीन काल में ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था और उसे कठिन परिश्रम से अर्जित किया जाता था। पंचतंत्र की कहानियों में राजा अपने पुत्रों को ज्ञान के लिए गुरु के पास भेजते थे। गुरु-शिष्य की परम्परा भी उससे जुड़ी हुई है। यह सब शिक्षा में लगने वाली मेहनत और महत्व दोनों को रेखांकित करता है। महान शिक्षकों से चीजें सीखने का प्रयास करना पड़ता था। ज्ञान और आलोचनात्मक सोच के महत्व को बहुत समझा और सराहा गया।

अब एक और हिंदू पौराणिक कथा पर लौटते हैं। नटराज प्रतिमा सबसे आम मूर्तियों में से एक है, जिसमें शिव की तांडव करते हुए आकृति है। यदि आपने नटराज प्रतिमा पर ध्यान दिया है, तो आपने देखा होगा कि उसमें शिव का दाहिना पैर एक बौने पर रखा हुआ है, जिसका सिर राक्षस का और शरीर बच्चे का है। इसे 'अपस्मार' नाम से वर्णित किया गया है। माना जाता है कि अपस्मार अज्ञानता और निरर्थक भाषण का प्रतिनिधित्व करता है। उसे नटराज के पैर के नीचे दबाने की अवधारणा यह है कि किसी भी प्रकार की अज्ञानता को दबा दिया जाना चाहिए। माना जाता है कि अपस्मार को मारना नहीं है, क्योंकि अगर अज्ञान पूरी तरह खत्म हो जाएगा और हर किसी को ज्ञान बिना मेहनत के मिल जाएगा तो यह ज्ञान का सभी रूपों में अवमूल्यन होगा और तर्क-वितर्क की परंपरा को खत्म कर देगा।

लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक मतदाता और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया या चैटजीपीटी पर भरोसा न करके स्वयं ही उम्मीदवारों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

आधुनिक समय अपने साथ अनेक नई चुनौतियों के लेकर आता है। हम सोशल मीडिया के समय में जी रहे हैं, जहां कंटेंट से ज्यादा महत्व पैकेजिंग को दिया जाता है। सोशल मीडिया ने अच्छे वक्तृत्व-कौशल और बिना पर्याप्त सार के भावनाओं से खेलने वाले लोगों को सेलिब्रिटी बना दिया है। सुकरात जिस बात की आलोचना करते थे, वह आज हो रही है। जबकि सोशल मीडिया और चैटजीपीटी के उपयोगकर्ता को यह समझने की जरूरत है कि अगर कोई एआई टूल किसी बात को पहले से जानता है, तो वह जानने लायक नहीं है। सर्च इंजनों पर निर्भरता आलोचनात्मक सोच और मस्तिष्क की क्षमता को कमजोर करती है। मेहनत के बिना ज्ञान प्राप्त करने में रुचि अपस्मार को शक्तिशाली बनाती है।

चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में हम सभी को सुकरात की बात समझनी चाहिए और लच्छेदार बातों व वक्तृत्व-कौशल के धनी लोगों को नहीं, बल्कि उन उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, जो बदलाव लाने में सक्षम हों। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

क्लाइमेट • अंटार्कटिका इस पृथ्वी का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है, इसकी बर्फ डरावनी गति से घट रही

'धरती के रेफ्रिजरेटर' पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत

साधना शंकर
लेखिका और पूर्व भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी
sadhna99@hotmail.com

अंटार्कटिका में हाल ही में तीसरा भारतीय पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ। इससे जुड़ी खबरें भी सामने आईं। अंटार्कटिका में तीन हजार किमी के दायरे में भारत के दो रिसर्च स्टेशन हैं- मैत्री और भारती। भारती स्टेशन पर खुला यह तीसरा पोस्ट ऑफिस गोवा पोस्टल डिवीजन का हिस्सा है और उसका पिन होगा एमएच 1718... बहरहाल यह दिल को खुशी देने वाली बात है, लेकिन अंटार्कटिका क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर सोचने की जरूरत है।

क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो अंटार्कटिका पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है, इसमें दक्षिणी ध्रुव शामिल है और दुनिया की 90 फीसदी बर्फ यहीं है। यह इन मायनों में खास है कि यहां की अपनी कोई मूल आबादी नहीं है और यह पेंग्विन की कॉलोनी के रूप में जाना जाता है। यह महाद्वीप एक शांतिपूर्ण सहयोगी अंटार्कटिका संधि प्रणाली से संचालित होता है, जिसमें 56 देश शामिल हैं। इस संधि से अंटार्कटिका 'वैज्ञानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र' बन गया है और वैज्ञानिक जांच की आजादी के साथ पर्यावरण संरक्षण भी संभव हुआ है।

अंटार्कटिका इस पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर कहलाता है क्योंकि यहां की बर्फ की चादरों में धरती का सबसे ज्यादा पानी समाया हुआ है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड में बर्फ का पिघलना काफी समय से दुनिया का ध्यान खींच रहा था और माना जाता था कि अंटार्कटिका इससे अछूता है। जबकि हाल के शोध बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से यह महाद्वीप बड़े बदलावों से गुजर रहा है। इस महाद्वीप को ढंकने वाली बर्फ अब पिघल रही है और इसके परिणाम दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे।

बीते साल के उत्तरार्ध में खतरे की घंटी तब बजी, जब इस महाद्वीप के चारों ओर तैरने वाली समुद्री बर्फ 2022 की तुलना में 10 प्रतिशत कम हो गई। सर्दियां तो आईं, लेकिन बर्फ वापस जमने में दिक्कतें हुईं और यह औसत से कम हो गई। इलाके की पूरी बर्फ की चादरों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल मिलाकर बर्फ का नुकसान नई बर्फबारी पूरा नहीं कर पा रही है। अंटार्कटिका की ये 'आइस शीट' घट रही हैं।

यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि सदियों से ये 'रेफ्रिजरेटर' धरती को शीतल रखे हुए हैं। बर्फ पिघलने से न सिर्फ दक्षिणी महासागर के चारों ओर समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि समुद्रों पर पड़ने वाला बर्फ का गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर पड़ रहा है। इससे भी समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा। इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा, जहां ज्यादातर आबादी रहती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय सर्कुलेशन को भी बदल देती हैं जो भूमध्य रेखा और उससे आगे, अमेजन और साहेल (अफ्रीका) में बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती हैं।

अंटार्कटिका के इर्द-गिर्द फैला दक्षिणी महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और धरती की गर्मी को समाहित कर लेता है। यह मानव गतिविधि के कारण होने वाले वार्षिक कार्बन उत्सर्जन का लगभग 12% सोख लेता है। अगर अरबों टन ताजा पानी बर्फ से पिघलकर समुद्र में मिलेगा, तो समुद्री करंट यानी पानी का पैटर्न बदल जाएगा। इससे समुद्र गर्म होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आएगी।

ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और खतरे की घंटी बज रही है, ऐसे में इन बदलावों को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए शोध इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस संधि से जुड़े देशों को इन बदलावों से जुड़े शोध पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ताकि इस धरती का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर अपना काम करता रहे।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

भाजपा का घोषणापत्र

विकास का वादा

भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में 'ज्ञान' एवं विकास पर जोर दिया गया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने लंबी प्रतीक्षा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'ज्ञान'-गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति के कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता प्रकट की। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में यह घोषणापत्र प्रस्तुत किया। मोदी ने रेखांकित किया कि इसका उद्देश्य 'विकसित भारत' अवधारणा पर केन्द्रित प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों का सशक्तीकरण शामिल है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए गरिमा व जीवन की गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए ऐसी पहलों का वादा किया जिनमें प्रत्येक परिवार को पाइप से गैस पहुंचाने तथा सोलर पावर के माध्यम से मुफ्त बिजली शामिल हैं। इस घोषणापत्र में केन्द्र की मुफ्त राशन योजना का विस्तार करने तथा आवश्यक खाद्य पदार्थों, जैसे दालों, खाद्य तेलों और सब्जियों के मामले में आत्मनिर्भरता व उनके मूल्य स्थिर कर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही इसमें 'आयुष्मान भारत' तथा 'पीएम आवास योजना' जैसी योजनाओं का विस्तार कर हर घर को स्वच्छ पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करना है। कृषि क्षेत्र में भाजपा ने किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता जारी रखने, तकनीक के माध्यम से फसल बीमा का दायरा बढ़ाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि का वादा किया है। इसमें 'समान नागरिक संहिता', 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पहल, 5जी नेटवर्क का विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना तथा ट्रेन यात्रा की प्रतीक्षा सूची समाप्त करना भी शामिल है।

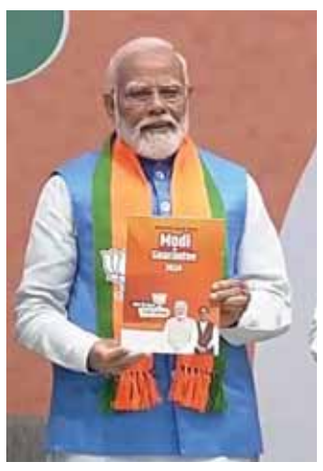

भाजपा के घोषणापत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, ढांचागत विकास तथा सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करते हुए जाति-आधारित राजनीति अथवा सत्ता तक पहुंचने के लिए 'खैरातें' बांटने को पूर्णतः अनदेखा किया गया है। इस प्रकार भाजपा का 'संकल्प पत्र' अपने प्रति दृढ़ आत्मविश्वास का परिचायक है। नड्डा ने भाजपा का चुनावी नारा बन चुके 'मोदी की गारंटी' में समाहित सभी वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भाजपा अपनी स्थापना के समय से ही अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़ती रही है। इनमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर तथा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही समान नागरिक संहिता भी शामिल थी। पहले दो वादे पूरे होने के बाद उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू की है। अब भाजपा ने इसे पूरे देश में लागू करने का वादा कर अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है। पिछले दस साल में देश की अर्थव्यवस्था को दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर लाने में सफल भाजपा 2047 तक विकसित भारत के लिए संकल्पबद्ध है और उसका चुनाव घोषणापत्र इसी दिशा में एक कदम है। भाजपा ने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। इसके साथ ही अब भारत हथियार निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। इसके एकदम उलट 'इंडिया' गठबंधन में शामिल माकपा ने सत्ता में आने पर देश के सभी आणविक आयुध नष्ट करने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने येन-केन-प्रकारेण सत्ता तक पहुंचने के लिए षडयंत्र करने वाले विपक्षी दलों के इन 'खतरनाक' इरादों से जनता को सतर्क किया है। उम्मीद है कि जनता मतदान करते समय भाजपा के संकल्प पत्र को समुचित महत्व देगी।

बंगाल में राय परिवार की विरासत

टीएमसी और भाजपा के बीच हाल में एक ऐतिहासिक विमर्श पर तीखी बहस हुई जिसका संबंध बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के पतन में राय परिवार की भूमिका से है।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

टीएमसी और भाजपा के बीच हाल में एक ऐतिहासिक विमर्श पर तीखी बहस हुई जिसका संबंध बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के पतन में राय परिवार की भूमिका से है। 2024 का लोकसभा चुनाव अभियान तेज होने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कीचड़ उछालने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जबकि यदि ऐसा न होता तो ज्यादा अच्छा था। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी ने भाजपा की कृष्णानगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार श्रीमती अमृता राय पर इसलिए कीचड़ उछाला क्योंकि उनका संबंध कृष्ण चंद्र राय के परिवार से है। कृष्ण चंद्र राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था जो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का मुकाबला कर रही थी। कृष्णानगर में राय परिवार की वर्तमान राजमाता ने यह कह कर अपने परिवार का उस समय का कृत्य सही ठहराया कि यदि कृष्ण चंद्र राय ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ न दिया होता तो अत्याचारी नवाब सिराजुद्दौला के राज्य में सनातन धर्म व बंगाली संस्कृति नष्ट हो जाती।

उन्होंने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया कि उस समय न केवल अमृता राय के पूर्वज राजा कृष्ण चंद्र राय के साथ ही जगत सेठ तथा नाभा के राजा कृष्ण देव ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। केवल इतना ही नहीं, मीर जाफर तथा अनेक अन्य लोग भी नवाब सिराजुद्दौला का अंत चाहते थे। सिराजुद्दौला के अत्याचारों ने आम जनता में इतना गुस्सा भर दिया था कि ज्यादातर लोग उसके शासन का अंत चाहते थे। सिराजुद्दौला सनातन धर्म तथा बांग्ला संस्कृति का घोर विरोधी था और इस कारण भी उसके विरोध में गुस्सा बढ़ रहा था।

सवाल है कि यदि इन व्यापारी राजकुमारों ने सिराजुद्दौला को उखाड़ फेंकने में सफलता न पाई होती तो बंगाल का भविष्य कैसा होता? यदि नवाब का शासन चलता रहता तो संभवतः नादिया जिला तथा आज का पश्चिम बंगाल पाकिस्तान और अंततः बांग्लादेश में चला जाता। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इसकंदर मिर्जा सिराजुद्दौला के सीधे वारिस थे। उनका परिवार मुर्शिदाबाद में रहता था, लेकिन देश का विभाजन निकट आने पर वह जल्दी से कराची चला गया जो पाकिस्तान की तत्कालीन राजधानी थी। इसकंदर पाकिस्तान के पहले रक्षा सचिव तथा मार्च, 1956 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला 1756 में सिंहासन पर बैठा। उसने जल्द ही अपना रंग दिखाना शुरू किया और अपने प्रमुख मंत्री राय दुर्लभ को पद से हटा दिया जिनको उसके बाबा नवाब अलीवर्दी खान ने नियुक्त किया था।

युवा नवाब ने राज्य के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ का अपमान किया। उनको दरबार में खुलेआम थप्पड़ मारे गए तथा सुन्नत करवाने या 'खतना' करवाने की धमकी दी गई। इसकंदर मिर्जा के पुत्र हुमायूं मिर्जा ने अपनी पुस्तक 'प्लासी टु पाकिस्तान' में इसका वर्णन किया है। व्यापारी राजकुमार मध्य एशियाई मूल वाले लोगों द्वारा शासन के पक्ष में नहीं थे और वे शासन-प्रशासन में स्थानीय लोगों को ज्यादा स्थान देना चाहते थे। लेकिन उनके पास सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाने के लिए सैनिक संगठन नहीं था। 1757 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल के आदेश से राबर्ट क्लाइव कुछ नाविकों और सैनिकों के साथ मद्रास पहुंचे। वे पिछले साल कोलकाता के फोर्ट विलियम में अंग्रेजों के अपमान का बदला सिराजुद्दौला से अच्छी तरह लेना चहते थे। इस घटना ने नवाब सिराजुद्दौला का भविष्य अंधकारमय बनाने में पूरी भूमिका निभाई।

सिराजुद्दौला के नवाबी शासन में 'व्यापारी राजकुमारों' को यह बहुत अच्छा अवसर लगा जिसका लाभ उठा कर वे सिराजुद्दौला का शासन समाप्त कर सकते थे। ब्रिटिश हथियारों और बंगालियों के पैसे से उसके क्रूर शासन का अंत किया जा सकता था। इसके साथ ही वे अपने संबंधों के माध्यम से भी विजय की उम्मीद कर रहे थे। उस समय राबर्ट क्लाइव के पास केवल 3,000 सैनिक थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास एक लाख की सेना के साथ ही घुड़सवार और हाथी थे। इस विशाल सेना को अलग-अलग टुकड़ों में विभाजित करना था। नवाब की आधी सेना का संचालन मीर जाफर के पास था। उससे वादा किया गया था कि यदि वह सिराजुद्दौला की पराजय सुनिश्चित करने में सहायता करे तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप सिराजुद्दौला की आधी से अधिक सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इस प्रकार 23 जून, 1757 को प्लासी के युद्ध ने सिराजुद्दौला के शासन और उसके जीवन का अंत कर दिया। हम जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय बंगाल में दो संस्कृतियां -बंगाली व इस्लामिक थीं। 12वीं शताब्दी के बाद से यह क्षेत्र बंगाली प्रभाव से बाहर निकल रहा था और दो-तिहाई अरब हो गया था। 1757 में प्लासी युद्ध ने इस परिघटना को पहला निर्णायक धक्का दिया। सिराजुद्दौला की पराजय और उसकी हत्या के बाद नवाबी शासन का अंत हो गया।

इसके बाद अनेक सालों में पहली बार हिंदुओं ने खुलेआम राजा नाभा कृष्ण देव के महल में विशाल दुर्गा पूजा का आयोजन किया था जिसमें राबर्ट क्लाइव मुख्य अतिथि थे। इससे स्पष्ट होता है कि बंगाल में सिराजुद्दौला के अत्याचारी शासन के अंतर्गत सनातन धर्म तथा हिंदू जनता कितने भयानक दमन और उत्पीड़न का सामना कर रही थी। कल्पना करें कि यदि बंगाल 'इस्लामी' रास्ते पर चलता रहता तो क्या होता। ऐसे में बंगाल में कोई ऐतिहासिक 'पुनर्जागरण' न होता जिसके लिए बंगाल को याद किया जाता है और उसका सम्मान होता है। यदि ऐसा होता तो बंगाल में राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर व निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग न होते। ऐसे में यह कल्पना ही की जा सकती है कि यह क्षेत्र कैसा होता। गोपाल कृष्ण गोखले ने 100 साल से भी पहले कहा था कि 'जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल सोचेगा।' लेकिन यदि सिराजुद्दौला जैसे लोगों का शासन बना रहता तो आज बंगाल ही न होता।

गांधीजी ने भारतीयों को स्वतंत्रता, राजनीति, आध्यात्मिक व अर्थशास्त्र के मूल्यों के प्रति जागरूक किया, लेकिन विजेता के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज-आईएनए हमारे सामने आई। इस तथ्य को किसी और ने नहीं, बल्कि क्लीमेंट एटली ने स्वीकार किया था जो 1946 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। एटली ने ही ब्रिटिश नेता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता कानून, 1947 पर हस्ताक्षर किए थे और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता का दरवाजा खोला था। अपना पद छोड़ने के बाद एटली भारत आए और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती के अतिथि बने। एक रात्रि भोज के दौरान चक्रवर्ती ने अपने अतिथि से पूछा कि 1947 में अंग्रेज इतनी जल्दी भारत छोड़ कर भाग क्यों गए, जबकि उस समय ऐसा कोई तात्कालिक कारण नहीं था। उस समय 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन लगभग विफल हो चुका था।

इस पर पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जवाब में अनेक कारण गिनाए थे। इनमें सर्वाधिक प्रमुख भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ब्रिटिश राज के प्रति स्वामिभक्ति में आई कमी थी। इसका कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाया अभियान था। जब चक्रवर्ती ने एटली से पूछा कि गांधीजी के अहिंसक सत्याग्रह का अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा था तो एटली ने अपने शब्द के हर अक्षर पर जोर देते हुए 'मिनिमल' या न्यूनतम कहा था। एटली के चेहरे पर उस समय एक व्यंग्यात्मक मुस्कराहट थी। यदि सिराजुद्दौला जैसे लोगों के लगातार शासन से बंगाल में 'इस्लामवाद' हावी हो जाता और स्थानीय बांग्ला तथा हिंदू संस्कृति का विनाश हो जाता तो बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। यदि बंगाल ही न होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे होते जिनकी आजाद हिंद फौज के प्रभाव में अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। इस दृष्टिकोण से श्रीमती अमृता राय के पूर्वज कृष्ण चंद्र राय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देना सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी था और उसे इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जलवायु परिवर्तन का आध्यात्मिक समाधान

> विकास की प्रत्येक इच्छा के लिए, आप शरीर की पहचान, उपभोग, प्रजनन और उसके बाद विनाश के बीच संबंध देखेंगे। जब वैश्विक तापमान तीन या चार डिग्री बढ़ जाएगा, तो ये सभी शिशु फूल मुरझा जाएंगे।

आचार्य प्रशांत
(लेखक वेदांत शिक्षक हैं)

प्रजनन को सीमित करना शायद स्थिरता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां लोग छोटी छोटी अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आसानी से इस तथ्य से दूर रह सकें कि हम जो कर रहे हैं वह बहुत बुरी बात है। अधिकांश लोगों को उपभोग की आदत होती है समस्या उपभोग नहीं है यह चीज़ों का अंधाधुंध और अंधाधुंध उपभोग है जो वैसे भी आपको कोई लाभ नहीं पहुँचाएगा। यही तो समस्या है। तो ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान पूरी तरह से उपभोग के त्याग के बारे में नहीं है। ऐसे संकेत हैं जो जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न गतिविधियों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए कार मुक्त होना, ट्रान्साटलांटिक उड़ान से बजाय हरित ऊर्जा चुनना, इलेक्ट्रिक कार से कार मुक्त पर स्विच करना, शाकाहारी आहार चुनना, एक सामान्य कार को हाइब्रिड से बदलना, गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी में कपड़े धोना, पुनर्चक्रण, सूखे कपड़े लटकाना, ऊर्जा कुशल प्रकाश बल्बों में उन्नयन। ग्राफिक का शीर्षक है प्रत्येक कार्य करने वाले एक व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष टन सीओ2 समकक्ष बचाया गया (वाइन्स और निकोलस 2017, पर्यावरण अनुसंधान पत्र, खंड 12, संख्या 7)। लेकिन ये 10 गतिविधियाँ लोकप्रिय हैं जहाँ सभी अच्छे लोग इन सभी दस गतिविधियों को करने में व्यस्त हैं और वे महान मिशनरी उत्साह और उससे भी अधिक मिशनरी गर्व के साथ घूमते हैं।

और फिर यह विशाल बार है जो लगभग साठ टन सीओ2 से मेल खाता है जो एक ही कार्य करने से आता है यानी एक बच्चा पैदा करना। हम जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदानकर्ता के बारे में बात नहीं करते क्योंकि यहीं पर हमारा अहंकार रहता है, यहीं पर शारीरिक और शारीरिक प्रवृत्तियाँ रहती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रजनन के संबंध में, बच्चे पैदा करने के संबंध में यह बात क्यों बोल रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आज आपके और मेरे, ग्रह और लाखों प्रजातियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही वह चीज़ है जिस पर मनुष्य को इस समय तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जाति के सामने इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध नहीं, परमाणु प्रसार नहीं, कुछ भी नहीं। यह सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आप कृपया बच्चे पैदा करना बंद कर सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। यदि आप इसका समाधान कर तो हर चीज़ का समाधान हो जाएगा।

विकास की प्रत्येक इच्छा के लिए, आप शरीर की पहचान, उपभोग, प्रजनन और उसके बाद विनाश के बीच संबंध देखेंगे। जब वैश्विक तापमान तीन डिग्री या चार डिग्री बढ़ जाएगा, तो ये सभी शिशु फूल मुरझा जाएंगे। वैसे भी फूलों की बहुत अधिक प्रजातियाँ रोपने लायक नहीं रहने वाली हैं। जलवायु परिवर्तन कितना दोषी है यह आईयूसीएन रेड लिस्ट में कम से कम 10967 प्रजातियों को प्रभावित करता है और अनुमानों से पता चलता है कि यदि 2100 तक वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई तो भूमि पर सभी प्रजातियों में से लगभग 18 प्रतिशत को विलुप्त होने का उच्च जोखिम का सामना करना पड़ेगा।

और इसे केवल मुकदमेबाजी के माध्यम से संबोधित नहीं किया जा सकता है। आपको एक आध्यात्मिक आंदोलन की आवश्यकता है, मैं जो कह रहा हूं उसे समझने और जो मैं इंगित कर रहा हूं उस पर कार्य करने के लिए आपको गहरी आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। इस शरीर पहचान को ख़त्म किए बिना आप बच्चों की संख्या सीमित नहीं कर सकते। जब तक आपका भौतिक शरीर है आप उपभोग करते रहेंगे, आपको उपभोग करना ही पड़ेगा। हम शरीर पहचान, उपभोग, प्रजनन और विनाश के बीच संबंध नहीं देखते हैं। हम उन्हें अलग-अलग चीजों के रूप में देखते हैं। विकास की यह चाहत आपको क्या लगता है, इस ग्रह की तबाही से कोई लेना-देना नहीं है वास्तव में विकास की परिभाषा क्या है, जो तुम्हें आनंद देता है। जो आपके लिए आराम और सुविधा लाता है। इसी तरह आप विकास को परिभाषित करते हैं। मानव जाति के इतिहास में वह समय आ गया है जब उस मूल समस्या को संबोधित किए बिना, आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और यदि आप अभी मूल समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो कल कोई नहीं होगा।

आप की बात

सीएए का विरोध

एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए का विरोध हमारी पार्टी की तरफ से लगातार जारी रहेगा क्योंकि यह कानूनन असंवैधानिक है, इसे भाजपा ने बनाया है, इसका आधार धर्म है जो समानता के अधिकार के खिलाफ है। भाजपा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई भेद नहीं करती है। सीएए के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी को भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है। यह हर तरह से उचित एवं कानून सम्मत है। आज यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता रहा है। इसका प्रमाण वहां की जनसंख्या में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या नगण्य होना है। सवाल है कि आखिर उत्पीड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध व पारसी यदि भारत की ओर नहीं तो दुनिया में किस देश की ओर देखेंगे। देश में पहले से नागरिक रहे किसी भी नागरिक की नागरिकता पर सीएए का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह नागरिकता छीनने के बजाय नागरिकता देने का कानून है। अतः सीएए का अनुचित विरोध अब बंद होना चाहिए।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

युद्ध का विस्तार

ईरानी दूतावास पर मिसाइल हमले में उसके सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान ने खुले रूप से इसराइल को सबक सिखाने की घोषणा की है। इसराइल पर अनेक मिसाइलों व ड्रोन के हमले से उसने इसकी शुरुआत भी कर दी है। रूस-यूक्रेन और हमास-इजरायल युद्ध के बाद ईरान-इजरायल के खुलकर युद्ध के मैदान में कूदने से अंतर्राष्ट्रीय हालात अत्यंत जटिल और विकट हो गए हैं। युद्धरत देशों की जनता के अलावा इन युद्धों का प्रभाव समूचे विश्व की जनता भुगत रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं तथा समुद्री यातायात में बाधा आ रही है। युद्ध का विस्तार दुनिया में किसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यह तथ्य भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ईरान अपने द्वारा पाले पोसे गए तथा आर्थिक रूप से समर्थित हमास, हिजबुल्ला व हूती आतंकवादियों, विद्रोहियों व विघटनवादियों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। इसके चलते जहां इसराइल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, वहीं दुनिया भर में इस्लामवादी, जिहादी व कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिलने की आशंका है। आतंकवाद को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

ईरान-इज़राइल टकराव

ईरान द्वारा इजराइल पर हमले के बाद भारत के कुछ खास वर्ग के लोग ईरान की सराहना करते दिखाई पड़ रहे हैं और फिलिस्तीन में जश्न मनाया जा रहा है। फिलिस्तीनियों की खुशी को एक बार सही समझा जा सकता है पर भारत से ऐसे जश्न और समर्थन की तस्वीरें समझ के परे हैं। हमास द्वारा इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुई बर्बरता पर भी कुछ लोग खुशी मना रहे थे परन्तु जैसे ही इजराइल ने पलटवार किया इन्ही लोगों का रुदन आरम्भ हो गया और अब तक जारी है। इजराइल अपने ऊपर हुए ईरानी हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। इस सूरत में एक बार फिर कुछ लोगों को पुनः कष्ट होना स्वाभाविक है। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने तथा दुश्मनों पर हमला करने का पूरा अधिकार है। वर्तमान समय में अधिकांश भारतीय जनता इज़राइल और यहूदी समुदाय पर सैकड़ों सालों से मंडराते खतरे को समझती है। इज़राइल के अस्तित्व को दुनिया के मानचित्र से मिटा देने की बात करने वाले ईरान का किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता है। ईरान की तानाशाही सरकार अपने ही देश की महिलाओं पर जो अत्याचार ढा रही है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद युद्ध किसी के हित में नहीं है।

– **मनोज पुरुषार्थी,** मेरठ

अंबेडकर जयंती

डॉ अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। दिल्ली में महमहिम राष्ट्रपति से लेकर जन साधारण तक संसद भवन स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आज भारत के सभी राजनीतिक दल बाबा साहब को महत्व देते हैं और अंबेडकर जयंती मनाते हैं। यह एक अच्छी परंपरा है। बाबा साहब डॉ अंबेडकर ने दलित-वंचित समाज के लिए संवैधानिक प्रावधान किए तथा आरक्षण का अधिकार दिया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन यह समाज आज भी जातीय अत्याचार व उत्पीड़न का शिकार है। ग्रामीण महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता है तथा जातीय द्वेष भावना कम नहीं हो रही है। आज भी दलित समाज का दूल्हा अपनी बारात को लेकर निकल नहीं पाता है और उसे पुलिस सुरक्षा मांगनी पड़ती है। कभी किसी को मूछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने या अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जाता है। 14 अप्रैल को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए सरकार व समाज को सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाना चाहिए ताकि डा. अंबेडकर के सपने पूरे हो सकें और दलित समाज का योगदान सुनिश्चित हो।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 51

निरंतरता का संकेत

भारतीय जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव 2024 के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र या संकल्पपत्र जारी किया। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या हासिल किया है और यदि वह तीसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित होती है तो किस तरह से देश को आगे लेकर जाएगी। आर्थिक लिहाज से देखें तो यह घोषणापत्र कुछ महत्त्वपूर्ण सुधारों के साथ निरंतरता या उपलब्धियों की बुनियाद पर निर्माण का संकेत देता है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे अहम उपलब्धियों में से एक यह रही, जिसकी शायद पर्याप्त सराहना नहीं की गई है, कि उसने व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया है। साल 2014 में वृहद आर्थिक परिदृश्य-जब साल 2013 में मुद्रा संकट जैसी स्थिति बन गई थी-आज से काफी अलग था। आज भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और पिछले एक दशक में अब बैंकिंग प्रणाली सबसे अच्छी स्थिति में है। महामारी के दौरान भारत की संयमित राजकोषीय प्रतिक्रिया और कानूनी रूप से तय महंगाई के लक्ष्य के प्रति केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद की है। इस तरह भाजपा ने वृहद आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराकर अच्छा कदम उठाया है जो कि वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है।

दो अन्य जो महत्त्वपूर्ण वादे किए गए हैं, वे हैं- सांख्यिकीय संस्थानों को मजबूत करना और पंचायती राज संस्थाओं में राजकोषीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना। इन दोनों प्रतिबद्धताओं से शासन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में नीतिगत फैसलों के लिए यह जरूरी है कि आंकड़े समय से मिल जाएं। वैसे तो भारत के पास एक मजबूत सांख्यिकीय व्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था की मांगों की बदलती प्रकृति के साथ तालमेल बनाने के लिए इसमें व्यापक बदलाव करना होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय लेखा के आंकड़े काफी देर से मिलते हैं और इसमें कई बार बड़े संशोधन हो जाते हैं। इससे नीति निर्माण प्रभावित होता है और कारोबार के लिए फैसले लेने में ज्यादा कठिनाई होती है। सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार का एक अहम पहलू यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों को स्वतंत्र और भरोसेमंद बनाया जाए। समय से आंकड़े मिलने लगें तो फैसले करने की प्रक्रिया में सुधार होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारतीय शासन प्रणाली की एक वाजिब आलोचना यह होती है कि यहां सत्ता का पर्याप्त विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह है कि सरकार के तीसरे स्तर यानी स्थानीय निकाय, जो कि नागरिकों को कई तरह की सेवाओं की आपूर्ति बेहतर तरीके से कर सकते हैं, पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं हैं।

इस संबंध में, भाजपा के इस वादे का स्वागत करना चाहिए कि वह पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देगी, हालांकि यह कैसे होगा यह देखना अहम होगा। पिछले वर्षों में देखें तो कुछ संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के अलावा कुछ खास नहीं किया गया है। जैसा कि इस क्षेत्र के लिए पहले भी यह बात सामने आ चुकी है, अनुदान सहित हर पंचायत का औसत राजस्व साल 2022-23 में महज 21.23 लाख रुपये था। स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वायत्त और बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें संसाधन जुटाने में सक्षम बनाया जाए और उनके कोष का पूर्वानुमानित हस्तांतरण हो सके। एक संभावित तरीका यह हो सकता है, जिसके लिए कानूनी बदलाव करना होगा, कि उनको सीधे वित्त आयोग के जरिये संसाधनों का आवंटन किया जाए। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह से हासिल राजस्व का एक हिस्सा उन्हें देना भी एक विकल्प हो सकता है। भाजपा के अन्य वादों की बात करें, तो उसने कहा है कि सत्ता में वापस आने पर वह निवेश और बुनियादी ढांचा निर्माण पर जोर देना जारी रखेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार का सृजन होगा। भाजपा का इरादा विनिर्माण क्षेत्र में भी कई पहल करने का है जिससे नौकरियों का सृजन हो। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यापार नीति की समीक्षा करना उपयोगी हो सकता है। निर्यात में सतत तरीके से वृद्धि, आर्थिक विकास और नौकरियों के सृजन, दोनों लिहाज से एक बड़ा वाहक साबित हो सकता है। आर्थिक तर्क के साथ एक बड़ा राजनीतिक वादा 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का है। वैसे तो यह विचार नीतिगत अनिश्चितता को कम करने का वादा करता है, लेकिन उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सुझाए गए आगे के रास्ते पर बड़े पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए।

बिनय सिन्हा

नब्बे वर्ष के केंद्रीय बैंक का सराहनीय प्रदर्शन

जब केंद्रीय बैंक अच्छा प्रदर्शन करता है, जब वह सरकार समेत सभी अंशधारकों की सहमति से काम करता है, तो राजनीतिक सत्ता भी उसे उसका काम करने देना चाहती है। बता रहे हैं टी टी राम मोहन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 90 वर्ष की अवस्था में भी न केवल सुस्थिर बल्कि चपल और फुर्तीला नजर आ रहा है। ऐसे में उसे इस अवसर पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से उचित ही सराहना मिली। आर्थिक उदारीकरण की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका प्रदर्शन शानदार रहा है। बीते चार-पांच वर्षों में उसका प्रदर्शन खासा उल्लेखनीय है क्योंकि इस दौरान उसके समक्ष कई तरह की चुनौतियां आईं।

2020 में कोविड-19 संकट हमारे सामने आया। उस समय बैंकिंग व्यवस्था पहले ही फंसे हुए कर्ज से जूझ रही थी। 2019-20 में कुल कर्ज में इसकी हिस्सेदारी 8.5 फीसदी हो गई थी। फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अनिश्चित बनाया है। दो दशकों में वैश्विक वृद्धि अपने निचले स्तर पर गिर गई।

इस तनावपूर्ण समय में रिजर्व बैंक ने सभी क्षेत्रों में विश्वसनीय ढंग से काम किया। इसमें मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वित्तीय स्थिरता के प्रबंधन को सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2020 के महामारी संकट के बाद केवल साढ़े तीन साल में फंसा कर्ज 3.2 फीसदी पर आ जाना मामूली उपलब्धि नहीं है। समय के साथ वित्तीय स्थिरता में योगदान देने वाली कई नीतियां उभरीं। कुछ नीतियां महामारी से निपटने के क्रम में उबरीं। दोनों तरह की नीतियों पर नजर डालना उपयोगी है।

समय के साथ उभरी नीतियों में पहली है नियमन और निगरानी का एकीकृत तरीका। हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूबीसी) के एकीकृत नियमन की दिशा में पहल की है। इससे नियामक को इन कारोबारों के परस्पर संबंध को समझने और कमजोरियों को तत्काल भांपने में मदद मिलती है। दूसरा, रिजर्व बैंक ने हल्के विनियमन से परहेज किया है। वह इस बात में यकीन नहीं करता है कि जोखिम प्रबंधन का काम पूरी तरह बैंकों के बोर्ड और प्रबंधन पर छोड़ा जा सकता है। उसने जरूरत पड़ने पर विस्तृत पहल भी की है।

उदाहरण के लिए बैंकों के लिए लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। तीसरा, रिजर्व बैंक ने बैंक पूंजी के मामले में नियामकीय कर्व से आगे रहने का चयन किया। बेसल मानक जहां 8 फीसदी न्यूनतम पूंजी की बात कहते हैं, वहीं रिजर्व बैंक ने 9 फीसदी की जरूरत बतायी है। समझ यही है कि बैंकिंग में अधिक पूंजी का होना बेहतर है। चौथा, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी का नियमन सख्त किया है। उसका मानना है बड़ी और महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी को बैंकों में बदला जाना चाहिए और उन्हें सख्त नियमन के दायरे में लाया जाना चाहिए जो बैंकों पर लागू हैं। पांचवां, रिजर्व बैंक अन्य केंद्रीय बैंकों के उलट लंबे समय से विविध संकेतकों वाले रुख का इस्तेमाल कर रहा है। वह मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देता है। ये संकेतक परस्पर गति देते हैं। सभी संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर नतीजे हासिल करने में मदद मिलती है। छठा, बैंकों में निजी और विदेशी स्वामित्व को लेकर एक खाका है जहां किसी भारतीय में एक कंपनी या संस्था के स्वामित्व की सीमा बताई गई है। विदेशी बैंकों के लिए भी नीति है जहां अनुषंगी मार्ग से आने पर उनके साथ भारतीय बैंकों जैसा व्यवहार किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने महामारी के दौरान भी अनेक रचनात्मक प्रतिक्रियाएं दीं। इनमें से तीन का उल्लेख जरूरी है।

पहला कदम था कर्ज भुगतान पर छह महीने का स्थगन। विश्लेषकों का मानना था कि सभी इसका लाभ लेना चाहेंगे लेकिन केवल 40 फीसदी बकाया कर्ज के लिए यह सुविधा ली गई। जिन लोगों के पास नकदी की दिक्कत नहीं थी उन्होंने समय पर ऋण चुकाना सही समझा।

दूसरा, कॉर्पोरेट और पर्सनल लोन के पुनर्गठन की योजना पेश की गई। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि करीब पांच फीसदी बकाया कर्ज का पुनर्गठन करना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें से आधा अनचुकता रह जाएगा और फंसे हुए कर्ज में इजाफा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। औसतन कुल कर्ज का केवल 1.5 फीसदी पुनर्गठित हुआ। महज 0.2 फीसदी कॉर्पोरेट ऋण का पुनर्गठन हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पुनर्गठन के लिए सख्त मानक और निगरानी व्यवस्था तय की गई थी। इनके जरिये फर्जी मामलों को छांटा जाना था। जैसा कि हमने पहले भी कहा फंसे हुए कर्ज का स्तर बढ़ने के बजाय कम हुआ।

मई 2020 में सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करके इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) प्रस्तुत की। आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों को पूरी गारंटी वाली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की मदद से तीन लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त फंडिंग प्रदान की गई। कुछ लोगों ने इस योजना को भी एक और लोन मेले की तरह देखा जो बैंक में फंसा हुआ कर्ज बढ़ाने वाली थी। इस योजना के तहत दिए गए कुल कर्ज में 5 फीसदी फंसा कर्ज है। एमएसएमई में मार्च 2023 तक यह औसतन 6.8 फीसदी था। कई अर्थशास्त्री नियामकीय सहनशीलता को सही नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इसके अंतर्गत समस्या को भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने उन्हें गलत साबित किया। उसने यह दिखाया कि अगर नियामकीय सहनशीलता को सही ढंग से बनाया और क्रियान्वित किया जाए तो इससे सकारात्मक नतीजे हासिल हो सकते हैं।

बैंकिंग में बदलाव से अपेक्षित परिणाम निकले। सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात जो बैंकिंग संकट के दौरान जोर पकड़ गई थी वह कमजोर पड़ गई। इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार ही इसकी इकलौती वजह नहीं है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसे सरकारी बैंकों का इस प्रकार निजीकरण करना पड़े जिससे बैंकिंग की स्थिरता के लिए तैयार निजी और विदेशी स्वामित्व ढांचे के साथ समझौता करना पड़े।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के पद संभालने के पहले लगातार दो गवर्नरों की विवादास्पद विदाई हुई थी। उस समय भारतीय और विदेशी मीडिया में देश के केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता में कमी आने को लेकर कई तरह की बातें हो रही थीं। दास ने दिखाया कि रिजर्व बैंक जरूरी स्वायत्तता का इस्तेमाल कर सकता है और दुनिया भर में उच्च विश्वसनीयता हासिल कर सकता है। वह ऐसा बिना राजनीतिक प्राधिकार से भिड़े कर सकता है।

यहां एक अहम सबक है। स्वायत्तता कोई ऐसी चीज नहीं है जो केंद्रीय बैंक को आसानी से हासिल हो सके। जब केंद्रीय बैंक अच्छा प्रदर्शन करता है, सरकार सहित सभी अंशधारकों के हितों को ध्यान में रखता है तो राजनीतिक प्राधिकार उसे अपने तरीके से काम करने देता है और इस पर प्रसन्न होता है।

क्यों बरकरार है रोजगार निर्माण की समस्या?

अतार्किक विकल्प
देवाशिष बसु

मार्च के अंतिम सप्ताह में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर सकती है। उन्होंने इसके लिए बेरोजगारी का उदाहरण दिया। उन्होंने चकित करते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी के मोर्चे पर और लोगों को काम पर रखने के अलावा कर ही क्या सकती है? उन्होंने कहा, 'सामान्य तौर पर रोजगार देने का काम वाणिज्यिक क्षेत्र करता है।' दिसंबर तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8 फीसदी बढ़ा जबकि स्नातकों में बेरोजगारी की दर 40 फीसदी से अधिक है। रोजगारविहीन वृद्धि कोई नया विचार नहीं है। बीते 25 वर्षों में हर सरकार इससे जूझती रही है और इसमें दो कांग्रेसनीत गठबंधन सरकारें शामिल रही हैं। मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य ने इसी समाचार पत्र में अपने स्तंभ में कहा था कि सन 2000 के दशक के मध्य में भी मजबूत वृद्धि के बावजूद रोजगार में इजाफा नहीं हुआ था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्रियों और अफसरशाहों की टीम थी। सरकार और उसके बाहर के बेहतरीन मस्तिष्क वाले लोगों ने कई योजनाएं तैयार कीं जिनमें रोजगार गारंटी योजना भी शामिल है। परंतु इसका कोई खास लाभ नहीं हुआ। बेरोजगारी ऊंचे स्तर पर बनी रही। मोदी सरकार ने भी कई नीतियां पेश कीं लेकिन बेरोजगारी बनी रही। 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता पाने के लिए प्रचार अभियान चला रहे थे तो वह अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में युवाओं से कहते थे, 'आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए?' नवंबर 2013 में अपने आरंभिक चुनावी भाषणों में से एक में उन्होंने कहा था कि अगर वह सत्ता में आए तो हर साल एक करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। जनवरी 2018 में जब ज़ी टीवी ने उनसे इस वादे के बारे में पूछा तो मोदी ने कहा कि सड़क पर पकोड़े बेचने वालों को भी रोजगारशुदा लोगों में गिना जाना चाहिए और इस प्रकार देश में बेरोजगारों की संख्या काफी कम है। उनकी इस बात काफी मजाक उड़ाया गया जबकि उनके समर्थकों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उद्यमिता को लेकर सही टिप्पणी की है।

सरकार के लिए रोजगार तैयार करना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी एक वजह तो वही है जो नागेश्वरन ने कही, 'कारोबारी क्षेत्र को लोगों को काम पर रखना चाहिए।' लेकिन तब क्या उन्हें खुद से या वाणिज्यिक क्षेत्र से यह नहीं पूछना चाहिए कि वह अधिक रोजगार क्यों नहीं तैयार कर रहा? कारोबारी केवल किसी को काम देने के लिए काम नहीं देते। वे जरूरत पड़ने पर लोगों को काम पर रखते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि नेता, बाबू और रोजगार तलाशने वाले मशीनों के बजाय लोगों को काम पर रखने के ही हामी हैं। विनिर्माण और भवन निर्माण के कई काम अब मशीन से होते हैं और कारोबार के लिए यही उपयुक्त है। मनुष्यों को कौशल और बेहतर प्रबंधन की जरूरत होती है तथा किसी के काम छोड़ने पर नए लोगों की जरूरत होती है। यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन श्रम आधारित क्षेत्रों मसलन कपड़ा और सेवा क्षेत्र के लिए जरूरी भी है। निश्चित तौर पर यात्रा, परिवहन, स्वागत, स्वास्थ्य सेवा, सॉफ्टवेयर विकास, रखरखाव और मरम्मत, डिजाइन, फाइनैंस और मार्केटिंग के क्षेत्र में कुशल कर्मचारियों की कमी है। इन क्षेत्रों में कुशल लोगों के लिए रोजगार की कमी नहीं। ऐसे में क्या सरकारी नीतियां कारोबारियों को अधिक लोगों को काम पर रखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकतीं? यकीनन कर सकती हैं। यह बात हमें रोजगार रहित वृद्धि की दूसरी वजह की ओर ले आती है: 2014 के चुनाव के पहले मोदी ने रोजगार का वादा किया था लेकिन छह साल तक उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया। 2014 और 2020 के बीच उनकी पहलें सामाजिक क्षेत्र में रहीं। मसलनः स्वच्छ भारत, जन धन, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन, सॉइल हेल्थ कार्ड आदि।

इस अवधि की आर्थिक नीतियां मसलन मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा ऋण और स्टार्टअप इंडिया में नारेबाजी अधिक थी और रोजगार निर्माण पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। नोटबंदी एक तुगलकी योजना थी जिसने छोटे कारोबारों और रोजगारों को नष्ट कर दिया। आश्चर्य नहीं कि भारत की जीडीपी वृद्धि कोविड-19 के पहले गिरकर 5 फीसदी तक आ चुकी थी। ऐसा तब था जबकि जीडीपी के आकलन का तरीका बदलकर आंकड़ों में 1.5 से दो फीसदी तक का इजाफा कर दिया गया था। अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा। हड़बड़ाहट में आकर सरकार ने 20 सितंबर, 2019 में कॉर्पोरेट कर की दरों में नाटकीय कटौती की ताकि कारोबारी अधिक निवेश करें और रोजगार दें। यह कोशिश नाकाम रही क्योंकि कारोबारियों ने रुचि नहीं दिखाई।

बहरहाल, कोविड के बाद के दौर में जीडीपी वृद्धि में इजाफा हुआ और राजस्व में बढ़ोतरी हुई। सरकार के पास नई महत्त्वाकांक्षी नीतियां तैयार करने का अवसर था। इस बार उसने विकास योजनाओं पर जोर दिया और कई दिशाओं में एक साथ पहल कीं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। सरकार ने कोविड-19 के दौरान उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। उसके बाद रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति तथा रेलवे के आधुनिकीकरण की शुरुआत की गई। 2023-24 के बजट में सरकार ने अधोसंरचना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की असाधारण राशि आवंटित की।

रेलवे, रक्षा उत्पादन, सड़क-परिवहन, शहरी अधोसंरचना, पानी, बिजली आदि क्षेत्रों में क्रियान्वयन नजर आ रहा है। भारतीय वन अधिनियम में नुकसानदेह बदलाव तक किए गए ताकि कथित विकास के मार्ग की बाधा दूर की जा सके। यकीनन इससे रोजगार बढ़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि कारोबारी क्षेत्र रोजगार दे तो उसे कारोबारी सुगमता की लागत कम करनी होगी और चीन से सस्ते माल की आवक रोकनी होगी। सात साल पहले रोजगार निर्माण के मसले पर लिखते हुए मैंने कहा था कि सरकारों ने कारोबारियों का जीवन मुश्किल किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसी टीम हो सकती है जिसका इकलौता काम कारोबारियों के मन की बात सुनना हो कि आखिर क्यों उनकी लागत अधिक है और कारोबारी सुगमता मुश्किल। बार-बार सामने आने वाली समस्याओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्यों के साथ तालमेल में काम करना होगा। उक्त टीम कुछ श्रम आधारित परियोजनाओं की निगरानी करके गतिरोध का पता लगा सकती है और बदलाव सुझा सकती है। शायद हमें मोदी के बतौर प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में ऐसा देखने को मिले।

आखिरकार वह सामाजिक योजनाओं से विकास परियोजनाओं की फंडिंग तक का सफर तय कर चुके हैं। केंद्र से लेकर तालुका स्तर पर भ्रष्ट और विनाशकारी नीतियों से रोजगार निर्माताओं को आजाद करना तीसरा और अंतिम कदम है जिसकी आवश्यकता है।

(लेखक मनीलाइफडॉटइन के संपादक और मनीलाइफ फाउंडेशन में ट्रस्टी हैं)

आपका पक्ष

पर्यावरण के लिए समुद्र के तल में जमा प्लास्टिक खतरा

मानव की लापरवाही के कारण समुद्र भी आज काफी तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। एक अध्ययन से पता चला है कि समुद्र तल में एक करोड़ 10 लाख टन प्लास्टिक जमा हो गया है जो आज न केवल पर्यावरण बल्कि जैव विविधता के लिए भी गंभीर संकट बन चुका है। एक अध्ययन के अनुसार हर मिनट कचरे से भरे एक ट्रक के बराबर प्लास्टिक लगातार समुद्र में समा रहा है। शोधकर्ताओं का यह भी अनुमान है कि 192 देशों से निकला करीब 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष महासागर में समा रहा है। समुद्र में पहुंचने वाला करीब 80 फीसदी कचरा जमीन पर ठोस कचरे के कुप्रबंधन से जुड़ा है। शेष 20 फीसदी कचरे के लिए समुद्र तट के किनारे बसी हुई बस्तियां जिम्मेदार हैं। एक शोध बताता है कि हर साल पैदा होने वाला प्लास्टिक कचरा वर्ष 2060 तक करीब तीन गुना बढ़ जाएगा। एक अनुमान के अनुसार यह अगले 37 वर्षों में बढ़कर 101.4 करोड़ टन से ज्यादा हो जाएगा। दुनिया भर में समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे बड़े उत्सर्जक 10 देश हैं। इनमें सबसे अधिक से लेकर कम तक क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, फिलिपींस, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, मिश्र, मलेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया आते हैं।

एमएम राजावतराज, शाजापुर

एक अध्ययन के अनुसार समुद्र तल में एक करोड़ 10 लाख टन प्लास्टिक जमा हो गया है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है

ईरान-इजरायल संघर्ष से सबका नुकसान

ईरान के दूतावास पर मिसाइल हमले से उसके सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान ने खुले रूप से इजरायल को सबक सिखाने की घोषणा की है। रूस-यूक्रेन और हमास-इजरायल युद्ध के बाद ईरान और इजरायल के खुलकर युद्ध के मैदान में कूद जाने से अंतरराष्ट्रीय हालत जटिल हो गए हैं और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है तथा युद्धरत देशों की जनता के अलावा इसका प्रभाव विश्व की जनता भुगत रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। समुद्री यातायात अवरुद्ध हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, रूस, भारत और चीन को मिलकर इसके लिए कारगर प्रयास करने चाहिए कि इन देशों में तनाव नहीं बढ़े। भारत देश के लिए युद्ध के नए मोर्चे खुलाने से कई नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं और महंगाई के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति भी धर्मसंकट में पड़ गई है क्योंकि जिन राष्ट्रों से भारत के अच्छे संबंध हैं वे ही अगर आपस में युद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का तटस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

सोने पर लगाएं दांव

निवेश में जोखिम तो सदैव बना रहता है। बाजार का उतार-चढ़ाव निवेशकों को कभी नफा तो कभी नुकसान देता ही है। इस समय सोने के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं तो वैश्विक राजनीतिक उथल-पुथल के चलते शेयर बाजार में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल ही रहे हैं। ऐसे में दोनों में फायदे का सौदा ढूंढना मुश्किल काम है। फिर भी लोगों को अगर आज निवेश करना ही है तो सोने पर दांव लगाना चाहिए क्योंकि शेयर बाजार की तरह इसके भाव एकदम औंधे मुह नहीं गिरते।

अमृतलाल मारू रवि, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शिमला में आयोजित परेड का निरीक्षण किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 16 अप्रैल 2024

रेवड़ी से परहेज़

आगामी आम चुनावों के लिए रविवार को जारी BJP का घोषणापत्र इस मायने में आश्वस्त करने वाला कहा जाएगा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की लुभावनी घोषणाओं से प्रभावित हुए बगैर इसने विकास योजनाओं पर अपना जोर बनाए रखा है। इसमें सरकार के अब तक के काम और मोदी की विश्वसनीयता पर पार्टी का सबसे ज्यादा भरोसा दिखता है।

रेवड़ी कल्चर से परहेज | यह राहत की बात है कि मुफ्त एलानों को घोषणापत्र का अहम हिस्सा बनाने का ट्रेंड कुछ टूटता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ समय से जोर पकड़ रहे इस ट्रेंड को इकॉनमी के एक्सपर्ट्स तो खतरनाक बता ही रहे थे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकाधिक मौकों पर इससे आगाह किया था। दिलचस्प है कि कुछ विधानसभा चुनावों में BJP भी इस मामले में फिसलती दिखी थी। लेकिन इस बार पार्टी ने कड़ा रुख दिखाया। हालांकि इसी वजह से उसे कांग्रेस का यह आरोप भी झेलना पड़ा है कि उसके घोषणापत्र में गरीबों के लिए कुछ नहीं है।

BJP का घोषणापत्र

विकसित भारत | मुफ्त राशन योजना पांच साल जारी रखने की गारंटी जरूर दी गई है, लेकिन इसके अलावा पार्टी घोषणापत्र मुख्यतः सुधार कार्यक्रम और विकास योजनाएं जारी रखते हुए 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की ही बात करता है। ज्यादा IIT, IIM और AIMS बनाने, सस्ता आवास मुहैया कराने और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान के दायरे में लाने जैसी बातें हैं, जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के पार्टी के संकल्प को रेखांकित करती हैं।

आत्मनिर्भर भारत | रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता पर जोर इस घोषणापत्र की एक खास बात है। इसके तहत मिलिट्री थिएटर कमान स्थापित करने और सीमाओं पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट की बात कही गई है। घोषणापत्र से संकेत मिलता है कि दुनिया में भारत की साख मजबूत करने वाली मौजूदा सरकार की छवि पर पार्टी को भरोसा है और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में वह इसका इस्तेमाल करना चाहेगी।

पुराने वादों का हवाला | पार्टी के पुराने वादों की बात की जाए तो इसमें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और समान आचार संहिता (UCC) के साथ ही एक देश एक चुनाव का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। एक अहम तथ्य यह है कि इस बार नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) का कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान रहे, CAA को आम तौर पर NRC से जोड़कर देखा जा रहा था और इसके व्यापक विरोध का यह एक बड़ा कारण माना गया था।

भविष्य के सपने | कुल मिलाकर यह 'संकल्पपत्र' बताता है कि पार्टी ने पीएम मोदी के काम, उनकी छवि और अगले दो-ढाई दशकों के लिए देशवासियों को दिखाए उनके सपनों पर भरोसा किया है। यह भरोसा कितना कारगर है यह तो चुनाव नतीजों से साबित होगा, लेकिन फिलहाल इसे BJP के आत्मविश्वास का संकेत जरूर माना जा सकता है।

धूप-छांव

नया प्रतिद्वंद्वी

प्रणव प्रियदर्शी

संघर्ष कहिए या प्रतिद्वंद्विता या अस्तित्व बचाने की लड़ाई, सच है कि यह प्रकृति में हर तरफ दिखता है। यही हमें लगातार बेहतर भी बनाता चलता है। कोई न कोई प्रतिद्वंद्वी हमारा जरूर होना चाहिए। मनॉपली किसी भी तरह की हो, जीवन को बहते पानी जैसा नहीं रहने देती। हालांकि पिछले कुछ हजार वर्षों से इस दुनिया में इंसान की मनॉपली कायम हो चुकी है। नतीजा हम इंसानी जीवन की सुख-सुविधाओं में बेहिसाब बढ़ोतरी और बाकी पूरी दुनिया की निरंतर बिगड़ती शक्ल – कटते जंगल, घटते भूजल स्तर, हवा में फैलते जहर, पानी में बढ़ते प्रदूषण – के रूप में देख भी रहे हैं। पर करें क्या? हम अगर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं तो इसमें हमारी क्या गलती?

क्या इसी अहंकार ने हमें खुद ही अपना एक नया प्रतिद्वंद्वी रचने को प्रेरित किया है? जेनरेटिव AI भले कहने को हमारी ही बनाई एक मशीन भर हो, यह खुद को लगातार बेहतर किए जा रही है और हमारे लगभग सारे काम हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से कर दे रही है। यह ऐसा ही है जैसे नया आया एम्प्लॉयी आपसे कहे, 'बॉस आप बस हुक्म करो, मैं करता हूं न आपका हर काम।' और फिर धीरे-धीरे आपकी कोई जरूरत ही न रह जाए। अब यह हमें सोचने की भी जहमत नहीं दे रहा। इशारा भर करें तो नई तस्वीर, नया लेख, नई कहानी, नई नज्म हमारे सामने हाजिर कर देता है। तो क्या हम अमीरी की उस हास्यास्पद स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां जॉगिंग के लिए भी नौकर रखने की कल्पना की जाती है?

पर अगला सवाल है कि मशीन से बनी कोई तस्वीर, AI की लिखी कविता हमारे अंदर उसी तरह के भाव पैदा कर पाएगी, हमें वही संतोष दे पाएगी जो किसी चित्रकार या लेखक की कृति देती है? हम हाथ में उंगलियों के बीच फंसी अपनी कलम से लिखें या कंप्यूटर/ लैपटॉप/ मोबाइल पर की दबाते हुए, जब तक कंटेंट हमारा है, तब तक उस पर इंसानी छाप है। लेकिन एक इशारे पर मशीन उपन्यास लिखने लग जाए तो वह उपन्यास चाहे जितना भी उम्दा हो, एक पाठक के तौर पर वह हमें कितना संतुष्ट करेगा? आखिर किसी उपलब्धि की अहमियत तो उसके इंसानी जुड़ाव की ही उपज होती है। तेज दौड़ने का हो या ऊंची कूद का, हर रेकॉर्ड मायने इसलिए रखता है कि वह इंसानी क्षमता की नई हद तय करता है। मूक फिल्मों के दौर से चलकर हम वहां पहुंचे हैं कि कैमरे में तकनीक का बड़े से बड़ा कमाल भी असंभव नहीं लगता। लेकिन वहां भी इंसान की कल्पना, उसकी रचनात्मकता को ही आकार लेते देखते हैं। खुशी आखिरकार उसी की होती है।

क्या ऐसा कोई दौर आएगा जब हम AI की कृतियों पर खुशी की वही पुलक महसूस करेंगे? अगर हां तो हमारी मनॉपली को सचमुच खतरा है। अगर नहीं तो यह अभी कायम रहने वाली है।

बोल वचन

सिलबट्टे की चटनी

राहुल पाण्डेय

खट्टी कच्ची अमिया बाजार में आ गई हैं। ठेले वाले हांक लगा रहे हैं- चटनी बना लो, चाट-चाट के खा लो। जिनके यहां मिक्सर-ग्राइंडर है, उनमें से अधिकतर लोग आम देखकर आह भरते हैं कि काश, सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी होती! साथ में चाहे एक सूखी रोटी ही होती तो वो भी अमृत लगती! आज भी सबको मिक्सी में पीसी गई चटनी के सामने सिलबट्टे पर पिसी चटनी का स्वाद सपनों में आता है। सिलबट्टा है ही ऐसी चीज। उत्तराखंड में इसे सिल-लौढ़ कहते हैं तो महाराष्ट्र में पाटा-वरवंता। बंगाल इसे शिल नोरा पुकारता है तो ओडिशा सिल पुआ। साउथ इसे अम्मी कल्लू या अम्मी कल के नाम से पहचानता है तो दक्षिण अमेरिका इसे बेटन-उना पुकारता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बदरीनाथ में हर साल भगवान बदरी विशाल के अभिषेक के लिए तिल का जो तेल आता है, वह नरेंद्रनगर राजमहल में सिलबट्टे पर ही पिरोया जाता है। मानते हैं कि सिलबट्टे पर पिसी चीज में न केवल भूमि तत्व मिलते हैं, बल्कि मसालों को प्राणवायु भी मिलती है क्योंकि सिलबट्टे पर अक्सर चीजें खुले में ही पीसी जाती हैं। सिलबट्टा कोई आज की चीज नहीं है। आग से भी पहले इंसान ने तोड़ने, कूटने, फोड़ने के लिए पत्थर को पहचान लिया था। संसार की हर संस्कृति में सिलबट्टा है, अलबत्ता नाम अलग-अलग हैं। इंग्लिश में सिल को grinding stone और बट्टे को rolling stone कहते हैं, तो स्पेनिश में इसे molinos कहा जाता है। अमूमन पत्थर हरेक शहर के आसपास मिल जाते हैं, मगर राजस्थान के धौलपुर, हरियाणा के रोहतास, यूपी के चित्रकूट और उत्तराखंड में अल्मोड़ा की गगास नदी के किनारे जनरिया में पाए जाने वाले पत्थरों का सिलबट्टा विशेष स्थान रखता है। मगर इन सबसे ऊपर स्थान रखती है सिलबट्टे पर प्रेम से पीसी गई धनिया, पुदीना, मिर्च और आम की चटनी, जिसे चाटते ही बड़ी से बड़ी आह भी वाह में बदल जाती है।

Subrata Dhar

अभी तक जो संकेत मिले हैं, उन्हें देखकर यही लग रहा है कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं

इस्राइल पर ईरानी हमले का क्या होगा अंजाम

Israel

रहीस सिंह

बीते शनिवार की देर रात ईरान ने इस्राइल पर 300 से अधिक मिसाइलें और किलर ड्रोन दागे। ईरान के इस हमले ने मध्य-पूर्व में पहले से चले आ रहे युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया, जिसके प्रभाव व्यापक हो सकते हैं। वैसे यह संभावित था क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन तैयार हो गई थी, जब दमिश्क में ईरानी कॉन्स्युलेट पर हवाई हमला हुआ था। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई ने इस्राइल को दंडित करने की बात कही थी।

नया वॉर जोन | ईरान और इस्राइल लंबे समय से एक-दूसरे के विरुद्ध प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब यह प्रॉक्सी नहीं रह गया। हमले के बाद ईरानी सैन्य प्रमुख मेजर जनरल बाघेरी ने इस्राइल और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि यदि जवाबी कार्रवाई की गई तो अंजाम कहीं बुरा होगा। उधर, इस्राइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान को अंजाम भुगतना होगा। यदि ऐसा हुआ तो केवल मध्य-पूर्व ही नहीं, संभव है पूरी दुनिया एक नए 'वॉर जोन' में दाखिल हो जाए।

सतर्क था इस्राइल | ईरान और इस्राइल की दुश्मनी ऐसे तो खत्म नहीं हो पाएगी। इस्राइली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का कहना है, 'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमारा सिद्धांत है कि जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे।' यह बात भी गौर करने लायक है कि इस्राइल इस हमले के लिए तैयार था। अमेरिकी खुफिया तंत्र के हवाले से ब्लूमबर्ग ने पहले ही बता दिया था कि ईरान, इस्राइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों या ड्रोन से हमला कर सकता है। परिणाम यह हुआ कि इस्राइल ने बहुस्तरीय वायु-रक्षा प्रणाली से 90% हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन अगर दोनों तरफ से हमले बढ़ते हैं तो इस स्तर की सुरक्षा संभव नहीं हो पाएगी।

क्यों गंभीर है मामला

- युद्ध से जियो-पॉलिटिक्स में बदलाव
- जंग से इकॉनमी को भी होगा नुकसान
- 25% तेल सप्लाई बाधित हो सकती है

जोखिम उठाने की वजह | कुछ विश्लेषक ईरान को सचेत कर रहे थे कि यदि उसने इस्राइल पर मिसाइल या ड्रोन हमला किया तो यह उसके लिए जोखिम भरा होगा। फिर भी उसने हमला किया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उसने निर्णायक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रखी है?

छद्म युद्ध का सामना | दरअसल, ईरान लंबे समय से इस्राइल की तरफ से लड़े जा रहे एक छद्म युद्ध का सामना कर रहा है। वह केवल यहूदी धरती पर ही छद्म युद्ध नहीं लड़ रहा बल्कि एक और युद्ध लड़ रहा है, जिसके लिए मजबूत सैन्य एवं रक्षा तंत्र की जरूरत है। इस्लामी दुनिया शिया बहुल और सुन्नी बहुल में बंटी हुई है। पश्चिमी जगत पहले के साथ खड़ी दिख रही है।

सुन्नी बम का जवाब | जब पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया तो उसे सुन्नी बम कह गया। जवाब में ईरान भी 'शिया बम' बनाना चाहता था। वह उसके करीब पहुंच भी गया था लेकिन जुलाई 2015 में ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, रूस और अमेरिका ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर इस पर अल्पविराम लगा दिया। 2018 में अमेरिका के इससे बाहर होने की घोषणा ने उसे एक और मौका दे दिया। उसके बाद ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की जो सीमा करार में 3.67% तय की गई थी, उसे तोड़कर 2021 की शुरुआत में वह 20% तक चला गया था। यही नहीं, धीरे-धीरे वह 90% तक संवर्धन करने लगा, जो परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी होता है।

AI Image

IAEA की चेतावनी | इसे देखते हुए ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के डायरेक्टर जनरल रफाएल मैरियानो ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी महत्वाकांक्षा और क्षमता बढ़ रही है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि ईरान ने परमाणु क्षमता विकसित कर ली हो और अब फिजिकल रेस्पॉन्स के लिए भी तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के रुख की वजह तो समझना चाहते हैं, पर उससे उलझने से बच रहे हैं?

जटिल सैन्य तंत्र | दूसरा पहलू ईरान के जटिल सैन्य तंत्र का है। उसके पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़े आकार वाली सेना है। इंटरनैशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटिजिक स्टडीज के अनुसार, ईरान सशस्त्र बल में 5,80,000 एक्टिव जवान हैं। इसके साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर में विभक्त लगभग 2,00,000 प्रशिक्षित जवान सुरक्षित रखे गए हैं। ये जमीन, वायु और समुद्र में एक्टिव हैं। उसका कुद्स बल मध्य-पूर्व में लड़ाकू गुटों के एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है। देखा जाए तो यह ईरान का रीजनल कोऑपरेटिव फोर्स है, जो उसके लिए प्रतिबद्ध होकर लड़ता है। यही नहीं, ईरान ने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, स्पीडबोट और पनडुब्बियों के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है।

ग्लोबल इकॉनमी को नुकसान | बहरहाल, यह युद्ध जारी रहा तो न केवल भू-राजनीतिक समीकरणों को बदलेगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है ईरान होरमुज जलडमरूमध्य को बाधित करे। ऐसा हुआ तो दुनिया में तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। दुनिया में तेल की कुल खपत का लगभग 25% इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसका भारत सहित दूसरे देशों पर गहरा असर हो सकता है। भारत के दोनों ही देशों से कारोबारी रिश्ते हैं। बीते वर्ष भारत का दोनों देशों के साथ करीब 1.1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है।

पीछे हटना मुश्किल | ईरान और इस्राइल बीच संघर्ष इस समय 'ग्रे जोन' में है, जहां अभी कुछ भी साफ नहीं दिख पा रहा है। परंतु संकेत कुछ ऐसे हैं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने की मनःस्थिति में नहीं है। यानी अभी की स्थिति को देखते हुए माना जा सकता है कि इस्राइल पर ईरानी हमला एक शुरुआत भर है।

(लेखक विदेश मामलों के जानकार हैं)

कूल बनने की भूल : गर्दिश में आए सुनक के तारे

खरी-खरी

कहते हैं- जैसी करनी, वैसी भरनी। लगता है कि ब्रिटेन की किस्मत में अपनी करनी का फल भोगने का वक्त आ गया है। भारत समेत दुनियाभर में ब्रिटेन ने उपनिवेशों में जो लूट मचाई थी, अब वह अलग-अलग रास्तों से निकल रही है। मानो कुदरत ब्रिटेन से बदला ले रही है। विडंबना देखिए कि जिस भारत पर 200 बरस तक ब्रिटेन ने राज किया, लूटपाट मचाई, आज उसके सामूहिक दुख की वजह और कोई नहीं, ऋषि सुनक नाम का एक भारतीय मूल का व्यक्ति ही है। भारत का कोहिनूर वापस न करने वाले ब्रिटेन पर वक्त का बदला नहीं तो और क्या है!

आम तौर पर हर मसले पर बंटी हुई राय रखने वाले ब्रिटेन के लोगों में सिर्फ इस एक मुद्दे पर एकता नजर आती है और वह मुद्दा है सुनक! उन्हें नापसंद करने के मामले में लगभग पूरा देश एकमत है। वैसे तो गाहे-बगाहे वहां की जनता सुनक के खिलाफ अपनी नापसंदगी जाहिर कर ही रही थी, लेकिन पूरा देश इस कदर उनसे चिढ़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा नज़ारा देखने को मिला सुनक के एक इंटरव्यू के बाद। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू में Adidas Samba ब्रैंड के जूते पहन लिए। सफेद रंग के जूते नहीं, मानो गाज हो, जो सुनक पर गिर पड़ी। हालत यह हो गई कि कूल समझे जाने वाले उन जूतों पर ही लोगों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। उनका अंदाज़ जनता को इतना Uncool लगा कि लोग उस ब्रैंड के जूते को ही जूते मारने लगे। ब्रिटिश लोग नाक-भौं सिकोड़ने लगे कि अब सुनक जैसे बंदे ने ये पहन लिया तो ये Adidas Samba कूल नहीं रहा, हटाओ इसे। सच पूछिए तो यहां जूता बस एक रूपक है, वे तो हटाना चाहते हैं सुनक को। इस चक्कर में पुराने गिले-शिकवे भुलाकर पूरा ब्रिटेन एक हो गया है।

सुनक को ज्यों ही अंदाजा हुआ कि जूता नहीं, यह तो कोई बला है तो उन्होंने जनता से माफी मांग ली। वैसे राजनीति में जूतों का चक्कर पुराना है। आपको याद ही होगा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर एक इराकी पत्रकार ने जूता फेंका था। जूते से तो बुश साहब बच निकले, लेकिन 'परमाणु तकनीक और जनसंहार के हथियारों' का झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने इराक पर जो हमला किया था, वह उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला।

सुनक के लिए भी Adidas Samba प्रकरण राजनीतिक संदेश लेकर आया है। जैसे आपने message in a bottle सुना होगा, वैसे ही यह message in Shoes है। मेसेज यह कि सुनक और उनकी पार्टी की अगले चुनाव में हार तय है। ब्रिटिश पब्लिक की उनसे नाराजगी की कई वजहें हैं। एक तो यही कि अभी तक ब्रिटेन में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें सुनक सबसे अमीर बताए जाते हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति तो क्वीन से भी ज्यादा दौलतमंद हैं।

Uday Deb

दूसरी बात के तार सुनक के लड़कपन से जुड़ते हैं। तब उन्होंने कहा था कि उनका कोई दोस्त वर्किंग क्लास से नहीं है। अगर इसे जबान का फिसलना भी मान लिया जाए तो सुनक ने ऐसा कहकर सारी हदें पार कर दीं। खैर, अब वह पीएम हैं और अमीर पीएम का देश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। और तो और, जिस भारत को अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलाम बनाए रखा, अपनी तिजोरी यहां की दौलत से भरते रहे, आज वही भारत ब्रिटेन से बड़ी इकॉनमी बन चुका है।

यह भी विडंबना ही है कि आज भारतीय मूल के सुनक ब्रिटेन की सत्ता में शीर्ष पर हैं। ऐसे में जनता को मौका मिला तो वह सुनक पर शुरू हो गई। उसे लग रहा है कि सुनक ने उसके गरीबी के घावों पर जूता मारा है। अब उन्हें कौन समझाए कि एक भला आदमी, जिसने गरीबी देखी नहीं, वह बस थोड़ा गरीब बनने की कोशिश में है ताकि बाकी गरीबों के साथ घुल-मिल सके।

सुनक ही नहीं, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी भी जनता की नजरों में खलनायक बनी हुई है। हालिया सर्वे बताते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने 14 बरसों के कंजर्वेटिव शासन का अंत करने का मन बना लिया है। सुनक ने 18 महीने पहले सत्ता संभाली थी और तब से पार्टी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है। उनके दिन इतने बुरे चल रहे हैं कि वह जो भी काम करने जाते हैं, उसी में 'जूते' पड़ जाते हैं। शरणार्थियों वाले मसले को ही ले लीजिए। सरकार रवांडा प्लान लेकर आई थी, लेकिन ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया। रवांडा को ढाई हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भी देनी पड़ी और एक भी शरणार्थी ब्रिटेन से रवांडा नहीं गया।

सुनक का हुनर कुछ ऐसा है कि काम को छोड़कर उनकी बाकी सारी बातें हेडलाइन बन जाती हैं। कभी उनकी पत्नी अक्षता पत्रकारों को हजारों रुपये कीमत वाले कप में चाय परोस कर महंगाई से त्रस्त अंग्रेजों के दिल जला देती हैं, तो कभी वह खुद ग्रीक पीएम से भिड़ जाते हैं। इसीलिए इंतजार कीजिए कि अगला जूता किस बात पर चलता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सेना में भर्ती का पुराना तरीका सही, अग्निवीर जैसा बड़ा बदलाव अचानक करना ठीक नहीं

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

राजस्थान की बाड़मेर-जैसलमेर लोकसभा सीट से विधायक रवींद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी रैली के कई विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक वक्त BJP के साथ रहे भाटी ने पहले बगावत करके निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। अब वह लोकसभा में पहुंचने की दौड़ में हैं। **रवींद्र सिंह भाटी** ने इस सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। उनसे बात की **पूनम पाण्डे** ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :

■ आप BJP में रहे हैं, बगावत करके निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपकी विचारधारा क्या BJP की विचारधारा है?

राजनीति में कई सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। ऐसे में हर बार मुझे ही टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं देश के साथ हूं। जो देश के लिए, मेरे लोगों के लिए ठीक रहेगा, मैं उसके साथ रहूंगा।

■ विचारधारा का नहीं बताया...

मैं BJP की विचारधारा के साथ हमेशा से था। 2019 में जब मैंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा, उस वक्त मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में था और ABVP से टिकट चाह रहा था। लेकिन नहीं मिला। तब निर्दलीय लड़ा। 2023 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे, उससे पहले मैंने BJP जॉइन की थी, लेकिन तब भी टिकट नहीं मिल पाया। वैचारिक रूप से जो देश के लिए सही होंगे, उनके साथ रहूंगा।

■ आपने ABVP का जिक्र किया। आप उसमें रहे हैं, जो RSS का छात्र संगठन है। RSS में हमेशा अनुशासन की बात होती है। आपका बगावत करके निर्दलीय लड़ना क्या माना जाए? क्या जब आप ABVP में थे, तब अनुशासन की कमी रही?

अनुशासन की कमी नहीं थी। युवाओं का आदेश था और उस आदेश को मैंने पूरा किया। मेरा राजधर्म यह कहता है कि जो जनता का आदेश है उसका पालन करूं। मैंने वही किया। मेरे साथ उनका आशीर्वाद रहा, उनका सहयोग रहा। चुनाव जीता भी, लोगों के लिए काम भी किया, आगे भी करता रहूंगा।

■ अगर आप निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो क्या उसके बाद BJP में शामिल हो सकते हैं?

यह उस समय की परिस्थितियां तय करेंगी। मेरे क्षेत्र के लिए जो बेहतर होगा वह करूंगा।

■ BJP ने आपके एक पोस्टर की शिकायत की थी, जिसमें पीएम मोदी की फोटो का इस्तेमाल किया गया था। क्या मसला था?

मुझे नहीं पता कि वो कौन सा पोस्टर था। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट चलती रहती हैं। जब तक कोई वेरिफाई सोर्स से न आए, तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए। वह सोशल मीडिया पर कोई प्लांड ट्रैप था और मैं यही निवेदन करूंगा सभी से कि ऐसी भ्रामक चीजों से बचें।

■ निर्दलीय चुनाव जीतने पर क्या आप उस तरह से अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर पाएंगे, जैसे एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद कर सकते हैं?

बिल्कुल, मैं मजबूती से काम कर पाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है। सबको साथ में लेकर मैं आने वाले वक्त में और अच्छे से काम कर सकता हूं।

■ अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं, BJP उम्मीदवार से या कांग्रेस उम्मीदवार से?

मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जनता का आशीर्वाद साथ में रहेगा और आने वाले समय में और अच्छे तरीके से काम करूंगा।

■ आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं?

मेरा क्षेत्र है बाड़मेर-जैसलमेर, जो आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी यहां पानी की दिक्कत है। मल्टिनैशनल कंपनी, क्रूड ऑयल, मिनरल्स पर हम टॉप पर हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। पर हमें कुछ नहीं मिलता। यूथ बेरोजगार हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां आने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जिन चीजों से हम वंचित हैं मैं उन पर काम करूंगा, और आने वाले वक्त में सभी मूलभूत जरूरतें आम जनता तक पहुंचाऊंगा।

■ आपके लोकसभा क्षेत्र के लोग आपको वोट क्यों दें?

इसलिए दें क्योंकि इस बार आप किसी नेता को नहीं, अपने बेटे को चुन रहे हैं। आपका छोटा भाई मजबूती से आपकी बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखकर आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ेगा, जैसा हमेशा लड़ता आया है।

■ राजस्थान से भी बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। अग्निवीर मसले पर आप क्या सोचते हैं?

सेना में भर्ती का जो पहले तरीका था, वह सही था। अग्निवीर जब आया तो इतना बड़ा बदलाव अचानक से ले आए, यह सही नहीं था। बदलाव के भी तरीके होते हैं। राजस्थान से सटा 60% इंटरनैशनल बॉर्डर मेरे क्षेत्र में आता है। युवा सेना में जाकर चार साल में वापस आ जाएंगे, उससे अच्छा होता कि वे लंबे वक्त तक सेना में रहकर देश की सेवा करते। लेकिन जब केंद्र सरकार ने फैसला ले ही लिया है, तो सबको मिलकर साथ में चलना चाहिए।

■ आप प्रचार के लिए अपने क्षेत्र से बाहर दूसरे इलाकों में भी जा रहे हैं, क्यों?

मैं मारवाड़ क्षेत्र से आता हूं। यहां के बहुत लोग प्रवासी के रूप में बाहर रहकर व्यापार करते हैं। अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद- हर जगह हमारे लोग व्यापार की दृष्टि से पहले से हैं। वे चुनावी रूप में भी सक्रिय रहते हैं। क्षेत्र के विकास में भी भागीदारी रहती है। मैं उनसे समर्थन की अपील करने गया था।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ युद्ध रुकने चाहिए

यह पत्र 15 अप्रैल के संपादकीय 'युद्ध फैलने का खतरा' से संबंधित है। ईरान के दूतावास पर मिसाइल हमले से उसके सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान ने खुले रूप से इस्राइल को सबक सिखाने की घोषणा कर दी थी। शनिवार देर रात उसने इस्राइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर भी दिया। डर है कि दोनों देशों में बाकायदा युद्ध न शुरू हो जाए। यह अच्छा संकेत नहीं है। दुनिया पहले ही दो युद्ध झेल रही है। इन युद्धों का प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ रहा है। अमेरिका, भारत और चीन जैसे बड़े देशों को आपसी मतभेदों के बीच से गुंजाइश निकालते हुए इन युद्धों को जल्द से जल्द बंद करवाने का प्रयास करना चाहिए।

सुभाष बुडावन वाला, ईमेल से

■ जागरूकता बढ़ाना जरूरी

13 अप्रैल के संपादकीय 'फ्री में चेक हो BP' पढ़ा। हमारे देश में हृदय रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अपने ब्लड प्रेशर की जानकारी नहीं होती। फ्री ब्लड प्रेशर चेक होने से लोगों में तेजी से जागरूक बढ़ेगी। और कई स्तरों पर उन्हें फायदा मिलेगा। हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी रोग जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इन बीमारियों का प्रसार रोकने में भी इससे आसानी होगी।

प्रतिभा रावत, ईमेल से

■ साझा अजेंडा

चुनावों का दौर है। हर तरफ घोषणाओं का शोर है। हर दल अपनी भावी योजनाओं की घोषणा कर रहा है। ऐसे में एक बात समझ नहीं आती कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का घोषणापत्र कहां है। इस गठबंधन में शामिल सभी दल अपना-अपना मेनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। कोई तीस लाख नौकरियों की बात कर रहा है तो कोई एक करोड़ की। इनमें कोई आपसी तालमेल ही नहीं दिख रहा। जब इस गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ना तय किया तो वोटरों के सामने अपनी बात भी तो एक साथ मिलकर रखना चाहिए था। और कुछ नहीं तो न्यूनतम साझा कार्क्रम ही पेश कर देते। लोगों को पता तो चलता कि ये इकट्ठा मिलकर सत्ता में आए तो किस अजेंडे पर आगे बढ़ेंगे।

इंद्रसिंह धिगान, किग्जवे कैंप

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

पाकिस्तान में सरबजीत के हत्यारे का हुआ मर्डर – एक खबर
– शायद इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी!

कपिल राण

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

सच को समझना है तो अंधविश्वास का पर्दा हटाना होगा

आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

एक असली चीज जो कि कल्पना से परे है, उसे कल्पना में मान लेना ही अंधविश्वास है। भगवान चूंकि मन, बुद्धि, कल्पना से परे है और हम उसे कल्पना से मानते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। कल्पना उस चीज की कर सकते हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। लेकिन जो अस्तित्व में है, चैतन्य है, उसकी कल्पना करने का क्या तुक? भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है, 'तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। मैं सबकी आत्मा में निवास करता हूं और ज्ञान से बोध प्राप्त कर मुझे प्राप्त किया जा सकता है।'

एक फकीर एक बंजारे की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने बंजारे को एक गधा भेंट में दिया, कि वह कुछ कमा सके। उस गधे को पाकर बंजारा बहुत खुश हो गया क्योंकि अब न तो उसे बोझ ढोना पड़ेगा और न ही पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन एक समय लंबी यात्रा के बीच वह गधा बीमार पड़ गया और परलोक सिधार गया। बंजारे ने एक गड्ढा खोदकर मृत गधे को दफना दिया और वहीं बैठकर रोने लगा। इतने में एक यात्री वहां से गुजरा।

उस यात्री ने बंजारे को रोते देखा और मान लिया कि किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वह थोड़ा सा झुकता है और वहां कुछ पैसे चढ़ा देता है। यह देख बंजारा हैरान हुआ। पर जल्द ही उसे ख्याल आया कि इस तरह दूसरे यात्री भी आएंगे, पैसा चढ़ाएंगे तो उसका अच्छा खासा धंधा हो जाएगा। अब वह नित्य प्रति वहां आता, वहां बैठकर रोने का ड्रामा करता। लोग आते, नतमस्तक होते और पैसा चढ़ाते। अब उसने उस स्थान को एक कब्र का रूप दे दिया। गांव-गांव खबर फैल गई कि किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप गधे की कब्र ही महान व्यक्ति की समाधि बन गई।

एक रोज वही फकीर वहां दर्शन करने पहुंच जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि यह वही बंजारा है, जिसको मैंने गधा दिया था। फकीर को देखते ही बंजारे ने कहा, 'यह उसी गधे की कब्र है, जो आपने मुझे दिया था। जीते जी तो उसने सेवा की ही, मरने के बाद भी सेवा कर रहा है।' फकीर ने हंसते हुए कहा, 'वहां भी ऐसे ही है जिस गांव में मैं रहता हूं। वहां पर भी महान व्यक्ति की कब्र है। तुझे पता है वह कौन है? अरे भाई, वह इसी गधे की मां की कब्र है।'

धर्म या ईश्वर के नाम पर इसी प्रकार का अंधविश्वास है लोगों में। बिना कुछ सोचे-समझे, जैसा औरों को देखते हैं वैसा करते हैं। कभी उसके मर्म को समझने की कोशिश नहीं करते। बतौर कबीर- तेरा साईं है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। तुम्हारा असली भगवान तुम्हारे ही अंदर है, जो कि जीता-जागता है। अपने उस भगवान के भी तो दर्शन करने चाहिए। असली तीर्थ भी तुम्हारे ही अंदर है। वहां जाना चाहिए और परमानंद को प्राप्त करना चाहिए। सचमुच में अगर आप दुविधा से बचना चाहते हैं तो अंतर्मुखी होइए और उस चीज को पहचानिए जो आपके अंदर है।

तो मित्रो! सोचो, समझो और विचार करो कि हमारे पूर्व संत-महात्माओं ने क्या कहा है? ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में आग। त्यों तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। यदि हम अपने आप नहीं जान पा रहे हैं तो सतगुरु की मदद लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कहा है- गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपनी, जिन्ह गोविंद दियो बताय। इसलिए गुरु की महिमा का गुनगान गाया जाता है।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

कल्पमेधा

धनी होने का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं है। वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, जो इमानदारी के रास्ते पर अडिग है।

– विलियम एलेरी

वादे और इरादे

राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्र एक प्रकार से उस दल के विभिन्न मुद्दों पर दृष्टिकोण और वचनबद्धता का दस्तावेज होते हैं। उनके आधार पर लोगों को यह निर्णय करने में मदद मिलती है कि किस पार्टी की सरकार उनके हितों के लिए काम करेगी। लगभग सभी पार्टियां अपने घोषणापत्र जारी कर चुकी हैं। भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसका लोगों को काफी समय से इंतजार था। इसलिए कि सत्ताधारी दल की घोषणाओं पर सबसे अधिक नजर रहती है। भाजपा अपने घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' कहती है, इस बार उसमें 'मोदी की गारंटी' पद और जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री कई महीनों से सार्वजनिक मंचों से कुछ कार्यों और योजनाओं की गारंटी का एलान करते आ रहे हैं। वे बातें संकल्प पत्र में भी शामिल कर ली गई हैं। इसमें पिछले संकल्प पत्रों में किए गए वादों को पूरा करने का भी उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद तीन सौ सत्तर, राम मंदिर आदि शामिल हैं। मगर अगली सरकार में ज्यादातर पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ाने और उनका दायरा विस्तृत करने पर जोर है। मसलन, आयुष्मान योजना, जन औषधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, लखपती दीदी, अगले पांच साल तक मुफ्त राशन आदि।

इस पर विपक्ष ने यह कहते हुए निशाना साधना शुरू कर दिया है कि संकल्प पत्र में उन बुनियादी वादों को बड़ी चतुराई से छिपा दिया गया है, जो पिछले चुनावों में किए गए थे। इसके उदाहरण के रूप में वे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल, पहले ही कार्यकाल में भाजपा ने हर वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वह वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। बेरोजगारी का स्तर चिंताजनक बन चुका है। भाजपा ने अपने ताजा संकल्प पत्र में भी दोहराया है कि उसके कार्यकाल में पच्चीस करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, मगर सच्चाई यह भी है कि करीब बयासी करोड़ लोग मुफ्त राशन पर गुजारा करने को अभिशप्त हैं। अगर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते, तो लोग खुद मेहनत करके कमाते और खाते। महंगाई से पार पाने में भारतीय रिजर्व बैंक के पसीने छूट रहे हैं। किसानों की आय अगर सचमुच दोगुनी हो गई होती तो इस तरह आंदोलन न खड़े होते, जिन पर काबू पाने के लिए सड़कों पर दीवारें खड़ी करनी पड़ीं और आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े।

हालांकि विपक्ष के इन आरोपों के जवाब में भाजपा विकास का जो नक्शा पेश कर रही है, उसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए गारंटीशुदा योजनाएं हैं। संकल्प पत्र में युवाओं के लिए आधारभत ढांचे, विनिर्माण, स्टार्टअप, खेल, निवेश, उच्चस्तरीय सेवाओं और पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करने का नक्शा है। विपक्ष का कहना है कि सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्तियां करने का बजाय भाजपा निजी उद्यम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिला रही है। इस तरह विकास की क्या सूरत बन सकती है? संकल्प पत्र में कही बातों के अलावा चुनावी मंचों से जो बातें कही जा रही हैं, वे अलग हैं। एक देश, एक चुनाव और समान नागरिक संहिता पर बल है। भ्रष्टाचार मिटाने पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। मगर भ्रष्टाचार के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर खुद सरकार के कामकाज पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। देखना है, पक्ष और विपक्ष के इन विश्लेषणों से परे संकल्प पत्र आम मतदाता पर कितना प्रभाव छोड़ पाता है।

बढ़ता खतरा

उच्च शिक्षा या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने वाले भारतीयों के लिए कनाडा और अमेरिका आकर्षक विकल्प होते हैं। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी वहां जाते हैं। मगर हाल के वर्षों में अमेरिका और कनाडा में भारतीयों पर हिंसक हमले और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, उससे एक चिंता का वातावरण बन गया है। खबर के मुताबिक, पिछले हफ्ते शुक्रवार को हरियाणा के सोनीपत से कनाडा के वैंकूवर गए एक छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इस घटना के संबंध में अब तक जो ब्योरा सामने आ सका है, उसके मुताबिक जान गंवाने वाले छात्र की किसी से दुश्मनी नहीं थी और घटना के कुछ ही देर पहले उसने अपने परिवार से खुशी-खुशी बात की थी। कुछ दिन पहले कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एक निर्माण कारोबारी की सरेआम गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

सवाल है कि आखिर क्यों बिना किसी वजह के भी भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है? कनाडा की कानून व्यवस्था ऐसी क्यों हो गई है कि अपराधी जहां चाहें, किसी की हत्या करके फरार हो जा रहे हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो रहा है? माना जाता है कि कनाडा में कानून व्यवस्था इस कदर चौकस है कि कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी काम करके आसानी से नहीं बच सकता है। मगर हकीकत यह है कि सड़क किनारे सोनीपत के युवक की हत्या करके अपराधी गायब हो गए और पुलिस के लिए उनका पता लगा पाना चुनौती बन गया। कनाडा में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर वहां की सरकार इतनी संवेदनशील हो गई कि उसमें भारत का हाथ बताया। मगर आए दिन सामान्य भारतीयों की हत्या या उन पर हमले को लेकर कनाडा सरकार उतनी ही संवेदनशील क्यों नहीं दिख रही? अमेरिका में भारतीयों पर हुए हमलों या उनकी हत्या के पीछे तो नस्लीय दुराग्रह के संकेत भी देखे गए। कनाडा अपनी उदार आप्रवासन नीति के तहत भारतीयों को आकर्षित करता है। लेकिन अब जिस तरह भारतीय मूल के लोगों की जिंदगी वहां असुक्षित होती जा रही है, वह गहरी चिंता का विषय बन गया है।

अंग प्रत्यारोपण का अमानवीय संजाल

मानव अंग के कारोबार में संलिप्त गिरोह बहुत सुनियोजित तरीके से गरीब और असहाय लोगों को बहुत मामूली रकम की एवज में जीते-जी अपने अंग बेचने को तैयार कर लेते हैं।

देवाशीष प्रसून

पूरी दुनिया में हर साल करीब डेढ़ लाख से अधिक मानव अंगों का प्रत्यारोपण होता है, जबकि इसकी चाहत रखने वाले लोगों की गिनती पंद्रह लाख से अधिक है। भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 में लागू हुआ। उसके बाद मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अलबत्ता मानव अंग के कारोबार में संलिप्त गिरोह बहुत सुनियोजित तरीके से गरीब और असहाय लोगों को बहुत मामूली रकम की एवज में जीते-जी अपने अंग बेचने को तैयार कर लेते हैं। हालांकि कई बार पीड़ितों को तय की गई धनराशि नहीं मिलती और उन्हें वादाखिलाफी और ठगी का दंश झेलना पड़ता है। हाल में ऐसे ही एक गिरोह का पता चला, जिसके तार बांग्लादेश से लेकर झारखंड होते हुए गुरुग्राम और जयपुर से जुड़े थे। यह गिरोह बांग्लादेश के गरीब लोगों को जीते-जी अपना गुर्दा बेचने के लिए तैयार करता था। फिर उन्हें गुरुग्राम लाया जाता, कुछ दिन वहां ठहराकर उन पर तमाम तरह की चिकित्सीय जांच होती और किडनी प्रत्यारोपण के लिए उन्हें जयपुर ले जाया जाता, जहां दो बड़े अस्पतालों में उनके स्वस्थ अंग निकाल कर किसी अमीर व्यक्ति के बीमार शरीर में लगा दिया जाता था।

कुछ मरीज जीने की लालसा में कानून तोड़ने और अंग प्रत्यारोपण के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, भले इस प्रक्रिया में कमजोर और गरीब लोगों का भीषण शोषण होता हो। 'ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी' द्वारा 'वैश्विक अपराध और विकासशील विश्व' विषय पर मार्च 2017 में प्रकाशित एक रपट में मानव-अंगों के वैश्विक वार्षिक अवैध कारोबार को करीब 84 करोड़ से 1.7 अरब अमेरिकी डालर का आंका गया, जिसमें हर वर्ष अवैध रूप से करीब बारह हजार अंग प्रत्यारोपण कराया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2007 में प्रकाशित एक शोध-प्रबंध के अनुसार भारत में 305 लोगों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि अपना गुर्दा बेचने में उनतीस फीसद स्त्रियां और इकहत्तर फीसद पुरुष शामिल थे। उनमें 60 फीसद स्त्रियां और 95 फीसद पुरुष दिहाड़ी मजदूरी या रेहड़ी-पटरी पर श्रम आधारित कारोबार करते और कुल मिलाकर 71 फीसद लोग गरीबी रेखा से बेहद नीचे रहने वाले थे। अंगदान के बाद 86 फीसद लोगों ने अपनी सेहत में लगातार गिरावट महसूस किया था। 96 फीसद अंग विक्रेताओं ने कर्ज चुकाने के लिए अपना गुर्दा बेचा था। बावजूद इसके, इस सर्वेक्षण के मुताबिक उनमें से तीन-चौथाई लोग कर्जमुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता लगातार कम होती जा रही थी और वे पहले की तरह मजदूरी कर कमाने के काबिल नहीं बचे थे।

अंग प्रत्यारोपण के दौरान चिकित्सीय और साफ-सफाई के घटिया इंतजाम की वजह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआइवी जैसी बीमारियों का खतरा भी अंगदाताओं के सामने मंडराता रहता है। अंग बेचने से होने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा सर्जरी के बाद देखभाल के घोर अभाव के कारण होने वाले अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों के कारण अंगदाताओं का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता चला जाता है। जाहिर है कि जिनकी देह से अंग निकाला जाता है, उनकी सेहत की भरपाई किसी भी तरह, कभी भी नहीं हो पाती है।

विभिन्न रपटों के विश्लेषण से पता चलता है कि मानव अंगों में सबसे अधिक बिकने वाला अंग गुर्दा या किडनी है, जिसकी कीमत तेरह सौ से डेढ़ लाख अमेरिकी डालर है। इसके बाद औसतन चार हजार से लेकर 1.57 लाख अमेरिकी डालर तक की कीमत पर उपलब्ध लीवर दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला अंग है। इनके अलावा नेत्रपटल, अनिषेचित मानव अंडे, रक्त, त्वचा, अस्थियों और अस्थि-बंधनों की भी मांग बनी रहती है। हृदय और फेफड़ा जैसे महत्त्वपूर्ण अंगों की तो बहुत अधिक मांग है, इसलिए इनकी कीमतें भी बहुत अधिक हैं, पर प्रत्यारोपण सर्जरी की परिष्कृत प्रकृति और तकनीकी जटिलता के कारण इनका अवैध कारोबार कम ही होता है।

> विभिन्न रपटों के विश्लेषण से पता चलता है कि मानव अंगों में सबसे अधिक बिकने वाला अंग किडनी है, जिसकी कीमत तेरह सौ से डेढ़ लाख अमेरिकी डालर है। इसके बाद औसतन चार हजार से लेकर 1.57 लाख अमेरिकी डालर तक की कीमत पर उपलब्ध लीवर दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला अंग है। इनके अलावा नेत्रपटल, अनिषेचित मानव अंडे, रक्त, त्वचा, अस्थियों और अस्थि-बंधनों की भी मांग बनी रहती है। हृदय और फेफड़ा जैसे महत्त्वपूर्ण अंगों की तो बहुत अधिक मांग है, इसलिए इनकी कीमतें भी बहुत अधिक हैं।

गैर-कानूनी अंग प्रत्यारोपण में भेदभाव से जुड़ा एक और चिंताजनक आयाम यह है कि अमूमन स्वस्थ अंगों की बिक्री सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग करते हैं और इसके लाभार्थी अक्सर संपन्न लोग होते हैं। इस प्रवृत्ति का खुलासा कई स्तरों पर होता है- मसलन, विकासशील देशों के लोग अंगदाता होते हैं और विकसित देशों के लोग प्राप्तकर्ता। महिलाएं अंग देनेवाली होती हैं और लेनेवाले पुरुष। मसलन, अश्वेत लोगों से गुर्दा, जीवित ऊतक या लीवर आदि लेकर गोरे लोगों में लगाया जाता है। बड़े शर्म की बात है कि अफ्रीकी, दक्षिण एशियाई या फिलिपिनो लोगों के गुर्दा के मुकाबले तुर्किए या पेरू मूल के लोगों का गुर्दा कई गुना महंगा है। मानो, मानव अंग न हुआ, अलग-अलग नस्लों की भेड़-बकरियां हों।

'वर्ल्ड किडनी फोरम' के दिसंबर 2009 अंक में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 5.4 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 98 देश, जो दुनिया की तत्कालीन आबादी का 82 फीसद हिस्सा थी, पर हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2004 में किडनी प्रत्यारोपण के 10 फीसद मामलों में विकसित देशों के मरीजों ने आर्थिक रूप से विपन्न राष्ट्रों के अंगदाताओं से स्वस्थ गुर्दा की खरीदारी की थी। इस अध्ययन के अनुसार, पाकिस्तान, भारत और तुर्किए जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े देशों ने दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय 'किडनी बाजार' होने की अप्रिय प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी, जहां महज पंद्रह हजार से लेकर डेढ़ लाख अमेरिकी डालर तक के पैकेज में गुर्दा प्रत्यारोपण का धंधा जोरों पर चल रहा था। कीमतें मांग और आपूर्ति के बाजार नियम से संचालित होती हैं, जिसकी बोलियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगती हैं। 2007 में पाकिस्तान से 2500 गुर्दे बिके, जिनके दो-तिहाई खरीदार विदेशी थे। भारत में भी 2008 में अरबों रुपए का 'किडनी घोटाला' सामने आया था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीबों से गुर्दा लेकर यूएस, यूके, कनाडा, सऊदी अरब और ग्रीस के ग्राहकों में प्रत्यारोपित किया गया था।

अंगों की कालाबाजारी में मनुष्यता का यों पतन कर उसे ऐसे जानवरों की तरह बना देना, जिसके अंगों का खरीद-बिक्री खुले बाजार में होती हो, मानवाधिकारों का घोर अपमान है। अंगों के कालाबाजारी की आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते उपजी गोपनीयता के कारण वर्तमान हालात के बारे में कोई सटीक ताजा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, फिर भी पुराने आंकड़ों से हम इस धंधे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा, अंगदाताओं की ऐसी करुण-कथा के मद्देनजर आज आवश्यक हो गया है कि इस तरह के मामले में निजी स्वार्थों से ऊपर उठ कर इंसानियत के मूल्यों की रक्षा की जाए और अपने जीवन की तरह लोग दूसरों के जीवन के प्रति भी संवेदनशील बनें। विचारणीय है कि स्वार्थवश किसी मजलूम की मजबूरियों का फायदा उठा कर अगर कोई अपनी धनशक्ति की बदौलत दूसरों के अंग छीनकर दो-चार साल की उम्र बढ़ा भी ली जाए, तो यह अमानवीयता से कम नहीं होगी।

विचार की शृंखला

कल्पना मनोरमा

विचार एक प्रकार की ऊर्जा है। जिस तरह से मस्तिष्क मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है, उसी तरह विचारों द्वारा वह अपने जीवन को परिभाषित कर सकता है। मनुष्य के विचार परिपक्व और अच्छे होने चाहिए। उसका सोचना, महसूस करना और चाहना तर्कसंगत और कल्याणकारी होना चाहिए। किसी भी मनुष्य के विचारों में जितनी ताकत होगी, उतनी ही वह अपने और अपनों के जीवन को सगुण रूप से फलित होते देख सकेगा। इस तरह की बातें खूब सुनने में आती रहती हैं। विचार शक्तिमान है। दुनिया भर में जितने भी आविष्कार हुए हैं, वे वैचारिक संपन्नता के आलोक में ही संपन्न हो सके और हो रहे हैं। विचार शून्यता अभिशाप है। वैचारिक विपन्नता गरीबी से भी जयादा कष्टकारी है।

यह मान सकते हैं कि मनुष्य को वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए। पर ऐसा संभव हो कैसे? कैसे प्रत्येक मनुष्य तर्कशील और विचारशील हो सके? जबकि वैचारिक तौर पर कुंद लोगों की कमी नहीं दुनिया में। कुंद मन और सोच वाले परिवार में ऐसी चीज जन्म लेती है जो सामान्य तौर पर मुखर तो दिखती है, मगर जल्दी ही वह नष्ट भी हो जाती है। अगर किसी बच्चे पर यह संस्कार हावी है तो वह कैसे विचारशील बन सके? कैसे वह वैचारिक असहिष्णुता से बच सके? इस पर विचार करना होगा, क्योंकि रंग-रूप की कुरूपता तो एक सामाजिक अवधारणा और आग्रहों से जुड़ा प्रश्न है, मगर वैचारिक असहिष्णुता बेहद दुखदायी है।

जब यह कहा जाता है कि मद्धिम सोच वाले बच्चे की कोई गलती नहीं है और उसे तो पारिवारिक धरातल ही कुंद मिला, इसलिए उसकी सोचने की क्षमता भी संकुचित हो गई, तब लोग आक्रामकता के साथ कहते मिलते हैं कि बच्चे के ऊपर परिवार का महत्त्व तभी तक रहता है, जब तक बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता। जिस दिन बच्चे ने घर की दहलीज लांघी, समाज में घुलने-मिलने लगा तो वैचारिक संपन्नता और विपन्नता दोनों प्रकार के कारक वह समाज से ही ग्रहण करता है। ऐसा बोलकर छुट्टी पाने वाले अभिभावकों से बस इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने शैशवकाल से लेकर बाल्यकाल तक अपने बच्चे के सीखने या ग्रहण करने वाले स्थान पर कैसा चुंबक चिपका दिया है! जैसा चुंबक उन्होंने बनाया होगा, उसी के अनुसार वह लोगों और विचारों की ओर आकर्षित होता चला जाएगा। लोग यह भी कहते हैं कि 'संगत ही गुण ऊपजे, संगत ही गुण जाएं'। यह बिल्कुल सही कहावत है और अक्सर अपने आसपास इसके अर्थ को महसूस किया जा सकता है। मगर संगत का चुनाव भी बच्चा अपनी प्राथमिक सोच और महसूस करने वाली विधि के मद्देनजर ही चुनेगा। यों कहें कि चुनता भी है।

व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा और संपन्न या छोटा और विपन्न जीवन जी चुका हो, उसकी छवियों और हाव-भाव की गहराइयों में उसके मां-बाप की छाप दूर से दिखाई पड़ती है। उसी तरह, जिस तरह एक पेड़ की उपलब्धि और योग्यता उसकी उस भूमि पर निर्भर होती है, जिस पर वह उगाया गया होता है। धान की फसल अच्छी चाहने वाले किसान धान की पौध को तैयार करने के समय बेहद सजग और चैतन्य रहते हैं।

यह भी ध्यान रखने की बात है कि विचार करने की क्षमता शारीरिक क्षमता के साथ बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही परिवार के सभी लोगों को अपने शिशु से जुड़ी बातों में, मसलन, खाना, पीना, कपड़े, रंग आदि के जुड़े किसी भी मुद्दे को उसके समाने रखकर बार-बार अपने बच्चे से पूछना और कहना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम विचार करो। समय लेकर सोचो और उसके बाद हमें बताओ। तुम्हारी राय महत्त्वपूर्ण है हमारे लिए।

हर किसी को खुले मन के स्वस्थ संवाद और अपनी भूमिका अहम होने की चाह होती है। बचपन में कोई भी बच्चा किसी की भी बात को हल्के में या सतही तौर पर नहीं लेता है, क्योंकि आरंभिक समय में संसार की हर वस्तु और विचार उसके लिए अहम होते हैं। सीखने और करने की लालसा उसमें प्रबल होती है। वह हमारे कहे के अनुसार जरूर अपने को अहमियत देना, सोचना, सुनना और सीखना शुरू कर देगा। मगर यहां भी माता-पिता को चौकस रहने की जरूरत होगी। उम्र के तकाजे के मुताबिक उसकी राय अपरिपक्व और अपनी तरह की होगी। हमें 'उसकी तरह' को ही सुधारना है। सही को सही और गलत को गलत कहना है। स्वीकार और अस्वीकार, दोनों भाव व्यक्ति को बचपन से ही समझ में आ जाने चाहिए।

हमारे द्वारा निर्देशित प्रश्नों के मद्देनजर बच्चे अपने विचार और निर्णय के साथ जब हमारे समाने आएं तो यह बिल्कुल जरूरी नहीं होगा कि किसी मामले में वह सौ फीसद सही हो, लेकिन जब वह अपनी क्रियाशीलता के साथ हमारे सामने आएगा, तब उसकी सुनने, देखने और ग्रहण करने की क्षमता उर्वर होगी। वह हमारी बातों में रुचि ले रहा होगा। उसी समय हम अपने मंतव्यों और प्रश्नों को दोहराते हुए उसके द्वारा सोचे या विचार किए गए उत्तरों में सुधार कर सकते हैं। बच्चा बड़ी सहजता से अपने सोचे हुए विचारों में सुधार करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमारी बात उसे अपने ऊपर थोपी हुई न लग कर अपने होने का अहसास नजर आएगा उसमें। बच्चा एक अलग इंसान है। माता-पिता उसे आपकी जायदाद न समझें। इस बारे में अभिभावकों को एक बार सोचना चाहिए।

> बचपन में कोई भी बच्चा किसी की भी बात को हल्के में या सतही तौर पर नहीं लेता है, क्योंकि आरंभिक समय में संसार की हर वस्तु और विचार उसके लिए अहम होते हैं। सीखने और करने की लालसा उसमें प्रबल होती है। वह हमारे कहे के अनुसार जरूर अपने को अहमियत देना, सोचना, सुनना और सीखना शुरू कर देगा।

दुनिया मेरे आगे

लोकलाज की जगह

संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना न की होगी कि जिन बिंदुओं को वे संविधान की धाराओं में भी प्रविष्ट नहीं कर रहे हैं, उसे ही संविधान की शपथ लेने वाले लोग तार-तार करेंगे। कुछ राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने जेल जाने के बाद भी अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। यह सच है, मगर पूर्व में घटित अनेक उदाहरण साक्षी हैं, जिसमें कई मुख्यमंत्रियों ने लोकलाज और नैतिकता के तकाजे के तहत अपना पद त्याग दिया था। वर्तमान परिदृश्य निश्चित ही जनतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक गरिमा को धूमिल करते हुए निजी जिद और कुर्सी मोह की खुली दास्तान बयां करता है। कभी देश के कुछ गणमान्य नेताओं ने आरोप लगते ही अपनी सांसदी का परित्याग कर एक विशिष्ट राजनीतिक आचरण प्रस्तुत किया था। मगर अब जो हो रहा है, उसे वोट की राजनीति पर सवार होकर टूटते-बिखरते संवैधानिक मूल्यों को शीत निष्क्रियता में रखने की कुचेष्टा कहा जाना चाहिए। उचित यह है कि ऐसी दुर्लभ और चिंताजनक हालात से उपजे दांवपेच को समाप्त करने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के जेल जाते ही उसे बर्खास्त किया जा सके।

– अशोक कुमार, पटना, बिहार

जनता के सामने

आम चुनाव की गहमागहमी है। जनप्रतिनिधि अपने लाव-लश्कर के साथ नजर आने लगे हैं। राजनीतिक दल अपना-अपना घोषणा-पत्र भी जारी कर रहे हैं। अक्सर चुनावी घोषणा-पत्र महज लुभावना पर्चा होता है, जिससे जनता आकर्षित होती तो है, लेकिन सरकार में आने के बाद राजनीतिक दल उतनी तेजी से अपने घोषणा-पत्र पर अमल नहीं कर पाते हैं। शायद उन्होंने घोषणा-पत्र केवल चुनाव जीतने के लिए बनाया हुआ था। राजनीतिक दल मीडिया के समक्ष अपना अपना घोषणा-पत्र जारी कर देते हैं, लेकिन जनता को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपना मांग-पत्र मीडिया के समक्ष रख सके, ताकि जनता की मांग भी राजनीतिक दलों तक पहुंचे। साथ ही राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा-पत्र को कैसे, कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा, उससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, बाकायदा इसको भी समझाना चाहिए। चुनावी घोषणा पत्र केवल हवा-हवाई नहीं होना चाहिए।

– अभिषेक कुमार शुक्ल, सुल्तानपुर

घाटे की पटरी

भारत में रोज कमाने-खाने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। वे काम ढूंढ़ने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। इसके लिए ट्रेन भी आने-जाने का एक माध्यम है। ऐसे लोगों को ऊंचे सपने दिखाने के लिए पहले से प्रयास चालू हैं। अब इस कड़ी में वंदे भारत ट्रेन जुड़ी है। इसमें यात्रा करना हरेक के बूते में नहीं है। आखिर व्यक्ति का पैसा मेहनत का है। मात्र दो-तीन घंटे की यात्रा के लिए ऊंची कीमत चुका कर वह ऐसी ट्रेन में क्यों बैठेगा? अब ऐसी ट्रेन के लिए यात्री नहीं मिल रहे हैं। किसी चीज को चलाने के लिए आय का साधन पर्याप्त होना चाहिए। जब यात्री नहीं होंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी? इसलिए ऐसी ट्रेनें घाटे का सौदा है। दूसरी तरफ रेलवे कहता है कि उसे हर यात्री टिकट पर घाटा होता है। यह कैसा विरोधाभास है? एक तरफ ट्रेन खाली दौड़े और दूसरी तरफ हर यात्री पर घाटा दिखाना। सरकार को इस गणित को समझना चाहिए।

– दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

खतरे की आवाज

तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण ने प्रदूषण के विभिन्न आयाम खोले हैं, जिनमें से एक ध्वनि प्रदूषण भी है। आज का युवा तेज आवाज में गाने सुनना, शादियों मे तेज डीजे का बजाना अपना अधिकार समझता है। इससे भले ही किसी और को परेशानी होती हो। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग नौ फीसद आबादी बुजुर्गों की है, जिनमें से अधिकांश उच्च रक्तचाप, बहरापन, चिड़चिड़ापन नींद की समस्या आदि से ग्रसित हैं। इतना ही नहीं, आज इयरफोन, हेडफोन जैसे उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में बहरापन, चिड़चिड़ापन, घबराहट आदि समस्याओं का होना स्वाभाविक है। आज शहरों में छोटी-छोटी बात पर होने वाले झगड़े भी इसी धवनि प्रदूषण की देन है। एक स्वस्थ शरीर तभी बेहतर काम कर सकता है जब एक स्वस्थ दिमाग हो और एक स्वस्थ दिमाग का विकास शोरगुल रहित माहौल में ही हो सकता है।

– बिंदू अभय लक्की, बलिया

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

https://t.me/AINewsPaperPdf

www.readwhere.com

बढ़ता डिजिटल सेवा निर्यात

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक से संबंधित वस्तुओं के बढ़ते निर्यात के साथ-साथ भारत डिजिटल माध्यम से मुहैया करायी गयीं सेवाओं के निर्यात में भी वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है. विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत ने 257 अरब डॉलर मूल्य के ऐसी सेवाओं का निर्यात किया है, जो 2022 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. इस क्षेत्र में भारत जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गया है. अब भारत से आगे केवल अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड हैं. डिजिटल माध्यम से सेवा मुहैया कराने का अर्थ यह है कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर शिक्षा, गेमिंग, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के लिए दक्ष ऑपरेटर, कुशल प्रोग्रामर और कोडिंग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं. वैश्विक सेवा व्यापार में डिजिटल माध्यम से मुहैया करायी जाने वाले सेवाओं का हिस्सा अब 20 फीसदी से भी ज्यादा हो गया है. यह आंकड़ा 2005 में 14 प्रतिशत था. वस्तुओं के निर्यात में कई कारणों- भू-राजनीतिक तनाव, हिंसक संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध, मुद्रास्फीति में वृद्धि, मांग में कमी आदि- से बीते वर्षों में उतार-चढ़ाव होता रहा है. हालांकि इस वर्ष बेहतरीन की उम्मीद जतायी जा रही है, लेकिन आशंकाएं भी बनी हुई हैं. इस रुझान के उलट कोरोना महामारी के दौर से पहले के तुलना में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल सेवाओं का निर्यात अभी 50 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर है. इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बहुत है क्योंकि कई देश सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, कोडिंग आदि डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने में जुटे हैं. अनेक देश ऐसी सेवाओं के आयात करने के बजाय अपने देश में इन्हें विकसित कर रहे हैं, भले ही उनकी गुणवत्ता कमतर हो. फिर इन सेवाओं से डाटा सुरक्षा और संग्रहण के मुद्दे भी जुड़े होते हैं. ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि से यह इंगित होता है कि इन सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता उत्कृष्ट है तथा सुरक्षा को लेकर भी भारतीय सेवा प्रदाताओं पर भरोसा बढ़ा है. बीते वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच भारत से वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 709 अरब डॉलर से अधिक रहा है तथा इस अवधि में हमारा कुल आयात 782 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ है. हाल के वर्षों में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों, नीतिगत पहलों तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है. घरेलू बाजार में भी देशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है. विदेशी निवेश, तकनीक और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी सरल नियमों को लागू किया जा रहा है. इन प्रयासों के उत्साहजनक नतीजे हमारे सामने हैं. डिजिटल सेवा जैसे क्षेत्र में वृद्धि से नया बाजार भी हासिल हो रहा है.

डिजिटल माध्यम से मुहैया करायी गयीं सेवाओं के निर्यात में भारत चौथे स्थान पर आ गया है.

क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया

राजन कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू
rajan75jnu@gmail.com

ईरान और इस्राइल के बीच तनातनी और हिंसक कार्रवाइयों का इतिहास पुराना है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब ईरान ने अपनी धरती से इस्राइल पर सीधे हमले किये हैं. इससे पहले के हमले ईरान अपने समर्थक समूहों, जैसे- हमास, हिज्बुल्लाह, अंसारअल्लाह, पॉपुलर मोबिलाइजेशन आदि के जरिये कराता रहा है. अब तक वह सीधे इस्राइल से लड़ाई से बचता रहा है. सीरिया में उसके दूतावास पर हुए हमले की जवाबी कार्रवाई में किये गये इन हमलों से यह संकेत मिलता है कि ईरान अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव कर रहा है. ईरान ने दूतावास हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है. ईरान ने इन हमलों को सीमित हमला कहा है, जिसके कुछ निशाने तय थे. हमलों के बाद उसने यह भी कहा है कि उसका जवाब पूरा हो गया और वह आगे हमले नहीं करेगा. साथ ही, उसने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इस्राइल ने फिर हमला किया, तो वह ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा. मेरी राय में ये हमले सांकेतिक थे और इनकी पूरी तैयारी की गयी थी. इस कार्रवाई के बारे में पश्चिमी देशों को बता भी दिया गया था. इसी कारण अमेरिका और भारत समेत विभिन्न देशों ने अपने नागरिकों को निकल जाने को कहा था तथा हवाई सेवाओं को भी रोक दिया गया था.

उल्लेखनीय है कि ईरानी शासन पर उनके अपने लोगों का भी दबाव बहुत था. अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, तो शासन के प्रति लोगों के भरोसे में कमी आना स्वाभाविक था. इसलिए ये हमले हुए. और, हमले भी ऐसे थे, जिनसे इस्राइल अपना बचाव कर सकता था. एक तो पूर्व सूचना थी, सो तैयारी के लिए समय मिल गया. दूसरी बात यह है कि ईरान से ड्रोन, मिसाइल आदि इस्राइल पहुंचने में जो वक्त लगा, उससे भी बचाव में मदद मिली. इसके साथ-साथ जॉर्डन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि कुछ देशों ने भी अपने स्तर से सहयोग किया. ईरान को यह भी पता था कि इस्राइल के पास मिसाइल डिफेंस क्षमता है. अगर ईरान चाहता, तो वह लेबनान स्थित हिज्बुल्लाह के जरिये भी सैकड़ों मिसाइलों से हमला करा सकता था. हिज्बुल्लाह के पास ऐसे हथियारों का बड़ा जखीरा है. उससे इस्राइल को भारी नुकसान हो सकता था. ईरान यमन और इराक में अपने समर्थकों के साथ एक-साथ हमले भी कर सकता था. या वह बैलेस्टिक मिसाइलों या बड़े पैमाने पर बमबारी वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था. कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि ईरान ने पश्चिमी देशों को बता भी दिया था. पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना के प्रमुख ने बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के कुछ दिन पहले इस्राइल की यात्रा भी की थी.

अब देखना यह है कि इस्राइल की ओर से क्या प्रतिक्रिया होती है. अगर दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति पैदा हो जायेगी. इस्राइल की कोशिश है कि इस क्षेत्रीय तनाव में अमेरिका पूरी तरह शामिल हो जाए. अगर लड़ाई आगे बढ़ती है, तो अमेरिका को इसमें आना ही होगा और यही इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं. अमेरिका ने कहा है कि अगर इस्राइल द्वारा ईरान पर हमला किया जाता है, तो वह उसमें शामिल नहीं होगा. वह केवल इस्राइल के बचाव में मददगार होगा. लेकिन हमले और बचाव को लेकर इस तरह की नीति बहुत भ्रामक होती है. जब हमले और जवाबी हमले का सिलसिला शुरू हो जायेगा, तो यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि क्या हमला है और क्या बचाव है. लेकिन अमेरिका की अभी यही रणनीति है कि वह इस्राइल को रोके. इसका कारण यह है कि पहले ही अफगानिस्तान को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की बहुत आलोचना हो चुकी है. गाजा में पिछले कई महीने से जो भयावह स्थिति है, उसे लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है. यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी रवैये को उनके देश में बहुत समर्थन नहीं मिल रहा है. उनसे विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के ही नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भी बहुत से नेता एवं समर्थक नाराज हैं. पश्चिम एशिया में नया युद्ध चुनाव में बाइडेन के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है.

ईरान और इस्राइल सैन्य शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं. ईरान के पास अपनी क्षमता के साथ-साथ विभिन्न देशों में लड़ाकों का समूह है. इस्राइल के साथ अमेरिका और पश्चिम के देश हैं. इस बार की तरह अरब के देश भी उसे सहयोग कर सकते हैं, पर तब अरब के शासकों को अपनी जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, युद्ध की स्थिति में फिलिस्तीन का मसला पीछे हो जायेगा और ईरान से लड़ाई या युद्धविराम मुख्य मुद्दा बन जायेगा. बाइडेन चुनाव के समय इस तरह के मामले में उलझना नहीं चाहते. उस जटिल स्थिति से सभी परहेज करना चाहते हैं. अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल नेतन्याहू चाहते हैं कि यह युद्ध बढ़े ताकि उन्हें अधिक समर्थन मिले और उनकी सरकार बची रह सके. यह एक तथ्य है कि ईरान को हरा पाना संभव नहीं होगा. तो, युद्ध बहुत लंबा खींच सकता है. उस स्थिति में पश्चिम एशिया में जो तबाही होगी, वह तो होगी ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी उसके असर को भुगतना होगा. बीते दिनों तेल के दाम बढ़े हैं. युद्ध की स्थिति में लाल सागर, फारस की खाड़ी, स्वेज नहर आदि तमाम महत्वपूर्ण रास्ते बाधित होंगे. तब केवल तेल ही नहीं, सभी तरह की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ेंगे.

भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने सभी पक्षों को संयम से काम लेने का अनुरोध किया है. ईरान भी ब्रिक्स समूह का सदस्य है. हालांकि भारत के संबंध ईरान और इस्राइल दोनों से अच्छे हैं, पर इन पर शांति के लिए दबाव बनाना आसान नहीं है. यही स्थिति चीन के साथ है. पश्चिम एशिया में बड़ी अशांति चीन के आयात और निर्यात पर बड़ी चोट कर सकती है. युद्ध की स्थिति रूस के लिए कुछ फायदेमंद हो सकती है क्योंकि दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट जायेगा और तेल व गैस की कीमतें बढ़ेंगी. अमेरिका और पश्चिम के देश यूक्रेन को पर्याप्त मात्रा में हथियारों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं. उनके यहां उत्पादन भी धीमी गति से चल रहा है. ऐसे में पश्चिम एशिया में हथियारों की खपत करना पश्चिम के लिए बहुत घाटे का सौदा हो सकता है. पश्चिम एशिया में युद्ध किसी के लिए हितकर नहीं है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसे रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए. अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी के असर में है. यूक्रेन और अन्य लड़ाइयों ने भी नुकसान किया है. एक और युद्ध भयावह साबित होगा.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने सभी पक्षों को संयम से काम लेने का अनुरोध किया है. ईरान भी ब्रिक्स समूह का सदस्य है. हालांकि भारत के संबंध ईरान और इस्राइल दोनों से अच्छे हैं, पर इन पर शांति के लिए दबाव बनाना आसान नहीं है.

वैश्विक ऊंचाई पर भारतीय खिलौना कारोबार

डॉ जयंतीलाल भंडारी
अर्थशास्त्री
article@jlbhandari.com

व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच तेज प्रगति की है. इस अवधि में निर्यात में 239 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई, जबकि आयात में 52 प्रतिशत तक की कमी आयी. इससे यह रेखांकित होता है कि 'मेक इन इंडिया' अभियान से भारत का खिलौना उद्योग वैश्विक ऊंचाई पर है. इस अभियान ने चीन को झटका देते हुए खिलौना निर्माण को भारत के लिए फायदे का सौदा साबित कर दिया है. चीन से खिलौनों की खरीदारी करने वाले कई देश अब भारत का रुख कर रहे हैं. यह कोई छोटी बात नहीं हैं क्योंकि कोई एक दशक पहले खिलौनों की भारत से मुश्किल से ही किसी तरह की खरीद होती थी. इस समय हैम्ब्रो, मैटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग सेंटर जैसे खिलौने के वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए भारत पर अधिक निर्भर हैं. इटली की दिग्गज कंपनी ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंकास आदि भी अपना ध्यान चीन से हटाकर भारत पर केंद्रित कर रही हैं. पांच-छह वर्ष पहले तक भारत खिलौनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और 80 फीसदी से अधिक खिलौने चीन से आयात किये जाते थे. विभिन्न सर्वेक्षणों में लगातार कहा जा रहा था कि चीन से आयातित दो-तिहाई खिलौने असुरक्षित थे. उनमें सीसा, कैडमियम और बेरियम जैसे असुरक्षित तत्व पाये गये थे.

भारतीय खिलौना उद्योग की बहुत कम समय में हासिल ऐसी सफलता की कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. भारत का खिलौना निर्यात पांच-छह वर्षों में तेजी से बढ़कर 2,600 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूएइ, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों को खिलौने निर्यात किये जा रहे हैं. इस समय भारतीय खिलौना उद्योग का कारोबार करीब 1.5 अरब डॉलर का है, जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 0.5 फीसदी मात्र है, पर जिस तरह इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे इसके इसी वर्ष तीन अरब डॉलर तक होने की संभावना है. इस बढ़ोतरी के कई कारण हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार देश के लोगों से स्वदेशी भारतीय खिलौने खरीदने, घरेलू डिजाइनिंग सुदृढ़ बनाने, भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की अपील की है. बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन-प्लस-वन रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने जैसे उपायों से खिलौना उद्योग में तेजी आयी है. बीआइएस ने घरेलू निर्माताओं को 1,200 से अधिक लाइसेंस और विदेशी निर्माताओं को 30 से अधिक लाइसेंस प्रदान किये हैं.

सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग के लिए अधिक अनुकूल विनिर्माण परितंत्र बनाने में मदद मिली है. वर्ष 2014 से 2020 तक की अवधि में विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गयी, जबकि आयातित वस्तुओं पर निर्भरता 33 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गयी. वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) मंत्रालय 19 खिलौना उत्पादन केंद्रों की मदद कर रहा है तथा वस्त्र मंत्रालय 13 केंद्रों को डिजाइनिंग करने और जरूरी साधन मुहैया कराने में सहयोग कर रहा है. स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रचार पहल भी की गयी हैं, जिनमें इंडियन टॉय फेयर 2021, टॉयकैथॉन आदि शामिल हैं. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने घटिया स्तर के खिलौनों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक आयात खेप का नमूना परीक्षण अनिवार्य कर दिया है. वर्ष 2014-15 के बाद से इस बार के अंतरिम बजट तक में लगातार सरकार ने खिलौना उद्योग के विकास के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन और समर्थन देने की पहल की है. खिलौना उद्योग को देश के 24 प्रमुख सेक्टरों में स्थान दिया गया है.

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीतिगत पहलों के साथ-साथ घरेलू निर्माताओं के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. पर अभी भी कई बाधाएं हैं. भारतीय खिलौना उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कार्य योजना, संबंधित एजेंसियों के बीच उपयुक्त तालमेल व चीन की तरह देश में खिलौने के विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की जरूरत है. खिलौनों पर जीएसटी दर में कटौती की जानी चाहिए. अधिकांश भारतीय खिलौने ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि घरेलू खिलौनों की बिक्री बढ़ सके. पारंपरिक और यांत्रिक खिलौनों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शीघ्र शुरू की जाए. सुगठित खिलौना प्रशिक्षण और डिजाइन संस्थान की स्थापना को मूर्त रूप देना होगा. बैंकों से ऋण तथा वित्तीय सहायता संबंधी बाधाओं को दूर करना होगा. हम उम्मीद करें कि सरकार देश को खिलौनों का वैश्विक हब बनाने और खिलौनों के वैश्विक बाजार में चीन को अधिक टक्कर देने की डगर पर आगे बढ़ेगी. घरेलू बाजार के सस्ते और गुणवत्तापूर्ण खिलौनों से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बढ़ेगी. अधिक निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई के साथ-साथ रोजगार के मौके भी तेजी से बढ़ेंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

भारतीय खिलौना उद्योग की बहुत कम समय में हासिल ऐसी सफलता की कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. भारत का खिलौना निर्यात पांच-छह वर्षों में तेजी से बढ़कर 2,600 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है. भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों को खिलौने निर्यात किये जा रहे हैं.

देश दुनिया

विदेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे पाकिस्तान

इसी वर्ष मार्च में बिशम में चीनी इंजीनियरों पर हमला हुआ था. चीनी परियोजनाओं को कमजोर करने के उद्देश्य से मार्च में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा हमला था. चीनियों ने देशभर में परियोजनाओं में अरबों का निवेश किया है और पाक-चीन संबंध लगभग पाकिस्तान जितने ही पुराने हैं. हमले के लिए विशेषज्ञ धार्मिक अतिवाद, सीपीइसी के तहत चलने वाले विकास परियोजनाओं से पारंपरिक मूल्यों को होने वाले कथित खतरे, नॉन-स्टेट एक्टर्स और अलगाववादियों की ओर संकेत कर रहे हैं. पर आंतरिक सुरक्षा खामियों और प्रभावी आतंकवाद विरोधी रणनीतियों की कमी को लेकर आत्मनिरीक्षण किये बिना बाहरी तत्वों को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है. हमें याद रखना चाहिए कि टीटीपी जैसे आतंकवादी समूहों के साथ देश के समझौते के इतिहास ने केवल नापाक इरादे वाले लोगों को ही प्रोत्साहित किया है. हम इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकी हमलों में तेज वृद्धि हुई है. जबकि बिशम हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है. सुरक्षा प्रतिष्ठान को इसमें विदेश हाथ की संभावना लगती है. पर केवल अनुमान से हमें हमारी परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलेगा. हमला चाहे जिसने भी किया हो, समस्या अभी भी बनी हुई है. विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल राजनयिक संबंधों के लिए, बल्कि हमारे आर्थिक भविष्य के लिए भी सर्वोपरि है. पाकिस्तान को इस चुनौती से निपटने में गंभीरता बरतनी चाहिए. इसके अतिरिक्त, विकास परियोजनाओं के संबंध में चिंताओं को कम करने के लिए निवासियों के साथ जुड़ना, स्थानीय विकास परियोजनाओं पर उनके साथ काम करना और उग्रवाद के मूल कारणों से निपटना भी आवश्यक है. तभी पाकिस्तान अपने मेहमानों और अपने राष्ट्रीय हितों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के सुरक्षित रहने की उम्मीद कर सकता है.

DAWN

बोधि वृक्ष

नचिकेता का प्रण

नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है. उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी, जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति- अपना घर, सारा सामान, यहां तक कि अपनी पत्नी, बच्चे- सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में देना था. नचिकेता के पिता ने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी, वे सब दान में दे डाली. मगर जिन चीजों की उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चे, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा. नचिकेता को यह देख बहुत दुख हुआ. वह अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बातें करने लगा. उसकी उम्र उस समय सिर्फ पांच वर्ष की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी. नचिकेता ने अपने पिता से कहा, 'आपने ठीक नहीं किया. यदि आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे, तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए थी. मुझे बताइए कि आप मुझे किसे दान करने वाले हैं?' पिता क्रोधित होकर बोले, 'मैं तुम्हें यम को देने वाला हूं.' बालक ने पिता की बात को गंभीरता से लिया और यम के पास चला गया. यम उस समय यमलोक में नहीं थे. नचिकेता पूरे तीन दिन तक भोजन-पानी के बिना यम के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा. तीन दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने इस छोटे से बालक को देखा. यम बोले, 'तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें तीन वरदान देता हूं.' नचिकेता ने कहा, 'मेरे पिता बहुत लालची हैं. वह सांसारिक सुख-सुविधाएं चाहते हैं. उन्हें राजा बना दीजिए.' यम ने कहा 'तथास्तु'. उसने दूसरा वरदान मांगा, 'मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की जरूरत है.' यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए. फिर नचिकेता ने पूछा, 'मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है?' यम ने इस प्रश्न को टालने की हरसंभव कोशिश की, पर बालक ने अपनी जिद नहीं छोड़ी. कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई. उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गये और उसने स्वयं को विलीन कर दिया.

-सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

राजनीति में सयानापन

संतोष उत्सुक
व्यंग्यकार
santoshutsuk@gmail.com

अब तो नेता ऐसा चाहिए जो सिर्फ सयाना न हो. नेताओं की शानदार जिंदगी में सयानापन, कितनी बार स्यापा डलवा देता है. राजनीति का खेल संभावनाओं का ही नहीं असंभावनाओं का खेला भी है. इसलिए इसमें चूकने वाले नेता नहीं चाहिए. किसी भी स्थिति में, किसी भी कीमत पर, किसी भी मोड़ पर इधर जरा सा चूके, उधर कोई और मैदान मार जाता है. ज्यादा सयाने नेता का खेल बिगड़ जाता है. एक बार खेल हार जाओ या जीतते-जीतते हार जाओ तो फिर कहां जीता जाता है. चुनाव सिर पर हों और नेता सयानेपन पर फिदा हों, तो दूसरों की गले की फांस बन जाते हैं. कुछ सयाने नेता राजनीति के साथ-साथ, सच्ची समाज सेवा करके नाम और पुण्य कमाना चाहते हैं. ऐसे नेता अपना नुकसान तो करते ही हैं, समाज का नुकसान भी होता है. सच्ची राजनीति का स्तर भी गिरता है और राष्ट्रीय क्षति भी होती है. जय, पराजय में बदल जाती है.

चुनाव छोटा हो या बड़ा, नाराजगी, विरोध, सहयोग, इस्तीफा, घोषणा और पत्रकार सम्मेलन होना जरूरी है. गठबंधन से महागठबंधन में शामिल होना या महागठबंधन से लघु गठबंधन या सिर्फ बंधन में आना सयानेपन के हिसाब से नहीं, उचित समय के हिसाब से होना बहुत जरूरी है. यह शुद्ध अवसरानुसार होना चाहिए. सिर्फ गुणगान करना ही नहीं, शुभ मुहूर्त में प्रशंसागीत को भजन में बदल देना भी आना चाहिए. सभी तरह के साज बजाना आना भी लाजमी है. झुककर प्रणाम करते-करते, साष्टांग प्रणाम कर डालना भी राजनीतिक कारीगरी मानी जाती है. दूसरे की पसंद की सस्ती खुशबू लगाकर, प्यार की नकली झप्पी मारना भी सामयिक और सशक्त अदाकारी का नमूना है. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मंत्री पद की ऑफर आते-आते अचानक कहीं ठहर जाती है. जबानी बयानबाजी कई बार जान की बाजी बन जाती है. राजनीतिक पुनर्वास होते-होते, आवास भी जाता है. इसे 'घर के रहे न घाट के' भी कह सकते हैं. कई बंदों के कमबख्त जन्म नक्षत्र भी काम नहीं होने देते.

तोड़-जोड़ की राजनीति के जमाने में बाहुबली छवि भी धराशायी हो जाती है. अनेक बार कपड़े बदलकर माफी मांगने या माफ कर देने से भी बड़े-बड़े ख्वाब पूरे हो जाते हैं. कन्नी काटने से भी बुरे समय की काट तत्काल मिल जाती है और अच्छा समय धूप की तरह निकल आता है. सयानापन नहीं, अब तो सभी तरह की बुनावट के वस्त्र धारण कर सकने वाला, किसी भी शरण में जा सकने वाला, सभी का गुण गायक, सबको पिता बनाने वाला, कैसा भी कहने, सुनने और देख सकने वाला, सियार, भैंसे, गीदड़, चूहे की खाल ओढ़ सकने वाला बहुमुखी प्रतिभा का नेता सफल होता है. यही राजनीतिक सयाना होना होता है.

आपके पत्र

स्वस्थ तन-मन के लिए करें योग

योग मनुष्य के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इससे मनुष्य तन व मन से स्वस्थ रहता है. योग करने वाले लोग मानसिक व शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ रहते हैं. योग से मन को शांति मिलती है. वर्तमान समय में जिस स्तर से रोग बढ़ रहे हैं, उसमें योग और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. योग करने से आप इन सभी बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं. योग से हृदय रोग, रक्तचाप की समस्या आदि से छुटकारा पाया जा सकता है. इसलिए योग को स्कूलों में भी शामिल करना चाहिए. इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे.

पंकज कुमार, सीतामढ़ी

लोन के जाल में फंस रहे ग्रामीण

माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आसानी से लोन देती है, जिसके जाल में ग्रामीण इलाकों के गरीब लोग फंस जाते हैं. लोन का ब्याज दर काफी अधिक होता है. समय पर किश्त नहीं देने पर मूलधन के साथ ब्याज तेजी से बढ़ता जाता है. लोन नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी उन्हें काफी प्रताड़ित करते हैं. इनके वसूली एजेंट की प्रताड़ना काफी खतरनाक होते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि अपराध बोध में लोन लेनेवाले गरीब व भोले-भाले लोग आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं.

अखिलेश सिंह, बेगूसराय

न्याय पर दबाव

आजकल न्यायपालिका में चल रही हलचल का असर अक्सर सामने दिखने लगता है। न्यायपालिका की साख की चिंता स्वाभाविक और स्वागतयोग्य है। कोई आश्चर्य नहीं, देश के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। हाल के दिनों में न्यायपालिका के सर्वोच्च अंग को पत्र लिखकर सचेत करने की यह तीसरी कोशिश है। ऐसे दो पत्र अधिवक्ताओं के जरिये पहले आ चुके हैं और तीसरा पत्र पूर्व जजों ने लिखा है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। दरअसल, अधिवक्ता तो अलग-अलग विचारधारा के हिसाब से विभाजित हैं। अधिवक्ताओं के एक समूह को लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर अनावश्यक नैतिक दबाव बनाकर फैसले कराए जा रहे हैं और इसको रोका जाना चाहिए। दूसरे समूह को लगता है कि न्यायपालिका को किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए। ताजा पत्र में इन पूर्व न्यायाधीशों ने सोचे-समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने की बढ़ती कोशिशों की ओर ध्यान खींचा है।

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारतीय न्यायपालिका के आलोचक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत हितों से प्रेरित हैं। वैसे, न्यायमूर्तियों को उदाहरण के साथ बताना चाहिए था कि पिछले दिनों क्या ऐसी घटनाएं हुई हैं या क्या ऐसे फैसले हुए हैं, जिनसे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय दबाव में है? कोई दोराय नहीं कि किसी भी लोकतंत्र में अलग-अलग प्रकार के दबाव समूह काम करते हैं और अपने अनुरूप फैसले लेना चाहते हैं। अच्छा लोकतंत्र तो वही है, जहां किसी फैसले का पूरा संदर्भ लोगों को पता हो। यह अक्सर कहा जाता है कि न्याय करने से ज्यादा जरूरी है, लोगों में न्याय का एहसास पैदा करना। आदर्श न्याय यही है कि दोषी को भी अपने अपराध का एहसास हो जाए और वह सजा मंजूर कर ले। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज अनेक ऐसे न्यायिक निर्णय हैं, जिन पर पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग राय है। विपक्ष को लगता है कि न्यायपालिका किसी दबाव में आकर कुछ फैसले कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष को लगता है कि विपक्ष न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। हां, पिछले दिनों एकाध बार देखा गया कि विपक्ष ने सीधे न्यायमूर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, वह लोकतंत्र और न्याय की दुहाई देता रहा है। यह एक प्रकार का भावुक भयादोहन है, जिस पर विस्तार से विमर्श की जरूरत है।

न्यायपालिका के सर्वोच्च अंग को पत्र लिखकर सचेत करने की यह तीसरी कोशिश है। ऐसे दो पत्र अधिवक्ता लिख चुके हैं और तीसरा पत्र पूर्व जजों ने लिखा है।

बहरहाल, यह उजागर तथ्य है कि अदालतें इसी समाज का हिस्सा हैं। अदालतों से समाज और समाज से अदालतें प्रभावित होती हैं। यह कहना उचित नहीं कि अदालतों को समाज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ज्यादा उचित तो यह है कि अदालतें अपने किसी भी फैसले को सिर्फ संविधान की कसौटी पर कसें और समाज में न्याय के संदेश का विस्तार करें। दबाव पक्ष का हो या विपक्ष का, न्यायालय को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। न्यायपालिका में न्याय सुनिश्चित करना, गरीबों और शोषितों को मजबूत करने की दिशा में जितनी जिम्मेदारी न्यायमूर्तियों पर है, उतनी ही जिम्मेदारी अधिवक्ताओं पर भी है। ऐसा हो नहीं सकता कि मौका आने पर अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी से भागें और सिर्फ न्यायमूर्तियों से न्याय की उम्मीद करें।

लाल गलियारे में भी चुनावी बिगुल

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

आम चुनाव में माओवादियों के सशस्त्र हस्तक्षेप की अब तक कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी है, जिससे उम्मीद बंधती है कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में पूरा चुनाव शांतिपूर्वक होगा।

झारखंड के लातेहार व गढ़वा और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिलों की सीमाओं को छूता बूढ़ा पहाड़ 2024 के आम चुनावों में प्रतीकात्मक ही सही, इतने महत्वपूर्ण बिंब की तरह क्यों उभरा है? पचास से अधिक किलोमीटर विस्तृत और घने जंगलों वाला यह दुर्गम इलाका पिछले तीन दशकों तक कई प्रदेशों में फैले माओवादियों के ट्रेनिंग और कमांड सेंटर के तौर पर काम करता रहा है। सुरक्षा बलों के लिए लगभग अभेद्य इस इलाके में वाम अतिवादियों की ही चलती थी और यहीं से वे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र तक फैले लाल गलियारे में अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहे हैं। पिछले कई आम चुनावों को उनके सशस्त्र हस्तक्षेप ने रक्त-रंजित तो किया ही, राज्य के सामने उनके प्रभाव क्षेत्रों में सही सलामत चुनाव करा पाना मात्र भी एक बड़ी चुनौती रही है। यह चुनौती काफी हद तक खत्म हुई 27 जनवरी, 2023 को, जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर उतरा और उन्होंने इलाके के विकास के लिए सौ करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की।

आजादी बाद से ही देश में कम्युनिस्ट पार्टी या पार्टियों ने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया था, जो शोषण-विहीन व समता मूलक हो और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे समय-समय पर अपनी रणनीति बदलते रहे। एक बड़े सशस्त्र आंदोलन के रूप में तेलंगाना (1948-51) पहला प्रयास था, जो निजाम शासन की ज्यादतियों और भूमि सुधारों के लिए लड़ा गया। इसे राज्य ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1952 के पहले आम चुनाव में भाग लिया और देश के कई हिस्सों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

साल 1967 में पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण इलाके नक्सलबाड़ी से कम्युनिस्टों ने भूमि सुधार को लेकर एक दूसरा हथियारबंद आंदोलन शुरू किया, जिसने भारतीय समाज में राजनीति, साहित्य, आर्थिक नीतियों समेत हर अंग को प्रभावित किया। यहां तक कि हमारी भाषा भी इस आंदोलन के चलते बदली। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन चेयरमैन माओ से प्रभावित होने के कारण इन्हें नक्सलवादी के साथ-साथ माओवादी भी कहा गया। यह आंदोलन एक दशक तक चला और इसे भी राज्य ने कुचल दिया। इसमें सक्रिय कई कम्युनिस्ट गुट चुनावों में भाग लेने लगे, लेकिन इसी से निकले नेतृत्व ने देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र विद्रोहों की ऐसी शृंखलाएं खड़ी कर दीं, जिनसे निपटने में राज्य को दशकों लग गए और अब जाकर ऐसा लगने लगा है कि माओवाद के नाम से जाना जाने वाला यह आंदोलन अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।

वाम दुस्साहसवाद में विश्वास करने और सशस्त्र संघर्ष से राज्य-सत्ता पर कब्जा करने का सपना देखने वाले इस यथार्थ को नजरअंदाज करते रहे हैं कि पिछली दो शताब्दियों में राज्य एक बड़ी मजबूत संस्था के रूप में उभरा है। उसे किसी बड़े जन-उभार से हिलाया तो जा सकता है, मगर किसी हथियारबंद संगठन द्वारा उस पर कब्जा कर पाना लगभग असंभव है। फिलहाल तो जनता द्वारा सीधे अपने शासकों के चुनाव से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए बार-बार यह नारा देने के बावजूद कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, वाम लड़ाके चुनावों की तरफ लौटते रहे हैं। एक सकारात्मक असर इन संगठनों का यह जरूर दिखा कि सशस्त्र संघर्षों से निकले इनके काडरों ने बिहार जैसे इलाकों के गांवों में दबंगों की बूथ लूटने की घटनाओं पर कुछ हद तक नकेल जरूर लगाई है। दूसरा दिखने वाला असर उन दुर्गम पिछड़े इलाकों में सड़कों, बिजली या संचार के खंभों और शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाओं की पहुंच के रूप में दिखता है, जहां कुछ वर्षों पूर्व तक इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

चुनावों के दौरान घात लगाकर कुछ पुलिस वालों या चुनाव कर्मियों को मार डालना और मतदान केंद्रों पर लूट-पाट करना आमतौर से प्रचार हासिल करने का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करता है। चुनावों की गहमागहमी शुरू होते ही ये अति वामपंथी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में परचों, पोस्टरों या जनसभाओं के जरिये वोटरों से चुनावों के बहिष्कार की अपील करने लगते हैं। सुरक्षा में सेंध लग जाए, तो उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की हत्याएं करने से भी नहीं चूकते। एक मौके पर तो उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का ही सफाया कर डाला था। यह अलग बात है कि भारतीय मतदाता उनकी चेतावनी की उपेक्षा करके बढ़-चढ़कर मतदान करते रहे हैं। इस बार स्थिति कुछ बदली नजर आ रही है। 18वीं लोकसभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुए लगभग एक पखवाड़ा हो रहा है और अभी तक माओवादियों के सशस्त्र हस्तक्षेप की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी है। इससे उम्मीद बंध रही है कि उनके प्रभाव वाले इलाकों में पूरा चुनाव इस बार शांतिपूर्वक निपट जाएगा।

यह परिवर्तन कोई रातोंरात नहीं हुआ। किसी तरह के सशस्त्र नागरिक विद्रोह से निपटने के लिए एक सर्वमान्य प्रविधि तक पहुंचने में भारतीय राज्य को कई दशक लग गए। कभी इसे शांति-व्यवस्था का मुद्दा समझा गया, तो कभी विकास का अभाव कारण माना गया और कभी दोनों। किसी बड़ी घटना से बौखलाकर सरकार कभी बलों की उपस्थिति बढ़ाती, तो कभी वार्ता के नए दौर शुरू करती। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पहुंच जाने के बाद वहां माओवादियों ने अपने हथियार डाल दिए हों। उलटे यह जरूर हुआ कि उन्होंने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सड़कें बनने में बाधाएं खड़ी कीं, संचार के खंभे उखाड़ डाले या स्कूलों और अस्पतालों की इमारतें जला दीं। ठेकेदारों, व्यापारियों या सरकारी कर्मचारियों से लेवी के तौर पर वसूले गए धन के नेतृत्व द्वारा दुरुपयोग की शिकायतें आम हो गई हैं। उनकी इन्हीं हरकतों से नागरिक अधिकार संगठनों के वे लोग कमजोर हुए हैं, जो सरकार से बातचीत कर उन्हें मुख्यधारा में लाने की पैरवी करते रहे हैं। हाल के दिनों में केंद्र और राज्य सरकारों का रवैया स्पष्ट रूप से सख्त हुआ है कि बिना हथियार डाले किसी से बात नहीं हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई हालिया बयान इस परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। शायद यही कारण है कि दशकों बाद ऐसी संभावना बनी है कि रेड कॉरिडोर के नाम से पहचाने जाने वाले कई हजार वर्ग किलोमीटर और आधा दर्जन प्रदेशों में फैले इलाकों में बिना खून खराबे के चुनाव संपन्न हो रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रश्नकाल का आखिर कितना फायदा उठा पाईं विपक्षी पार्टियां

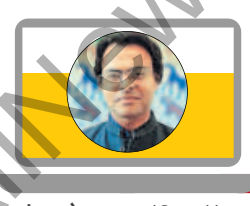

युगांक गोयल | एसोशिएट प्रोफेसर, फ्लेम यूनिवर्सिटी

कार्यपालिका से सवाल पूछने के लिए विधायिका के हाथ का एक सशक्त औजार है प्रश्नकाल। लोकसभा के प्रत्येक सत्र की शुरुआत दोपहर 11 बजे प्रश्नकाल से ही होती है, जिसमें सांसद तमाम नीतिगत मसलों पर जवाब हासिल करने के लिए मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। इसके लिए सवालों को दो सप्ताह पहले संसद में रखना होता है, ताकि संबंधित मंत्री जवाब देने की तैयारी कर सकें। ऐसे वक्त में, जब देश अगली लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव में भाग लेने जा रहा है, हमने पिछले चार लोकसभा कार्यकाल में पूछे गए सभी तारांकित (मौखिक) प्रश्नों के विश्लेषण की सोची। चूंकि, प्रश्नकाल कार्यपालिका से विधायी पूछताछ है, इसलिए ऐसे विश्लेषणों से पार्टियों की मंशा के साथ यह जानकारी भी मिलती है कि मंत्रालयों में सवाल कैसे बांटे जाते हैं।

गौर कीजिए, प्रश्नकाल का उपयोग विपक्ष ही नहीं करता, सत्ता पक्ष के सदस्य भी करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग अपनी ताकत या अपनी बातों को जनता के ध्यानार्थ लाने के अवसर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, हमने अपना अध्ययन विपक्षी दलों के सदस्यों के सवालों पर ही केंद्रित किया है। हमने उन सवालों का अध्ययन किया, जो गैर-पूरक थे और सिर्फ एक सदस्य द्वारा पूछे गए। 80 फीसदी से अधिक मौखिक प्रश्न ऐसे ही हैं, हालांकि इनसे एक दिलचस्प पैटर्न का पता चलता है। पिछली चार लोकसभाओं में प्रश्नकाल में करीब 10 हजार सवाल पूछे गए, यानी क्रमशः 2466, 2059, 2864 और 2347। इनमें से विपक्षी दलों ने क्रमशः 67 फीसदी, 63 फीसदी, 31 फीसदी और 51 फीसदी सवाल पूछे। जाहिर है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की तुलना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) कहीं अधिक मुखर विपक्ष नजर आया। खासकर, एनडीए का नेतृत्व करने वाली भाजपा ने 2004-14 के दौरान 1,217 सवाल पूछे, जब संप्रग केंद्र की सत्ता में था। इसके विपरीत, 2014-24 के दौरान जब राजग सत्ता में था, तब कांग्रेस ने 644 सवाल पूछे। हालांकि, इसका एक पक्ष लोकसभा में विपक्ष की ताकत में असमानता भी हो सकता है। 2004 से 2014 के दौरान भाजपा के पास औसतन 127 सीटें थीं, जबकि 2014-2024 के दौरान कांग्रेस के पास औसतन 52 सीटें। इसलिए विपक्ष की भूमिका के आकलन के लिए हमें भाजपा-कांग्रेस की प्रतिद्वंद्विता से परे जाना होगा और प्रश्न-प्रति सीट की गणना करनी होगी। आंकड़े बताते हैं कि 2014-19 के दौरान विपक्ष सबसे कमजोर था, जब पूछे गए सवाल सीटों की संख्या से भी कम थे, यानी 0.815 सवाल-प्रति सीट। 2004-09, 2009-14 और 2019-24 में यह क्रमशः 1.15, 1.21 और 1.37 था, जिसका मतलब है कि विपक्ष की मजबूती के हिसाब से 2019-24 का प्रश्नकाल सबसे शानदार था। यहां यह जानना भी जरूरी है कि सांसद को सवाल पूछने का मौका देना अध्यक्ष का अधिकार है।

प्रश्नकाल का उपयोग विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी करता है। सत्ता पक्ष के लोग तथ्यों को जनता के ध्यान में लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।

इसी तरह, यदि हम पार्टी के स्तर पर प्रश्नकाल का वर्गीकरण करें, तो 2004-14 के दौरान भाजपा 2014-24 की कांग्रेस की तुलना में कुछ शांत दिखती है। माकपा सबसे मजबूत स्वर साबित हुई है और उसके सवाल पूछने की दर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। 2004-09 में तेलुगु देशम और शिव सेना बहुत मजबूत थीं, पर अगली लोकसभा में वे दोनों कमजोर पड़ गईं। बीजद ने एक विपक्षी पार्टी की सुसंगत भूमिका निभाई है, हालांकि बाद की लोकसभा में वह भी शांत हो गई। 2014-19 में कहीं ज्यादा प्रश्न पूछने वाली समाजवादी पार्टी 2019-24 में पिछड़ गई। चूंकि विपक्षी दल मंत्रालयों की जांच करने के लिए प्रश्नकाल का उपयोग करते हैं, इसलिए हमने यह जानने का प्रयास किया कि किस मंत्रालय से ज्यादा सवाल पूछे गए। आंकड़े बताते हैं कि एक विपक्षी गठबंधन के रूप में एनडीए ने 2004-14 के दौरान संप्रग सरकार के पेट्रोलियम, मानव संसाधन, कृषि, वाणिज्य व उद्योग से जुड़े सवाल पूछे, जबकि 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद संप्रग ने स्वास्थ्य, वित्त व ग्रामीण विकास से जुड़े मसले उठाए।

बहरहाल, यह शोध अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उम्मीद है, इससे सियासी दलों में संवेदनशीलता बढ़ेगी।

(साथ में श्रेयस रामकुमार)

मनसा वाचा कर्मणा

युद्ध के कारणों को समझिए

हरेक युद्ध हमारे दैनिक जीवन का ही व्यापक और खूनी प्रक्षेपण है। वह हमारी आंतरिक अवस्था की ही एक बाहरी अभिव्यक्ति है, हमारे दैनिक कर्म का ही एक विस्तार है। यकीनन, वह अधिक व्यापक, अधिक नृशंस, अधिक विध्वंसक है, परंतु है तो वह हमारी व्यक्तिगत क्रियाओं का ही सामूहिक परिणाम। इसलिए आप और मैं ही युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न यह है कि उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट है, हमेशा सिर पर मंडराता युद्ध आपके और मेरे द्वारा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसे रफ्तार पहले ही मिल चुकी है; वह चल ही रहा है। हालांकि, इस समय मुख्यतः वह मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। और चूंकि यह युद्ध पहले से ही जारी है, इसे रोका नहीं जा सकता। मुद्दे बहुत अधिक हैं और पहले से ही तय हैं।

परंतु यह देखकर कि मकान में आग लगी है, हम उस आग के कारणों को समझ सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं और एक नई जगह का निर्माण अलग उपादानों, चीजों से कर सकते हैं, जो ज्वलनशील न हों; जो और युद्धों को न रचें। हम बस इतना ही कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वह क्या है, जो युद्धों को जन्म देता है और यदि हमारी रुचि युद्धों को रोकने में है, तो हम अपने आप को बदलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही युद्ध के कारण हैं।

वर्षों पहले की बात है। युद्ध के दौरान एक अमेरिकी महिला मुझसे मिलने आई। उसने कहा, वह इटली में अपना एक पुत्र गंवा चुकी है और उसका दूसरा बेटा सोलह वर्ष का है। वह उसकी सलामती चाहती है। मैंने उसे सुझाव दिया कि अपने पुत्र को बचाने के लिए उसे अमेरिकी पहचान के मोह को त्यागना होगा; उसे लालची होने से निजात पानी होगी; उसे शक्ति व अधिकार प्राप्त करना बंद करना होगा और नैतिक रूप से सरल होना होगा- महज लिबास और बाहरी चीजों में ही नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और संबंधों में भी सरल होना होगा। उसने कहा, 'यह तो आप बहुत अधिक की मांग कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, हालात इतने ताकतवर हैं कि उनमें बदलाव लाना मेरे बस की बात नहीं।' इस

अंदरूनी तौर पर भ्रष्ट रहते हुए, बाहरी समाज को बदलने के लिए सिर्फ कानून पर निर्भर रहना समाज को नष्ट करता है, चाहे उस समाज का निर्माण कितने भी वैज्ञानिक ढंग से किया गया हो।

प्रकार अपने पुत्र के विनाश के लिए वही जिम्मेदार थी।

हालात पर हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि हालात हमने ही बनाए हैं। समाज हम सभी के संबंध से बना है। यदि हम अपने संबंधों में, खुद में बदलाव लाते हैं, तो समाज बदलता ही है। अंदरूनी तौर पर भ्रष्ट रहते हुए; सत्ता और प्रभुत्व की तलाश में जुटे रहकर, बाहरी समाज को बदलने के लिए सिर्फ कानून पर निर्भर रहना उस समाज को नष्ट ही करता है, चाहे उसका निर्माण कितनी भी सावधानी और वैज्ञानिक ढंग से किया गया हो। जो अंदरूनी है, वह बाहरी पर हमेशा हावी होता रहता है।

जे कृष्णमूर्ति

जो बाइडन | अमेरिकी राष्ट्रपति

इजरायल के खिलाफ ईरानी हमलों के बारे में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मैंने नवीनतम जानकारी ली है। मैं यह साफ कर दूं कि ईरान से इजरायल की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 16 अप्रैल, 1949

विंध्य प्रदेश

बघेलखण्ड और बुन्देलखण्ड को संयुक्त करके जिस रियासती संघ को जन्म दिया गया था, उसे ही विंध्य प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। इस संघ के प्रारंभिक जीवन में ही ऐसी घटनायें घटित हुई हैं, जो सभी दृष्टिकोणों से शोचनीय समझी जा सकती हैं। धीरे-धीरे मामला इतना गंभीर बनता चला गया कि अन्त में भारत-सरकार के रियासती सचिवालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। कथित लोकप्रिय मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया है और विंध्य प्रदेश का शासन प्रबन्ध भारत सरकार के प्रादेशिक कमिश्नर सम्हाल रहे हैं। बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड की रियासतों का एकीकरण तो हुआ, इन रियासतों के राजा-महाराजाओं ने महान देश के भविष्य की खातिर अपनी सत्ता और पृथक अस्तित्व का त्याग किया, किन्तु जो लोग जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते थे, वे पुरानी बुन्देलखण्डी और बघेलखण्डी भावनाओं को अपने दिमाग से अलग न कर सके। उनके बीच शुरू से रस्साकशी शुरू हो गई। पहले प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के संगठन के संबंध में झगड़े शुरू हुए और उन्हीं झगड़ों का प्रतिबिम्ब मंत्रिमण्डल पर भी पड़ा। आखिर में मंत्रिमण्डल की रस्साकशी तो हद दर्जे को पहुंच गई। मंत्रियों के दो गुट बन गये और प्रत्येक गुट ने दूसरे के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये और विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे अपने साथी मंत्रियों के साथ मिलकर शासन नहीं चला सकते। सरदार पटेल और रियासती सचिवालय ने बहुत धीरज से काम लिया। परामर्श और चेतावनियां भी दीं, किन्तु किसी का कुछ नतीजा नहीं निकला। वही बेढंगी रफ्तार जारी रही। रियासती सचिवालय ने विंध्य प्रदेश के संबंध में जो कदम उठाया है, उसके लिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता। उसकी समस्त जिम्मेदारी विंध्य प्रदेश के मंत्रियों पर है। जो दायित्व परिस्थितियों के संयोग से उनके कंधों पर आया था, उसको निभाने में वे बुरी तरह असफल हुए हैं।

शायद विंध्य प्रदेश का यह गोलमाल कुछ दिन और चलता रहता, हालांकि उससे न शासन को कोई लाभ होने वाला था और न विंध्य प्रदेश की जनता को ही। किन्तु विंध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री की रिश्वतखोरी के अभियोग में गिरफ्तारी ने ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके का काम किया। जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा गम्भीर आरोप हो, वह मंत्री पद पर निश्चय ही बना नहीं रह सकता।

बहुसंख्यकों की आस्था से खिलवाड़

लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। एक-दूजे पर बढ़त बनाने के लिए हरेक पार्टी के नेता कुछ नया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में कई बार वे अपनी सीमा भी भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव की ताजा हरकत कुछ ऐसी ही है। लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक वीडियो ने चुनावी विमर्श में खान-पान को भी शामिल कर दिया है। हुआ यह कि तेजस्वी यादव ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ मछली खाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर सभी अपनी-अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने लगे हैं। कहा जा रहा है कि यह वीडियो नवरात्र के पहले दिन का है और नेताद्वय बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको अल्पसंख्यकों का वोट मिल सके।

बेशक, देश भर में शाकाहारी परिवारों की संख्या बहुत कम है। एक सर्वे में तो यहां तक कहा गया था कि बिहार प्रदेश में ही 92 प्रतिशत से अधिक लोग मांसाहारी हैं। इस सर्वे में तेलंगाना सबसे ऊपर था, जहां के 98.7 प्रतिशत लोग मांसाहार का सेवन करने वाले पाए गए थे। देश में एक नियमित अंतराल पर मांसाहार करने वालों की संख्या करीब 60 प्रतिशत है। मगर अन्य समुदायों को छोड़ दें, तो सिर्फ हिंदुओं में 44 फीसदी शाकाहारी को छोड़कर बाकी 39 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो त्योहारी मौसम में मांसाहार से परहेज करते हैं या बिल्कुल ही नहीं खाते। ऐसे में, सवाल सिर्फ शाकाहारी अथवा मांसाहारी होने का नहीं है। निस्संदेह, देश की बड़ी आबादी मांसाहारी है, किंतु यह भी एक कटु सच है कि नवरात्र जैसे पावन पर्व पर ये लोग सामुदायिक आस्था का सम्मान करते हैं और इन विशेष अवसरों पर मांसाहार के सेवन से बचने का प्रयास करते हैं। लिहाजा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता का वह वीडियो किस आबादी को तुष्ट करने का प्रयास था और किस आबादी को चिढ़ाने का, यह स्वतः स्पष्ट है।

असल में, देश में तुष्टीकरण का ऐसा वातावरण बना है कि किसी भी हद तक जाना पड़े, झूठे-सच्चे जो भी वायदे करने पड़े, न चाहते हुए भी नेतागण विशेष समुदाय का हमदर्द बनने की कोशिश करते रहते हैं। मगर ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि देश की मुख्यधारा, देश की संस्कृति, बहुसंख्यकों की आस्था, राष्ट्रीय भावनाओं से अलग होकर आप न अपना भला कर सकते हैं, न दूसरे का और न ही देश का चहुंमुखी विकास कर सकते हैं। उलटे, इससे उनको नुकसान ही हो सकता है।

उमेश प्रताप वत्स, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

नवरात्र और खान-पान

शक्ति के उपासकों की प्रचलित प्रथा

राजद नेता तेजस्वी यादव को मछली खाते देखकर कुछ लोगों की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, क्योंकि वे खुद को शुद्ध हिंदू बता रहे हैं, जिनकी शुद्धता का पैमाना बस यह है कि मंगल, गुरुवार और नवरात्र और त्योहारों में वे मांसाहार नहीं करते, बाकी सालों भर उनमें और मांसाहार में चोली-दामन जैसा रिश्ता रहता है। ये वे लोग हैं, जो 'बीफ एक्सपोर्टर' से दबोचकर चंदा लेते हैं, लेकिन सामने वाले के मछली खाने पर भी आपत्ति जताते हैं। गजब का पाखंड है यह तो। ऐसे लोग भूल रहे हैं कि भारत में खान-पान की आजादी है, जिसको जो पसंद है, वह खा सकता है। जैसा उसे रहना अच्छा लगता है, रह सकता है। यह उसका जीवन है, जिस पर उसका अपना अधिकार है। ऐसे में, आपत्ति जताने वाले भला क्यों तीसमारखां बन रहे हैं?

अमन सूरी, टिप्पणीकार

मौलिक अधिकार

तेजस्वी यादव के वीडियो पर चल रहा हंगामा इस बात का संकेत है कि भारत में अब मुद्दों की राजनीति नहीं होती, बल्कि मुद्दों को भटकाकर धर्म-जाति आदि के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो चुनाव में रोजगार मुद्दा होता, महंगाई पर चर्चा होती, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर बात होती, टूट रहे सामाजिक ढांचे पर चिंता जाहिर की जाती, लेकिन हमारे नेतागण बात कर रहे हैं मछली खाने पर और गोल टोपी न पहनने पर। यह सब बताता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मुद्दों का अभाव हो गया है और सियासी दल बेमतलब के मुद्दों पर एक-दूसरे से नूरा-कुश्ती लड़ रहे हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। वैसे भी, जब हमारा संविधान कुछ विशेष उपबंधों के साथ सभी लोगों को तमाम तरह के अधिकार देता है, तो बतौर नागरिक हम कैसे दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और उसके खाने-पीने पर टोक सकते हैं? वास्तव में, लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसी में है कि लोग न सिर्फ आजाद हों, बल्कि आजादी महसूस भी करें। यानी, उन पर किसी तरह का प्रतिबंध आयद न हो। मगर तेजस्वी यादव का प्रकरण बताता है कि एक खास विचारधारा के लोग पूरे देश पर हावी होना चाहते हैं। इसमें हमारी चुप्पी खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें ऐसे लोगों का मुखर विरोध करना चाहिए। वैसे भी देश के एक बड़े हिस्से में नवरात्र में बलि प्रदान की परंपरा है और वहां मांसाहार को देवी का प्रसाद माना जाता है। लिहाजा, नवरात्र में मांसाहार से आपत्ति क्यों?

दीपक, टिप्पणीकार

https://epaper.livehindustan.com

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 16 अप्रैल, 2024

दैनिक जागरण

धैर्य धारण कर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है

लोकतंत्र से छल

चुनाव आयोग की ओर से दी गई यह जानकारी चकित करने वाली है कि वह हर दिन शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर नकदी भी जब्त कर रहा है। नकदी समेत जो सामग्री जब्त की जा रही है, उसका कुल मूल्य करीब सौ करोड़ रुपये प्रतिदिन है। अब तक 4,650 करोड़ रुपये की नकदी और सामग्री जब्त की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के समय बरामद की गई धन और सामग्री से अधिक है। यह इसलिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तो मतदान का पहला चरण भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस बार प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने यानी उनके वोट खरीदने के लिए कहीं अधिक पैसा खपाने के साथ शराब, ड्रग्स आदि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली बहुत सी नकदी और सामग्री चुनाव आयोग की पकड़ में नहीं आ पाती होगी। भले ही चुनाव आयोग ने विभिन्न एजेंसियों को सतर्क कर रखा हो, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं कि हर वाहन और व्यक्ति की तलाशी लेने के साथ गांव-गांव निगरानी कर सकें।

चूंकि राजनीतिक दल इससे परिचित हैं कि आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग चुनावों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सक्रिय हो जाता है, इसलिए वे चुनाव की घोषणा होने के पहले ही लोगों के बीच पैसे और तरह-तरह की सामग्री बांटने लगते हैं। वहां तो यह काम शुरू ही हो जाता है, जहां चुनावों की घोषणा के पहले ही प्रत्याशी तय हो जाते हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में मतदाताओं के बीच वितरित की जाने वाली सामग्री के साथ नकदी जब्त की जा रही है, लेकिन इस पर हैरानी नहीं कि इसकी मात्रा तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में अधिक है। चुनावों में किस्म-किस्म की सामग्री और धन बांटने का रिवाज तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। पहले राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में यह वादा करते थे कि यदि वे सत्ता में आए तो अमुक-अमुक वस्तुएं या सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगे, लेकिन अब वे ऐसा वादा करने के साथ-साथ गुपचुप रूप से भी लोगों के बीच शराब, ड्रग्स के साथ पैसे बांटने लगे हैं। यह ठीक है कि बंगाल को छोड़कर चुनावों में बाहुबल पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन यह चिंताजनक है कि धनबल की भूमिका इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब पैसे और शराब आदि बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश की जाने लगी है। कुछ प्रत्याशी इस कोशिश में कामयाब भी होने लगे हैं। यह लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला एक बड़ा छल है। समस्या यह है कि जहां औसत मतदाता और विशेष रूप से गरीब तबका प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार रहता है, वहीं राजनीतिक दल चुनाव सुधारों को लेकर गंभीर नहीं।

असुरक्षित स्कूल वाहन

हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछले दिनों हुई दुर्घटना के बाद प्रदेश भर में स्कूल बसों और वाहनों की जांच हो रही है। खराब हालत और नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूल वाहनों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इस जांच में काफी संख्या में स्कूल बसों और वाहनों में खामियां मिलना चिंताजनक है। यह स्कूल संचालकों की लापरवाही को स्पष्ट तौर पर दिखाता है और यह बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है। कुछ स्थानों पर तो जांच में बसों के फर्श तक टूटे होने सहित कई गंभीर खामियां मिलीं। इस तरह की लापरवाही की अनदेखी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है। इस जांच के दौरान कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठते हैं। कई स्थानों पर नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों को लेकर स्कूल संचालकों पर महज 500-500 रुपये के चालान करना कार्रवाई के नाम पर मजाक ही लगता है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे का कारण बस की फिटनेस नहीं, इसके चालक का नशे में होना था। वाहनों की फिटनेस भी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्कूल वाहनों के चालकों और अटेंडेंट की नियमित जांच की व्यवस्था भी अति आवश्यक है। आरटीओ या पुलिस के साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी इसका दायित्व लेना होगा। जब चालक बस या वाहन लेकर स्कूल पहुंचें तो उनकी जांच हो और छुट्टी के बाद वे बच्चों को लेकर रवाना हों, उससे पहले भी जांच की जाए कि कहीं उन्होंने नशा तो नहीं किया है। इस जांच की स्कूलों में नियमित व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दायित्व प्रशासन और शिक्षा विभाग को लेना होगा। स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर भी लगा हो यह सुनिश्चित किया जाए।

> नियमों का पालन नहीं करने वाले पर महज 500-500 रुपये के चालान करना कार्रवाई के नाम पर मजाक है

चुनाव बाद की तैयारी में मोदी

संदीप घोष

प्रधानमंत्री मोदी के लिए चार सौ पार का नारा महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि अपने वादों को पूरा करने की एक जरूरत है

अवधेश राजपूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'अबकी बार, चार सौ पार' के चुनावी आह्वान पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अधिकांश लोग इसकी व्याख्या एक मजबूत नेता की सत्ता में वापसी को लेकर उसके आत्मविश्वास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे विपक्षी खेमे का हौसला पस्त करने वाला जुमला बता रहे हैं। कुछ लोग इसे विपक्ष को रौंदने का प्रयास और तानाशाही की ओर बढ़ते कदम के अशुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने खुलेआम आरोप लगाए हैं कि भाजपा की योजना संविधान बदलने और लोकतंत्र के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने की है। उन्होंने ऐसे किसी संभावित 'दुस्साहस' के परिणाम भुगतने और सड़कों पर उतरकर उसके विरोध की धमकी भी दी है। ऐसे उकसावे और संकेतों से मोदी विरोधियों ने वैश्विक समुदाय के समक्ष यही संदेश देने का प्रयास किया है यदि मोदी सत्ता में लौटते हैं तो इससे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जोखिम बढ़ सकते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों को अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक हिस्से द्वारा लपक लिया जाता है। वह लोकतांत्रिक संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे, मीडिया पर नियंत्रण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी बांड के जरिये भ्रष्टाचार से जुड़े विपक्ष के आरोपों में अपना सुर मिलाने लगता है। कुछ लोग तो न्यायपालिका तक को नहीं बख्शते कि उसकी भी सरकार से मिलीभगत है। कुछ को ईवीएम में खोट नजर आता है कि उसके जरिये चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। इन सबके बीच मोदी बेफिक्र होकर अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुटे हुए हैं।

मोदी कई मंचों पर कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल की उनकी कार्ययोजना तैयार है। आचार संहिता लागू होने से पहले ही उन्होंने सत्ता में वापसी के बाद शुरुआती सौ दिनों का एजेंडा भी पेश किया। भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपने घोषणा पत्र में भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया है, जिसमें कई नीतियों में निरंतरता रखने का उल्लेख है। एक ऐसे समय में जब लगभग हर एक राजनीतिक पंडित भाजपानीत राजग की सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है, तब भी मोदी पूरे जी-जान से चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं तो इसी कारण कि वह 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि इतनी सीटें जीतकर मोदी राजीव गांधी के रिकार्ड को तोड़ना चाहते हैं तो वे प्रधानमंत्री की मानसिकता को नहीं समझते। मोदी अपनी एक विरासत छोड़ना चाहते हैं। दो कार्यकालों के अनुभव से वह जानते हैं कि भाजपा और राजग को अपने वादे पूरे करने हैं तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत चाहिए होगा। इसीलिए मोदी और अमित शाह दो स्तरों पर काम में जुटे हैं।

जहां मोदी मतदाताओं को साधने में लगे हैं, जो केवल वही कर सकते हैं तो वहीं शाह गठबंधन के साथ ही विपक्षी नेताओं को जोड़ने में लगे हैं, जो भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ाने में योगदान दे सकें। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब भाजपा जीत को लेकर इतनी ही आश्वस्त है तो फिर वह क्यों इतने गठबंधन कर रही है, जिसमें कई बार उसे कुछ अतिरिक्त सीटें सहयोगियों के साथ साझा करनी पड़ रही हैं? इसका जवाब लोकसभा चुनावों से इतर की राजनीति में निहित है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव तो साथ में ही हो रहे हैं और कुछ राज्यों के लोकसभा के तत्काल बाद होने हैं। पिछले दस वर्षों में मोदी ने 'डबल इंजन' सरकार की महत्ता समझी है। उन्होंने समझा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़िया जुगलबंदी के बिना विकास के एजेंडे को सिरे चढ़ाना संभव नहीं। विपक्षी दलों की सत्ता वाले कई राज्यों में यह देखने में आया है कि उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की कई योजनाओं की राह में अवरोध खड़े किए। साथ ही श्रम सुधारों के साथ ही अन्य विकास गतिविधियों के लिए जमीन अधिग्रहण में भी अपेक्षित एवं आवश्यक सहयोग नहीं दिया। अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के मोदी के प्रयासों के पीछे कुछ और भी कारण हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यों में रेवड़ियां बांटने की होड़ बढ़ी है। इसने वित्तीय फिसलन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि लुभावने चुनावी वादों की पूर्ति के चक्कर में राज्य सरकारें कर्ज का अंबार लगा बैठी हैं। अंततः इसका बोझ केंद्र पर ही पड़ना है। हाल में दक्षिण के कुछ राज्यों द्वारा राहत पैकेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाएं इसका उदाहरण हैं। इसके चलते विकास गतिविधियों के लिए धन का अभाव निश्चित है। यह स्थिति न केवल वित्तीय रूप से घातक है, बल्कि इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश के संघीय ढांचे पर भी खतरे बढ़ा सकती है।

विपक्ष के सामने हाशिये पर पहुंचने का संकट बढ़ गया है। खासतौर से कांग्रेस बहुत परेशान है और इससे उबरने के लिए वह वामपंथी रुख अख्तियार करते हुए अति लोकलुभावन वादे करने में लगी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों और 'न्याय' के नाम पर नकदी इसके उदाहरण हैं। कांग्रेस से सबक लेते हुए कुछ क्षेत्रीय दल और आगे की सोच रहे हैं। वे भी रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं। कुछ नस्लीय विवाद छेड़ने पर आमादा हैं तो कुछ संसाधनों के वितरण की दृष्टि से उत्तर एवं दक्षिण के बीच विभाजन की खाई को गहरा करने में लगे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की सक्रियता के मुद्दे पर भी टकराव है। कुछ दलों ने भाजपा के हिंदुत्व की हवा निकालने का दांव चला है तो कुछ जातिगत जनगणना के जरिये भाजपा को घेरने और अपनी नैया पार लगाने की जुगत में लगे हैं। विपक्षी दलों का मोर्चा आइएनडीआइए छिन्न-भिन्न सा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ही भाजपा को मुख्य रूप से चुनौती पेश कर रही है।

विपक्षी दलों की राजनीति खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारों की वापसी की दिशा में ले जाने वाली है। दूसरी ओर भाजपा और मोदी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी का मानना है कि युवा भारत आकांक्षी है, जो मुफ्त रेवड़ियों के बजाय समृद्ध भारत की राह चुनेगा। ऐसा भारत बनाने के लिए मोदी को व्यापक बहुमत की आवश्यकता होगी। इस वजह से चार सौ पार का आह्वान उनके लिए महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक अपरिहार्यता है। इसीलिए वह पूरे देश को नापने में लगे हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

जमीनी हकीकत में बदलाव की चाहत

गिरीश्वर मिश्र

प्रलोभन देकर वोट बटोरने की कुप्रथा अंततः नुकसान ही करती है। इससे बचने की जरूरत है

जनता और दलों में बढ़ती दूरी। फाइल

आजादी के सात दशक बाद देश ने अमृतकाल की अवधि में एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्प लिया है। इस कार्य के लिए पूरे भारतीय समाज की संलग्नता जरूरी है। इस लक्ष्य के प्रति एकल समर्पण के साथ ही देश आगे बढ़ सकेगा। इसके लिए गणतंत्र की परिधि में कार्य करना होगा, जिसे संसदीय प्रणाली के अनुसार होना है। इस दृष्टि से लोकसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगली लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच सभी दल घोषणा पत्रों के जरिये जनता को लुभाने के लिए किस्म-किस्म के वादे करने में जुट रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है जनसमर्थन हासिल करना, ताकि अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जा सकें। हालांकि विभिन्न पार्टियों के परस्पर विरोधी दावे अक्सर दिग्भ्रमित भी करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा है कि पीएम मोदी की उपस्थिति, छवि और संवादपटुता ने उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उनकी गतिशीलता ने भारत की छवि को भरोसेमंद बनाया है। उनकी रीति-नीति में समावेश की प्रवृत्ति झलकती है। उनके नेतृत्व में डिजिटलीकरण, संसाधनों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आर्थिक मोर्चे पर मजबूती, प्रतिरक्षा तंत्र का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम आश्वस्ति का संकेत देते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

चूंकि राजनीति में भरोसा बड़ा अहम होता है। ऐसे में पार्टी हाईकमान राज-काज में भागीदारी के लिए योग्यता या अनुभव की जगह उम्मीदवार के रूप में अपने विश्वासपात्रों को तलाश रहे हैं, जो अविचल भाव से पार्टी नेतृत्व के प्रति 'वफादार' बने रहें। दूसरी ओर जनता को विश्वास में लेने के लिए 'न्याय' और 'गारंटी' जैसे जुमले तैरने लगे हैं। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में युवा, स्त्री, मजदूर, किसान, गरीब आदि समुदायों के लिए तरह-तरह की मुफ्त की खैरात बांटने का प्रलोभन देने वाली घोषणा दर घोषणा की भरमार दिख रही है। इस तरह वादों को जनता की भलाई का नुस्खा बनाकर पेश किया जा रहा है। मसलन नौकरी के अवसर देने, कर्ज की व्यवस्था एवं कर्जमाफी करने, महिला एवं किसान जैसे विभिन्न वर्गों के लिए अनुग्रह राशि देने और जातिगत जनगणना कराने के द्वारा सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दल परिवार-प्रथम की युक्ति भी आजमा रहे हैं। वे जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति पर काम करते भी दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामले नेताओं की साख के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। विपक्ष संकल्पहीन प्रतीत हो रहा है। सबसे पुराना दल कांग्रेस जिस तरह अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, वह चिंता की बात है। उसके लिए गहरे आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर जनता का भरोसा भाजपा को आश्वस्ति देता है।

आज जाति, क्षेत्र और मजहब जैसे समाज विभाजक आधारों का आसरा लेकर चुनाव की तैयारी की जा रही है। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति खतरनाक है। कई नेता गैर-जिम्मेदार होकर प्रलोभनों की इस तरह से बौछार कर रहे हैं, मानों वे देवताओं के खजांची कुबेर हैं और उनके खजाने पर उन्हीं का कब्जा है। इस तरह मतदाताओं को बहकावे में लाने की हर कोशिश चल रही है। सुरा, सुविधा और रुपया-पैसा बांटकर जनता से वोट की सौदेबाजी राजनीति को घृणित आधार दे रही है। नए माहौल में अब संसदीय प्रत्याशी को भी करोड़पति होना जरूरी हो रहा है। वह बाहुबली या संदिग्ध अपराधी हो तो भी चलता है।

भारत की जनता में सहनशीलता है और वह उदारतापूर्वक सबको अवसर देती है। चुनावी सफलता पाने के बाद नेता अक्सर सत्ता सुख भोगने में लग जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आम जनता के सुख-दुख पर उनका ध्यान कम ही जा पाता है। कटु सत्य यह भी है कि सत्तासीन सरकार के नुमाइंदे और जनता के बीच का बड़ा अंतराल आता गया है। यह एक तथ्य है कि आम जन और नेताओं के बीच का संवाद क्रमशः घटता गया है। संवाद का अभाव राजनीतिक प्रतिनिधियों और उनके दलों के प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार नेताओं की साख भी घटती-बढ़ती है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी कामकाज की धीमी गति और उबाने वाली नौकरशाही पूरी व्यवस्था की प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़ा कर देती है। आमजन अक्सर इनसे उद्धार पाने के लिए व्याकुल रहता है। नारों और वादों से उकता चुकी जनता को अब जमीनी हकीकत में बदलाव की चाहत है। इस आम चुनाव की भी यही कसौटी रहेगी। इसके लिए देश की जनता के मन में भी एजेंडा है। एक जनघोषणा पत्र चाहिए, जिसमें किसी एक की संतुष्टि नहीं, बल्कि लोककल्याण सर्वोपरि हो। लुंज-पुंज हो रही संस्थाओं का पुनर्जीवन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और सदाचार का पोषण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वंचितों की मौलिक सामर्थ्य बढ़ाना आवश्यक है, न कि उन्हें परोपजीवी बनाए रखना। इसके साथ ही पारदर्शिता के साथ सुशासन की व्यवस्था हो, न्याय प्रणाली को सुधारा जाए और शिक्षा का महत्व समझ कर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। युवा भारत के कर्णधार सरीखे लोगों जैसे महिलाएं, किसान, मजदूर और युवा वर्ग को सार्थक जीवन का अवसर उपलब्ध कराया जाए। भविष्य का भारत इन्हीं पर टिका है। फौरी प्रलोभन देकर वोट बटोरने की कुप्रथा अंततः नुकसान ही देती है और इससे बचने की जरूरत है। देश एक ऐसे सशक्त भारत का स्वप्न देख रहा है, जिसमें ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो, जो लोक कल्याण से प्रतिबद्ध हो और सबकी सहभागिता हो।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अंतिम समय

जीवन के अंतिम समय में अक्सर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे-बुरे कर्मों की याद उसे आने लगती है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि अंतिम समय में मनुष्य जो भी सोचता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विवेक द्वारा अपने परलोक को सुधारे। यह अवसर केवल मानव योनि में ही प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य जीव को विवेक प्राप्त नहीं होता है। रामचरितमानस में वर्णन है कि आखिरी समय में दशरथ जी को वह दृश्य याद आने लगा जिसमें उन्होंने श्रवण कुमार की अनजाने में हत्या कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप श्रवण कुमार के पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो रही है इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। भीष्म पितामह भी मृत्यु से पहले पूरे छह महीने तीरों की शैया पर पड़े रहे थे, परंतु दार्शनिकों के अनुसार भीष्म यादों के बाणों की शैया पर थे। कुरु वंश में भीष्म सबसे अधिक आयु के थे। इस स्थिति में उनसे आशा थी कि वह परिवार में होने वाले अनैतिक कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, परंतु उनके सामने भरी सभा में उनकी कुल वधू का चीरहरण होता रहा और वह चुपचाप देखते रहे, जिसका अपराधबोध उनके मन में बैठ गया। इसी कारण उन्हें आखिरी समय में तीरों जैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा था।

आज के युग में कई लोग जानबूझकर अनैतिक कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिस कारण वे अक्सर अशांत तथा आक्रोशित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब आखिरी समय आता है तब मन उसकी वृत्ति पशुओं जैसी बना देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होती है। इसके विपरीत शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामस्वरूप ईश्वर की छवि दिखाई देने लगती है। इसके फलस्वरूप वह परमेश्वर में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त होता है।

कर्नल शिवदान सिंह

राजनीति में भाषा का गिरता स्तर

सोनम लवंशी

> आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमर्यादित भाषा के वायरस से पीड़ित हो गया है, जो बहुत चिंताजनक है

लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां उफान पर हैं। सियासत के सूरमा जिक्र तो लोक कल्याण और समावेशी विकास करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर अनर्गल बयानबाजी ने राजनीति की शुचिता को तार-तार कर दिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को अमर्यादित भाषा के वायरस से कलंकित करने में हमारे राजनेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों कंगना रनौत, हेमा मालिनी और ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इसकी ताजा मिसाल हैं।

चुनाव आते ही हमारे देश में महिला सशक्तीकरण पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी आधुनिक समाज में भी चरम पर है। माना कि चुनाव का दौर चल रहा है और जीतने के लिए मुद्दे गढ़े जाते हैं, लेकिन यह कौन सा तरीका हुआ कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाएं। वह भी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं द्वारा। किसी भी महिला के खिलाफ किसी राजनेता को अभद्र टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? हमारी मां-बहन-बेटियां हैं। उनकी भी तो कोई इज्जत है। फिर किसी सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिला के खिलाफ बेजा बयानबाजी क्यों? दुखद तथ्य यह है कि अब तो महिलाएं स्वयं महिलाओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां कर रही हैं। कंगना रनौत से जुड़ा मामला कुछ ऐसा ही है। वैसे भी नारी की जिंदगी मर्यादा में सिमटी हुई है। पितृसत्तात्मक समाज के इस दौर में महिलाओं के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। आज भी आधुनिक होते समाज में महिलाओं के लिए पाबंदियां कम नहीं हैं।

आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमर्यादित भाषा के वायरस से पीड़ित हो चुका है, जो उसके लिए बहुत चिंता वाली बात है। राजनीति का अर्थ यह तो कतई नहीं होता कि सियासतदां एक-दूसरे के निजी जीवन पर आक्षेप करने लग जाएं। अभिव्यक्ति की आजादी यह तो नहीं कहती कि आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान को भंग करें। राजनीति निजी दुश्मनी अदा करने का कोई अखाड़ा भी नहीं। जब संवैधानिक व्यवस्था में राजनीति का जन्म देश को सुचारु रूप से आगे ले जाने के लिए हुआ फिर मूल उद्देश्य को क्यों बिसार रहे राजनेता? भाषा हमारे सामाजिक परिवेश का स्तर तय करती है। भाषा हमारे सोच का पैमाना होती है। बदजुबानी करने वाले नेता अपने बारे में न सोचकर एक बार देश की संस्कृति और परंपरा की चिंता कर लें, क्योंकि उनकी ओछी टिप्पणियां हमारे देश की छवि को निकृष्ट करने का कार्य करती हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भारत का उद्दीपन

'भारत के विकसित बनने की राह' शीर्षक से लिखे आलेख में रमेश कुमार दुबे ने विकसित भारत के संकल्प के ध्येय का उल्लेख करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों ने दिखाया है कि भारत के विकास का मार्ग संभव है। इसमें दो राय नहीं कि उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं गरीबी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रही हैं। गरीबी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों ने लाखों परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेने से बचाया है और बिजली के क्षेत्र में सुधार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को सुधारा है। इसके साथ ही गरीबी को मापने के लिए नए सूचकांकों की शुरुआत ने सरकार को सही दिशा में ले जाने में मदद की है। बहरहाल अब सरकार को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में नए और तकनीकी उपायों का प्रयोग करके हम युवाओं को रोजगार में सक्रिय कर सकते हैं। साथ ही कृषि और कृषि संबंधी उद्योगों में नवाचार को प्रोत्साहित करने से हम ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इससे हमें युवाओं को सक्रिय रूप से रोजगार में शामिल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। ऐसा कर हम न केवल अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर होंगे।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

मोदी की गारंटी पर विश्वास

राहुल वर्मा ने अपने आलेख ''मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र'' में भाजपा के संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं के साथ विगत दस वर्षों की उन उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में उज्ज्वल भविष्य का खाका खींचा हैं। लोक कल्याण के दायरे का विस्तार, जो कहा वो किया, सामाजिक, आर्थिक मोर्चे में तालमेल, विकसित भारत की परिकल्पना में निरंतरता संकल्प पत्र के केंद्र बिंदु हैं। अनुच्छेद-370, राम मंदिर निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून से सरकार ने अपनी विचारधारा को गति प्रदान कर लोगों के विश्वास को प्रबल किया कि मोदी है तो मुमकिन है। एक देश एक चुनाव के क्रांतिकारी बदलाव की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है। आर्थिक मोर्चे पर अपने तीसरे कार्यकाल में उनका संकल्प देश को दुनिया की तीसरी आर्थिकी के पायदान पर पहुंचाना है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार पर प्रहार भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जन कल्याण के दायरे का विस्तार, युवा शक्ति, महिलाओं, वंचितों, गरीबों, किसानों को महत्व, आयुष्मान योजना का विस्तार, 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के उपचार आदि की व्यवस्था भी संकल्प पत्र में है। उम्मीद है जनता के विश्वास पर संकल्प पत्र '400 के पार' ले जाने में सफल होगा।

कैलाश मेहरा, गुरुग्राम

धर्म है सेवा और सहयोग

पीड़ित मानवता की सेवा मानव की उदार भावनाओं का परिणाम है। यह मात्र नैतिक आचरण ही नहीं, धार्मिकता भी है। मानव के जन्म लेने के बाद जब तक वह जीवित रहता है, तब तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों व्यक्ति उसका सहयोग करते हैं। जन सहयोग से ही मानव जीवन का विकास होता है। लोक जीवन के इस उपकार का ऋण हम मानवता की सेवा करके ही उतार सकते हैं। हमारी संस्कृति सेवा की ही संस्कृति है। सेवा और जीव दया के हजारों प्रसंग हमारे इतिहास में भरे हैं। आज हम सेवा और सहयोग के मार्ग को त्याग कर निपट स्वार्थ में अंधे होकर जीने लगे हैं तो यह अपना सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पतन है। धन संचय को जीवन का मौलिक लक्ष्य न बनाएं। अपने धन का पीड़ित मानवता की सेवा में उपयोग करने से न केवल धन का सदुपयोग होगा, अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्योपार्जन का लाभ भी मिलेगा। पुण्य वे पवित्र कर्म हैं, जो जीवन को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। समाज में फैली हुई अमीर-गरीब की खाई को धनिक व्यक्ति चाहें तो मिटा सकते हैं।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

धैर्य धारण कर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है

लोकतंत्र से छल

चुनाव आयोग की ओर से दी गई यह जानकारी चकित करने वाली है कि वह हर दिन शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर नकदी भी जब्त कर रहा है। नकदी समेत जो सामग्री जब्त की जा रही है, उसका कुल मूल्य करीब सौ करोड़ रुपये प्रतिदिन है। अब तक 4,650 करोड़ रुपये की नकदी और सामग्री जब्त की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के समय बरामद धन और सामग्री से अधिक है। यह इसलिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी तो मतदान का पहला चरण भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस बार प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने यानी उनके वोट खरीदने के लिए कहीं अधिक पैसा खपाने के साथ शराब, ड्रग्स आदि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली बहुत सी नकदी और सामग्री चुनाव आयोग की पकड़ में नहीं आ पाती होगी। भले ही चुनाव आयोग ने विभिन्न एजेंसियों को सतर्क कर रखा हो, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं कि हर वाहन और व्यक्ति की तलाशी लेने के साथ गांव-गांव निगरानी कर सकें। चूंकि राजनीतिक दल इससे परिचित हैं कि आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग चुनावों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सक्रिय हो जाता है, इसलिए वे चुनाव की घोषणा होने के पहले ही लोगों के बीच पैसे और तरह-तरह की सामग्री बांटने लगते हैं। वहां तो यह काम शुरू ही हो जाता है, जहां चुनावों की घोषणा के पहले ही प्रत्याशी तय हो जाते हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में मतदाताओं के बीच वितरित की जाने वाली सामग्री के साथ नकदी जब्त की जा रही है, लेकिन इस पर हैरानी नहीं कि इसकी मात्रा तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में अधिक है। चुनावों में किस्म-किस्म की सामग्री और धन बांटने का रिवाज तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। पहले राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में यह वादा करते थे कि यदि वे सत्ता में आए तो अमुक-अमुक वस्तुएं या सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगे, लेकिन अब वे ऐसा वादा करने के साथ-साथ गुपचुप रूप से भी लोगों के बीच शराब, ड्रग्स के साथ पैसे बांटने लगे हैं। यह ठीक है कि बंगाल को छोड़कर चुनावों में बाहुबल पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन यह चिंताजनक है कि धनबल की भूमिका इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब पैसे और शराब आदि बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश की जाने लगी है। कुछ प्रत्याशी इस कोशिश में कामयाब भी होने लगे हैं। यह लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला एक बड़ा छल है। समस्या यह है कि जहां औसत मतदाता और विशेष रूप से गरीब तबका प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार रहता है, वहीं राजनीतिक दल चुनाव सुधारों को लेकर गंभीर नहीं।

कड़ी सजा मिले

शराबबंदी के बावजूद प्रदेश में भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हो रही है। सरकार धंधेबाजों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने की हरसंभव कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद दूसरे राज्यों से इसकी आपूर्ति निर्बाध जारी है। ऐसा नहीं है कि संबंधित विभाग की ओर से इससे रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे। शराब आपूर्ति को लेकर दूसरे राज्यों के कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इनका नेटवर्क काफी हद तक ध्वस्त भी किया जा चुका है। चिंता की बात है कि इसके साथ ही अन्य नशीले पदार्थों का व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। खासकर सीमांचल के इलाके में स्थिति गंभीर है। स्थानीय प्रशासन इसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है। इससे यह साफ है कि इस तरह के अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को कानून का डर नहीं रह गया है या फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल रही। जाहिर है, पुलिस व मद्यनिषेध विभाग को इस दिशा में और गंभीर होने की आवश्यकता है। संबंधित विभागों को सूचना तंत्र को भी और मजबूत करना होगा, ताकि सटीक इनपुट पर बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई की जा सके। अहम यह है कि जो लोग इस धंधे के आरोप में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत पुख्ता साक्ष्य के साथ न्यायालय में पैरवी की जाए, जिससे उन्हें जल्द से जल्द सजा मिल सके। साथ ही, उन अधिकारियों-कर्मचारियों को चिन्हित करने की जरूरत है जो कहीं न कहीं आर्थिक लाभ के लिए अपने कार्य में कोताही कर इस सिंडिकेट की मदद कर रहे। इनलोगों को जबतक बेनकाब नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी प्रयास नाकाफी ही साबित होगा।

नशीले पदार्थों के धंधे पर पूरी तरह नकेल के लिए संबंधित विभाग व पुलिस को रणनीति में बदलाव पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप इजरायल पर ईरान के हमले के फलस्वरूप पश्चिम एशिया को बड़ी अशांति की ओर बढ़ते देख रहे हैं?

आज का सवाल

क्या पूर्व न्यायाधीशों का यह कहना सही है कि न्यायपालिका को दबाव में लेने की कोशिश हो रही है?

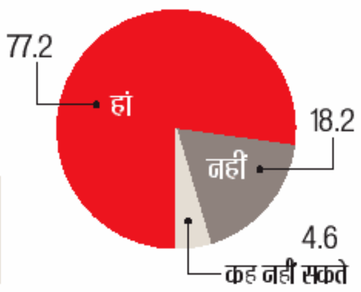

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

चुनाव बाद की तैयारी में मोदी

संदीप घोष

प्रधानमंत्री मोदी के लिए चार सौ पार का नारा महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि अपने वादों को पूरा करने की एक जरूरत है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'अबकी बार, चार सौ पार' के चुनावी आह्वान पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अधिकांश लोग इसकी व्याख्या एक मजबूत नेता की सत्ता में वापसी को लेकर उसके आत्मविश्वास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे विपक्षी खेमे का हौसला पस्त करने वाला जुमला बता रहे हैं। कुछ लोग इसे विपक्ष को रौंदने का प्रयास और तानाशाही की ओर बढ़ते कदम के अशुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने खुलेआम आरोप लगाए हैं कि भाजपा की योजना संविधान बदलने और लोकतंत्र के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने की है। उन्होंने ऐसे किसी संभावित 'दुस्साहस' के परिणाम भुगतने और सड़कों पर उतरकर उसके विरोध की धमकी भी दी है। ऐसे उकसावे और संकेतों से मोदी विरोधियों ने वैश्विक समुदाय के समक्ष यही संदेश देने का प्रयास किया है यदि मोदी सत्ता में लौटते हैं तो इससे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जोखिम बढ़ सकते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों को अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक हिस्से द्वारा लपक लिया जाता है। वह लोकतांत्रिक संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे, मीडिया पर नियंत्रण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी बांड के जरिये भ्रष्टाचार से जुड़े विपक्ष के आरोपों में अपना सुर मिलाने लगता है। कुछ लोग तो न्यायपालिका तक को नहीं बख्शते कि उसकी भी सरकार से मिलीभगत है। कुछ को ईवीएम में खोट नजर आता है कि उसके जरिये चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। इन सबके बीच मोदी बेफिक्र होकर अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुटे हुए हैं।

मोदी कई मंचों पर कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल की उनकी कार्ययोजना तैयार है। आचार संहिता लागू होने से पहले ही उन्होंने सत्ता में वापसी के बाद शुरुआती सौ दिनों का एजेंडा भी पेश किया। भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपने घोषणा पत्र में भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया है, जिसमें कई नीतियों में निरंतरता रखने का उल्लेख है। एक ऐसे समय में जब लगभग हर एक राजनीतिक पंडित भाजपानीत राजग की सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है, तब भी मोदी पूरे जी-जान से चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं तो इसी कारण कि वह 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो ऐसा सोचते हैं कि इतनी सीटें जीतकर मोदी राजीव गांधी के रिकार्ड को तोड़ना चाहते हैं तो वे प्रधानमंत्री की मानसिकता को नहीं समझते। मोदी अपनी एक विरासत छोड़ना चाहते हैं। दो कार्यकालों के अनुभव से वह जानते हैं कि भाजपा और राजग को अपने वादे पूरे करने हैं तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत चाहिए होगा। इसीलिए मोदी और अमित शाह दो स्तरों पर काम में जुटे हैं।

अवधेश राजपूत

जहां मोदी मतदाताओं को साधने में लगे हैं, जो केवल वही कर सकते हैं तो वहीं शाह गठबंधन के साथ ही विपक्षी नेताओं को जोड़ने में लगे हैं, जो भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ाने में योगदान दे सकें। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब भाजपा जीत को लेकर इतनी ही आश्वस्त है तो फिर वह क्यों इतने गठबंधन कर रही है, जिसमें कई बार उसे कुछ अतिरिक्त सीटें सहयोगियों के साथ साझा करनी पड़ रही हैं? इसका जवाब लोकसभा चुनावों से इतर की राजनीति में निहित है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव तो साथ में ही हो रहे हैं और कुछ राज्यों के लोकसभा के तत्काल बाद होने हैं। पिछले दस वर्षों में मोदी ने 'डबल इंजन' सरकार की महत्ता समझी है। उन्होंने समझा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़िया जुगलबंदी के बिना विकास के एजेंडे को सिरे चढ़ाना संभव नहीं। विपक्षी दलों की सत्ता वाले कई राज्यों में यह देखने में आया है कि उन्होंने आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की कई योजनाओं की राह में अवरोध खड़े किए। साथ ही श्रम सुधारों के साथ ही अन्य विकास गतिविधियों के लिए जमीन अधिग्रहण में भी अपेक्षित एवं आवश्यक सहयोग नहीं दिया। अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के मोदी के प्रयासों के पीछे कुछ और भी कारण हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यों में रेवड़ियां बांटने की होड़ बढ़ी है। इसने वित्तीय फिसलन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि लुभावने चुनावी वादों की पूर्ति के चक्कर में राज्य सरकारें कर्ज का अंबार लगा बैठी हैं। अंततः इसका बोझ केंद्र पर ही पड़ना है। हाल में दक्षिण के कुछ राज्यों द्वारा राहत पैकेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाएं इसका उदाहरण हैं। इसके चलते विकास गतिविधियों के लिए धन का अभाव निश्चित है। यह स्थिति न केवल वित्तीय रूप से घातक है, बल्कि इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश के संघीय ढांचे पर भी खतरे बढ़ा सकती है।

विपक्ष के सामने हाशिये पर पहुंचने का संकट बढ़ गया है। खासतौर से कांग्रेस बहुत परेशान है और इससे उबरने के लिए वह वामपंथी रुख अख्तियार करते हुए अति लोकलुभावन वादे करने में लगी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों और 'न्याय' के नाम पर नकदी इसके उदाहरण हैं। कांग्रेस से सबक लेते हुए कुछ क्षेत्रीय दल और आगे की सोच रहे हैं। वे भी रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं। कुछ नस्लीय विवाद छेड़ने पर आमादा हैं तो कुछ संसाधनों के वितरण की दृष्टि से उत्तर एवं दक्षिण के बीच विभाजन की खाई को गहरा करने में लगे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की सक्रियता के मुद्दे पर भी टकराव है। कुछ दलों ने भाजपा के हिंदुत्व की हवा निकालने का दांव चला है तो कुछ जातिगत जनगणना के जरिये भाजपा को घेरने और अपनी नैया पार लगाने की जुगत में लगे हैं। विपक्षी दलों का मोर्चा आइएनडीआइए छिन्न-भिन्न सा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ही भाजपा को मुख्य रूप से चुनौती पेश कर रही है।

कांग्रेस और विपक्षी दलों की राजनीति खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारों की वापसी की दिशा में ले जाने वाली है। दूसरी ओर भाजपा और मोदी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी का मानना है कि युवा भारत आकांक्षी है, जो मुफ्त रेवड़ियों के बजाय समृद्ध भारत की राह चुनेगा। ऐसा भारत बनाने के लिए मोदी को व्यापक बहुमत की आवश्यकता होगी। इस वजह से चार सौ पार का आह्वान उनके लिए महज चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक अपरिहार्यता है। इसीलिए वह पूरे देश को नापने में लगे हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

जमीनी हकीकत में बदलाव की चाहत

गिरीश्वर मिश्र

प्रलोभन देकर वोट बटोरने की कुप्रथा अंततः नुकसान ही करती है। इससे बचने की जरूरत है

आजादी के सात दशक बाद देश ने अमृतकाल की अवधि में एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण के लिए संकल्प लिया है। इस कार्य के लिए पूरे भारतीय समाज की संलग्नता जरूरी है। इस लक्ष्य के प्रति एकल समर्पण के साथ ही देश आगे बढ़ सकेगा। इसके लिए गणतंत्र की परिधि में कार्य करना होगा, जिसे संसदीय प्रणाली के अनुसार होना है। इस दृष्टि से लोकसभा का चुनाव एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगली लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच सभी दल घोषणा पत्रों के जरिये जनता को लुभाने के लिए किस्म-किस्म के वादे करने में जुट रहे हैं। सबका एक ही लक्ष्य है जनसमर्थन हासिल करना, ताकि अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जा सकें। हालांकि विभिन्न पार्टियों के परस्पर विरोधी दावे अक्सर दिग्भ्रमित भी करते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा है कि पीएम मोदी की उपस्थिति, छवि और संवादपटुता ने उनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उनकी गतिशीलता ने भारत की छवि को भरोसेमंद बनाया है। उनकी रीति-नीति में सम्मावेश की प्रवृत्ति झलकती है। उनके नेतृत्व में डिजिटलीकरण, संसाधनों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, आर्थिक मोर्चे पर मजबूती, प्रतिरक्षा तंत्र का स्वदेशीकरण, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम आश्वस्ति का संकेत देते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

चूंकि राजनीति में भरोसा बड़ा अहम होता है। ऐसे में पार्टी हाईकमान राज-काज में भागीदारी के लिए योग्यता या अनुभव की जगह उम्मीदवार के रूप में अपने विश्वासपात्रों को तलाश रहे हैं, जो अविचल भाव से पार्टी नेतृत्व के प्रति 'वफादार' बने रहें। दूसरी ओर जनता को विश्वास में लेने के लिए 'न्याय' और 'गारंटी' जैसे जुमले तैरने लगे हैं। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में युवा, स्त्री, मजदूर, किसान, गरीब आदि समुदायों के लिए तरह-तरह की मुफ्त की खैरात बांटने का प्रलोभन देने वाली घोषणा दर घोषणा की भरमार दिख रही है। इस तरह वादों को जनता की भलाई का नुस्खा बनाकर पेश किया जा रहा है। मसलन नौकरी के अवसर देने, कर्ज की व्यवस्था एवं कर्जमाफी करने, महिला एवं किसान जैसे विभिन्न वर्गों के लिए

जनता और दलों में बढ़ती दूरी ● फाइल

अनुग्रह राशि देने और जातिगत जनगणना कराने के द्वारा सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दल परिवार-प्रथम की युक्ति भी आजमा रहे हैं। वे जातिवाद और तुष्टीकरण की नीति पर काम करते भी दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्तता के मामले नेताओं की साख के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। विपक्ष का एक मोर्चा आइएनडीआइए संकल्पहीन प्रतीत हो रहा है। सबसे पुराना दल कांग्रेस जिस तरह अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, वह चिंता की बात है। उसके लिए गहरे आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर जनता का भरोसा भाजपा को आश्वस्ति देता है।

आज जाति, क्षेत्र और मजहब जैसे समाज विभाजक आधारों का आसरा लेकर चुनाव की तैयारी की जा रही है। इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति खतरनाक है। फिर भी इसे अंजाम देने की मुहिम जारी है। कई नेता गैर-जिम्मेदार होकर प्रलोभनों की इस तरह से बौछार कर रहे हैं, मानों वे देवताओं के खजांची कुबेर हैं और उनके खजाने पर उन्हीं का कब्जा है। इस तरह मतदाताओं को बहकावे में लाने की हर कोशिश चल रही है। सुरा, सुविधा और रुपया-पैसा बांटकर जनता से वोट की सौदेबाजी राजनीति को घृणित आधार दे रही है। नए माहौल में अब संसदीय प्रत्याशी को भी करोड़पति होना जरूरी हो रहा है। वह बाहुबली या संदिग्ध अपराधी हो तो भी चलता है।

भारत की जनता में सहनशीलता है और वह उदारतापूर्वक सबको अवसर देती है। चुनावी सफलता पाने के बाद नेता अक्सर सत्ता सुख भोगने में लग जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आम जनता के सुख-दुख पर उनका ध्यान कम ही जा पाता है। कटु सत्य यह भी है कि सत्तासीन सरकार के नुमाइंदे और जनता के बीच का बड़ा अंतराल आता गया है। यह एक तथ्य है कि आम जन और नेताओं के बीच का संवाद क्रमशः घटता गया है। संवाद का अभाव राजनीतिक प्रतिनिधियों और उनके दलों के प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसी के अनुसार नेताओं की साख भी घटती-बढ़ती है। महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी कामकाज की धीमी गति और उबाने वाली नौकरशाही पूरी व्यवस्था की प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़ा कर देती है। आमजन अक्सर इनसे उद्धार पाने के लिए व्याकुल रहता है। नारों और वादों से उकता चुकी जनता को अब जमीनी हकीकत में बदलाव की चाहत है। इस आम चुनाव की भी यही कसौटी रहेगी। इसके लिए देश की जनता के मन में भी एजेंडा है। एक जनघोषणा पत्र चाहिए, जिसमें किसी एक की संतुष्टि नहीं, बल्कि लोककल्याण सर्वोपरि हो। लुंज-पुंज हो रही संस्थाओं का पुनर्जीवन, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और सदाचार का पोषण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, वंचितों की मौलिक सामर्थ्य बढ़ाना आवश्यक है, न कि उन्हें परोपजीवी बनाए रखना। इसके साथ ही पारदर्शिता के साथ सुशासन की व्यवस्था हो, न्याय प्रणाली को सुधारा जाए और शिक्षा का महत्व समझ कर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। युवा भारत के कर्णधार सरीखे लोगों जैसे महिलाएं, किसान, मजदूर और युवा वर्ग को सार्थक जीवन का अवसर उपलब्ध कराया जाए। भविष्य का भारत इन्हीं पर टिका है। फौरी प्रलोभन देकर वोट बटोरने की कुप्रथा अंततः नुकसान ही देती है और इससे बचने की जरूरत है। देश एक ऐसे सशक्त भारत का स्वप्न देख रहा है, जिसमें ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो, जो लोक कल्याण से प्रतिबद्ध हो और सबकी सहभागिता हो।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अंतिम समय

जीवन के अंतिम समय में अक्सर व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे-बुरे कर्मों की याद उसे आने लगती है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि अंतिम समय में मनुष्य जो भी सोचता है वही उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विवेक द्वारा अपने परलोक को सुधारे। यह अवसर केवल मानव योनि में ही प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य जीव को विवेक प्राप्त नहीं होता है।

रामचरितमानस में वर्णन है कि आखिरी समय में दशरथ जी को वह दृश्य याद आने लगा जिसमें उन्होंने श्रवण कुमार को अनजाने में हत्या कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप श्रवण कुमार के पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो रही है इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। भीष्म पितामह भी मृत्यु से पहले पूरे छह महीने तीरों की शैया पर पड़े रहे थे, परंतु दार्शनिकों के अनुसार भीष्म यादों के बाणों की शैया पर थे, जिनके द्वारा उन्हें तीरों से भी ज्यादा पीड़ा मिल रही थी। कुरु वंश में भीष्म सबसे अधिक आयु के थे। इस स्थिति में उनसे आशा थी कि वह परिवार में होने वाले अनैतिक कार्यों के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, परंतु उनके सामने भरी सभा में उनकी कुल वधू का चीरहरण होता रहा और वह चुपचाप देखते रहे, जिसका अपराधबोध उनके मन में बैठ गया। इसी कारण उन्हें आखिरी समय में तीरों जैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा था।

आज के युग में कई लोग जानबूझकर अनैतिक कर्मों में लिप्त रहते हैं, जिस कारण वे अक्सर अशांत तथा आक्रोशित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जब आखिरी समय आता है तब मन उसकी वृत्ति पशुओं जैसी बना देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे अगले जन्म में पशु योनि प्राप्त होती है। इसके विपरीत शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामस्वरूप ईश्वर की छवि दिखाई देने लगती है। इसके फलस्वरूप वह परमेश्वर में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए।

कर्नल शिवदान सिंह

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

भारत का उद्दीपन

'भारत के विकसित बनने की राह' शीर्षक से लिखे आलेख में रमेश कुमार दुबे ने विकसित भारत के संकल्प के ध्येय का उल्लेख करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों ने दिखाया है कि भारत के विकास का मार्ग संभव है। इसमें दो राय नहीं कि उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं गरीबी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रही हैं। गरीबी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों ने लाखों परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेने से बचाया है और बिजली के क्षेत्र में सुधार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को सुधारा है। इसके साथ ही गरीबी को मापने के लिए नए सूचकांकों की शुरुआत ने सरकार को सही दिशा में ले जाने में मदद की है। बहरहाल अब सरकार को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में नए और तकनीकी उपायों का प्रयोग करके हम युवाओं को रोजगार में सक्रिय कर सकते हैं। साथ ही कृषि और कृषि संबंधी उद्योगों में नवाचार को प्रोत्साहित करने से हम ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इससे हमें युवाओं को सक्रिय रूप से रोजगार में शामिल करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। ऐसा कर हम न केवल अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर होंगे।

awanishg30@gmail.com

दल बदलने वालों को परखें

जब समय की धारा बदलती है, तो विचार भी बदल जाते हैं। राजनीतिक मैदान में भी यही हो रहा है। कांग्रेस से भाजपा में और फिर वापस, या फिर उम्मीदवारों की विचारधारा को बदलने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या यह केवल वोटों के लिए है या कुछ और? आम नागरिक के लिए ऐसे बहुत से सवाल बहस का विषय हैं। इस समय देश में आस्था में बदलाव की हवा चल रही है, एक ओर नेताओं का दल बदलना तो दूसरी ओर, नेताओं की विचारधारा का बदलना। क्या यह सच में एक साफ व स्वतंत्र मन का परिणाम है, या कुछ और? जागरूक जनता यह सोचने को विवश है कि क्या यह नेताओं की चालाकी का खेल है या फिर उनके वास्तविक आत्मविश्वास का प्रतीक है। देश भर में हो रहे दल बदल से नेताओं में भाजपा की विचारधारा के प्रति विश्वास बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नेता केवल अपने हितों के लिए ही बदल रहे हैं, या फिर वास्तव में वे जनता के हित में काम करने के लिए आदान-प्रदान का खेल कर रहे हैं। विचार बदलना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यह भी सच है कि इस प्रकरण में नेता का आत्मविश्वास हो, या फिर चालाकी का खेल। जनता को सोचने का एक नया आयाम होना चाहिए। क्या हमें अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है, या फिर हमें उनकी निष्पक्षता पर कुछ संदेह है। यह सवाल हर नागरिक को ध्यान में रखना चाहिए। समय बदल रहा है, तो हमें भी अपने सोच को बदलने की आवश्यकता है। यह नहीं कि हमें अपनी विचारधारा का एकबारगी त्याग देना चाहिए, हमें अपने नेताओं पर विश्वास करने की वजह की जांच करनी चाहिए। तभी लोकतंत्र सशक्त होगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

भाजपा का सियासी रथ दक्षिण की ओर

तमिलनाडु में भाजपा की स्थिति मजबूत होती जा रही है। वहां की नौ लोकसभा सीटों पर कांग्रेस एवं 30 सीटों पर डीएमके गठबंधन का कब्जा है। तमिलनाडु में भाजपा के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। कन्याकुमारी में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है। इस बार भाजपा का सियासी रथ पहुंचने और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की 'मेरी मिट्टी, मेरे लोग' के नारे से सियासी हवा का रुख बदलता दिख रहा है। इस बार भाजपा का सियासी रथ राज्य के 234 विधानसभा क्षेत्रों से गुजर चुका है। अब भाजपा तमिलनाडु में मजबूत होती दिख रही है। कांग्रेस की इस बार दाल गलती नहीं प्रतीत हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने रोड शो किया। उधर, अमित शाह का रथ कन्याकुमारी में पहुंचने पर लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा इस बार तमिलनाडु में 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। राज्य में मोदी की गारंटी का असर है। नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उनकी जनसभा में जुट रही भीड़ भाजपा के बढ़ते जनाधार का प्रमाण है। तमिलनाडु में योजनाओं एवं परियोजनाओं के विकास लक्षित कार्यों का प्रभाव है। जयललिता के बाद सियासी हालात बदले हैं। राममंदिर और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से भाजपा के प्रति लगाव बढ़ा है। तमिलनाडु में ये दोनों मुद्दे असरकारी दिख रहे हैं। दक्षिण में सनातनी संस्कारों के प्रति आम जनमानस में आग्रह बढ़ा है।

कांतिलाल मांडोत, पटना

पोस्ट

इजरायल का एयर डिफेंस अद्भुत है। इसीलिए ईरान के हवाई हमले से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि इजरायल जो पलटवार करेगा, उसमें क्या होगा? अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

कुछ दिन पहले जर्मनी की सरकार भारत में लोकतंत्र को लेकर चिंता व्यक्त कर रही थी, जबकि इस समय जर्मनी में सभाएं-रैलियां करना तक मुश्किल हो गया है। कुछ यही हाल पश्चिम के कई अन्य देशों में होता जा रहा है।

प्रकाश के. रे@pkray11

राजनाथ सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान उन्हें अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। असल में भूलने की बीमारी ने देश का बड़ा नुकसान किया है। देश को भारत विभाजन और आपातकाल कभी नहीं भूलना चाहिए। अगली पीढ़ियों को इस बारे में विस्तार से तथ्यात्मक जानकारियां दी जानी चाहिए। रंगनाथ सिंह@rangnathsingh_

रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद मुंबई इंडियंस मैच हार गई। हार्दिक पांड्या ने चेन्नई की जीत का श्रेय भले ही धौनी को दिया हो, लेकिन कप्तान के रूप में उन्हें अपने प्रदर्शन की समीक्षा भी करनी होगी। मुंबई के लिए आगे की राह दुर्गम होती जा रही है। सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जनपथ

इजरायल पर दाग कर गोला- बम ईरान,
समझ रहा है स्वयं को सबसे बड़का डान।
सबसे बड़का डान उठे अब यदि अमरीका,
घूमेगा ईरान लिए तब चेहरा फीका।
खाकर गहरी चोट शेर जब होता घायल,
समझो वैसा आज हो चुका है इजरायल।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक पिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 5

****

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

हृदय की गहन खुशी एक चुंबक की तरह है, जो जीवन का मार्ग बताती है। -मदर टेरेसा

आज अगर दुनिया में बिकने वाला हर सातवां आईफोन भारत में ही बन रहा है, तो इससे देश में 2014 में शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' अभियान की सार्थकता ही साबित होती है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए ऐसी कामयाबियों को अन्य उत्पादों के संदर्भ में दोहराना भी जरूरी है।

मेक इन इंडिया

आईफोन निर्माता कंपनी एपल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से करीब दस अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात करके, जो उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में किसी सिंगल ब्रांड उत्पाद का भारत से किया गया अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है, एक नया कीर्तिमान तो स्थापित किया ही है, देश की अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक असर भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एपल का वित्तीय वर्ष 2024-25 तक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत दस अरब डॉलर का निर्यात-लक्ष्य था, जिसे एक वर्ष पहले ही हासिल कर लेना निस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि है। ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि एपल ने 2023-24 के दौरान भारत में 14 अरब डॉलर के आईफोन निर्मित किए, और अब दुनिया में बिकने वाले कुल आईफोन के 14 फीसदी का उत्पादन भारत में ही हो रहा है। आज अगर दुनिया में बिकने वाला हर सातवां आईफोन भारत में ही बन रहा है, तो इससे 2014 में शुरू 'मेक इन इंडिया' अभियान की सार्थकता ही साबित होती है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका व चीन के बीच तल्ख रिश्तों को देखते हुए एपल को अपनी आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए उसने चीन से, जो अब भी सबसे ज्यादा आईफोन बनाने वाला देश है, बाहर कुछ विनिर्माण प्लांट लगाने की सोची और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार भारत की ओर रुख किया। 2017 में भारत में आईफोन का निर्माण शुरू हुआ था। ताइवान की दिग्गज कंपनियों, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की मदद से अपने स्थानीय उत्पादन का विस्तार किया। इसके अलावा, कर्नाटक में विस्ट्रान कारपोरेशन का भी संयंत्र है, जिसका कुछ ही समय पहले टाटा समूह ने अधिग्रहण किया था। गौरतलब है कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा पहले देश में स्मार्टफोन का प्रसार हुआ और शुरुआत में भारतीय खरीदारों का रुझान अपने बजट के अनुकूल चीन में निर्मित हैंडसेट की ओर ही दिखा, लेकिन हालिया वर्षों में स्टेटस सिंबल के तौर पर आईफोन के प्रति भारतीयों का आकर्षण तेजी से बढ़ा है। एपल के इस प्रसार से देश में विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ने के साथ एक सशक्त विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा भी स्थापित हुई है। यही नहीं, पीएलआई की शुरुआत के बाद से इसने डेढ़ लाख नई प्रत्यक्ष और करीब तीन लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। कुल मिलाकर देखें, तो यह 'मेक इन इंडिया' की कामयाबी की कहानी है, जिसे, 2047 तक विकसित राष्ट्र होने के लिए, अन्य उत्पादों के संदर्भ में दोहराना भी जरूरी है।

पूरा इलाज बनाम मरहम-पट्टी

जहां भाजपा ने अपने घोषणापत्र को महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीबों पर केंद्रित रखा है, वहीं कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों एवं वंचित समुदाय के लिए सामाजिक न्याय की बात की है।

क्या

अकेले चुनाव घोषणापत्र से चुनाव जीता जा सकता है? खैर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ऐसा ही सोचती हैं। उन्होंने अपने घोषणापत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें भविष्य के भारत के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट किया है। कांग्रेस ने जहां अपने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है, वहीं भाजपा ने 'संकल्प पत्र'।

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, भाजपा का घोषणापत्र विकसित भारत के चार स्तंभों-महिला शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीबों पर केंद्रित है। यह 'जीवन की गरिमा', 'जीवन की गुणवत्ता', 'अवसरों की संख्या' के साथ-साथ 'अवसरों की गुणवत्ता' की बात करता है। दूसरी तरफ, कांग्रेस का घोषणापत्र राहुल गांधी के नजरिये को प्रतिबिंबित करता है अथवा वह समस्याओं के वास्तविक समाधान के बारे में क्या सोचते हैं। यह पांच 'न्याय' अथवा युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों एवं हाशिये के समुदाय के लिए सामाजिक न्याय की पांच गारंटी की बात करता है। इसमें सरकारी नौकरी, जातिगत जनगणना, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के खाते में धन हस्तांतरण का वादा किया गया है। यह 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी का वादा करता है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

कई विशेषज्ञों ने यह समझने के लिए दोनों घोषणापत्रों की तुलना करने की कोशिश की है कि कौन-सी पार्टी पूर्ण उपचारों की बात करती है और कौन-सी अनिवार्य रूप से मरहम-पटटी की। कांग्रेस का घोषणापत्र मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत ही आकर्षक और सरल समाधान जैसा दिखता है। भाजपा का घोषणापत्र भी पार्टी की कल्याणकारी राजनीति को जारी रखने और विस्तारित करने, गरीबों और हाशिये पर रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा रोजगार पैदा करने वाली नीतियों का वादा करता है।

भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं, गरीबों, युवाओं एवं किसानों समेत 10 सामाजिक समूहों और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था समेत 14 क्षेत्रों को गारंटी सूची में शामिल किया गया है। हरेक मामले में मोदी ने नीतिगत हस्तक्षेप, जमीनी कार्यान्वयन और योजनाओं के पूरा होने का आश्वासन दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भाजपा के अंत्योदय का मार्गदर्शक मंत्र पूरा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा के वादों को मोदी की गारंटी का समर्थन है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने और फिर 2019 में दूसरा कार्यकाल पाने के बाद से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी सरकार अकेले सभी वादों को पूरा करने में विश्वास करती है। इससे यह भी समझ में आता है कि भाजपा 'हिंदुत्व' पर ज्यादा जोर नहीं देगी, बल्कि यह मोदी के इच्छानुसार 'सबका विकास' पर जोर देगी। भाजपा मध्यवर्ग और नव-मध्यवर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है, जिसके बारे में उसका दावा है कि उसे उसने पिछले दशक में गरीबी से बाहर निकाला है। हर पहल के लिए मोदी की गारंटी की वजह यही है कि मतदाताओं की समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमता पर भरोसा दिलाने के लिए भाजपा पूरी तरह से मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर है।

गरीबों से अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन, रियायती स्वास्थ्य सेवा, आवास सुविधाएं, सौर ऊर्जा उत्पादन जैसी योजनाओं के जरिये शून्य बिजली बिल का वादा किया गया है। मध्य वर्ग के लिए, दूसरी एवं तीसरी श्रेणी के शहरों में उच्च वेतन वाली नौकरी के सृजन, जीवन की सुगमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा का वादा किया गया है।

महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, कल्याण, सुरक्षा और कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया है। गौरतलब है कि महिलाओं ने पिछले लोकसभा चुनाव एवं कई राज्यों के चुनावों में जीत हासिल करने में भाजपा की मदद की थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी लगातार मोदी सरकार की पहुंच में बने हुए हैं। घोषणापत्र में उनकी विरासत और संस्कृति की रक्षा, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और उनके लिए आजीविका के स्तरों का विस्तार करने की बात कही गई है।

दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि उसे गरीब समर्थक एवं कल्याणोन्मुख घोषणापत्र पर टिके रहना चाहिए। यह गरीबों के लिए आर्थिक भुगतान, श्रमिकों को उच्च मजदूरी एवं ग्रेजुएटों के लिए अनिवार्य तौर पर भुगतान के साथ इंटर्नशिप का वादा करता है। कांग्रेस ने अपने मूल मतदाताओं का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की है। इसने सभी गरीब परिवारों को एक लाख रुपये देने का वादा किया है, हालांकि 2011 के बाद से देश में कितने गरीब हैं, उसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, जब आखिरी बार सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। कांग्रेस ने दूसरे भूमि सुधार में अतिरिक्त सरकारी जमीन को गरीबों में बांटने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने राष्ट्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कानून बनाने का भी वादा किया है, जिसके तहत किसी को भी एमएसपी से कम मूल्य पर अनाज खरीदने की इजाजत नहीं होगी। यह फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन देने और खेती को भी मनरेगा के दायरे में लाने का वादा करती है। पार्टी ने कहा है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। और किसानों की ऋण आवश्यकता और उनकी वित्तीय स्थिति तथा मंडियों से बाहर भी किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता की समीक्षा करने के लिए भी एक निकाय बनाने का वादा किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया है कि इन सभी वादों को पूरा करने के लिए वह धन कहां से लाएगी, क्योंकि इन्हें पूरा करने पर सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा हटाने और मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने जैसे विभिन्न वादों को लागू करने की समय सीमा भी नहीं बताई गई है। कांग्रेस के वादों का राजकोष पर बोझ बढ़ सकता है। वर्ष 2012 के गरीबी अनुमान के अनुसार, प्रति गरीब परिवार को एक लाख रुपये का भुगतान करने पर सरकार को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च करना पड़ सकता है। सभी खाली पदों को भरने से भी खजाने पर बार-बार बोझ बढ़ेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि मतदाता किस पर भरोसा करते हैं-नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के वादों पर!

जीवन धारा

आचार्य विद्यासागर

भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य योग है। भोग, आशा-तृष्णा के द्वारा अलौकिक शांति नहीं मिल सकती है। दवा के द्वारा रोग निकल सकता है, शक्ति भोजन से ही मिलती है।

नाम के पीछे पड़कर हम भाव को भूल गए

आचार्यों, संत-महात्माओं की दृष्टि द्वेष की तरफ नहीं जाती है। आंतरिक विशेषता की तरफ ही आचार्यों की दृष्टि रहती है। यदि हम शीतल जल चाहते हैं, तो हमें पानी को गर्म हवा व उष्णता से दूर रखना पड़ेगा। अनादिकाल से कर्म का संबंध आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसे प्रेरणा, क्षेत्र, काल इत्यादि को पाकर विशुद्ध बनाया जा सकता है। अनेक व्यक्ति इस रहस्य के बारे में जानते भी नहीं हैं।

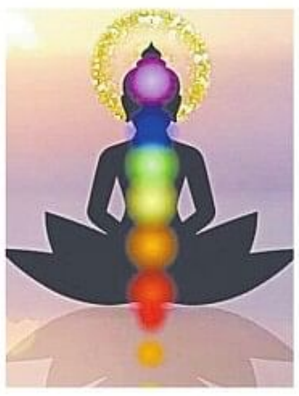

वर्तमान में विद्या का प्रचार बहुत हो रहा है। आज से 50 साल पूर्व अगर कोई मैट्रिक पास कर लेता था, तो उसे बहुत आदर मिलता था, पर आज तो अनेकों बीए, एमए, पीएचडी पास घूमते हैं। आज हम नाम के पीछे खुश हो जाते हैं। अपने गुरु का भी आदर नहीं करते। गुण दो प्रकार के होते हैं-जो विपरीत दिशा की तरफ झुक जाएं, वे अवगुण और सीधी तरफ झुक जाने पर सद्गुण हो जाते हैं। कीमत फ्रेम की नहीं है, बल्कि उसमें जड़े कांच की होती है। लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है। फ्रेम की कीमत है और कांच की नहीं। फ्रेम सारयुक्त तभी बन सकता है, जब उसमें दृष्टि के अनुसार कांच हो। हालांकि कांच की रक्षा फ्रेम से होती है। लेकिन कांच के बिना भी फ्रेम की कोई कीमत नहीं है। हमारी दृष्टि सिर्फ फ्रेम तक ही जाती है। हम आत्मा रूपी दर्पण (कांच) की तरफ नहीं देख रहे हैं। हमारी दृष्टि अंतरंग की ओर न जाकर, बाहर की ओर जा रही है। आज ऐसी विद्या की तरक्की हो रही है, जिसे ग्रहण करके विद्यार्थी दास बनता जा रहा है। विद्या ऐसी ग्रहण करनी चाहिए कि जिससे दास बनने के बजाय हम मार्गदर्शक बन जाएं। पहले व्यापार और त्याग करने में हमारा नाम पहले आता था, पर आज हम सिर्फ नाम के पीछे पड़ गए। नाम-निक्षेप के पीछे पड़कर भाव-निक्षेप को भूल गए। भाव-निक्षेप वाला ही कृत-कृत्य कहलाता है। वही सुखी बन पाता है।

आज जीवन का लक्ष्य बना है अर्थ कमाना। हमने विद्या को अर्थ का माध्यम बना रखा है। इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है, जब वह समीचीन विद्या ग्रहण करे। आज सभी अर्थ के लिए विद्या ग्रहण करते हैं। इस विद्या से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं।

भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य योग है। भोग, आशा-तृष्णा के द्वारा अलौकिक शांति नहीं मिल सकती है। दवा के द्वारा रोग निकल सकता है, शक्ति भोजन से ही मिलती है। लौकिक विद्या व भोगों में भारत से बाहर के देश बहुत आगे हैं, लेकिन वहां पर अरबपति भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। विदेशों में भी इसलिए लोग भोग से ऊब चुके हैं। हमारे आचार्यों ने ऐसी विद्या बताई है कि जिससे आना-जाना गति-भ्रमण सब खत्म हो जाता है। विद्या पाकर इधर-उधर भटकना नहीं है। समझदार व्यक्ति स्वर्गादि की इच्छा नहीं करते।

धन का सदुपयोग...

सूत्र

कीमत जौहरी की है, जवाहरात की नहीं। जवाहरात के नष्ट होने पर तो और भी उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु जौहरी का नाश होने पर जवाहरात की कीमत कौन आंकेगा? सुख के लिए हमें प्रवृत्ति को रोककर निवृत्ति को अपनाना पड़ेगा। मानव कल्याण केवल लौकिक शिक्षा से नहीं कर सकते। आज समाज के लाखों रुपये विपरीत दिशा में खर्च हो रहे हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए।

दूसरा पहलू

हरियाणा दुनिया का संभवतः पहला राज्य है, जिसने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को भी पेंशन देने की योजना शुरू की है।

बुजुर्गों की तरह पेड़ों को भी पेंशन

हरियाणा देश ही नहीं, दुनिया का संभवतः पहला राज्य है, जिसने बुजुर्गों की तरह 75 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ों को भी पेंशन देने की योजना प्रारंभ की है। दरअसल, 'प्राण वायु देवता पेंशन योजना' के तहत राज्य में कुल 3,810 पेड़ों का चयन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पेड़ को सालाना 2,750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि उस व्यक्ति के खाते में भेजी जाएगी, जो उस पेड़ की देखभाल करेगा। यही नहीं, पेड़ों के लिए निर्धारित पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। यह इसलिए भी अहम है कि इसमें पेड़ों को 'आर्थिक वस्तु' नहीं, बल्कि एक 'जीवित इकाई' के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ों को पेंशन देने का अर्थ है, उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना। इससे उनकी ऑक्सीजन व अन्य उपदान देने की क्षमता का विस्तार होगा।

सुधीर कुमार

इस योजना के तहत 40 प्रजातियों के पेड़ों को शामिल किया गया है, जिनमें पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर और कदंब आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक महत्व के पेड़ों का संरक्षण करना है।

पेड़-पौधे वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा जैव-विविधता का पोषण करने में भी सहायक हैं।

इस पेंशन योजना के तहत 40 प्रजातियों के पेड़ों को शामिल किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर और कदंब जैसे पेड़ शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य पारिस्थितिक महत्व के विशाल पेड़ों का संरक्षण करना है। इससे छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है और पुराने पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है, क्योंकि पेंशन मिलने की उम्मीद में ऐसे पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण पर जोर देती है और जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने में मददगार साबित हो सकती है।

पेड़-पौधे वातावरण से नुकसानदेह ग्रीनहाउस गैसों को अपने अंदर सोख कर ग्लोबल वार्मिंग से हमारी रक्षा करते हैं। एक वयस्क पेड़ एक साल में वातावरण से लगभग 48 पौंड से अधिक कार्बन डाई-ऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। शोध बताते हैं कि एक वर्ष में एक एकड़ में लगे पेड़ उतना कार्बन डाई-ऑक्साइड सोख लेते हैं, जितना एक कार औसतन 2,600 मील की दूरी तय कर उत्पन्न करती है।

कुछ साल पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने एक पेड़ की औसत कीमत 74,500 रुपये बताई थी। इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने की लागत और समस्त पारिस्थितिक लाभों को जोड़ा गया था। पेड़-पौधों का संरक्षण पृथ्वी की खुशहाली के लिए जरूरी है। ये वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा जैव-विविधता का पोषण करने में भी सहायक हैं। बहरहाल, बुजुर्ग नागरिकों की तरह बुजुर्ग पेड़ों को भी संरक्षित करने की यह पहल स्वागतयोग्य है, इससे देश सामाजिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से सबल हो सकता है।

आंकड़े

भारतीय स्मार्ट फोन आयातक

2023-24 के अप्रैल से जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मूल्य के 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन अमेरिका ने आयात किए।

अमेरिका	406.92
यूएई	222.12
नीदरलैंड	83.27
इटली	59.57
चेक	57.40

(आंकड़े करोड़ डॉलर में) | स्रोत: DoC

मन मिट्टी से सनी हुई सुई है और ईश्वर है चुंबक। मिट्टी के रहते हुए सुई का चुंबक के साथ संयोग नहीं हो सकता, इसलिए मिट्टी को धोना जरूरी है।

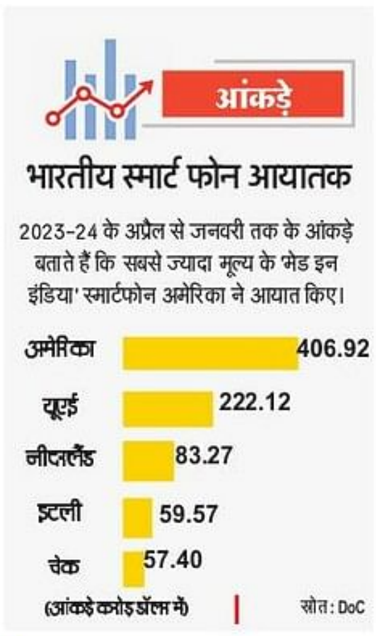

सत्संग और प्रार्थना

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आया और बोला, 'महाराज, आप कहते हैं कि संसार में रहकर में भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मैं तो रोज ईश्वर को पुकारता हूं, परंतु मन को कोई सुकून ही नहीं मिलता।'

स्वामी जी ने कहा, 'ईश्वर को पाने के लिए निरंतर सत्संग और प्रार्थना करनी चाहिए।'

उस व्यक्ति ने कहा, 'प्रार्थना तो मैं निरंतर करता हूं, प्रभु! लेकिन प्रार्थना के बाद सत्संग क्यों आवश्यक है?'

स्वामी जी ने समझाया, 'जिस प्रकार तुम अपने बाग को जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर बाड़ लगाते हो, उसी प्रकार सत्संग भी तुम्हारे मन को विकारों से दूर रखता है।'

उन्होंने उस व्यक्ति को प्रार्थना के नए ढंग बताते हुए कहा कि ईश्वर के सम्मुख रोकर प्रार्थना करो, क्योंकि रोने से मन का मैल धुल जाता है। मन मिट्टी से सनी हुई सुई है और ईश्वर है चुंबक। मिट्टी के रहते हुए सुई का चुंबक के साथ संयोग नहीं हो सकता, लेकिन जब सुई की मिट्टी धुल जाती है, तो चुंबक स्वयं उसे अपनी ओर खींच लेता है। यहां सुई से लगी मिट्टी से तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय-वासना आदि से है।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 20 जनवरी, 1952

मिस्र के दो गांवों पर अंग्रेजों का हमला

स्वेज क्षेत्र में घमासान
अंग्रेजों का दो मिस्री गांवों पर ह

स्वेज क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों ने टैंकों, तोपों व बख्तरबंद गाड़ियों से मिस्र के दो गांवों पर धावा बोल दिया। जवाब में अंग्रेजों पर भी गोलियां चलाई गईं।

पैसा है, तो दिखाएंगे

देश में नए तरह के व्यवसाय पनपने से समृद्ध भारतीयों की नई पौध जन्मी है, जिनकी क्रय शक्ति ज्यादा है और वे शानो-शौकत से जीना चाहते हैं।

मधुरेंद्र सिन्हा | चलन

जब कोई देश तरक्की के रास्ते पर चलने लगता है, तो वहां के पैसे वाले लोगों के जीने का तरीका ही बदल जाता है। वे शानो-शौकत की जिंदगी जीते हैं और खूब खर्च भी करते हैं। ऐसे में विलासिता और बड़े ब्रांड के सामान की बिक्री बढ़ जाती है। पुरुषों की कलाइयों पर महंगी घड़ियां चमकने लगती हैं, तो महिलाओं के हाथों में महंगे हैंडबैग होते हैं। स्वदेशी कारें उनकी पसंद नहीं होती हैं, बल्कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और यहां तक कि लैंबोर्गिनी उनकी पसंद हो जाती हैं। मध्य वर्ग फ्लैटों से निकल कर प्रीमियम मकान या फिर पेंट हाउस खरीदने लगता है।

ये सारी बातें इस सदी के शुरू में चीन में खूब देखने में आईं। कहते हैं कि जब पैसा आता है, तो वह सिर चढ़कर बोलता है। दुनिया का हर नामी ब्रांड वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा था।

इसी तरह नब्बे के दशक में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो यहां भी बदलाव दिखने लगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत तेजी आई है। कभी एक लैंडलाइन फोन के लिए धक्के खाने वाला शहरी भारतीय आज लाखों रुपये के मोबाइल फोन चमकाता दिख जाएगा। छोटी-सी मारुति या हुंडई की कारों में संतुष्ट रहने वाला भारतीय आज धड़ल्ले से लग्जरी कारें खरीद रहा है। वर्ष 2023 में भारत में हाई एंड कारों की बिक्री में उसके पिछले साल की तुलना में 21 फीसदी का इजाफा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और समृद्ध लोगों के रुझान बता रही है। लैंबोर्गिनी कारों की कीमतें साढ़े तीन करोड़ से लेकर पौने नौ करोड़ रुपये तक होती है। वर्ष 2023 में भारत में उसकी बिक्री बढ़कर 100 तक पहुंच गई। इसी तरह सुपर बाइकों का बाजार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दस-दस लाख रुपये की सुपर बाइकें सड़कों पर दौड़ती दिख रही हैं।

नई समृद्धि से प्रीमियम सेगमेंट के मकानों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और अब रियल एस्टेट में लग्जरी मकानों की भरमार होती जा रही है। बड़े डेवलपर करोड़ों रुपये कीमत वाले मकान बनाते जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण दिल्ली के समीप नोएडा में दिखाई पड़ रहा है, जहां कभी एक करोड़ रुपये के मकान बहुत ही कम दिखते थे और उसे प्रीमियम हाउसिंग माना जाता था, लेकिन अब वहां दस-दस करोड़ रुपये के मकान बनने लगे हैं। गुरुग्राम तो इसमें हमेशा आगे रहा है और वहां तो 30-35 करोड़ तक के मकान बन गए हैं और प्रीमियम सेगमेंट के मकानों की बाढ़ आ गई है।

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो छोटा-सा प्लॉट भी अरबों रुपये में बिकता है। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ ने बताया कि वहां इस समय तीन करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक के मकानों की खूब मांग है। जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में अच्छा-खासा पैसा कमा लिया है, वे खुलकर जिंदगी जीना चाहते हैं। उनका मोटो है-*लिव लाइफ किंग साइज*। आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 में लग्जरी मकानों की बिक्री में 2022 की तुलना में 81 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। लग्जरी मकानों की मांग इतनी है कि गुरुग्राम के एक शीर्ष डेवलपर ने सिर्फ तीन दिनों में 72 अरब रुपये के मकान बेच दिए। इनमें अल्ट्रा लग्जरी मकान भी शामिल हैं, जिनकी मांग बरकरार है। महानगरों में एक नया ट्रेंड आया है विला का। कई डेवलपर इस सेगमेंट में प्रवेश कर गए है, क्योंकि खरीदारों की मांग बढ़ती जा रही है। लग्जरी मकानों की यह चाहत अपने रुतबे को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। अति समृद्ध लोगों की लग्जरी मकानों में जबर्दस्त दिलचस्पी न केवल प्रतिष्ठा का विषय है, बल्कि बढ़िया निवेश का रास्ता भी। इसलिए एक से बढ़कर एक लग्जरी मकान देखने में आ रहे हैं।

लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनियां, जैसे गुच्ची, लुई विटो, क्रिश्चियन डीओर, शानेल, प्रादा वगैरह जो हैंड बैग बनाती हैं, उनकी कीमत लाखों में होती है और अब इनका इस्तेमाल करने वाली महिलाएं आपको भारतीय महानगरों में खूब दिखेंगी। यह उनका स्टेटस दिखाने का एक प्रयास भर है। भारत में लग्जरी घड़ियों का चलन रहा है और आने वाले समय में यह और बढ़ेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि देश में नए तरह के बिजनेस पनपे हैं। टेक्नोलॉजी ने इनमें बहुत साथ दिया है। देश में सैकड़ों स्टार्ट-अप को भारी सफलता मिली है, वेंचर कैपिटल कंपनियां काफी सक्रिय हैं। इन्हीं वजहों से समृद्ध भारतीयों की नई पौध सामने आई है, जिनकी क्रय शक्ति बहुत है और वे राजाओं की तरह शानो-शौकत से रहना चाहते हैं।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सभी जिम्मेदारी निभाएं, जीवनदायी जल बचाएं

चढ़ते पारे के बीच मौसम विभाग का आकलन खुशखबरी से कम नहीं है। पहले निजी एजेंसी स्काईमेट और अब भारतीय मौसम विभाग ने अच्छे मानसून की भविष्यवाणी करके आमजन में उम्मीद की किरण जगा दी है। मौसम विभाग के इस आकलन का इंतजार किसानों के साथ देश के हर वर्ग को रहता है। मौसम विभाग ने तो इस बार सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद जताई है। यानी 104 से 110 फीसदी बारिश होगी।

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान किसी से छिपा नहीं है। अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। एक सौ चालीस करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी जीविकोपार्जन के लिए कृषि सबसे बड़ा सहारा है। कम वर्षा होने की हालत में सरकारों को अरबों-खरबों रुपए सूखा राहत पर खर्च करने पड़ते हैं। इस इंतजाम में भ्रष्टाचारियों के वारे-न्यारे भी होते हैं। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी खुशी का मौका तो देती है, लेकिन साथ-साथ एक नई जिम्मेदारी भी देती है। सरकार को भी, सामाजिक संगठनों को भी और आमजन को भी। जिम्मेदारी यह कि सब जानते हैं कि पानी पैदा नहीं किया जा सकता सिर्फ संग्रहित किया जा सकता है। प्रकृति मानसून के रूप में हम पर मेहरबान होती है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका अच्छे तरीके से स्वागत करें। पानी व्यर्थ नहीं बहाएं और वर्षा जल को संग्रहित करने में भी अपनी भागीदारी निभाएं। देश में लम्बे समय से वर्षा जल संग्रह के लिए अलग-अलग राज्यों में अनेक योजनाएं चल रही हैं। इनमें कितनी ही तो सिर्फ कागजों पर होंगी, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसी योजनाओं का लाभ न सरकारें उठा पाती पाती हैं और न आमजन। जरूरत आज इसे पहचानने की है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना चुका है। अब देश के सामने नई चुनौतियां हैं। कहावत भी है 'जल बिन जीवन सूना'। सरकारों के साथ राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका इस मुद्दे पर अधिक बढ़ जाती है।

यदि सब मिलकर निश्चय कर लें तो वर्षा जल की एक-एक बूंद बचाकर भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है। सामान्य से बेहतर मानसून का मतलब साफ है कि प्रकृति इस बार जमकर बरसने वाली है। हम सबको अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। नदियों को जोड़ने के अभियान को भी गति देने का यह सर्वोत्तम समय हो सकता है। देश के अनेक हिस्सों में भूजल का स्तर रसातल में जा चुका है। अंधाधुंध जल दोहन नई समस्याएं पैदा कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पानी की महत्ता को न सिर्फ समझा जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए, तभी अच्छे मानसून की सार्थकता साबित हो पाएगी।

लोकसभा चुनाव 2024

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

बापतला में हुआ सबसे ज्यादा मतदान

लोकसभा चुनाव 2019 में आंध्र प्रदेश में कुल 80.38 प्रतिशत मतदान हुआ। थर्ड जेंडर का मतदान 17.79 प्रतिशत रहा। राज्य में बापतला संसदीय सीट पर सबसे ज्यादा 86.47 प्रतिशत मतदान हुआ था।

उत्तरप्रदेश: 28 के खिलाफ आपराधिक मामले

उत्तरप्रदेश में प्रथम चरण में चुनाव लड़ रहे 80 प्रत्याशियों में से 28 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 23 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रत्याशियों की ओर से घोषित संपत्ति के आंकड़ों के अनुसार 34 प्रत्याशी करोड़पति हैं।

चुनावी चटकारा

चार माह में कमियां कैसे दूर हो गईं...

राजस्थान में कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र में अपने दल के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे एक पूर्व मंत्री को मतदाताओं के सवालों का जवाब देने में पसीने आ रहे हैं। असल में दलबदल के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री के खिलाफ इस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गए थे। दिलचस्प बात यह है कि चार माह पहले विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री ने जिन्हें हराने की अपील की थी, अब वे उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। मतदाता पूछ रहे हैं कि जब ये आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे तो आपके कहने पर इन्हें हराया। अब ये दल बदलकर आपके ही पाले में आ गए तो अब आप ही इन्हें जिताने के लिए कह रहे हैं। पहले इनकी सारी कमियां गिना दी थी, अब अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए कि आप इनके लिए वोट मांग रहे हैं। आगे फिर ये आपकी पार्टी छोड़ जाएंगे तो फिर इनकी कमियां गिनाएंगे।

राग सियासी

बागी दागी निरदली,
और दलों के वीर।
नैया डगमग डोलती,
सबै तलाशैं तीर।।
सबै तलाशैं तीर,
पीर झलकत बानी में।
वोटर देखत धीर,
कौन कितने पानी में।।
दौड़भाग दिन रात,
धुकधुकी मन में लागी।
उगलत बने ना खात,
फंसे मुंह दागी बागी।।

-राम नरेश गौतम

मणिपुर शिविरों में मतदान का इंतजाम तो किया गया है लेकिन यह कितना असरकारी होगा पता नहीं

पूर्वोत्तर के 'मणि' से गायब है चुनावी चाशनी, हिंसा की आग से मतदाताओं में मायूसी

मणिपुर में इस बार हिंसा के कारण मतदाताओं में डर का माहौल है। मैतेई और कुकी आमने सामने हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन में मुकाबला है। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव का तो फैसला हो जाएगा लेकिन देखना यह होगा कि मणिपुर में हिंसा खत्म कब खत्म होगी?

इंफाल से
आनंद मणि त्रिपाठी

मुस्कुराइए आप मणिपुर में हैं... क्योंकि यह पोलो का जन्मदाता है। यह दुनिया के दुर्लभ हिरण संगाई का घर है। यह दुनिया के दुर्लभतम फूल सिरालीली का आंगन है। यह 287 वर्ग किलोमीटर में फैले एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की लोकटक झील का आंचल है। भगवान श्रीकृष्ण की सबसे मोहक, आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली रासलीला का मंचन यहां होता है। जन्मदिन हो या शादी इनके पूजन से ही कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। इन्हें यहां श्री श्री गोविंदा के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी तमाम खूबी से परिपूर्ण मणिपुर को देख आपका मन मस्तिष्क खुद ब खुद कह उठेगा मुस्कुराइए आप मणिपुर में हैं...

ऐसी खूबियों से परिपूर्ण राज्य के वीर टिकेंद्रजीत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आप जैसे ही उतरकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही ठीक सामने तीनों पद्म सम्मान से सम्मानित मुक्केबाज मैरी कॉम की तस्वीर आपका स्वागत करती है। जीवन में जीवटता की यह ऐसी तस्वीर है जो कि हर स्त्री को स्वांलबित होने का ख्वाब दिखाती है।वहीं निकास द्वार की दाहिनी तरफ आपको बांस और लकड़ी पर की गई कारीगरी यहां के लोगों के हुनर से वाकिफ कराती हैं। खुदमुख्तारी और कलाकारी की इस घेरे से निकलकर जैसे ही आप बढ़ते हैं सड़क का सन्नाटा यहां के स्याह पहलू को उजागर कर देता है। हिंसा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर पहुंचते-पहुंचते यह खबर आ गई कि एक बार फिर से विष्णुपुर, चुराचांदपुर, कोंगपोकोपाई, कुटरक और पश्चिमी इंफाल में हिंसा शुरू हो गई है। दो लोग मारे जा चुके हैं और इन इलाकों में कुकी और मैतेई के बीच जमकर फायरिंग हो रही है। इसके साथ ही आंखों में तैर रही मणिपुर की खुशनुमा तस्वीर जल सी जाती है। बाकी इनर लाइन परमिट आपको भारत के किसी अलग राज्य में होने की तस्दीक करती है।

ऐसे माहौल में मणिपुर में लोकसभा चुनाव का माहौल कैसा होगा, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। यहां न तो चुनावी नारे बज रहे हैं और न ही पोस्टर वार है। चुनावी हांडी में राजनीति बहुत ही धीमे धीमे पक रही है। करीब 16 लाख की आबादी वाले मैतेई समुदाय का राजनीति में वर्चस्व है। शहर में सन्नाटे के बीच में भाजपा कार्यालय पहुंचा। यहां एक सवाल के जवाब में भाजपा अध्यक्ष ए शारदा मुखिया कहती हैं कि चुनाव से पहले हमने लोगों को खोया है। ऐसे में हम लोकतंत्र का उत्सव उस तरह से नहीं मना रहे हैं, जिस तरह से हम मनाते आए हैं। नई दिल्ली के बाद देश में सबसे बेहतरीन प्रदेश कार्यालय तैयार कराने वाली भाजपा के इस कार्यालय में काफी चहलपहल है। रात को भी ऐसा ही नजारा है। बूथ, शक्ति केंद्र और क्षेत्र में मतदान के लिए रणनीति तैयार हो रही है। इसके बाद देर शाम में कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। यहां माहौल ठंडा है। रात के साढ़े नौ बजे हैं और सभी पदाधिकारी अपने अपने घर जा चुके हैं। कार्यालय में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बड़े बड़े बैनर छत से नीचे तक लटके हुए हैं। एक कोने पर मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर का होर्डिंग भी लगा है। कार्यालय के कर्मचारियों से जब प्रवक्ता से बात करने के लिए मोबाइल नंबर मांगा तो जवाब आया कि नंबर देना मना है। पार्टी के लोग जब आमजन को मोबाइल नंबर देने से कतरा रहे हैं, तो वे आम जनता से कैसे जुड़ेंगे। मणिपुर इनर की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 18 हजार वोटों से हार गई थी और यहां करीब सवा लाख वोट सीपीआइ ले गई थी। ऐसे में अगर यहां इंडिया गठबंधन काम करता है तो कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। यहां से कांग्रेस की तरफ से अंगमुच बिमल आकोईजम चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने भी इस गठबंधन का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रत्याशी बदलकर पूर्व आइपीएस बसंता कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा के साथ यहां एनपीपी और एनपीएफ दोनों की स्थानीय पार्टियां साथ आ चुकी हैं। वहीं जेडीयू और शिवसेना की स्थानीय इकाइयां भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। ऐसे में चल रही हिंसा के बीच मैतेई का मत मिला तो भाजपा यहां आगे निकल सकती है। यहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है।

मणिपुर आउटर में हिंसा का आलम यह है कि यहां दो चरणों में मतदान होने जा रहा है। यहां भाजपा समर्थित एनपीएफ का पलड़ा भारी है। एनपीएफ ने पिछले चुनाव में भी यहां जीत दर्ज की थी। एनपीएफ ने इस बार कचाई तिमथोई जीमक को चुनाव में उतारा है। कांग्रेस ने अल्फ्रेड आर्थर कंगम को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में भाजपा यहां नंबर दो पर थी और एनपीएफ ने यहां जीत दर्ज की थी। इस बार दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों सीटों पर यह बात साफ हो गई है कि कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन की आमने सामने लड़ाई है।

इंफाल. यहां सिर्फ महिलाओं को ही सामान बेचने की अनुमति है।

वोट डालें भी तो कैसे?

लोकसभा चुनाव 2024 में मणिपुर इनर और आउटर दोनों में ही हिंसा के कारण वोट का प्रतिशत घट सकता है। मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में अपना घर छोड़ा है। कौन कहां वोट डालेगा और कहां किसकी वोटर लिस्ट होगी यह भी पता नहीं चल पा रहा है। घाटी के शिविर में रह रहे आर्नोल्ड कहते हैं कि हम वोट कहां डालेंगे इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। मेरे जैसे हजारों लोग हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने शिविर में मतदान का इंतजाम किया है लेकिन यह कितना पुख्ता साबित होगा इसका पता 19 और 26 अप्रेल को चल पाएगा।

बतंगड़

'पार्टी' में खाते रहने की गारंटी का सुख

हरीश पाराशर

जहां देखो वहीं 'पार्टी'... पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। समझ में नहीं आता कौनसी पार्टी में जाएं और कौनसी में नहीं? ..सब कह रहे हैं कि हमारी 'पार्टी' में आ जाओ.. वैसे कहते भी हैं कि ज्यादा आनंद लेना हो तो किसी भी 'पार्टी' में चले जाओ.. बस वहां 'खाने' को मिलना चाहिए। काफी दिनों से एक ही तरह का 'खाते-खाते' उकता से गए थे इसलिए नेताजी ने नई 'पार्टी' में जाना ही मुनासिब समझा। पहले से ही किसी ने ज्ञान दे दिया था कि 'पार्टी' कैसी ही हो.. खाते वक्त दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो.. तब तक खाते रहो जब तक कि कोई ज्यादा खाने का आरोप नहीं जड़ दे। बात थोड़ी-थोड़ी समझ में आ गई थी इसलिए नेताजी बुलावे वाली एक 'पार्टी' में चले ही गए। यहां पहले से मौजूद दूसरे नेताजी 'खाते-पीते' लग रहे थे। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और फिर नए नेताजी को कंधे पर हाथ रख एकांत में ले गए.. बोले- डरना बिल्कुल नहीं.. यहां 'खाओ और खाने दो' का सूत्रवाक्य चलता है.. वैसे भी 'खाने' के लिए पार्टियां बदलते रहने में भला बुराई किस बात की...मुझे देखो .. किसी एक पार्टी के भरोसे कभी नहीं रहा..रात देखा न दिन.. आव देखा न ताव... जब भी कहीं से पार्टी का न्योता मिला फुर्ती से दौड़ पड़ा। देख नहीं रहे.. 'पार्टी... पार्टी' करते अपनी सेहत कितनी 'दुरुस्त' हो गई है...। पर इस बात की क्या गारंटी है कि वहां सभी 'खाने वाले' ही होंगे। पार्टी में ही कोई कह रहा है- 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'.. डर सा लग रहा है। खाते रहने की ही आदत है जो है। तो अभी कौनसी 'पार्टी' खत्म हुई है.. यहां मौका नहीं मिले तो दूसरी में जाकर खा लेना। तोंद पर हाथ फेरते नेताजी ने समझाया। बात समझ में तो आ रही है लेकिन 'गारंटी' कोई नहीं दे रहा। यही गारंटी न कि खाते रहो .. कोई कुछ नहीं कहेगा। 'पार्टीबाजी' में आनंद तो है पर खतरे भी कम नहीं। कहीं खाया-पिया हजम नहीं हुआ तो? मन में शंका हो गई है ..तो फिर पार्टीबाजी से ऊपर उठने का मौका भी तो है।

'पार्टीबाजी' में आनंद तो है पर खतरे भी कम नहीं। कहीं खाया–पिया हजम नहीं हुआ तो? मन में नई शंका पैदा हो गई है ... तो फिर पार्टीबाजी से ऊपर उठने का मौका भी तो है।

harish.parashar@epatrika.com

मध्यप्रदेश: जहां खास, वहां आस

कहीं प्रत्याशी कमजोर तो कहीं प्रचार

विजय चौधरी

मध्यप्रदेश में पहले चरण के लिए 19 अप्रेल को मतदान होना है। जिन छह सीटों पर मतदान होगा उनमें छिंदवाड़ा पर सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार 29 में से मात्र इसी एक सीट पर कांग्रेस कब्जा कर पाई थी। राजस्थान में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अपने पुत्रों के प्रचार में जुटे हैं, उसी तरह से छिंदवाड़ा में भी पूर्व सीएम कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ को उबारने में जुटे हैं। इसी का नाम समय है। तीनों ही अभिभावक जनता की मार खाए मौन से बैठे हैं। एक और सीट राजगढ़ की है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हैं। समग्र रूप से देखें तो खजुराहो के अतिरिक्त सभी सीटों पर भाजपा-कांग्रेस ही आमने-सामने हैं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों की टक्कर 5-7 सीटों पर ही है। भाजपा नेता भी इसे स्वीकारते हैं लेकिन दारोमदार मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कंधों पर ही है।

मध्यप्रदेश के चुनावी परिदृश्य का जायजा लेने पिछले दिनों इंदौर व भोपाल प्रवास पर आए पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के दौरान यही बात सामने आई कि यहां भाजपा व कांग्रेस में टक्कर दिखाई देती है।

सबसे अधिक चर्चा मण्डला सीट की है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में हारे फग्गनसिंह कुलस्ते को उतारा है। सामने कांग्रेस के विधायक ओंकारसिंह मरकाम हैं। रतलाम सीट पर कान्तिलाल भूरिया वर्षों से आदिवासी चेहरा हैं। उनके सामने राज्य के मंत्री नागरसिंह चौहान की पत्नी अनिता सिंह हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के प्रभाव क्षेत्र वाले धार में भाजपा की 2014 में सांसद रही सावित्री ठाकुर उम्मीदवार है वहीं उनका मुकाबला कांग्रेस से राधेश्याम मुवेल से है। इन तीनों आदिवासी सीटों के अलावा एक सीट है-राजगढ़। जहां से दिग्विजय सिंह अपने लिए सहानुभूति बटोर रहे हैं। दिग्विजय की लड़ाई सीधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। दिग्विजय और कमलनाथ दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। छिंदवाड़ा में पसीने भाजपा को भी कम नहीं छूट रहे। मुरैना विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर की सीट रही है। राजपूत और ब्राह्मण प्रमुख मतदाता हैं। भाजपा ने शिवमंगल सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के नीटू सिकरवार भी राजपूत हैं। यहां वोटों का बंटवारा हुआ तो फैसला ब्राह्मणों के हाथ रहेगा।

गठबंधन के तहत खजुराहो समाजवादी पार्टी को मिली थी। सपा ने टिकट दिया और निरस्त कर दिया । बाद में जिसे दिया, उसका निर्वाचन फॉर्म निरस्त हो गया और गठबंधन हाथ मलता रह गया। अब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को सपा और कांग्रेस ने समर्थन देकर मुकाबले में खड़ा कर दिया है। रणनीतिक तौर पर गठबंधन को यह सीट बहुत भारी पड़ी क्योंकि भाजपा ने यहां वीडी शर्मा को फिर से मैदान में उतारा है जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

विदिशा सीट भी स्टार उम्मीदवार के कारण चमक रही है। यहां से भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान को उतारा है। इस सीट पर वे पांच बार सांसद रह चुके हैं। मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से है। वे भी इसी सीट से दो बार सांसद रह चुके हैं। शिवराज के साथ उनका परिवार प्रचार में जुटा हुआ है।

गुना पर भी सबकी निगाह है। वहां भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया है। सिंधिया बीता चुनाव कांग्रेस के टिकट पर हार गए थे। उन्हें हराने वाले केपी सिंह यादव का टिकट काट कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव को मौका दिया है। इस बार वे छाछ को भी फूंक-फूंककर पी रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प है। कमलनाथ, शिवराज और दिग्विजय की तरह सिंधिया के साथ भी परिवार मैदान में उतरा हुआ है।

वैसे कांग्रेस सागर, दमोह और उज्जैन सीट को भी मुकाबले में मान रही है, मगर भाजपा कहती है, 'इस बार 29 की 29 सीटें बड़े अंतर से जीतेंगे।' कांग्रेस प्रत्याशी स्टार प्रचारकों को छोड़ जनसंपर्क और जातियों को साधने पर ही जोर दे रहे हैं तो भाजपा दल बदल के जरिए सियासी समीकरणों को अपने हाथों में लेते जा रही है। पहले चरण के बाद चुनाव के नए रंग-ढंग देखने को मिलेंगे।

आदिवासी क्षेत्र प्रभावी

मूलत: मध्यप्रदेश में आदिवासी क्षेत्र चुनावी मुद्दा बना हुआ है। इस बार मतदाता कुछ मुखर भी है। आदिवासियों को यह समझा दिया है कि भाजपा उनकी जमीनें छीनना चाहती है। कांग्रेस उनकी जमीनें लौटाना चाहती है। प्रदेश में 22 प्रतिशत आदिवासी हैं। इसी प्रकार किसान भी उत्साहित नहीं है। वोट तो मिलेगा किन्तु प्रतिशत कम हो सकता है। इनका मुख्य मुद्दा समर्थन मूल्य का है। सरकार ने चावल और गेहूं का क्रमश: 3100 और 2700 रुपए क्विंटल मूल्य तय तो कर दिया किन्तु मिला आज तक नहीं। किसान एक-एक मुट्ठी धान और गेहूं देकर इसका मूल्य मांग रहे हैं। बीमा राशि (फसल) में भी भ्रष्टाचार हावी है। घोषणा हजारों-करोड़ों की होती है। घर तक बहुत कम पहुंच पाता है। नहीं भी पहुंचता। इंदौर-भोपाल के किसान एक ही भाषा में बात करते हैं। कीटनाशक, खाद, बीज पर जो खर्चा आज हो रहा है, वह भी नहीं निकले तो खेती क्यों करें।

तमिलनाडु: दागी-करोड़पति प्रत्याशी

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान होगा। यहां 950 प्रत्याशी मैदान में हैं। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 137 ने अपने खिलाफ आपराधिक और 80 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

किस पार्टी के कितने प्रत्याशी करोड़पति

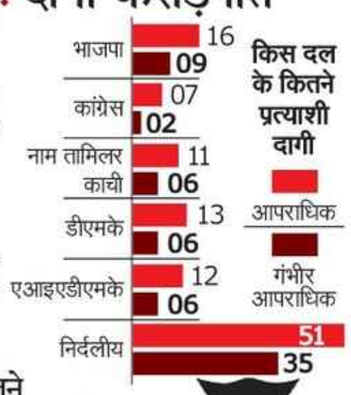

पोलीटून

आज का सवाल

भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

जान का भी खतरा

इजरायल और ईरान में भारतीयों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही भारत दोनों देशों के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापारिक संबंध साझा करता है जिससे भारतीय बाजार प्रभावित हो सकता है।

-राहुल कुमार पालीवाल, राजसमंद

व्यापार होगा प्रभावित

ईरान एवं इजरायल के बीच तनाव का भारत पर आर्थिक रूप से असर पड़ सकता है। सोना एवं क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू सकते हैं। शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो सकती है। वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है।

-ललित महालकरी, इंदौर

अर्थव्यवस्था पर असर

दो देशों के बीच बढ़ते तनाव से विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। ईंधन और सोने के रेट अप्रत्याशित रूप से बढ़ेंगे। किराए में वृद्धि हो सकती है। तनाव बना रहा तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

सतीश उपाध्याय, मनेंद्रगढ़ एमसीबी छत्तीसगढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'ईरान-इजरायल के बीच तनाव का भारत पर क्या असर होगा?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://rb.gy/9cj8my

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को रोकना जरूरी

पश्चिम एशिया में बढ़ रहे तनाव इस क्षेत्र के लिए खतरनाक तो है ही, लेकिन यह विश्व के लिए भी नुकसानदायक है। हमास व इजराइल युद्ध के बाद से ईरान जिस तरह सक्रिय हुआ है, इसे कूटनीतिक भाषा में अतिसक्रियता कही जा सकती है। विश्व पहले से ही रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से प्रभावित है, उसके बाद हमास व इजराइल के बीच जंग छिड़ने से संकट और बढ़ गया है। अब ईरान की ओर से इजराइल पर ड्रोनों व मिसाइलों से हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। ईरान की चाहे इजराइल से जो भी अदावत रही हो, लेकिन ईरान ने बदले की भावना से इजराइल पर हमले के लिए समय गलत चुना है। अमेरिका ने जिस तरह पहले ही चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हमला किया तो, वाशिंगटन चुप नहीं बैठेगा, इसके बाद भी ईरान ने इजराइल के ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका व ईरान के बीच तनातनी लंबे समय से है, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध से ईरान अमेरिका पर अधिक खफा है। यूं तो अमेरिका का यह प्रतिबंध अनुचित है, पर खफा ईरान अमेरिका को सबक देने की ताक में रहता है। इजराइल व हमास की जंग उसे यह मौका दे रही है, लेकिन ईरान समझ नहीं पा रहा है कि हमले करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, कूटनीतिक चैनल अधिक उपयोगी है। यूं तो जैसे इजराइल पर अमेरिका का हाथ है, वैसे ही ईरान पर रूस व चीन का हाथ है, लेकिन इजराइल व ईरान जैसे छोटी आबादी वाले देशों को समझना होगा कि वे अमेरिका, रूस व चीन जैसे बड़े व शक्तिशाली देशों की महत्वाकांक्षा व आपसी अदावत के शिकार न बनें। यूक्रेन से जंग में रूस केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, बल्कि वह यूएस व नाटो से भी लड़ रहा है, यूएस रूस को घुटने पर लाना चाहता है, पर क्यों यह अमेरिका को भी पता नहीं होगा। लेकिन इसमें बर्बादी यूक्रेन की हो रही है। ऐसे ही इजराइल व हमास की जंग में पहले जिस तरह ईरान, कतर, आतंकी गुट हुती और कई मुस्लिम देश आतंकी गुट हमास के पक्ष में खड़े हो गए तो अमेरिका भी खुल कर इजराइल के पक्ष में आ गया। लेकिन बर्बादी तो गाजा पट्टी में हो रही है, लोग वहां के मारे जा रहे हैं। अरब स्प्रिंग के बाद पश्चिम व खाड़ी देशों में एक के बाद एक कई राजशाही का तो अंत हो गया, लेकिन वहां लोकतांत्रिक ढांचा विकसित नहीं पाया, इसके चलते वहां अराजकता की स्थिति पैदा हुई। इसका फायदा कुछेक प्रायोजित आतंकी गुटों ने उठाया, कमजोर सरकारें भी हैं, इसलिए क्षेत्र में अशांति है। तेल के खेल में यह क्षेत्र हमेशा पिसता रहा है, इसके बावजूद शायद पश्चिम व अरब क्षेत्र के मुल्कों को यह भान नहीं हो रहा है कि वे शांति की स्थापना के लिए काम करें, वे बाहरी तत्वों के हितों के शिकार न बनें। ईरान ने इजराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया में शांति बहाली के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। इजराइल ऐसा मुल्क है जो अपने ऊपर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है, और बदला लेता है। बेशक अभी इजराइल हमास के साथ जंग में उलझा हुआ हो, लेकिन वह ईरान को यूं नहीं छोड़ेगा। अब इजराइल व ईरान के बीच दुश्मनी की बीज गहरी हो गई है, जो लंबे समय तक चलेगी। ईरान के कदमों से वैश्विक शांति की राह नहीं निकलेगी। ईरान के हमले की गूंज भारतीय शेयर बाजार तक पहुंची है, पश्चिम एशिया में तनाव के चलते शेयर बाजार औंधे मुंह गिरे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव को रोकने के लिए भारत, अमेरिका व चीन शांति के लिए आगे आएं।

विश्लेषण
निर्मल यादव

हिंदुत्व से सनातन की ओर सियासत

> इस बार का चुनाव इस मायने में अलग माना जा रहा है कि इसमें धर्म की राजनीति, एक नए शब्द के साथ की जा रही है। इस बार चुनाव में बात 'सनातन' की हो रही है। मजे की बात तो यह है कि उत्तर भारत में भाजपा सनातन पर हमला होने को लेकर जो माहौल बना रही है, वह हमला द्रविड़ अस्मिता का गढ़ रहे तमिलनाडु से हुआ है। उत्तर भारत में 'सनातन' को शाश्वत बताकर संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, जिसकी वजह से इसे सनातन संस्कृति का दर्जा दिया गया है। दक्षिण भारत से यदि इसके तार जोड़े जाएं तो यह आर्य बनाम अनार्य का सनातन संघर्ष है। इसे हिंदुत्व से सनातन की ओर राजनीतिक शिफ्टिंग माना जा सकता है।

इन दिनों भारत के नागरिक लोकतंत्र के महापर्व को पूरे जोश से मनाने के लिए तैयार है। अब तक के चुनावों में सियासी दलों की ओर से उठाए गए मुद्दों के आधार पर जनता, भावी सरकार की तस्वीर उकेरती थी, लेकिन इस चुनाव में मतदाताओं को यदि इस महापर्व को मनाने का जतन करना पड़ रहा है, तब फिर साफ है कि इस चुनाव के मुद्दे, गुजरे चुनावों से अलहदा हैं। चुनाव के मुद्दों की बात करने से पहले, चुनाव की ही बात कर ली जाए कि आखिर यह पिछले चुनावों से अलग क्यों है? भारत में आम चुनाव की परंपरा 75 साल पुरानी है। आजाद भारत के इतिहास में अब तक हुए 17 चुनाव किसी न किसी रूप में पिछले चुनावों से भिन्न रहे हैं। इस परंपरा को 18वां आम चुनाव भी शिद्दत से निभा रहा है। कई मायनों में यह चुनाव अनूठा है। इसमें तमाम सियासी दलों का भविष्य दांव पर लगा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सियासत में जातिवाद, परिवारवाद और बाहुबल की गहरी हो चुकी जड़ों का भविष्य भी यही चुनाव तय करेगा। इस चुनाव का फौरी तौर पर किया जा रहा विश्लेषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्तकबिल को तय करने तक सीमित है, वहीं इस चुनाव का विशद विश्लेषण, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल की भवितव्यता को भी सुनिश्चित करेगा।

यह चुनाव इस मायने में अलग है कि इसमें धर्म की चाशनी को इस कदर गाढ़ा करके पेश किया गया है कि इसकी खुमारी अब मतदाताओं के सिर चढ़कर बोलने लगी है। धर्म एक सार्वभौमिक सत्य है और इसका दायरा सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर सत्ता की ड्योढ़ी को यह अनादि काल से प्रभावित करता रहा है। दुनिया भर में राजनीति को धर्म के साथ पेश करने के अलौकिक आनंद की अनुभूति 'सनातन' रही है। भारत में भी यह बहस पुरजोर होती रही है कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए या राजनीति का धर्म होना चाहिए। मनुस्मृति से लेकर हम्मूराबी की विधि संहिता तक, न जाने कितनी बार राजनीति को धर्म से अलग करने या इसी में समाहित करने की वकालत हो चुकी है। 21वीं सदी के भारत में एक बार फिर नए शब्द के आवरण में चुनाव के असल मुद्दों को ढकने की कवायद तेज हुई है, यह है 'सनातन'।

अब तक के चुनावों में 'धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म' विषय ही विमर्श का मुद्दा बनता था, मगर अब 'सनातन' शब्द ने ऐसे बहुत से नेताओं को पाला बदलने का सुरक्षा कवच दे दिया है, जिनका सनातन के सही मायने से भी कोई सरोकार नहीं है। समाज और व्यक्तियों के स्तर पर हर किसी ने अपनी समझ के आधार पर सनातन को परिभाषित किया है। सनातन का विशद और व्यापक स्वरूप ही इसे परिभाषित करने वाले समाज एवं व्यक्तियों की समझ को परखने का कारगर औजार भी बनाता है। इसलिए कम से कम यहां सनातन को परिभाषित करने के बजाए मौजूदा चुनावी मौसम में इसके सियासी गुणा-गणति पर बात करना बेहतर होगा। यह पहला चुनाव नहीं है, जब इस देश ने धर्म को राजनीति का चोला पहने देखा हो। इससे पहले आजादी के बाद शुरुआती दौर में सोमनाथ से शुरू हुई यह कहानी अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर 1990

के दशक में विवादित ढांचा ढहाए जाने तक, चुनावी राजनीति के आवरण में ढंकी रही। मंदिर और मस्जिद के नाम पर होती रही राजनीति का लाभ, इससे सरोकार रखने वाले दोनों खेमों को मिलता रहा है। मंदिर के मुद्दे ने भाजपा के चुनावी सफर को सड़क से सत्ता तक पहुंचाया तो मस्जिद के नाम पर भाजपा के विरोधी दलों को भी सत्ता की खूब मलाई खाने को मिली।

इस बार का चुनाव इसी मायने में अलग माना जा रहा है कि इस चुनाव में धर्म की राजनीति, एक नए शब्द के साथ की जा रही है। इस बार चुनाव में बात 'सनातन' की हो रही है। मजे की बात तो यह है कि उत्तर भारत में भाजपा सनातन पर हमला होने को लेकर जो माहौल बना रही है, वह हमला द्रविड़ अस्मिता का गढ़ रहे तमिलनाडु से हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन विरोध का मोर्चा खोल रखा है। दरअसल उत्तर भारत में 'सनातन' को शाश्वत बताकर संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, जिसकी वजह से इसे सनातन संस्कृति का दर्जा दिया गया है। बोलचाल की भाषा में भी हिंदी पट्टी के लोग सिर्फ सनातन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि 'सनातन संस्कृति' कहना ज्यादा पसंद करते हैं।

दक्षिण भारत से यदि इसके तार जोड़े जाएं तो यह आर्य बनाम अनार्य का सनातन संघर्ष है। हिंदी भाषी राज्यों में आम जन को भले ही आर्य बनाम अनार्य के प्राचीन संघर्ष का इल्म न हो, लेकिन अपनी कला, संस्कृति, पहनावा और भाषा को लेकर बेहद सजग रहे दक्षिण भारत में जन जन को इस संघर्ष का भान है। आजादी के बाद 1950 के दशक में भाषायी आधार पर राज्य बनाने के लिए दक्षिण भारत में हुए आंदोलन, इस संघर्ष के गवाह भी हैं। तत्कालीन नेहरू सरकार को इस मसले पर तीन सदस्यीय 'जेवीपी कमेटी' बनानी पड़ी थी। खुद पं नेहरू के अलावा सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया राजू की मौजूदगी वाली इस समिति को दक्षिण में भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन के लिए हुए आंदोलन को शांत करना पड़ा था। भाषायी राज्य बने।

अब 21वीं सदी के सबसे चर्चित चुनाव से पहले उदयनिधि ने अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिक्रिया में सनातन पर हमला नहीं किया, बल्कि इस हमले की जड़ काशी में है। पीएम मोदी की पहल पर काशी में चल रहे 'तमिल संगमम' की सफलता, उदयनिधि की प्रतिक्रिया का परिणाम है। पीएम मोदी की पहल पर हो रहे तमिल संगमम का मौन असर काशी से ज्यादा दक्षिण में हो रहा है। यही वजह है कि इस चुनाव में भाजपा ने राजनीति में भरपूर इस्तेमाल हो चुके 'हिंदुत्व' शब्द के बजाय व्यापक अर्थ वाले 'सनातन' शब्द को मारक हथियार बनाया है। अव्वल तो इस शब्द के निहितार्थ, धर्म और समाज के इतिहास को गहराई से समझने वाले ही जानते है। ऐसे में आर्य और भारतीय अस्मिता के विशद स्वरूप की गहरी समझ रखने वाले भाजपा के रणनीतिकारों को पता है कि सीमित ज्ञान से लैस विपक्षी खेमे के अधिसंख्य राजनेताओं को सनातन के जाल में फंसाना आसान है। बेहतर होता, उदयनिधि सनातन पर हमला करने से पहले उस रावण का जिक्र करते, जिसे दक्षिण में पूज्य और उत्तर में धरती का सबसे प्रकांड पंडित माना जाता है। उदयनिधि को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि शिव जी के सबसे प्रिय भक्त रावण के पांडित्य पर उत्तर भारत में कभी सवाल नहीं उठा। सिर्फ राम के साथ बैर होने के कारण ही रावण को उत्तर में आज भी हर साल दहन होना पड़ता है। ऐसे में उदयनिधि के लिए भी बेहतर होता कि वे एक बार रावण की उस 'रक्ष संस्कृति' का अध्ययन कर लेते, जिसकी वजह से आज भी आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को 'राक्षस' समझा जाता है, जबकि दक्षिण की मान्यता है कि आर्य संस्कृति के विरोध में रावण द्वारा प्रवर्तित की गई रक्ष संस्कृति को मानने वाले राक्षस कहे जाते हैं। उदयनिधि भेद को समझकर यदि सनातन का मुद्दा उठाते तो भाजपा इस चुनाव में राम मंदिर और सनातन को अलग करके लाभ नहीं ले पाती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

जमीनी हालात
आर.के. सिन्हा

पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा पर प्रदर्शन दोहराने का दबाव

जिस पूर्वोत्तर भारत में सूरज की किरणें सबसे पहले पहुँचती हैं वहाँ की जानता तैयार है, एकबार फिर लोकसभा चुनावों में अपना फैसला सुनाने के लिए। बेशक, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है , तो 25 सीटें पूर्वांचल प्रदेशों की भी उसमें शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आगामी 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अगर बात पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी ने जो झंडे गाड़े थे, उसे इस बार भी थामे रखने का पार्टी को पूरा भरोसा है। इस भरोसे के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह से पूर्वोत्तर की विकास की योजनाएं सिरे चढ़ाई हैं, उसके बाद वहां की जनता उनकी पार्टी और सरकार को कभी नहीं भूलेगी। इसमें एक पक्ष यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूरे पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न शांति समझौते के तहत एक स्थायी शांति का माहौल बनाया है। चुस्त आंतरिक सुरक्षा के कारण ही पूर्वोत्तर के पूरे इलाके में कोई बड़ी हिंसक वारदात सुनाई नहीं पड़ रही है। हां मणिपुर इसका एक अपवाद अवश्य है और वहाँ भी गृह मंत्रालय ठोस समाधान की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर की "सेवन सिस्टर्स" या सात बहनें कही जाने वाली राज्य इकाइयों समेत क्षेत्र के सभी आठ राज्यों को मिलाकर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। असम में सबसे ज्यादा लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 25 में से 21 सीटें मिलीं थीं। भाजपा अब की बार पिछला आंकड़ा पार करना चाहती है।

अभी तक इंडिया गठबंधन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक पूर्वोत्तर के राज्यों में लगा है। ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी पिछले चुनावों में यहां कुछ करने की एक अलग कोशिश की भी थी, लेकिन इस बार वह कोशिश भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शरद पवार खुद अपनी पार्टी और अपनी वजूद के लिए अपने भतीजे से लड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी अपने घर में ही भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक उपद्रवियों को बचाने के कारण घिरी हुई हैं। पूर्वोत्तर में भाजपा पर विश्वास की वजह पिछले दस साल में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की सक्रिय रूप से विकास पर फोकस और शांति स्थापना की कोशिश है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारी डॉ. संबित पात्रा और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा के लगातार प्रवासों और दिन-प्रतिदिन की मॉनिटरिंग ने पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के संगठन को मज़बूत ही किया है । मणिपुर में हालांकि केवल 2 लोकसभा की सीटें है, लेकिन मोदी सरकार के लिए वहाँ के जनजातीय संघर्ष को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मणिपुर हिंसा इस समय एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, जो एकतरह से पिछली कांग्रेसी सरकारों की देन ही मानी जाती है। इस दशकों पुरानी समस्या के किसी सर्वमान्य निर्णय की लगातार कोशिश गृह मंत्री अमित शाह कर भी रहे हैं। हाल ही में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के सबसे पुराने सशस्त्र समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सामान्य रूप से उत्तर पूर्व और विशेष रूप से मणिपुर में शांति के एक नए युग की संभावना को जन्म देता है। पहली बार है कि घाटी स्थित एक मणिपुरी सशस्त्र समूह हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और संविधान और देश के कानूनों का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल यूएनएलएफ और सुरक्षा बलों के बीच शत्रुता को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी शताब्दी से अधिक समय से हजारों लोगों की जानें लीं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को दूर करने का अवसर भी प्रदान करेगा। यूएनएलएफ 1964 से ही सक्रिय था और यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह अपना ऑपरेशन चला रहा था। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही तत्पर और सक्रिय हैं। मोदी सरकार ने न केवल इन समस्याओं के स्थायी निदान के लिए पहल की, बल्कि उग्रवादी गुटों को भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ईमानदारी से कोशिश की। असम में पिछले 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा ने भारत और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर कायम है। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में हिंसा के काले दौर को समाप्त करने की एक ईमानदार कोशिश हुई। अब नजरें इस चुनाव पर हैं।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अशांत मन में अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप और ध्यान करें

संकलित
दर्शन

शुकदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? शुकदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं। ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है।

लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? शुकदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कहीं थीं, कि धरती पर जो धन-संपत्ति है, वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। परीक्षित ने शुकदेव की बातें ध्यान से सुनीं और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुकदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान, पूजा-पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे मन शांत होता है।

मानव धर्म ही सर्वोपरि

संकलित
प्रेरणा

एक विदेशी को अपराधी समझ जब राजा ने फांसी का हुक्म सुनाया तो उसने अपशब्द कहते हुए राजा के विनाश की कामना की। राजा ने अपने मंत्री से, जो कई भाषाओं का जानकार था, पूछा- यह क्या कह रहा है? मंत्री ने विदेशी की गालियां सुन ली थीं, किंतु उसने कहाः महाराज! यह आपको दुआएं देते हुए कह रहा हैः आप हजार साल तक जिएं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक अन्य मंत्री ने जो पहले मंत्री से ईर्ष्या रखता था, आपत्ति उठाईः महाराज! यह आपको दुआ नहीं गालियां दे रहा है। वह दूसरा मंत्री भी बहुभाषी था। उसने पहले मंत्री की निंदा करते हुए कहाः ये मंत्री जिन्हें आप अपना विश्वासपात्र समझते हैं, असत्य बोल रहे हैं। राजा ने पहले मंत्री से बात कर सत्यता जाननी चाही, तो वह बोलाः हां महाराज! यह सत्य है कि इस अपराधी ने आपको गालियां दीं और मैंने आपसे असत्य कहा। पहले मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहाः तुमने इसे बचाने की भावना से अपने राजा से झूठ बोला। मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर तुमने राजधर्म को पीछे रखा। मैं तुमसे बेहद खुश हुआ। फिर राजा ने विदेशी और दूसरे मंत्री की ओर देखकर कहाः मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। निर्दोष होने के कारण ही तुम्हें इतना क्रोध आया कि तुमने राजा को गाली दी और मंत्री महोदय तुमने सच इसलिए कहाः क्योंकि तुम पहले मंत्री से ईर्ष्या रखते हो। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं। तुम इस राज्य से चले जाओ। वस्तुतः दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से अन्य की हानि होने के साथ-साथ स्वयं को भी नुकसान ही होता है।

अंतर्मन

आज की पाती

जीना मुश्किल कर रहा वायु प्रदूषण

हाल ही में स्विस ग्रुप आईक्यू एयर ने विश्व भर के उन देशों की सूची जारी की है जिनमें सबसे ज्यादा प्रदूषण है। इस सूची में हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है। इस सूची के अनुसार पिछले साल 134 देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद हमारे देश की वायु गुणवत्ता बेहद खराब थी। वर्ष 2019 में भी ग्रीनपीस और एयर विजुअल की रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत के बहुत से शहरों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के सात शहर भी शामिल हैं। यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। **-मनीष देवांगन**, दुर्ग

ट्रेंड

हैरान करने वाला

कांग्रेस के गठबंधन वाली बिहार की आरजेडी के नेता कहते है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। जिनके अपने नेता खुद जेल में गए हों, वो मोदी जी को जेल में डालने की बात करते हैं। उनका कथन हैरान करने वाला है।

-राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री

इनाम स्वरूप

भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कारवाई करने की बजाय इसके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं।

-लालू यादव, राजद नेता

ऐसा करके दिखाएंगे

दिल्ली के उपराज्यपाल साहब और भाजपा के नेता कह रहे थे, जेल से दिल्ली की सरकार तो नहीं चलेगी। हमने साफ कहा कि सरकार तो जेल से ही चलेगी, तुमको पीछे हटना पड़ेगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ऐसा करके पूरे देश को दिखाएंगे।

-संजय सिंह, आप नेता

निराशाजनक

आईपीएल की शीर्ष फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को घरेलू मैदान पर अपमानित होते देखना निराशाजनक है। हार्दिक पंड्या कप्तानी और प्रदर्शन में संतुलन बिठाने में अभिभूत नजर आ रहे हैं।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

करंट अफेयर

डेलावेयर में बैसाखी के मौके पर किया गया भांगड़ा

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के गृह राज्य डेलावेयर के सात जनप्रतिनिधियों के एक समूह ने बैसाखी पर्व के मौके पर सिख समुदाय के साथ जुड़कर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। सभी जनप्रतिनिधि परंपरागत पंजाबी पोशाक पहनकर आये थे। इस समूह में डेलावेयर सीनेट में बहुमत दल के नेता ब्रायन टाउनसेंड, सीनेट बहुमत दल की सचेतक एलिजाबेथ लॉकमैन, सीनेटर स्टेफनी हांसेन, सीनेटर लॉरा स्टुरगियोन और राज्य प्रतिनिध पॉल बॉमबैश, शैरी डोर्सी वॉकर और सॉफी फिलिप्स शामिल थीं। एक जनप्रतिनिधि के सहयोगी भी इस प्रस्तुति में समूह का हिस्सा बने। टाउनसेंड ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के समूह ने भांगड़ा प्रशिक्षक भारतीय अमेरिकी विश्वास सिंह सोढ़ी से दो महीने करीब 30 घंटों तक नृत्य सीखा था। उन्होंने कहा, 'हमने करीब दो महीने में 30 घंटे तक अभ्यास किया था। हम आठ लोग थे। हमने साथ मिलकर जितना हो सकता था अभ्यास किया और हमारे पास विश्वास सिंह जैसे एक बेहद शानदार कोच थे।' जनप्रतिनिधियों द्वारा पहनी गयी पोशाक भारत में सिली गयी थी और वहीं से मंगवाई गयी थी। टाउनसेंड ने प्रस्तुति के बाद बताया, 'हमें इस बात की खुशी है कि (भांगड़ा करते वक्त) हममें से कोई भी नहीं गिरा।

ऑफ बीट

समुद्र में दुष्ट लहरें होती है विशाल लहरें

दुष्ट लहरें समुद्र की बहुत विशाल लहरें होती हैं – अपने आसपास की लहरों से दोगुनी ऊंची – जो कहीं से भी प्रकट होती हैं। दस मंजिला इमारतों जितने ऊँचे पानी के अकल्पनीय पहाड़ों की कहानियाँ सदियों से समुद्री लोककथाओं और साहित्य में व्याप्त हैं। हाल की तकनीक ने वैज्ञानिकों को समुद्र में लहरों का पता लगाने में सहायता दी है, जिससे किंवदंती वास्तविकता बन गई है। पहला और सबसे प्रसिद्ध माप ड्रापनर लहर का था, जो 1 जनवरी 1995 को उत्तरी सागर में 25.6 मीटर का राक्षस दर्ज किया गया था। अवलोकनों के बावजूद, हम अभी भी नहीं जानते कि दुष्ट लहरें कितनी बार उठती हैं, या क्या हम उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। दुष्ट लहर के रिकॉर्ड में ऐसी कोई खास विशेषताएं शामिल नहीं होती हैं, जो इसे इसके चारों ओर के समुद्र को अलग करती हैं, इसलिए हम तुलना नहीं कर सकते हैं या इसके बनने के लिए जरूरी आवश्यक स्थितियों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हमारी टीम दक्षिणी महासागर में दुष्ट लहरों का पीछा करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी आइसब्रेकर एस.ए. अगुलहास–I पर रवाना हुई, जहां शक्तिशाली हवाएं पृथ्वी की सबसे भयंकर लहरों को आकार देती हैं। दुष्ट लहरें क्या पैदा करती हैं?

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।